

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



दिसंबर 2020

खंड 74 अंक 12

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
देबा प्रसाद रथ
राजीव रंजन
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर
एस. गंगाधरन

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2020

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य 1

मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21

मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प, दिसंबर 2020 9

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 13

भाषण

भारत में वित्तीय बाजार सुधारों को गति देना
शक्तिकान्त दास 19

लेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 25

तत्काल स्थानिक गति संकेतक आर्थिक गतिविधि 43

सरकारी वित्त 2020-21 : अर्धवार्षिक समीक्षा 55

भारत में ग्रामीण – शहरी मुद्रास्फीति के आयाम 83

कोविड-19 काल में विनिमय दर अस्थिरता को नियंत्रित करना 95

सेवा और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण: हालिया प्रवृत्ति 103

बैंक ऋण सर्वेक्षण- हालिया रुझान 115

भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर मौसमी परिवर्तन का प्रभाव 125

वर्तमान सांख्यिकी 143

हाल के प्रकाशन 189

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य*

शक्तिकांत दास

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 2, 3 और 4 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसने घरेलू और वैश्विक दोनों के वर्तमान समष्टि आर्थिक और वित्तीय विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उन्नत संभावनाओं की समीक्षा की। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ने के लिए मतदान किया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक आवश्यक हो तब तक मौद्रिक नीति के निभावकारी रुख को जारी रखा जाए - कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष के दौरान - ताकि यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित किया जाए तथा COVID-19 के प्रभाव को कम किया जाए। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। रिजर्व रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है।

मैं आज इस अवसर पर अपनी मौद्रिक नीति के निर्णय में योगदान देने वाली बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन के लिए समिति के सदस्यों की सराहना करना चाहता हूँ। मैं रिजर्व बैंक में हमारी टीमों को उनके विश्लेषणात्मक और बौद्धिक सहायता, तथा तार्किक सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा।

मैं आज अपनी बात एमपीसी के निर्णय और उसके औचित्य के दौरान आए विचारों को स्थापित करते हुए शुरू करना चाहता हूँ। एमपीसी का विचार था कि सर्दियों के महीनों में नष्ट होने योग्य वस्तुओं की कीमतों में राहत और बम्पर खरीफ के आगमन के साथ मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी की संभावना है। यह संवृद्धि के समर्थन में कार्य करने के लिए उपलब्ध स्थान का उपयोग करने से वर्तमान समय में मौद्रिक नीति को बाधित करता है। उसी समय, बहाली के संकेत वैविध्यपूर्ण होने से बहुत दूर हैं और निरंतर नीतिगत समर्थन पर निर्भर हैं। आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों,

अत्यधिक मार्जिन और अप्रत्यक्ष करों द्वारा संवर्धित किए जा रहे मुद्रास्फीति सीढ़ी को तोड़ने के लिए अग्रसक्रिय आपूर्ति प्रबंधन कार्यनीतियों के लिए एक छोटी विंडो उपलब्ध है। आपूर्ति पक्ष द्वारा संचालित मुद्रास्फीति के दबावों को कम करने के लिए और प्रयास की आवश्यकता है। एमपीसी व्यापक समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को संभालने के लिए मूल्य स्थिरता के सभी खतरों की बारीकी से निगरानी करेगा। तदनुसार, एमपीसी ने आज निर्णय लिया कि नीतिगत दर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए और जब तक आवश्यक हो, तब तक निभावकारी रुख जारी रखा जाए- कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष के दौरान - ताकि यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित किया जाए तथा COVID-19 के प्रभाव को कम किया जाए।

वर्ष 2020 बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। इसने हमारी क्षमताओं और यहां तक कि शक्ति, धैर्य और भाग्य के हमारे आंतरिक भंडार का परीक्षण और विस्तार किया है। जैसे-जैसे वर्ष की समाप्ति करीब आ रही है, वैसे ही हमारे कार्यों और परिणामों की समीक्षा करना उचित होगा कि कैसे हमने महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मेरे विचार में, इस सर्वव्यापी प्रयास में, हर उस ट्राइल को लड़ने और उस पर काबू पाने का हमारा दृढ़ संकल्प था, जो हमारी सहायता के लिए तैयार था। मुझे यहां महात्मा गांधी के शब्द याद आ रहे हैं और उसे मैं उद्धृत करता हूँ: “शक्ति एक अदम्य इच्छाशक्ति से आती है।” वहां से सबक लेते हुए, मैं आगे के लिए हमारे विजन को स्थापित करने की कोशिश करूँगा।

2020: एक यादगार वर्ष

जब इस महामारी के निश्चित इतिहास को लिखा जाएगा, तो वर्ष 2020 को आधुनिक सभ्यता के इतिहास में एक निर्दिष्ट वर्ष के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिसे महामारी द्वारा चिह्नित किया जाएगा, जो कि 1918 के स्पैनिश फ्लू के अपने पैमाने से तुलनीय और 1930 के दशक के महामंदी के आर्थिक नुकसान से अधिक है। COVID-19 तब ही आया जब दुनिया गतिविधि के एक समकालिक मंदी की चपेट में थी जिसने इस यातना को और भी कष्टदायी बना दिया। इस मानवीय और आर्थिक त्रासदी के साथ-साथ, इतिहास केंद्रीय बैंकों और सरकारों, स्वास्थ्य प्रणालियों

* गवर्नर का वक्तव्य - 4 दिसंबर 2020

और कर्मियों, नागरिक समाज संगठनों और सबसे ऊपर, आम लोगों की अभूतपूर्व प्रतिक्रिया को भी दर्ज करेगा।

साथ में, हम मानवीय नुकसानों को नियंत्रित करने में कामयाब रहे, यह सुनिश्चित किया कि वित्तीय प्रणाली और बाजार सामान्य रूप से काम करते रहे, वित्त उपलब्ध रहे और प्रवाहमान रहे, और सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे। इसका परिणाम यह हुआ कि निकट अवधि के वित्तीय स्थिरता जोखिमों को समाहित कर लिया गया है। आर्थिक संकुचन सहज होने लगे हैं, उभरते बाजारों में पोर्टफोलियो प्रवाह में सुधार हुआ है और मजबूत क्रेडिट रेटिंग वाले लोगों के लिए हार्ड मुद्रा बांड का निर्गम संवर्धित हुआ है।

इस पूरी अवधि में, रिज़र्व बैंक ने वायरस द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने और भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए प्राथमिक रूप से कार्य किया। सम्पूर्ण प्रयास यह है कि आगे बढ़ते हुए, उत्पादन और रोजगार के नुकसान को समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के वातावरण में जल्दी से पुनः प्राप्त किया जाए।

हमारे कार्यसूची में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं के हित के संरक्षण के साथ, हम तेजी से दो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति को हल कर सकते हैं। हम वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और इस मोर्चे पर जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे। जबकि हम लगातार विनियमों को मजबूत करने और अपनी निगरानी को गहन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बैंकों और एनबीएफसी जैसी वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को भी अभिशासन की गुणवत्ता, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। वे वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता से संबंधित मामलों में रक्षा की पहली पंक्ति हैं।

ऋण प्रबंधक और सरकार को बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक की भूमिका का 2020 में पूर्णतया परीक्षण किया गया था, जिसे बाजार में उधार के उच्चतम स्तर द्वारा चिह्नित किया गया था। हमारी नीतियों के परिणामस्वरूप 16 वर्ष में सबसे कम उधार का भारत औसत लागत और रिकॉर्ड पर सार्वजनिक ऋण के स्टॉक की उच्चतम भारत औसत परिपक्वता हुई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान राज्य सरकारों के लिए 6.88 प्रतिशत एवज में अतिरिक्त उधार के बावजूद केंद्र के लिए भारत उधार की लागत

1 दिसंबर को 5.82 प्रतिशत के नए स्तर पर है। सरकारी उधार कार्यक्रम - केंद्र और राज्यों दोनों - ने वर्ष में अब तक सुचारू रूप से प्रगति की है और मैंने अक्टूबर में जो कुछ भी कहा था उसे पुनः दोहराना चाहूंगा - क्रमबद्ध बाजार गतिविधियों के लिए सहकारी समाधानों का महत्वा हमें प्रतिस्पर्धी होना चाहिए न कि जुझारू।

वित्तीय बाजार संभावनाएं

रिज़र्व बैंक द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए उपायों के परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रम में ब्याज दरों की संरचना, जोखिम स्प्रेड की संकीर्णता और कॉरपोरेट बॉन्डों के रिकॉर्ड निर्गम करने में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। समकालीन परिपक्वता वाले जी-सेक प्रतिफल की तुलना में एएए रेटेड 3-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्रतिफल 8 अक्टूबर को 60 बीपीएस से गिरकर 27 नवंबर 2020 को 17 बीपीएस हो गई। लोअर रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड पर स्प्रेड भी इसी अवधि के दौरान काफी कम था: एए-रेटेड 3-वर्षीय बॉन्ड्स और बीबीबी- (बीबीबी माइनस) रेटेड 3 वर्षीय बॉन्ड्स दोनों के लिए 34 बीपीएस तक। एएए रेटेड 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्रतिफल 8 अक्टूबर 2020 को 5.93 प्रतिशत घटकर 27 नवंबर 2020 को 5.93 प्रतिशत हो गई। वास्तव में, कॉरपोरेट बॉन्ड का स्प्रेड मियादी संरचना में पूर्व-महामारी के स्तर तक सीमित है। वित्तीय बाजार एक क्रमबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। वित्त पोषण की स्थिति में ढील वास्तव में, 2020-21 की दूसरी छमाही में दिखाई देने वाली रिकवरी के नवीन संकेतों को मजबूत करने के लिए जमीन तैयार कर रहा है।

ये घटनाक्रम रिज़र्व बैंक की चलनिधि प्रबंधन की प्रभावकारिता से संबंधित हैं, न केवल प्रतिफल और उधार लेने की लागत को कम करने में बल्कि सकारात्मक बाजार मनोभाव के निर्माण के साथ-साथ अक्टूबर में आरबीआई द्वारा दिए गए आश्वासनों में विश्वास और इसके मार्गदर्शन में कार्रवाई करने के लिए भी। सम्पूर्ण बांड बाजार की स्थिति एक व्यवस्थित तरीके से विकसित हुई है और वित्तीय बाजारों के अन्य खंडों के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा करता है जो जी-सेक प्रतिफल वक्र से वित्तीय लिखतों की कीमत लगाती हैं। ऋण प्रबंधन संचालन, मौद्रिक संचालन और बाजार की उम्मीदें सामंजस्य में हैं और एक समान संभावनाएं साझा करते हैं। यह वित्तीय स्थिरता के लिए शुभ संकेत है। मैं इस अवसर पर जिम्मेदार व्यवहार के लिए और

इन सकारात्मक परिणामों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बाजार सहभागियों की सराहना करना चाहता हूँ। रिज़र्व बैंक, अपनी ओर से, बाजार के प्रतिभागियों को चलनिधि और आसान वित्तपोषण स्थितियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है।

बाहरी मोर्चे में, यूएस में प्रतिफल का दृढीकरण 'रिफ्लेक्शन ट्रेड' से वृद्धि को दर्शाता है। राजनीतिक स्थिरता की संभावनाएं और राजकोषीय प्रोत्साहन की उम्मीदों ने जोखिम की भूख को बढ़ा दिया है, जिससे निवेशक अमेरिकी खजाने की सुरक्षित-स्थान (सेफ हेवेन) से बाहर निकल रहे हैं और रिटर्न की तलाश कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, भारत में पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई है। रिज़र्व बैंक अंतर्निहित घरेलू बुनियादों के साथ अस्थिरता को कम करने और विनिमय दर के क्रमिक विकास को सक्षम करने के लिए उपाय कर रहा है। घरेलू तरलता और मुद्रास्फीति के लिए इन कार्यों के परिणामों के प्रति जागरूक रहते हुए, विदेशी मुद्रा हस्तक्षेपों के माध्यम से चलनिधि की उपलब्धता को प्रतिवर्ती रेपो के माध्यम से अवशोषित करके निष्फल किया जा रहा है।

हम अपने चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के साथ घरेलू स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक स्पिलओवर पर अपनी प्रतिक्रिया जारी रखेंगे। हमारे आदेश पर विभिन्न लिखतों का उपयोग उचित समय पर किया जाएगा, ताकि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कैलिब्रेट किया जा सके कि सिस्टम में पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध है। ओएमओ खरीद, परिचालन ट्विस्ट और प्रतिवर्ती रेपो जैसे लिखतों का उपयोग जारी रहेगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि हर समय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा जाए और संरक्षित रखा जाए हमारा सर्वोपरि उद्देश्य संवृद्धि का समर्थन करना है।

मुद्रास्फीति और संवृद्धि का आकलन: संभावनाएं

अब मैं अंतर्निहित मुद्रास्फीति की गतिशीलता और संभावनाओं के एमपीसी के मूल्यांकन को निर्धारित करता हूँ। सीपीआई मुद्रास्फीति कुछ सबूतों के साथ कि मूल्य दबाव फैल रहा है, सितंबर में तेजी से 7.3 प्रतिशत और अक्टूबर 2020 में 7.6 प्रतिशत तक बढ़ गई। मुद्रास्फीति की संभावनाएं पिछले दो महीनों में उम्मीदों के विपरीत हो गया है। बम्पर खरीफ की फसल

की आगमन के साथ अनाज की कीमतें सौम्य हो सकती हैं और सर्दियों की फसल के साथ सब्जियों की कीमतें कम हो सकती हैं, अन्य खाद्य कीमतों में तेजी के स्तर पर बने रहने की संभावना है। लागतजन्य दबाव का कोर मुद्रास्फीति पर प्रभाव डालना जारी है, जो अस्थिर रह सकता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, जोखिम को व्यापक रूप से संतुलित करते हुए सीपीआई मुद्रास्फीति 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए 6.8 प्रतिशत, 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए 5.8 प्रतिशत और 2020-21 की पहली छमाही में 5.2 से 4.6 प्रतिशत तक होने की संभावना है।

बहाली और उसके बाद

इस पृष्ठभूमि पर, हमें नियंत्रित मांग को पूरा करने के बाद बहाली पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसे निरंतर, उच्च गुणवत्ता वाले विकास के एक मजबूत पथ पर स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए उपलब्ध डाटा इस बात की पुष्टि करते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितना उम्मीद किया था उससे ज्यादा तेजी से सुधार हो रहा है और अक्टूबर में अपने बयान में मैंने जिस मल्टी-स्पीड सुधार को उजागर किया था उससे अधिक क्षेत्र जुड़ रहे हैं। एनएसओ के नवंबर के अंत में प्रारंभिक अनुमानों में, दूसरी तिमाही में संकुचन, अक्टूबर में लगाए गए अनुमान से अधिक हो गया है।

नवंबर 2020 में क्रमशः 56.3 और 53.7 पर विनिर्माण और सेवा क्रय प्रबंधकों का सूचकांक (पीएमआई) विस्तार क्षेत्र में बना हुआ है। सेवाओं के उच्च आवृत्ति संकेतक ने बहुत से अपटिक्स (अनुलग्नक) में स्थिरता और वृद्धि दिखाई है। ग्रामीण मांग में सुधार के और मजबूत होने की उम्मीद है, जबकि शहरी मांग भी गति प्राप्त कर रही है, क्योंकि अनलॉकिंग के कारण गतिविधियां और रोजगार बढ़ रहे हैं, विशेषकर कोविड-19 से विस्थापित श्रमिकों के लिए। हालांकि, ये सकारात्मक आवेग देश के कुछ इलाकों में संक्रमण के बढ़ने के संभावना के कारण धूमिल बने हुए हैं, जिससे कुछ स्थानीय रोकथाम के उपाय हो रहे हैं। इसी समय, टीके परीक्षणों में सफलताओं पर काफी आशावाद के साथ बहाली दर 94 प्रतिशत को पार कर गई है और बढ़ रही है। आने वाले वर्ष में उपभोक्ता का विश्वास आशावादी हो गया है।

2020-21 की दूसरी तिमाही के लिए कॉर्पोरेट परिणाम संकेत देते हैं कि मांग की स्थिति में सुधार हो रहा है और व्यय संबंधी लागत बचत के पृष्ठभूमि में लाभ मार्जिन बढ़ रहा है और ऋण सेवा क्षमता बढ़ गई है। पिछली दो तिमाहियों में संकुचन में बने रहने के बाद निर्माण फर्मों के कारोबारी मूल्यांकन ने 2020-21 की तीसरी तिमाही में विस्तार क्षेत्र में प्रवेश किया है। 2020-21 की चौथी तिमाही में आगे बढ़ने की कारोबारी उम्मीदें बढ़ रही हैं।

संवृद्धि की संभावनाओं की ओर मुड़ते हुए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ग्रामीण मांग में बहाली और मजबूत होने की उम्मीद है, जबकि शहरी मांग की गति में भी वृद्धि हो रही है। उपभोक्ताएं, संभावनाओं के बारे में आशावादी बने हुए हैं और विनिर्माण कंपनियों के कारोबारी मनोभाव में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। राजकोषीय प्रोत्साहन विकास-वृद्धि निवेश का समर्थन करने के लिए खपत और चलनिधि के समर्थन से आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर, निजी निवेश अभी भी सुस्त है और क्षमता उपयोग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। जबकि निर्यात एक असमान बहाली पर है, वेक्सन पर प्रगति ने संभावनाओं को उज्ज्वल किया है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, जोखिम को व्यापक रूप से संतुलित करने के साथ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि 2020-21 में (-) 7.5 प्रतिशत, 2020-21 की तीसरी तिमाही में (+) 0.1 प्रतिशत तथा 2020-21 की चौथी तिमाही में (+) 0.7 प्रतिशत और 2021-22 की पहली छमाही में 6.5 प्रतिशत होने की संभावना है।

अतिरिक्त उपाय

इस पृष्ठभूमि में, रिजर्व बैंक अपने कुछ अतिरिक्त उपायों के साथ अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के अपने सर्वोपरि उद्देश्य के साथ दृढ़ रहेगा ताकि (i) अन्य क्षेत्रों से संबद्ध रहने वाले लक्षित क्षेत्रों में तरलता समर्थन को बढ़ाया जा सके ; (ii) वित्तीय बाजारों को गहन किया जा सके ; (iii) विनियामक पहलों के माध्यम से बैंकों और एनबीएफसी के बीच पूंजी का संरक्षण; (iv) लेखापरीक्षा कार्यों को मजबूत करने के माध्यम से पर्यवेक्षण को मजबूत करना; (v) निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार करके बाहरी व्यापार की सुविधा; तथा (vi) वित्तीय समावेशन का विस्तार करने और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए भुगतान प्रणाली सेवाओं का उन्नयन किया जा सके।

(i) चलनिधि गतिविधि को पुनर्जीवित करने के उपाय

ऑन टैप टीएलटीआरओ- ईसीएलजीएस 2.0 के साथ क्षेत्रों और सिनर्जी का विस्तार

9 अक्टूबर 2020 को घोषित ऑन टैप लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन का विस्तार सरकार के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस 2.0) के तहत उपलब्ध क्रेडिट गारंटी के साथ अन्य तनावग्रस्त क्षेत्रों को कवर करने के लिए किया जाएगा। इससे बैंकों को कम लागत पर तनावग्रस्त क्षेत्रों में ऋण सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

(ii) वित्तीय बाजार को गहरा करना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को वर्तमान में रिजर्व बैंक की तरलता खिड़कियों के साथ-साथ कॉल / नोटिस मनी मार्केट तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। मुद्रा बाजारों में भागीदारी का विस्तार करने और बेहतर तरलता प्रबंधन की सुविधा के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिजर्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी; और कॉल / नोटिस मनी मार्केट भी।

भारत में अविकसित ऋण व्युत्पन्न बाजार को भरने के लिए वित्तीय अनुबंधों के द्विपक्षीय नेटिंग के लिए हाल ही में अधिनियमित कानून के साथ, यह निर्णय लिया गया है कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाए और सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए शीघ्र ही ड्राफ्ट निदेश जारी किए जाएं। संशोधित निदेशों से ऋण व्युत्पन्न बाजार के विकास और विशेषकर कम अंकित जारीकर्ताओं के लिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए एक तरल और जीवंत बाजार की सुविधा की उम्मीद है।

वित्तीय बाजारों में विकास के उपलक्ष्य में और हाल के दिनों में किए गए विभिन्न उदारीकरण उपायों के कारण, 2011 में जारी किए गए व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) पर व्यापक दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है और आज सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट निदेश जारी किए जा रहे हैं। संशोधित दिशा-निर्देश बाजार के निर्माताओं द्वारा ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्न व्यवसाय में शासन के उच्च मानकों और आचरण को सुनिश्चित

करते हुए व्युत्पन्न बाजारों तक कुशल पहुंच को बढ़ावा देने का एक प्रयास होगा।

कॉल, नोटिस और मियादी मुद्रा बाजार पर व्यापक ड्राफ्ट निदेशों, जमा प्रमाण पत्र (सीडी), वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ आज सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किए जा रहे हैं। संशोधित निदेशों से जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य प्रतिभागियों के संदर्भ में उत्पादों में निरंतरता लाने की उम्मीद है।

(iii) विनियमन

(ए) बैंक

COVID-19 महामारी के जवाब में, रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, उधारकर्ताओं के बीच तनाव के समाधान और अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस प्रयास की निरंतरता में और बैंकों को पूंजी संरक्षण में मदद करने के लिए, ताजा ऋण देने के उपाय करते हुए, समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया है कि वाणिज्यिक और सहकारी बैंक लाभ को बनाए रखेंगे और वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबन्धित लाभ से किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे।

गैर-बैंक वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

वित्तीय प्रणाली में विभिन्न क्षेत्रों के साथ एनबीएफसी और उनके परस्पर संबंधों के बढ़ते महत्व ने इस क्षेत्र के लचीलेपन को बढ़ाना अनिवार्य बना दिया है। अतः, एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए मापदंडों के एक मैट्रिक्स के अनुसार पारदर्शी मापदंड रखने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रस्तावित मानदंडों और मापदंडों वाले एक ड्राफ्ट परिपत्र जल्द ही जारी किया जाएगा।

इसके अलावा, आनुपातिकता के सिद्धांत पर निर्मित एनबीएफसी क्षेत्र के लिए वर्तमान नियामक शासन की समीक्षा करना आवश्यक है। यह महसूस किया गया है कि एनबीएफसी के प्रणालीगत जोखिम योगदान से जुड़ा एक पैमाना-आधारित नियामक दृष्टिकोण आगे हो सकता है। हितधारक परामर्श प्रक्रिया

के हिस्से के रूप में, इस विषय पर एक चर्चा पत्र 15 जनवरी 2021 से पहले सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जाएगा।

(iv) पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) में शासन और आश्वासन कार्यों को सुधारने में पर्यवेक्षी ध्यान रिजर्व बैंक का ध्यान आकर्षित करना जारी रखा है। इस प्रयास में, निम्नलिखित उपायों की घोषणा आज की जा रही है। ये निम्नलिखित से संबंधित हैं (i) बड़े यूसीबी और एनबीएफसी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) की शुरुआत और (ii) वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार के लिए वाणिज्यिक बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर दिशानिर्देशों का सामंजस्य। इन उपायों पर ब्योरा विवरण के भाग-बी में हैं और उपरोक्त पर दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

(v) डिजिटल भुगतान सुरक्षा

उपयोगकर्ताओं के लिए मजबूत सुरक्षा और सुविधा के साथ डिजिटल भुगतान चैनलों के एको सिस्टम में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए, हम विनियमित संस्थाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण) निदेश जारी करने का प्रस्ताव रखते हैं। इन निदेशों में सुदृढ़ शासन के लिए आवश्यकताएं, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड से भुगतान, आदि जैसे चैनलों के लिए सामान्य सुरक्षा नियंत्रणों पर कुछ न्यूनतम मानकों के कार्यान्वयन और निगरानी निहित होंगे। इस संबंध में ड्राफ्ट निदेश सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

(vi) वित्तीय साक्षरता और शिक्षा

वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन को गहन बनाने और ग्राहकों की रक्षा के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा 2017 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुनिंदा बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) के माध्यम से एक समुदाय के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण का कार्यान्वयन किया गया। अब मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से देश के हर ब्लॉक में वर्तमान में 100 ब्लॉक से सीएफएल की पहुंच का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(vii) बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र

बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को बढ़ाने के उद्देश्य से, एक व्यापक रूपरेखा शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) ग्राहकों की शिकायतों पर खुलासे को बढ़ाना (ii) शिकायतों के निवारण की लागत की वसूली के रूप में मौद्रिक विघटन, और (iii) शिकायत निवारण तंत्रों की गहन समीक्षा करना और उनके निवारण तंत्रों में सुधार करने में विफल संस्थाओं के खिलाफ पर्यवेक्षी कार्रवाई शामिल है।

(viii) बाहरी व्यापार सुविधा

रिज़र्व बैंक ने निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी और प्रक्रियात्मक देरी को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इन प्रयासों के साथ, यह निर्णय किया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी(एडी) बैंकों को अतिरिक्त शक्तियां सौंपकर बाहरी व्यापार को और अधिक सुगम बनाना है ताकि (ए) निर्यात शिपमेंट के मूल्य के बावजूद निर्यातक द्वारा शिपिंग दस्तावेजों के प्रत्यक्ष प्रेषण के मामलों को नियमित करना; (बी) निर्दिष्ट परिस्थितियों में सीमा के बिना अवास्तविक निर्यात बिल राइट-ऑफ करना; (सी) विदेशी समूह / सहयोगी कंपनियों के साथ आयात भुगतान के लिए निर्यात प्राप्ति के सेट-ऑफ करने की अनुमति कुछ शर्तों के तहत दी जाएगी जब निर्यात और आयात दोनों एक ही कैलेंडर वर्ष के भीतर हुए हों; तथा (डी) दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन, आयात करने वाले देश में माल के आयात पर जोर दिए बिना, जो प्रकृति में खराब हो रहे हैं या बंदरगाह / सीमा शुल्क / स्वास्थ्य अधिकारियों / किसी अन्य मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा नीलाम / नष्ट कर दिए गए हैं, के बिना निर्यात आय के रीफंड पर विचार किया जा सके।

(ix) भुगतान और निपटान प्रणाली

जल्द ही आरटीजीएस प्रणाली 24x7 कर दी जाएगी। इस सक्षमता के साथ, सिस्टम में निपटान और डिफॉल्ट जोखिम को कम करने का प्रस्ताव है, जो सप्ताह के सभी दिनों में एईपीएस, आईएमपीएस, एनईटीसी, एनएफएस, रुपये, यूपीआई लेनदेन के

निपटान की सुविधा प्रदान करता है। इससे भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र अधिक कुशल हो जाएगा।

सावधानी और सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान को अपनाने का विस्तार करने के लिए, उपयोगकर्ता के विवेक पर, कार्ड के माध्यम से आवर्ती लेनदेन (और UPI) के लिए संपर्क रहित कार्ड लेनदेन और ई-जनादेश की सीमा 1 जनवरी 2021 से ₹2,000 to ₹5,000 को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार के लिए वृद्धि में तेजी आई है। सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत उपायों का उद्देश्य इन वृद्धि को अधिक मजबूती के लिए पोषण करना है। वायरस के बारे में संज्ञान और सावधानी के साथ, अर्थव्यवस्था के एक अंशकालिक अनलॉकिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। सतर्क रहते हुए, हमें अब महामारी द्वारा छोड़े गए निशान को कम करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की ओर मुड़ना चाहिए। वेक्सिन पर सकारात्मक समाचारों की स्थिति और स्वस्थ होने में लगातार वृद्धि के साथ क्षितिज और भी प्रकाशमान हो गया है। भारत का समय COVID-19 के भ्रूण से मुक्त होने और हमारे भाग्य को फिर से समनुरूप बनाने का आ गया है। हम दृढ़ता और साहस के साथ पैदा हुए हैं, जो महामारी के कहर का सामना कर सकते हैं। हमने जीवन और प्रियजनों को खो दिया है, लेकिन आशा नहीं, और दृढ़ विश्वास नहीं कि हम इस पर विजयी होंगे और मजबूत बनेंगे। यह अक्सर कहा जाता है कि COVID के बाद का जीवन फिर से पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन समय ने मानव प्रयास से दिखाया गया है कि एक नई दुनिया की तलाश में कभी देर नहीं होती है। हमें प्रयास करने, खोजने और नहीं हारने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ बढ़ना चाहिए। मुझे सुकरात द्वारा उद्धृत एक उद्धरण यहाँ याद आ रहा है, "विपत्ति के सामने, हमारे पास एक विकल्प है। हम कड़वे हो सकते हैं, या हम बेहतर हो सकते हैं।" जाहिर है हम बेहतर होने का प्रयास करेंगे।

सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

संलग्नक: उच्च आवृत्ति संकेतक- दिसंबर 03, 2020 की स्थिति (जारी)											
फरवरी 2020 = 100											
क्रम सं.	संकेतक	फर	मार्च	अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं
1	कृषि / ग्रामीण माँग										
	ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री*	100	41	15	76	89	101	119	98	84	
	दोपहिया की बिक्री*	100	69	0	20	72	89	100	108	123	
	तिपहिया की बिक्री*	100	64	0	7	29	34	34	38	50	
	कृषि निर्यात*	100	79	64	88	95	109	101	114	116	
	उर्वरक बिक्री*	100	80	135	105	93	107	96	94	115	
	कृषि ऋण (बकाया)	100	100	100	99	100	101	101	103	105	
	मनरेगा कार्य की माँग (हाउसहोल्ड्स)	100	93	60	168	201	144	109	109	109	100
2	औद्योगिक उत्पादन										
	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक*	100	79	45	67	80	89	88	92		
	आईआईपी: विनिर्माण*	100	77	35	63	80	89	88	92		
	आईआईपी: पूँजीगत वस्तुएँ*	100	68	9	40	69	80	83	92		
	आईआईपी: इंफास्ट्रक्चर एवं निर्माण वस्तुएँ*	100	75	17	61	78	90	90	92		
	आईआईपी: टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ*	100	66	5	33	67	81	87	96		
	आईआईपी: गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ*	100	78	53	91	115	103	98	102		
	आठ प्रमुख उद्योग (ईसीआई) सूचकांक*	100	88	62	76	83	89	87	89	88	
	ईसीआई : स्टील*	100	79	21	62	79	94	94	94	92	
	ईसीआई : सीमेंट*	100	73	16	71	82	79	74	83	86	
	इलेक्ट्रीसिटी माँग	100	95	82	99	101	108	105	108	106	94
	ऑटोमोबाइल्स उत्पादन										
	यात्री वाहन*	100	67	0	11	44	70	83	102	114	
	दोपहिया*	100	77	0	17	58	81	99	112	129	
	तिपहिया*	100	69	0	37	43	41	56	59	71	
	ट्रैक्टरों का उत्पादन*	100	52	0	37	101	90	95	102	114	
3	निर्माण										
	स्टील उपभोग*	100	80	19	61	80	103	96	100	106	
	सीमेंट उत्पादन*	100	73	16	71	82	79	74	83	86	
4	यातायात										
	ऑटोमोबाइल्स की बिक्री*	100	65	0	19	67	83	94	103	116	
	यात्री वाहनों की बिक्री*	100	53	0	14	51	74	87	101	111	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात*	100	60	0	3	17	17	24	33	38	
	घरेलू हवाई कार्गो*	100	66	8	17	50	57	63	76	82	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो*	100	70	25	42	62	70	72	81	81	
	मालभाड़ा निवल टन किलोमीटर*	100	84	65	76	87	90	93	100	101	102
	पोर्ट कार्गो*	100	92	78	73	84	86	88	94	92	
	कर संग्रह : मात्रा	100	77	9	50	74	79	88	100	111	113
	पेट्रोलियम उपभोग*	100	81	50	77	86	85	78	89	93	
5	घरेलू व्यापार										
	जीएसटी ई-वे बिल	100	71	15	45	76	85	86	100	112	97
	जीएसटी राजस्व	100	93	31	59	86	83	82	91	100	100

संलग्नक: उच्च आवृत्ति संकेतक- दिसंबर 03, 2020 की स्थिति (समाप्त)											
क्रम सं.	संकेतक	फर	मार्च	अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं
6	पर्यटन एवं आतिथ्य										
	विदेशी पर्यटक आगमन	100	32	0	0	0	0	0	0		
7	बाह्य व्यापार										
	पण्य निर्यात	100	77	37	69	79	85	82	99	89	84
	पण्य आयात	100	83	46	59	56	76	79	80	89	88
	गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात	100	82	50	75	63	81	78	96	103	101
	सेवाओं का निर्यात	100	102	93	95	96	96	93	98		
	सेवाओं का आयात	100	100	84	90	90	91	87	92		
8	भुगतान और निपटान संकेतक (मात्रा)										
	आरटीजीएस	100	89	41	68	90	94	88	98	104	99
9	मौद्रिक, बैंकिंग और वित्तीय समुच्चय										
	बकाया ऋण	100	103	102	101	102	102	101	102	102	103
	बैंक जमा	100	102	103	105	104	106	106	107	107	108
	जीवन बीमा पहले वर्ष का प्रीमियम	100	137	36	74	156	124	146	137	123	
	गैर-जीवन बीमा प्रीमियम	100	113	0	0	100	122	126	165	114	
	एम3	100	102	103	105	105	107	107	108	108	109
	आरक्षित मुद्रा	100	102	102	105	107	107	107	107	109	111
	सीपी: मासिक बकाया	100	86	104	106	98	94	93	91	95	
	सीडी: मासिक बकाया	100	93	97	86	65	56	49	41	42	
	एफपीआई निवल (मिलियन यूएस डालर)	1271	-15924	-1961	-973	3441	451	6662	-157	2974	8458
	एमएफ निवेश- इक्विटी (आईएनआर करोड़)	9863	30131	-7966	6523	-502	-9195	-8400	-4134	-14492	-22665
	एमएफ निवेश- कर्ज (आईएनआर करोड़)	18026	-16190	-9795	10699	41365	31898	24494	17005	30996	13129
	कॉर्पोरेट बॉण्ड निर्गम (आईएनआर करोड़)	80555	75734	54741	84871	70536	48122	58419	64389	62631	
10	पीएमआई										
	पीएमआई: विनिर्माण (>50 पिछले माह की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है)	54.5	51.8	27.4	30.8	47.2	46	52	56.8	58.9	56.3
	पीएमआई: सेवाएं (>50 पिछले माह की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है)	57.5	49.3	5.4	12.6	33.7	34.2	41.8	49.8	54.1	53.7
	पीएमआई: संयुक्त (>50 पिछले माह से वृद्धि को दर्शाता है)	57.6	50.6	7.2	14.8	37.8	37.2	46	54.6	58.0	56.3
11	रोजगार										
	सीएमआईई बेरोजगारी दर (%)	7.8	8.8	23.5	21.7	10.2	7.4	8.4	6.7	7.0	6.5

*मौसमी आधार पर समायोजित आंकड़ों को दर्शाता है

स्रोत: सीएमआईई, सीईआईसी, एनएसओ, मांस्पी, आरबीआई, सेबी, एफआईएमएमडीए

← कोविड-पूर्व स्तर से नीचे		गतिविधि में बहाली आना/सामान्य होना →		

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21

मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)
का संकल्प, दिसंबर 2020

मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (4 दिसंबर 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए;

नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी जाएं।

- यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने एक टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो- कम से कम चालू वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्त वर्ष में निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों को नीचे दिए गए विवरण में वर्णित किया गया है।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. 2020 की चौथी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए संभावनाएं पूरे यूरोप, यूएस और प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में लॉकडाउन के साथ COVID-19

संक्रमणों की वृद्धि की दूसरी लहर से छाई हुई है। हालांकि, वैक्सीन उम्मीदवारों पर प्रगति कुछ ऑफसेट आशावाद उत्पन्न करती है। वर्ल्ड ट्रेड ने तीसरी तिमाही में सुधार दर्ज किया क्योंकि लॉकडाउन को कम कर दिया गया था, लेकिन चौथी तिमाही में धीमी होने की संभावना है क्योंकि नियंत्रित (पेंट-अप) मांग कमजोर हो गई है, इन्वेंट्री रिस्टोकिंग पूरा हो गया है, और दूसरी लहर के साथ व्यापार से संबंधित अनिश्चितता बढ़ रही है। सीपीआई मुद्रास्फीति प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में मंद रही है, जबकि खाद्य कीमतों और आपूर्ति में बाधा के कारण कुछ ईएमई में इसमें बढ़ोतरी हुई। वैश्विक वित्तीय बाजार अत्यधिक निभावकारी मौद्रिक नीतियों और वैक्सीन पर सकारात्मक खबरों के समर्थन के कारण तेज बने हुए हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

3. भारत में, 27 नवंबर को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों ने 2020-21 (जुलाई-सितंबर) की दूसरी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.5 प्रतिशत का संकुचन दिखाया। 2020-21 की तीसरी तिमाही में, उच्च आवृत्ति संकेतक अक्टूबर में पैसेंजर व्हीकल और मोटरसाइकल बिक्री, रेलवे किराया ट्रेफिक और बिजली की खपत में डबल डिजिट संवृद्धि के साथ रिकवरी प्राप्त करने वाले कर्षण की ओर इशारा करते हैं, हालांकि नवंबर में इनमें से कुछ संकेतकों में मॉडरेशन था। अनुकूल मानसून के कारण, सहायक मिट्टी की नमी और जलाशय की स्थिति के तहत पिछले वर्ष इस समय कुल क्षेत्रफल में रबी की 4.0 प्रतिशत की बुआई के साथ कृषि संबंधी संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई है।

4. सीपीआई मुद्रास्फीति कुछ सबूतों के साथ कि मूल्य दबाव फैल रहा है, सितंबर में तेजी से 7.3 प्रतिशत और अक्टूबर 2020 में 7.6 प्रतिशत तक बढ़ गई। खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में दालें, खाद्य तेल, सब्जियां और कई आपूर्ति झटके पर मसाले सहित सभी प्रोटीन से भरपूर चीजों में दोहरे अंकों में पहुंच गई। खाद्य और ईंधन को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति, यानी सीपीआई भी सितंबर में 5.4 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 5.8 प्रतिशत हो गई। दोनों तीन महीने और एक वर्ष आगे की परिवार की मुद्रास्फीति की उम्मीदों में सर्दियों में खाद्य कीमतों की मौसमी मॉडरेशन की

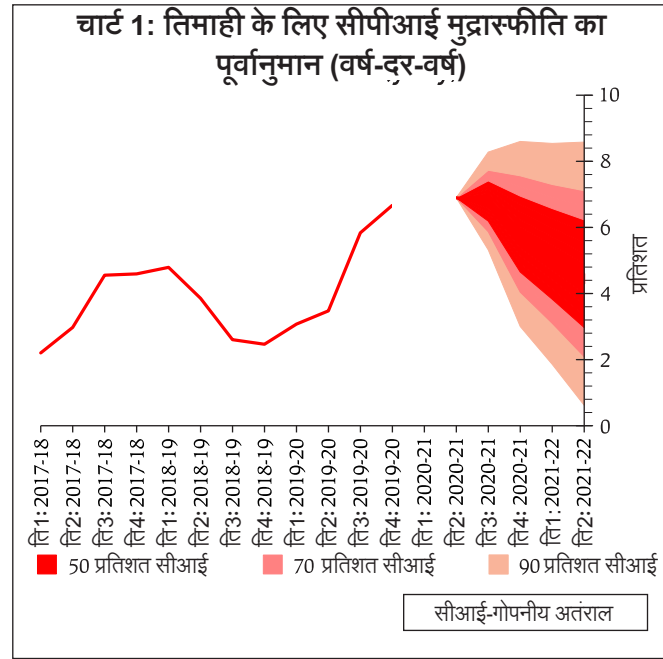
* 4 दिसंबर 2020 को जारी किया गया।

प्रत्याशा में और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को कम करने में मामूली कमी आई हैं।

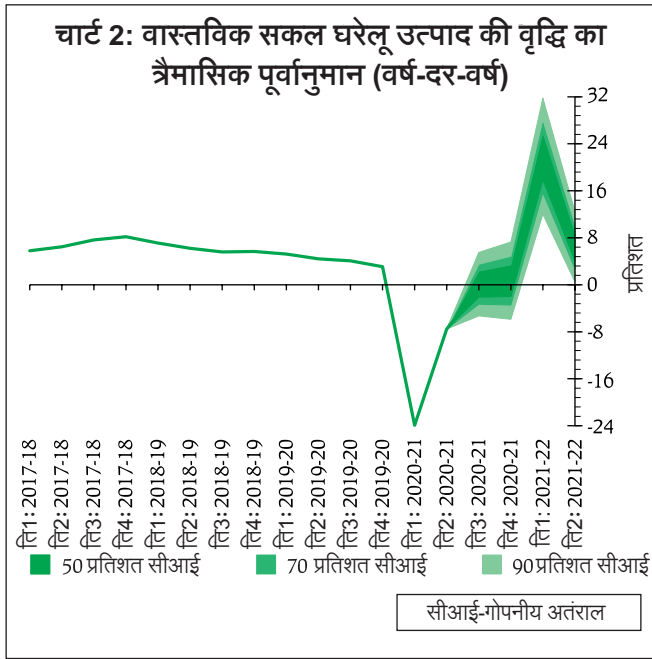
5. अक्टूबर-नवंबर में घरेलू वित्तीय स्थिति आसान रही और बृहद अधिशेष में प्रणालीगत चलनिधि बनी रही। मुद्रा की मांग में वृद्धि के कारण आरक्षित धन में 15.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) (27 नवंबर, 2020 तक) की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, मुद्रा आपूर्ति (एम 3) 20 नवंबर 2020 तक केवल 12.5 प्रतिशत बढ़ी। उल्लेखनीय विकास यह है कि वित्त वर्ष के आधार पर गैर-खाद्य ऋण वृद्धि में तेजी आई और नवंबर 2020 में पहली बार सकारात्मक क्षेत्र में आई - अब तक बैंकिंग प्रणाली में जमा बृहद अंतर्वाह मुख्य रूप से एसएलआर निवेश में नियोजित किया गया। कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गम अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान ₹4.4 लाख करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 3.5 लाख करोड़ थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 574.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (27 नवंबर को) था, जोकि एमपीसी के अंतिम संकल्प के समय 2 अक्टूबर को 545.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

संभावनाएं

6. मुद्रास्फीति की संभावनाएं पिछले दो महीनों में उम्मीदों के विपरीत हो गई। थोक और खुदरा मुद्रास्फीति के बीच की पर्याप्त वैज आपूर्ति-पक्ष की अड़चनों और उपभोक्ता को लगने वाले बड़े मार्जिन की ओर इशारा करती है। जहां अनाज की कीमतें बम्पर खरीफ की फसल की आगमन के साथ सौम्य बनी रह सकती हैं और सर्दियों की फसल के साथ सब्जियों की कीमतें कम हो सकती हैं, अन्य खाद्य कीमतों का तेजी के स्तर पर बने रहने की संभावना है। कच्चे तेल की कीमतें मांग में सुधार की आशा, ओपेक प्लस के उत्पादन में कटौती के बाद बढ़ी है और निकट अवधि में अस्थिर बने रहने की उम्मीद है। लागत-जन्य दबाव कोर मुद्रास्फीति पर प्रभाव जारी है, जो अस्थिर बना हुआ है और आर्थिक गतिविधियों को सामान्य कर सकता है और मांग में तेजी ला सकता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, जोखिम को व्यापक रूप से संतुलित करते हुए सीपीआई मुद्रास्फीति 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए 6.8 प्रतिशत, 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए 5.8 प्रतिशत और 2020-21 की पहली छमाही में 5.2 से 4.6 प्रतिशत तक होने की संभावना है।



7. संवृद्धि संभावनाओं की ओर रुख करते हुए, ग्रामीण मांग में रिकवरी और मजबूत होने की उम्मीद है, जबकि अन्लॉकिंग से गतिविधि और रोजगार विशेषकर COVID-19 द्वारा विस्थापित श्रम में बढ़ोत्तरी से शहरी मांग में गति आ रही है। हालांकि, ये सकारात्मक आवेग देश के कुछ हिस्सों में संक्रमणों के संभावित वृद्धि से घिरे हैं जो कुछ स्थानीय रोकथाम उपायों को प्रेरित करता है। इसी समय, रिकवरी दर 94 प्रतिशत को पार कर गई है और वेक्सिन परीक्षणों में सफलताओं पर काफी आशावाद है। उपभोक्ता आउटलुक के बारे में आशावादी बने हुए हैं, और निर्माण फर्मों की कारोबारी धारणा में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। राजकोषीय उत्तेजना विकास-वृद्धि निवेश का समर्थन करने के लिए खपत और तरलता के समर्थन से आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर, निजी निवेश अभी भी सुस्त है और क्षमता उपयोग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। जबकि निर्यात एक असमान रिकवरी पर हैं, वेक्सिन पर प्रगति के साथ संभावनाएं उज्ज्वल हो गई हैं। संपर्क-गहन सेवाओं की मांग सामाजिक दूरी के मानदंडों और जोखिम से बचने के कारण कुछ समय के लिए कम रहने की संभावना है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, व्यापक रूप से संतुलित जोखिम के साथ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि (-) 2020-21 में (-) 7.5 प्रतिशत: (+) 0.1 प्रतिशत क्यू3: 2020-21 और (+) 0.7 प्रतिशत क्यू4: 2020-21 में अनुमानित



है; और एच1: 2021-22 में (+)21.9 प्रतिशत से (+) 6.5 प्रतिशत दर्शाई गयी है (चार्ट 2)।

8. एमपीसी का विचार है कि सर्दियों के महीनों में नष्ट होने योग्य वस्तुओं की कीमतों में राहत के साथ मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी की संभावना है। यह संवृद्धि के समर्थन में कार्य करने के लिए उपलब्ध स्थान का उपयोग करने से वर्तमान समय में मौद्रिक नीति को बाधित करता है। इसी समय, बहाली के संकेत वैविध्यपूर्ण होने से बहुत दूर हैं और निरंतर नीतिगत समर्थन पर निर्भर हैं। आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों, अत्यधिक मार्जिन और अप्रत्यक्ष करों द्वारा संवर्धित किए जा रहे मुद्रास्फीति सीढ़ी को तोड़ने के लिए

अग्रसक्रिय आपूर्ति प्रबंधन कार्यनीतियों के लिए एक छोटी विंडो उपलब्ध है। आपूर्ति पक्ष द्वारा संचालित मुद्रास्फीति के दबावों को कम करने के लिए और प्रयास की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति व्यापक समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को संभालने के लिए मूल्य स्थिरता के सभी खतरों की बारीकी से निगरानी करेगा। तदनुसार, एमपीसी ने अपनी आज की बैठक में निर्णय लिया कि नीतिगत दर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए और जब तक आवश्यक हो, तब तक निभावकारी रूख जारी रखा जाए- कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष के दौरान - ताकि यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित किया जाए तथा COVID-19 के प्रभाव को कम किया जाए।

9. एमपीसी के सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. मृदुल के. सागर, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा और श्री शक्तिकांत दास - ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को बनाए रखने के लिए मतदान किया। इसके अलावा, एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से जब तक आवश्यक हो, तब तक निभावकारी रूख जारी रखने - कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष के दौरान - ताकि यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित करने तथा COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए वोट किया।

10. एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त 18 दिसंबर 2020 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति के उपायों i) अर्थव्यवस्था के लक्षित क्षेत्रों के लिए चलनिधि समर्थन को अन्य क्षेत्रों से जोड़ना; (ii) वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाना; (iii) विनियामक पहलों के माध्यम से बैंकों और एनबीएफसी के बीच पूंजी का संरक्षण; (iv) लेखा परीक्षा कार्यों के माध्यम से पर्यवेक्षण को मजबूत करना; (v) निर्यातकों के लिए कारोबार करने में आसानी के लिए बाहरी व्यापार को सुविधाजनक बनाना; और (vi) वित्तीय समावेशन का विस्तार करने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए भुगतान प्रणाली सेवाओं का उन्नयन, को निर्धारित करता है।

I. गतिविधि को पुनर्जीवित करने के लिए चलनिधि उपाय

1. मांग पर टीएलटीआरओ - ईसीएलजीएस 2.0 के साथ सेक्टर और सिनर्जी का विस्तार

विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों के फोकस को बढ़ाने के उद्देश्य से, जिनका पिछले और आगे दोनों से जुड़ाव और वृद्धि पर बहुस्तरीय प्रभाव हैं, रिजर्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2020 को मांग पर टीएलटीआरओ की घोषणा की जो 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगी। तदनुसार, योजना की प्रतिक्रिया की समीक्षा के बाद राशि और अवधि बढ़ाने के लचीलेपन के साथ पॉलिसी रेपो दर से सहलग्न अस्थायी दर पर कुल ₹1,00,000 करोड़ तक की राशि के लिए तीन वर्षों तक के लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालनों को मांग पर संचालित करने का निर्णय लिया गया था। 12 नवंबर 2020 को घोषित किए गए आत्म निर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 (ईसीएलजीएस 2.0) शुरू की, जिसके तहत रिजर्व बैंक की कामथ कमेटी द्वारा चिन्हित 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों में संस्थाओं को मौजूदा ईसीएलजीएस 1.0 के ₹ 3.0 लाख करोड़ के कोष को 100 प्रतिशत गारंटीकृत संपार्श्विक मुफ्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करने साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर जिनकी क्रेडिट बकाया राशि 29.2.2020 तक ₹ 50 करोड़ से अधिक और ₹ 500 करोड़ तक है के लिए बढ़ाया गया था। तदनुसार, 21 अक्टूबर 2020 को योजना के तहत घोषित

पांच क्षेत्रों के अलावा, अब मांग पर टीएलटीआरओ के तहत पात्र क्षेत्रों के दायरे में कामथ समिति द्वारा चिन्हित 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों को लाने का प्रस्ताव है। बैंकों को दो योजनाओं के तालमेल के लिए रिजर्व बैंक से मांग पर टीएलटीआरओ के तहत धनराशि का लाभ उठाने और तनावग्रस्त क्षेत्रों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए ईसीएलजीएस 2.0 के तहत गारंटी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त चलनिधि को संस्था द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जारी कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पेपर और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना चाहिए जो 30 सितंबर 2020 को ऐसे लिखतों में अपने निवेश के बकाया स्तर के अलावा हो। इस योजना के तहत प्राप्त चलनिधि का उपयोग इन क्षेत्रों के ऋणों और अग्रिमों को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। इस सुविधा के तहत बैंकों द्वारा किए गए निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यहां तक कि कुल निवेश का 25 प्रतिशत से अधिक एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल करने की अनुमति है। इस सुविधा के तहत सभी एक्सपोजर को बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के तहत गणना से छूट दी जाएगी।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए अधिक कुशल चलनिधि प्रबंधन की सुविधा

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को वर्तमान में रिजर्व बैंक की चलनिधि विंडो के साथ-साथ कॉल / नोटिस मनी मार्केट तक एक्सेस की अनुमति नहीं है। इन मुद्दों के समाधान के लिए अब दो नए उपाय प्रस्तावित हैं। (i) आरआरबी द्वारा प्रतिस्पर्धी दरों पर अधिक कुशल चलनिधि प्रबंधन की सुविधा के लिए, आरआरबी को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। (ii) आरआरबी को उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों के रूप में कॉल / नोटिस मनी मार्केट में भाग लेने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

II. विनियमन और पर्यवेक्षण

COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से रिजर्व बैंक की विनियामक प्रतिक्रिया ने वित्तीय स्थिरता की अनिवार्यता को देखते हुए उधारकर्ताओं द्वारा ऋण चुकौती पर तत्काल प्रभाव के

शमन, उधारकर्ता संस्थाओं के तनाव के विश्वसनीय समाधान को सक्षम कर और, अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाए जाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उसी के आगे, निम्नलिखित उपायों की घोषणा की जा रही है:

3. बैंकों द्वारा लाभांश वितरण

COVID-19 संबंधित आर्थिक झटके को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल 2020 में यह घोषणा की गई थी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) और सहकारी बैंक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से कोई लाभांश का भुगतान अगले निर्देश तक नहीं करेंगे, जिसे 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए बैंकों के वित्तीय परिणामों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। COVID-19 से संबंधित सतत तनाव और बढ़ी अनिश्चितता को देखते हुए, यह जरूरी है कि बैंक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और नुकसान को अवशोषित करने, यदि कोई हो, के लिए पूंजी का संरक्षण करते रहें। बैंकों के तुलन-पत्र को और मजबूत करने के साथ वास्तविक अर्थव्यवस्था को उधार देने का समर्थन करते हुए, समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि एससीबी और सहकारी बैंक वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित लाभ से कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। उपरोक्त उपाय पर दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

4. एनबीएफसी के लिए लाभांश वितरण नीति

बैंकों की तरह, वर्तमान में एनबीएफसी द्वारा लाभांश के वितरण के संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व और विभिन्न क्षेत्रों के साथ उनके अंतर संबंधिता को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण पर दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया है। एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों को सामान्य शर्तों के एक सेट के अधीन मानकों के मैट्रिक्स के अनुसार लाभांश घोषित करने की अनुमति होगी। इस संबंध में एक ड्राफ्ट परिपत्र सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

5. एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियामक ढांचा पर चर्चा पत्र

बैंकों के साथ ऋण मध्यस्थता के पूरक चैनल के रूप में एनबीएफसी के योगदान को अच्छी तरह से जाना जाता है।

एनबीएफसी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला विनियामक व्यवस्था आनुपातिकता के सिद्धांत पर बनाया गया है जिस से कैलिब्रेटेड विनियामक उपायों के माध्यम से इस क्षेत्र में पर्याप्त परिचालनगत लचीलापन उपलब्ध हो सके। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास हुआ है, जिसके कारण एनबीएफसी क्षेत्र के आकार और परस्पर संबद्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अतः, एनबीएफसी के बदलते जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप विनियामक ढांचे की समीक्षा करने की आवश्यकता है। यह महसूस किया गया है कि एनबीएफसी के प्रणालीगत जोखिम योगदान से जुड़ा एक स्केल-आधारित विनियामक दृष्टिकोण आगे हो सकता है। यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित विनियामक ढांचे को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों के साथ परामर्श किया जाए। इस संबंध में एक चर्चा पत्र 15 जनवरी 2021 से पहले सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जाएगा।

6. पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत करना : (i) बड़े यूसीबी और एनबीएफसी को जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) को अपनाए पर दिशानिर्देश जारी करना; (ii) वाणिज्यिक बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर दिशानिर्देशों का सामंजस्यकरण

हाल के दिनों में, रक्षा तंत्र की तीन लाइनों में कमजोरी, अक्सर कुछ बैंकों और एनबीएफसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रमुख गलती साबित हुई है। रक्षा की ये तीन लाइनें हैं: (i) कारोबार इकाई स्वयं; (ii) जोखिम प्रबंधन और अनुपालन; और (iii) आंतरिक लेखापरीक्षा। अतः, पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) में शासन और आश्वासन कार्यों को मजबूत करने में पर्यवेक्षी फोकस रिजर्व बैंक के लिए एक प्रमुख विषय बना हुआ है। रिजर्व बैंक में पर्यवेक्षी कार्यों के एकीकरण का लक्ष्य यूसीबी और एनबीएफसी के पर्यवेक्षण का मानक आनुपातिक रूप से वाणिज्यिक बैंकों के बराबर लाना था।

आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, रक्षा की तीसरी पंक्ति के रूप में, यूसीबी और एनबीएफसी में मजबूत करने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक द्वारा 2002 में वाणिज्यिक बैंकों के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) अनिवार्य किया गया था। अब बड़े यूसीबी और एनबीएफसी को आरबीआईए को

अपनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह स्वतंत्र जोखिम वाले आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली के निर्माण को सक्षम करेगा।

जबकि बाह्य सांविधिक लेखा परीक्षक एक पर्यवेक्षित इकाई के आंतरिक तंत्र के बाहर रहते हैं, उन्हें अक्सर रक्षा की चौथी पंक्ति के रूप में माना जाता है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 में हाल के संशोधन में यूसीबी में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति में रिज़र्व बैंक को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां देना भी उस दिशा में एक संकेत है। इसलिए, वाणिज्यिक बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर दिशा-निर्देशों के सामंजस्य का निर्णय लिया गया है। नए दिशानिर्देश एसई को ऑडिट फर्मों को उनकी जरूरतों के अनुसार समय पर, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से नियुक्त करने में सक्षम बनाएंगे। इससे एसई की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। इस संबंध में दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

7. डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों द्वारा निभाई जा रही विशेष भूमिका के कारण, रिज़र्व बैंक इसके आसपास सुरक्षा नियंत्रणों को सबसे अधिक महत्व देता है। अन्य के साथ, अब विनियमित संस्थाओं के लिए ऐसी प्रणालियों हेतु एक मजबूत शासन संरचना स्थापित करने और इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड भुगतान जैसे चैनलों के लिए सुरक्षा नियंत्रण के सामान्य न्यूनतम मानकों को लागू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण) दिशा-निर्देश 2020, जारी करना प्रस्तावित है। जबकि दिशा-निर्देश तकनीकी और प्लेटफॉर्म एनोस्टिक होंगे, यह ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान उत्पादों का कुशल और सुरक्षित तरीके से उपयोग करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाएगा और बढ़ाएगा। आवश्यक दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

8. वित्तीय साक्षरता और शिक्षण

समावेशी विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन को व्यापक करने और वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित कर ग्राहकों का संरक्षण करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 2017 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल)

की स्थापना कर 80 ब्लॉकों में समुदाय में भागीदारी पहुंच के माध्यम से एक अभिनव तरीके से वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने के लिए चुनिंदा बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल किया गया था। 2019 में इस प्रोजेक्ट को जनजातीय / आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 20 और ब्लॉकों तक विस्तारित किया गया था। प्राप्त अनुभव के आधार पर, हितधारकों (बैंकों और गैर सरकारी संगठनों) से प्राप्त फीडबैक और एक स्थायी तरीके से जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, सीएफएल की पहुंच को मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से देश में हर ब्लॉक में विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। हितधारकों को आवश्यक दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

9. बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र

रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित लोकपाल तंत्र एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र है। बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत और बेहतर बनाने और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को बढ़ाने के उद्देश्य से, एक व्यापक रूपरेखा शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा ग्राहकों की शिकायतों पर खुलासे को बढ़ाना, बैंकों से शिकायतों के निवारण की लागत की वसूली के रूप में मौद्रिक विघटन, जब अनुरक्षणीय शिकायतें काफी अधिक हों और शिकायत निवारण तंत्रों की गहन समीक्षा करना और समयबद्ध तरीके से उनके निवारण तंत्रों में सुधार करने में विफल बैंकों के खिलाफ पर्यवेक्षी कार्रवाई करना शामिल है। जनवरी 2021 तक रूपरेखा तैयार की जाएगी।

III. वित्तीय बाजारों को व्यापक करना

10. ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) दिशानिर्देशों की समीक्षा

ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) के लिए बाजार का विकास कॉरपोरेट बॉन्ड, विशेष रूप से कम रेटेड जारीकर्ताओं के बॉन्ड के लिए अर्थसुलभ बाजार के विकास के लिए अनिवार्य है। पिछली बार जनवरी 2013 में सीडीएस दिशानिर्देश जारी किए गए थे। हम बाजार के प्रतिभागियों से सुरक्षा विक्रेताओं के आधार के विस्तार की आवश्यकता और कुछ अन्य परिचालन बाधाओं के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहे हैं। द्विपक्षीय नेटिंग के लिए विधान के

पारित होने से भी सीडीएस बाजार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। तदनुसार, सीडीएस के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित ड्राफ्ट दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

11. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) पर व्यापक दिशानिर्देशों की समीक्षा

नवंबर 2011 में जारी किए गए व्युत्पन्न पर व्यापक दिशानिर्देश ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्न लेनदेन के संबंध में ग्राहक की उपयुक्तता और औचित्य, शासन व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन के संबंध में विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानकों और ब्याज दर और मुद्रा व्युत्पन्न से संबंधित नियमों में हाल के बदलावों के अनुरूप, मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है। संशोधित दिशानिर्देश व्युत्पन्न बाजारों में कुशल पहुंच को बाजार निर्माताओं द्वारा ओटीसी व्युत्पन्न कारोबार में शासन और आचरण के उच्च मानकों को सुनिश्चित करते हुए बढ़ावा देना चाहते हैं। ड्राफ्ट निद्श आज जारी किए जा रहे हैं।

12. मुद्रा बाजार निर्देशों की व्यापक समीक्षा

जैसा कि 6 जून 2019 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया है, मुद्रा बाजार लिखतों सहित मांग मुद्रा, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र और अन्य ऋण लिखतों जिनकी मूल परिपक्वता एक वर्ष से कम है पर मौजूदा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई और जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य प्रतिभागियों के संदर्भ में उत्पादों में स्थिरता लाने की दृष्टि से युक्तिसंगत बनाया गया। तदनुसार, कॉल, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजार पर ड्राफ्ट निर्देशों के तीन सेट; जमा प्रमाणपत्र (सीडी); और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) आज सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किए जा रहे हैं।

IV. बाह्य व्यापार – सुविधा सेवा

हाल के दिनों में, रिजर्व बैंक ने देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए बाह्य व्यापार से संबंधित कई उपायों की घोषणा की है और निर्यातकों और आयातकों को COVID-19 महामारी से

उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद की है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए, कुछ निर्यात लेनदेन को नियंत्रित करने वाली मौजूदा नीतियों में और उदारीकरण की घोषणा करने का निर्णय लिया गया है। ये उपाय, अधिकृत डीलर बैंकों को अधिक शक्तियाँ प्रदान करते हुए, अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करेंगे, जिससे कारोबार करने में आसानी होगी।

13. शिपिंग दस्तावेजों का प्रत्यक्ष प्रेषण

वर्तमान में, एडी श्रेणी - I बैंकों (एडी बैंकों) को उन मामलों को नियमित करने की अनुमति है, जहां शिपिंग दस्तावेजों के प्रेषण निर्यातक द्वारा सीधे परेषिती या उसके एजेंट को किए गए थे यदि प्रति निर्यात शिपमेंट की राशि 1.0 मिलियन अमरीकी डालर या इसके समकक्ष है। एडी बैंकों को ऐसे मामलों को नियमित करने में सक्षम करने के लिए निर्यात शिपमेंट के मूल्य पर विचार किए बिना जहां निर्यात आय की वसूली हुई है, मौद्रिक सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया है।

14. वसूल न किए गए निर्यात बिलों का "राइट ऑफ"

वर्तमान में, एडी बैंकों को एक निश्चित सीमा तक वसूल न किए गए निर्यात बिलों के राइट ऑफ करने की अनुमति है, और उससे अधिक के लिए एडी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन लेना होगा। प्रक्रिया को सरल बनाने, इस तरह के अनुमोदन के लिए लगने वाले समय को कम करने, ताकि विनियामक लागत में कमी आए, को देखते हुए वसूल न किए गए निर्यात बिलों के राइट-ऑफ को नियंत्रित करने वाली मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। तदनुसार, एडी बैंकों को राइट-ऑफ की अनुमति देने की शक्ति को सौंपने का निर्णय लिया गया है, यह निर्दिष्ट परिस्थितियों में सीमा के बिना, उदा. भारतीय दूतावास, विदेशी चैंबर ऑफ कॉमर्स या इसी तरह के संगठन के माध्यम से ऐसे मामले जहां विदेशी खरीदार दिवालिया हो गए हैं या प्राप्त होने वाली निर्यात आय का समझौता हो गया है या अगर सामान आयातित देश में पोर्ट / सीमा शुल्क / स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा, एडी बैंक को ऐसे राइट-ऑफ अनुरोधों को संभालने की अनुमति दी जाएगी, भले ही दस्तावेज निर्यातक द्वारा सीधे भेजे गए हों।

15. आयात शुल्कों के विरुद्ध निर्यात प्राप्तिओं का सेट-ऑफ

यह निर्णय लिया गया है कि एडी बैंकों को यह अनुमति दी जाए कि वे भारतीय कंपनियों को अपने विदेशी समूह / सहयोगी कंपनियों के साथ किसी केंद्रीयकृत ट्रेजरी व्यवस्था के माध्यम से शुद्ध आधार या सकल आधार पर माल और सेवाओं के संबंध में आयात शुल्कों के विरुद्ध अपने निर्यात प्राप्तिओं को सेट-ऑफ कर सकें। इसके अलावा, इस तरह के अनुरोधों को विदेशी व्यापार नीति के अनुपालन के अधीन, विधिक रूप से लागू संविदा / करार द्वारा समर्थित होने पर, एक ही विदेशी खरीदार / आपूर्तिकर्ता के संबंध में एडी बैंकों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह के नेट-ऑफ की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब निर्यात और आयात एक ही कैलेंडर वर्ष के दौरान हुए हों।

16. निर्यात प्राप्तिओं का रिफंड

वर्तमान में, यदि विदेशी आयातक को निर्यात किए गए माल की खराब गुणवत्ता के कारण निर्यात प्राप्तिओं का रिफंड किया जाना आवश्यक है, तो माल के पुनः आयात के अधीन, जिसके माध्यम से निर्यात प्राप्तियाँ प्राप्त हुई थी, इसकी एडी बैंक द्वारा अनुमति दी जाती है। समीक्षा करने पर, एडी बैंकों को दस्तावेजी साक्ष्य की प्रस्तुति पर, माल के आयात पर जोर दिए बिना रिफंड अनुरोधों पर विचार करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जो कि नष्ट होनेवाली प्रकृति के हैं या पोर्ट / सीमा शुल्क / स्वास्थ्य अधिकारियों / आयात में किसी अन्य मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा नीलाम / नष्ट कर दिए गए हैं।

V. भुगतान और निपटान प्रणाली

17. सप्ताह के सभी दिनों में भुगतान प्रणालियों के निपटान फ़ाइलों की पोस्टिंग को सक्षम करना

वर्तमान में, अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों के निपटान फ़ाइलों को रिज़र्व बैंक में

पोस्ट करने की सुविधा केवल आरटीजीएस कार्य दिवसों में उपलब्ध है। ईकुबेर (रिज़र्व बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम) और आरटीजीएस (जल्द ही शुरू होने वाली) की चौबीस घंटे उपलब्धता के कारण, भुगतान प्रणालियों (अर्थात्, एईपीएस, आईएमपीएस, एनईटीसी, एनएफएस, रूपे, यूपीआई) की निपटान फ़ाइलों को वर्ष के सभी दिनों में रिज़र्व बैंक को पोस्ट करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। यह उपाय निपटान और डिफॉल्ट जोखिम के बिल्ड-अप को कम करेगा और सदस्य बैंकों द्वारा निधि के बेहतर प्रबंधन में सक्षम बनाएगा। यह भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र दक्षता को भी बढ़ाएगा। इस संबंध में निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

18. संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन और आवर्ती लेनदेन के लिए कार्ड पर ई-जनादेश - सीमा में वृद्धि

आवर्ती लेन-देन के लिए कार्ड (और यूपीआई) पर संपर्क रहित कार्ड लेनदेन और ई-मेंडेंट ने प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से लाभ उठाते हुए आम तौर पर ग्राहक सुविधा को बढ़ाया है। विशेष रूप से वर्तमान महामारी के दौरान कुशल और सुरक्षित तरीके से भुगतान करने के लिए ये अच्छी तरह से अनुकूल हैं। कार्ड पर संपर्क रहित सुविधा को अक्षम करने और ग्राहकों को उनके कार्ड की सीमाओं को नियंत्रित करने में सक्षम बनाने के हाल के निर्देश उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा में भी लाए हैं। कुशल और सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए, उपयोगकर्ता के विवेक पर, कार्ड (और यूपीआई) के माध्यम से आवर्ती लेनदेन के लिए संपर्क रहित कार्ड लेनदेन और ई-मेंडेंट की सीमा को 1 जनवरी 2021 से ₹2,000 से ₹5,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। परिचालन निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

भाषण

भारत में वित्तीय बाजार सुधारों को गति देना
शक्तिकान्त दास

भारत में वित्तीय बाजार सुधारों को गति देना *

शक्तिकान्त दास

मैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चौथे वार्षिक दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया। यह एक उपयुक्त अवसर है जब हम वित्तीय बाजारों के और विशेष रूप से, विदेशी मुद्रा बाजारों के पिछले एक साल के घटनाक्रम पर विचार करने और उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। वर्ष 2020 अभूतपूर्व रहा है। एक ऐसा अज्ञात संकट सामने आ खड़ा हुआ जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति पर सहसा विराम लगा दिया और हाल के समय में नीतिगत विचार-विमर्श लगातार इस वैश्विक महामारी के प्रभाव पर ही केंद्रित रहा है, और यह उचित ही है। इसके बावजूद, देश में किए गए नियामक और संस्थागत सुधार घरेलू वित्तीय बाजारों को अगले प्रक्षेपवक्र तक ले जाने में सफल रहे हैं। बाजार के विविध संविभागों को समाहित करने वाले इन सुधारों के बल पर एक सरलीकृत, सिद्धांत-आधारित विनियामकीय फ्रेमवर्क का सूत्रपात हो रहा है जिसका उद्देश्य है बाजार तक पहुँच को आसान बनाते हुए, उसमें सहभागिता बढ़ाते हुए, नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए, उपयोगकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करते हुए और उचित आचार को बढ़ावा देते हुए बाजारों के आधार को अधिक व्यापक बनाना। आज मैं, हाल के समय में किए गए सुधारों के पीछे निहित कारणों और उनके प्रमुख घटकों पर चर्चा करना चाहूँगा विशेष रूप से उन्हें एक खुली और अविभाज्य अर्थव्यवस्था की आकांक्षाओं को समर्थन देने में सक्षम आधुनिक और दक्ष वित्तीय बाजार के व्यापक संदर्भ में रखते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा।

इस तथ्य के मद्देनजर कि हम अभी भी इस महामारी के चंगुल से बाहर नहीं आए हैं, और अभी भी हमारे चिंतन-मनन के केंद्र में निकट भविष्य से जुड़ी समष्टि आर्थिक चिंताएं ही बनी हुई हैं, ऐसे में, मैं अपनी बात समष्टि आर्थिक प्रत्याशाओं और वित्तीय बाजारों के मौजूदा हालात पर संक्षिप्त चर्चा के साथ प्रारंभ करूँगा।

समष्टि आर्थिक प्रत्याशाएं

वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की तीव्र गिरावट और दूसरी तिमाही में अगग-अलग गति

* फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) चौथे वार्षिक दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2020 को श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण।

से आर्थिक गतिविधियों के अपने सामान्य स्तर पर वापसी के उपरांत, भारतीय अर्थव्यवस्था में आशा से अधिक तेजी से बहाली देखी गयी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी तीसरी तिमाही में उम्मीद से ज्यादा रफ्तार से उठ खड़ी हुई है। इसे देखते हुए ही, आईएमएफ ने वैश्विक संवृद्धि-दर संबंधी अपने अनुमान को संशोधित करते हुए जून 2020 में व्यक्त पूर्वानुमान की तुलना में कम गिरावट दर्शायी है।

हालांकि, आर्थिक संवृद्धि संबंधी दृष्टिकोण में सुधार हुआ है, तथापि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में और भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में संक्रमण के अचानक तेजी से बढ़ने के कारण संवृद्धि में पुनः गिरावट आने का जोखिम बना हुआ है। हमें इस बात पर नज़र रखनी है कि माँग में जो उछाल आया है, वह त्योहारों के मौसम के बाद कितना बना रहेगा और वैक्सीन के आने के बाद बाजार की प्रत्याशाओं के संभावित पुनर्मूल्यांकन के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। अक्टूबर के मौद्रिक नीति का जो रुख रहा उसमें इस बात पर बल दिया गया कि जो अस्थायी मुद्रास्फीति दबाव उत्पन्न हुआ है, उसे दूर किए जाने की आवश्यकता है और कम से कम चालू वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक अवधि में निभावकारी रुख बरकरार रखा जाए।

हाल के महीनों में हम अर्थव्यवस्था पर पड़े इन आघातों को यदि झेल सके तो इसका प्रमुख कारण था हमारे बाह्य शेष की बेहतर स्थिति जिसमें लगातार दो तिमाहियों तक चालू खाता शेष की स्थिति अधिशेष में बने रहने, मजबूत एफडीआई आवक के चलते संविभाग पूंजी आवक की पुनः शुरुआत, तथा विदेशी मुद्रा भंडार के लगातार बढ़ने से मदद मिली। हाल ही में सरकार ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने की नीति पर ध्यान केंद्रित करने का जो निर्णय लिया है, जिसमें कुछ लक्षित क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का माध्यम भी शामिल है, उसमें भारत की बाह्य शेष की यह मजबूत स्थिति लाभकारी हो सकती है।

वित्तीय बाजार की गतिविधियाँ

अब मैं वित्तीय बाजारों की बात करूँगा। घरेलू वित्तीय बाजार की स्थिति वर्ष की शुरुआत में अनुकूल थी लेकिन जैसे ही कोविड-19 महामारी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया, स्थितियाँ अत्यंत दबावपूर्ण हो गयीं और अव्यवस्था फैल गयी। आर्थिक गतिविधियों के मंद पड़ जाने से बाजार में चलनिधि की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। लगभग सभी प्रकार की आस्तियों की वित्तीय कीमतों में अस्थिरता बढ़ गयी। सरकारी प्रतिभूति बाजार में

प्रतिफल बढ़ा और प्रतिफल वक्र में तीव्र चढ़ाव देखने को मिला जिसने राजकोषीय गिरावट और एफपीआई द्वारा निरंतर की जा रही बिकवाली से जुड़ी चिंताओं को जन्म दिया। वाणिज्यिक पत्रों और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में भी वित्तपोषण की स्थिति खराब हो गई, जो बाजार की समग्र स्थिति के साथ-साथ आम तौर पर जोखिम लेने से बचने की प्रवृत्ति का परिचायक है। बढ़ती अस्थिरता और वायदा प्रीमियम के बढ़ने के साथ-साथ रुपये में तेजी से मंदी आयी। रिजर्व बैंक ने अग्रसक्रियता दर्शाते हुए वित्तीय बाजार की स्थितियों को सामान्य बनाने और जोखिम को कम करने के लिए बड़ी ही तेजी से अनेक पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कदम उठाए। बाजार के सहभागियों की प्रतिक्रिया भी सतर्कता भरी रही और हमने मिलकर सभी संविभागों में बाजार को स्थिर और आघातसहनीय बनाए रखने में सफलता पायी। रिजर्व बैंक वित्तीय बाजारों के कामकाज के सुचारु रूप से संचालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और वह ऐसी सूचनाओं का मूल्यांकन करना जारी रखेगा जिनका प्रभाव वित्तीय बाजारों पर पड़ सकता है और यदि आवश्यक हुआ तो संवृद्धि में गिरावट के जोखिम को कम करने की दिशा में कदम भी उठाएगा।

पिछले तीन दशकों में वित्तीय बाजार सुधारों की गति तेज हुई है, हालांकि इसमें वित्तीय संकटों की वजह से बाधाएं पड़ी हैं। सन 1990 के दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्रमशः खोला जाना प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही, अपने देश से जुड़ी विशिष्टताओं के मद्देनजर संस्थागत संरचना को अधिक गहन बनाया गया है। जैसे-जैसे व्यवस्थाएं बदलती गयीं, बाजारों ने भी लंबी दूरी तय की है।

इन वर्षों में, भागीदारी एवं विभिन्न प्रकार के लिखतों की उपलब्धता और रिपो तथा व्युत्पन्नी बाजार के विकास के संदर्भ में देखें तो देश के बॉन्ड बाजार का आधार व्यापक हुआ है। संप्रभु प्रतिफल वक्र का विस्तार बढ़कर अब 40 वर्ष हो गया है और यह कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के विकास के लिए एक स्थिर मूल्य निर्धारण का आधार प्रदान करता है। विदेशी मुद्रा बाजार के लिखतों तथा बाजार सहभागियों में विविधता बढ़ने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ हमारी अर्थव्यवस्था अधिक एकीकृत होने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा बाजार ने भी एक लंबा रास्ता तय किया है। इन परिवर्तनों के साथ, बाजार के बुनियादी ढांचे में भी उल्लेखनीय सुधार हुए हैं जिनमें शामिल हैं- सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम की प्रक्रिया को अत्याधुनिक बनाना, केंद्रीय बैंक के भीतर एक कुशल और पूरी तरह से डीमैटरियलाइज्ड डिपॉजिटरी सिस्टम तैयार करना तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ट्रेड रिपोर्टिंग और केंद्रीय प्रतिपक्षीय निपटान हेतु प्लेटफॉर्मों की उपलब्धता।

हालांकि, वित्तीय बाजार विकसित हुए, तथापि कुछ खामियां भी देखने में आयीं। सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार में चलनिधि बढ़ी लेकिन यह कुछ विशिष्ट अवधियों के लिए ही सीमित थी। इनमें भागीदारी का आधार बढ़ता गया लेकिन इसके प्रति नजरिए में विविधता कम ही आ सकी और "खरीदो और रखे रहो" तथा "केवल दीर्घावधि" जैसे निवेश विकल्पों की ही प्रमुखता बनी रही। ब्याज दर व्युत्पन्नियों के बाजारों में तेजी आयी लेकिन यह वृद्धि एक ही उत्पाद के इर्द-गिर्द सीमित रही- ओवरनाइट इंडेक्सड स्वैप- और वह भी बाजार सहभागियों के एक छोटे से समूह के लिए। घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में भी संवृद्धि आयी, लेकिन यही स्थिति अपतटीय बाजारों की भी रही जिससे भारतीय रुपये के लिए वैश्विक बाजार टूट गया और बाजार की दक्षता को क्षति पहुंची। नए उत्पादों का विकास बाधित रहा जो आंशिक रूप से सीमित भागीदारी के कारण था और उन विनियामकीय प्रतिबंधों के कारण भी जो जटिल उत्पादों के प्रति पुराने अनुभवों की तथा कीमत निर्धारण एवं गलत बिक्री की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित किए गए थे। इस बीच, वैश्विक बाजारों में कदाचार और कुप्रथाओं के कतिपय प्रकरणों के कारण इस बात की महती आवश्यकता अनुभव की गयी कि अभिशासन के ढांचे में इस प्रकार सुधार किए जाएं कि घरेलू बाजार पहले से ही सुरक्षित किए जा सकें।

इन खामियों के बावजूद, वित्तीय बाजारों की आघातसहनीयता और उनकी मजबूत नींव, जो समय के साथ और अधिक सुदृढ़ होती गयी, ने एक अवसर भी उपलब्ध कराया। कम प्रतिभागियों वाले बाजार प्रायः ऐसे 'सीमित यूजर क्लब' बन जाते हैं जिनके व्यवहार का पूर्वानुमान लागाया जा सकता है। इतना ही नहीं, विरल बाजारों में सट्टा प्रवाह अव्यवस्था पैदा कर सकता है। सघन बाजारों में, यही प्रवाह चलनिधि के स्रोत बन जाते हैं और बाजारों को अधिक सुदृढ़ बना देते हैं। अर्थव्यवस्था को नपे-तुले अंदाज में खोलने से घरेलू बचत में वृद्धि होती है तथा संवृद्ध और विकास के लिए वित्त जुटाने में इससे सहायता मिलती है।

इसी पृष्ठभूमि में, रिजर्व बैंक ने उदारीकरण की गति को तेज करने के उद्देश्य से अगले चरण के सुधारों का श्रीगणेश करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इन सुधारों की दिशा में हाल में उठाए गए कदम, जिनमें से बहुतों का क्रियान्वयन अभी जारी है, चार प्रमुख विषयों पर केंद्रित हैं, (i) वित्तीय बाजारों को उदार बनाना और बाजार विनियमन को सरल बनाना; (ii) वित्तीय बाजारों का अंतरराष्ट्रीयकरण; (iii) "खरीद पक्ष" वाले उपयोगकर्ता के हितों

की रक्षा; और (iv) सुदृढ़ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब मैं इनमें से प्रत्येक विषय पर चर्चा करना चाहूंगा।

वित्तीय बाजारों को उदार बनाना और बाजार विनियमन को सरल बनाना

हाल की विनियामकीय पहलें मोटे तौर पर उस दृष्टिकोण से प्रेरित हैं कि यदि कोई व्यक्ति वित्तीय बाजारों तक पहुंचने की आवश्यकता महसूस करता है तो वह न्यूनतम लागत पर सुविधाजनक तरीके से ऐसा कर सके। ब्याज दर व्युत्पन्नियों और विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों के लिए जो सिद्धांत-आधारित विनियमन तैयार किया गया है, उसका व्यापक उद्देश्य यही है। प्रक्रिया-संबंधी विस्तृत विनिर्देशों के स्थान पर बुनियादी सिद्धांत बताए गए हैं जिनके माध्यम से बाजार-सहभागियों को अपेक्षाकृत अधिक परिचालनात्मक सुगमता सुलभ करायी गयी है। व्युत्पन्नी करारों के डिजाइन और विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों को रद्द करने और फिर से बुक करने के संबंध में जो प्रतिबंध पहले लगाए गए थे, उन्हें हटा लिया गया है। निवास-स्थान के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था, उसे दूर किया गया है या कम कर दिया गया है जिससे बाजार में प्रवेश या उससे निकासी के मामले में विदेशी प्रतिभागियों और घरेलू इकाइयों को एकसमान अवसर मिल रहा है। हालांकि, अंतर्निहित एक्सपोजर की मौजूदगी अभी भी बाजार तक पहुँच का आधार बनी हुई है, तथापि अनुमानित जोखिम की हेजिंग की अनुमति देते हुए हेजिंग में अधिक से अधिक उदार और आसान बनाया गया है। सीमित/कम हेजिंग अपेक्षा वाले उपयोगकर्ताओं को अंतर्निहित एक्सपोजर की मौजूदगी को प्रमाणित किए बिना ही यूएस \$10 मिलियन के समतुल्य राशि के अनुबंध करने की अनुमति दी गई है।

विनियमों को सरल बनाए जाने और प्रक्रियाओं में लचीलापन लाए जाने से परिचालन स्थितियों को सुगम बनाने में सहायता भी मिली है और इस प्रकार लागत और अक्षमता को भी कम करना संभव हुआ है। यद्यपि कुछ परिचालनगत बाधाएं अपरिहार्य हो जाती हैं, विशेष रूप से वे जो विवेकपूर्ण निर्णयों का परिणाम होती हैं, तथापि हमारा नज़रिया यह रहा है कि इन सीमाओं में रहते हुए भी परिचालनात्मक सहजता लायी जाए। इसका एक और उदाहरण हाल ही में पारित अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 है, जिसके आ जाने से परिचालन के सम्मुख आने वाली एक महत्वपूर्ण बाधा दूर हो गयी है। द्विपक्षीय नेटिंग को विधिक मान्यता प्राप्त न होने के कारण जोखिम प्रबंधन में व्युत्पन्नियों का प्रभावी तरीके से

उपयोग नहीं हो पाता था। यह कानून नकद और व्युत्पन्नी बाजार लेनदेन की प्रति-प्रविष्टि के लिए उपलब्ध फ्रेमवर्क को सशक्त बनाता है। इससे वित्तीय संस्थानों के लिए पूंजी-अपेक्षाओं को इष्टतम बनाना संभव हो सकेगा और व्युत्पन्नी बाजारों के विकास को गति मिलेगी।

वित्तीय बाजारों का अंतरराष्ट्रीयकरण

वित्तीय बाजारों के अंतरराष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप उनकी दक्षता बढ़ेगी जिससे लेनदेन लागत अपेक्षाकृत कम होने की संभावना है। पिछले तीन दशकों में भारत में आमूलचूल बदलाव आया है। पहले यह लगभग बंद अर्थव्यवस्था हुआ करता था, परंतु अब वह पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है और पहले की तुलना में इसके अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और पूंजी प्रवाह में मात्रात्मक रूप से भारी वृद्धि हुई है। आज, पूंजी खाता काफी हद तक परिवर्तनीय है। अधिकांश क्षेत्रों में आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति दी गयी है और भारतीय निगमित संस्थाओं को उनकी निवल मालियत के गुणज के आधार पर बाहरी देशों में एफडीआई की इजाजत है। बाह्य वाणिज्यिक उधार ढांचे को भी काफी हद तक उदार बनाया गया है ताकि इसके लिए अधिक से अधिक उधारकर्ता पात्र बन सकें, और साथ ही, परिपक्वता अपेक्षाओं को भी कम किया गया है और अंतिम उपयोग से जुड़े प्रतिबंधों में छूट दी गई है।

सुविचारित समष्टि-विवेकपूर्ण मानदंडों के भीतर कार्य करते हुए भारतीय कर्ज बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विस्तार किया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश के लिए मध्यम अवधि के ढांचे के तहत सीमाओं को धीरे-धीरे बढ़ाया गया है और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया गया है। एक स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) लागू किया गया है, जो समष्टि-विवेकपूर्ण नियंत्रणों से छूट प्रदान करता है लेकिन न्यूनतम प्रतिधारण अवधि में ही। अधिकाधिक अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, पूर्णतया अभिगम्य मार्ग (एफएआर) की शुरुआत की गयी जिसके तहत अनिवासी बिना किसी प्रतिबंध के निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थितियों का संज्ञान लेते हुए पूंजी खाता परिवर्तनीयता को एक प्रक्रिया मानने का दृष्टिकोण जारी रहेगा, न कि एक घटना भविष्य में, लघु और मध्यम अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए दीर्घावधि योजना पर कार्य करना होगा।

बाजारों को खोलने की दिशा में एक प्रमुख कदम उठाते हुए भारत के बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपतटीय रुपया व्युत्पन्नी बाजारों में कारोबार करें। इस पहल से यह उम्मीद की जाती है कि अस्थिरता पर लगाम लगाने और हेजिंग की लागत को कम करने के अलावा, घरेलू और अपतटीय बाजारों के बीच विभाजन को कम किया जा सकेगा। बैंकों को विदेशी मुद्रा लेन-देन को सामान्य घरेलू बाजार के कामकाज की अवधि के बाद भी जारी रखने की अनुमति भी दी गई है, ताकि बाजार में तत्काल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके एक पूरक उपाय के तौर पर, गिफ्ट सिटी में कामकाज करने वाली बैंकिंग इकाइयों और एक्सचेंजों को ओवर द काउंटर (ओटीसी) और एक्सचेंज ट्रेडेड रुपया डेरिवेटिव के लेनदेन की अनुमति भी दी गई है।

"खरीद पक्ष" को सुरक्षा देना - उपयोगकर्ता सुरक्षा

जब बाजारों को उदार बनाया जाता है और अपेक्षाकृत नये तथा अधिक परिष्कृत उत्पादों की शुरुआत की बात आती है तो उपयोगकर्ता- जो कि वित्तीय बाजारों के 'खरीद' पक्ष होते हैं- के हितों की रक्षा अनिवार्य हो जाती है। इस संबंध में कई पहलें की जा गई हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख मैं करना चाहता हूँ।

कम परिष्कृत उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, ओटीसी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर व्युत्पन्नी लेनदेन के लिए एक उपयोगकर्ता वर्गीकरण फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसमें उपयोगकर्ताओं को 'खुदरा' और 'गैर-खुदरा' में वर्गीकृत किया गया है। खुदरा उपयोगकर्ताओं को केवल ऐसे व्युत्पन्नी उत्पादों की पेशकश की जा सकती है जो जटिल न हों, जबकि गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए उनकी कारोबारी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों में नवाचार की अनुमति दी गई है।

विशेष रूप से एमएसएमई और अन्य छोटे उपयोगकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा उत्पादों के उचित और पारदर्शी मूल्य निर्धारण का मुद्दा लगातार हमारे ध्यान में है। बाज़ार-निर्माताओं के लिए अब यह अनिवार्य हो गया है कि वे खुदरा उपयोगकर्ताओं के साथ व्यापार करते समय शुल्क/प्रभार को अलग से दर्शाएं। साथ ही, रिज़र्व बैंक के कहने पर दि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा 'एफएक्स रिटेल' नाम के एक अनाम ऑर्डर मैचिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, की शुरुआत की गयी है। इस प्लेटफॉर्म पर कम राशि के लेनदेन वाले उपयोगकर्ता सर्वोत्तम उपलब्ध बाज़ार दरों पर लेनदेन कर सकते हैं। इन उपायों से खुदरा उपयोगकर्ता के लिए अधिक पारदर्शिता

और सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद है। यदि विदेशी मुद्रा बाजारों के प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के लाभ सुलभ कराने हैं, तो बैंकों को इस दिशा में गहन प्रयास करने होंगे।

व्युत्पन्नी बाजारों को जैसे-जैसे अधिक उदार बनाया जा रहा है, यह आवश्यक हो गया है कि उत्पादों की उपयुक्तता और उचित उपयोगकर्ता का सटीक आकलन करते हुए बाजार के परिचालन को सशक्त बनाया जाए। विनियामकीय दृष्टिकोण में होने वाले व्यापक परिवर्तनों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए इस संबंध में विनियामकीय अपेक्षाओं की समीक्षा की जा रही है।

सुदृढ़ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना

विभिन्न वित्तीय संकटों के दौरान भी भारत में वित्तीय बाजारों का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ बना रहा है। इस सुदृढ़ता को भविष्य में भी निरंतर बनाए रखने के लिए बाजारों की विफलता की अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से सीख लेते हुए और भी कई पहलें की गई हैं।

वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र में कामकाज कुशलतापूर्वक होता रहे और विश्वास बना रहे इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि बाजार का परिचालन न्यायोचित हो। अभी तक तो, फिक्सड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) और फेडाई जैसे बाजार निकायों द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करते हुए इसके सहभागी कारोबार करते थे। इनके पूरक के तौर पर और इन्हें अधिक सशक्त बनाने के लिए बाजार के दुरुपयोग को रोकने हेतु एक विनियामकीय फ्रेमवर्क लागू किया गया है।

रिज़र्व बैंक जी20 ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाजार सुधारों को लागू करने के लिए प्रयास कर रहा है। वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) को विनियामकीय दायरे में लाया गया है ताकि उनका अधिक दक्षता के साथ परिचालन सुनिश्चित हो सके और प्रणालीगत जोखिमों से निपटा जा सके। गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित किए जाने वाले व्युत्पन्नियों से प्रतिपक्षी जोखिम को कम करने के उद्देश्य से ओटीसी व्युत्पन्नियों हेतु वेरिफेशन मार्जिन के लिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क हाल ही में जारी किया गया है।

एक विधिक इकाई पहचानकर्ता (लेई) लागू करने के प्रयास वैश्विक स्तर पर किए जा रहे हैं, जो वित्तीय बाजार सहभागियों को एक विशिष्ट पहचान देता है और जोखिमों के एकत्रीकरण को संभव बनाता है। रिज़र्व बैंक जिन बाजारों का विनियमन करता है, उसके प्रतिभागियों के लिए लेई के उपयोग को बैंक द्वारा अनिवार्य कर

दिया गया है। वास्तव में, हम ऐसे कुछ देशों में से एक हैं जिन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजारों के साथ-साथ क्रेडिट बाजार (बड़े ऋण) में लेनदेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्युत्पन्नी बाजारों से बाहर भी लेई को लागू किया है।

एक प्रमुख मुद्दा जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी रही हैं, वह यह है कि लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट (लिबोर) से वैकल्पिक संदर्भ दरों में संक्रमण। भारत में, वित्तीय बेंचमार्क प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। हाल ही में, महत्वपूर्ण वित्तीय बेंचमार्क के प्रशासकों को विनियमन के दायरे में लाया गया था ताकि प्रभावी अभिशासन ढांचा और प्रक्रिया-नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। लिबोर से संक्रमण के लिए स्वयं को तैयार करने में ये सुधार हमारी सहायता करेंगे। वैकल्पिक बेंचमार्कों में संक्रमण की इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और ग्राहकों में जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय बैंक संघ बाजार के सहभागियों के साथ निकट संबंध स्थापित करते हुए काम कर रहा है। किसी ऐसे बेंचमार्क, जिसकी पैठ वित्तीय प्रणाली में बहुत गहरी रही हो, से सुविधाजनक तरीके से संक्रमण के लिए बहुत जरूरी है कि सभी हितधारक मिलजुलकर गंभीरतापूर्वक इसके लिए प्रयास करें।

IV. निष्कर्ष

मैंने आज उन व्यापक मुद्दों पर बात करने का प्रयास किया है जो वित्तीय बाजारों के उदारीकरण / सुधार की कार्ययोजना में नियामक मदों के रूप में रहे हैं। हाल के दिनों में जो बदलाव लाये गए हैं, उनका उद्देश्य रहा है कि वित्तीय बाजारों में संसाधनों के आवंटन में दक्षता को बढ़ाया जाए और उसके माध्यम से आर्थिक विकास में योगदान किया जाए। यह स्वतंत्रता अपने साथ कुछ उत्तरदायित्व भी लाती है। इसके वांछित परिणाम मिलते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वित्तीय संस्थाएं और बाजार के सहभागी वित्तीय बाजारों को व्यावसायिक बनाने तथा वित्तीय मध्यस्थता को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे इन सुधारों को कितना आगे तक ले जा पाते हैं। इन विनियमों को सरल बनाने और उनमें लचीलापन लाने के जो उपाय किए गए हैं, उसका लाभ अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचना चाहिए। नए उत्पादों और नए बाजार संविभागों का आकार-प्रकार तय करते समय, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जैसे-जैसे हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे आएं, वैसे-वैसे हमें अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और जबावदेह आचार-संहिता को विकसित भी करना होगा। इस कार्य में बाजार सहभागियों तथा फेडाई को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

लेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

तत्काल स्थानिक गति संकेतक आर्थिक गतिविधि

सरकारी वित्त 2020-21 : अर्धवार्षिक समीक्षा

भारत में ग्रामीण – शहरी मुद्रास्फीति के आयाम

कोविड-19 काल में विनिमय दर अस्थिरता को नियंत्रित करना

सेवा और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण: हालिया प्रवृत्ति

बैंक ऋण सर्वेक्षण- हालिया रुझान

भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर मौसमी परिवर्तन का प्रभाव

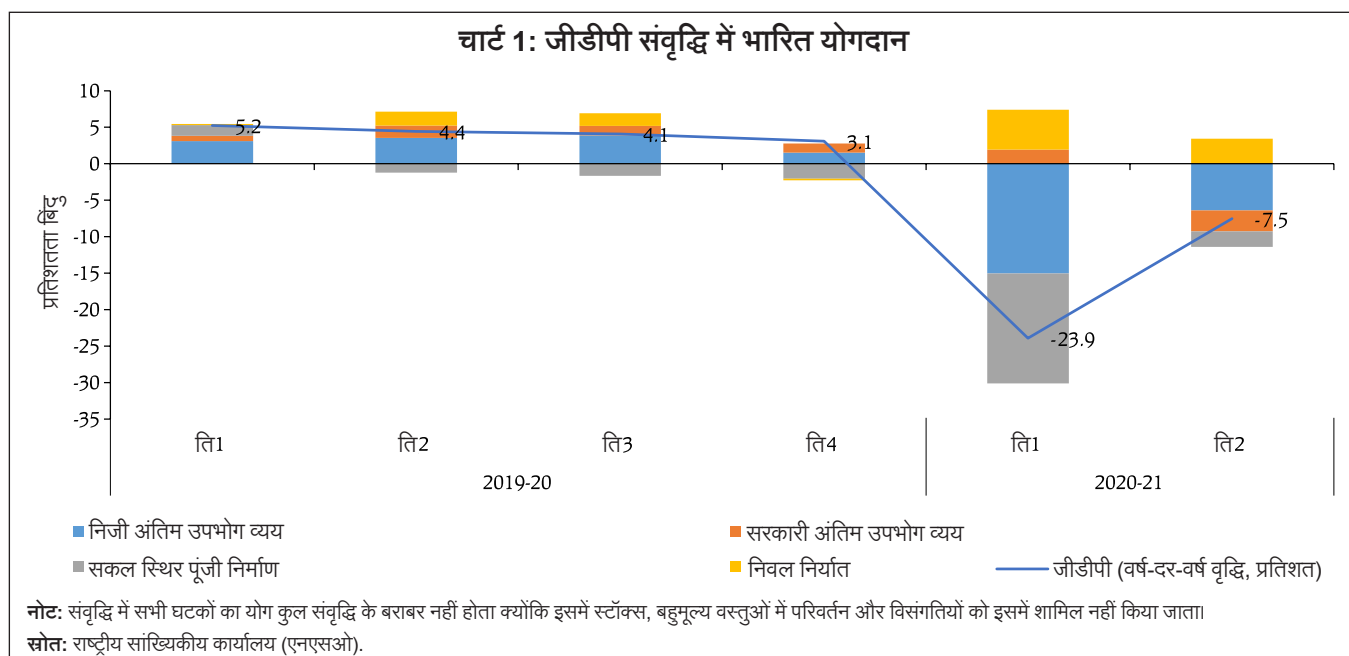
अर्थव्यवस्था की स्थिति*

पिछले माह के आलेख में प्रस्तुत आकलन के बाद से ऐसे और भी साक्ष्य मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 की निराशा से बाहर निकल रही है और तमाम पूर्वानुमानों को झुठलाने वाली गति से वापसी कर रही है। हालाँकि, मुश्किलें अभी भी हैं, परंतु यदि सभी हितधारक निरंतर दृढ़तापूर्वक अपने प्रयास जारी रखेंगे तो भारत और अधिक गति से विकास पथ पर बढ़ सकेगा।

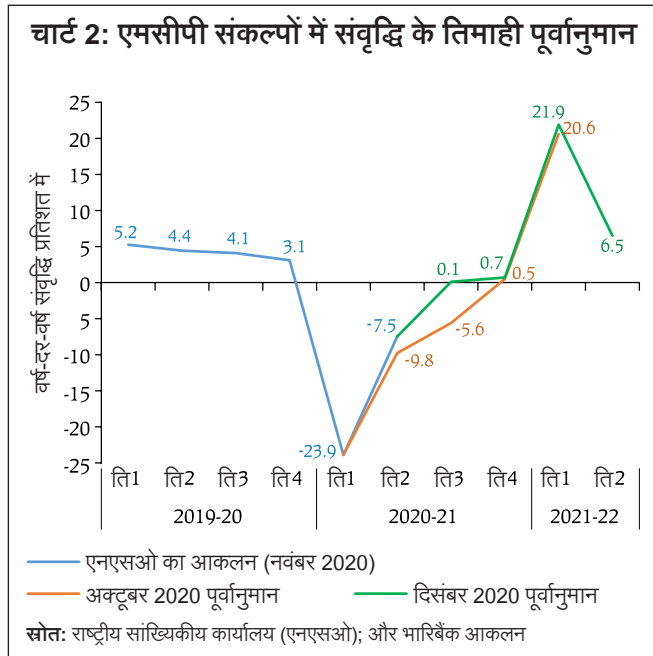
बीते माह के दौरान, ऐसे और भी सबूत मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 की घनघोर निराशा से बाहर निकल रही है और सर्दियों की लंबी घनी छाया के बीच से रास्ता बनाती हुई रोशनी की दुनिया में अपना आशियाना बना रही है। पहला सुखद आश्चर्य तब हुआ जब राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने अपने नवंबर अंत के आंकड़े जारी किए – वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था को दिए गए घाव दूसरी तिमाही में तुलनात्मक रूप से काफी सतही साबित हुए और अर्थव्यवस्था की बहाली की दर इतनी अच्छी रही

है कि यह तमाम पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ चुकी है (चार्ट 1)। दूसरा, पिछले महीने के बुलेटिन (कुमार, 2020) में प्रस्तुत किए गए तात्कालिक पूर्वानुमानों में अद्यतन आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) से यह संकेत मिलता है कि तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि के फिर से धनात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद है – हालांकि मात्र 0.1 प्रतिशत तक। तीसरा, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के चौथे द्विमासिक संकल्प में नीतिगत दरों को और रुख को तो यथावत बनाए रखा गया; लेकिन सख्त संदेश दिया गया: विकास के पूर्वानुमानों- लक्षित मुद्रास्फीति वाले एक लचीले फ्रेमवर्क के तहत मध्यवर्ती लक्ष्य और सबसे असरदार संचरण उपाय – में अक्टूबर की तुलना में 200 आधार अंकों का धनात्मक संशोधन किया गया और यदि यह प्रभावी रहा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 की दूसरी छमाही के 0.4 प्रतिशत से आगे बढ़ते हुए 2021-22 की पहली छमाही में 14.2 की वृद्धि दर हासिल कर लेगी (चार्ट 2)।

वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहा है, उसके पीछे दो महत्वपूर्ण ताकतें मिलकर काम करती नज़र आ रही हैं। प्रथम, भारत में कोविड-19 संक्रमण का वक्र झुकने लगा



* यह लेख आशीष थॉमस जॉर्ज, कृष्ण मोहन कुशवाहा, मधुरेश कुमार, कुणाल प्रियदर्शी, पलक गोदरा, जितेंद्र सोकल, मनु शर्मा, भानु प्रताप, शोभित गोयल, बरखा गुप्ता, साक्षी सूद, प्रियंका सचदेवा, ऋषभ कुमार, ऋषभ कुमार, रिज्जेन यांगडोल, राजस सरॉय, शशिधर एम. लोकरे और माइकल देवव्रत पात्र ने तैयार किया है। इस लेख में व्यक्त विचार इन लेखकों के निजी विचार हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।



है: सितंबर मध्य के बाद से, कुछेक जगहों पर हुई वृद्धि को छोड़ दें, तो सप्ताह-दर-सप्ताह संक्रमण कम हो रहा है, और स्वस्थ होने की दर 95 प्रतिशत के स्तर को छू रही है। कई वैक्सीन न केवल परीक्षण की स्थिति में पहुंच गयी हैं, बल्कि उनके भारत में यातायात/परीक्षण/उपयोग संबंधी उपयुक्तता की जाँच भी की जा रही है (सारणी 1)। दूसरा, अब यह स्पष्ट हो रहा है कि राजकोषीय प्रोत्साहन एक तरीका होता है, एक 'पद्धति', यदि आप चाहें। चलनिधि / गारंटी के साथ प्रारंभ करते हुए अर्थव्यवस्था के लिए नकद / वस्तुओं के रूप में समर्थन – जो कि उस समय की

आवश्यकता थी जब महामारी ने करोड़ों लोगों से उनका जीवन और उनकी आजीविका छीन ली – यह अब धीरे-धीरे निवेश और उपभोग की मांग में वृद्धि में योगदान कर रही है। राजकोषीय उपायों को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) में खपत व्यय से लेकर आत्म निर्भर 2.0 और 3.0 (चार्ट 3) में निवेश व्यय तक केंद्रित किया गया है। कुल मिलाकर, ऊपर-नीचे की राजकोषीय उत्तेजना 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत के करीब बढ़ने की संभावना होगी (सरकारी वित्त पर बाद के लेख में बॉक्स 1 देखें)। दूसरे शब्दों में, उच्च आवृत्ति संकेतकों में निहित अस्थिरता से परे देखना समझदारी है। कंपनियां पहले से ही ऐसा कर रही हैं - 12 महीने के आगे की कमाई के विश्लेषण से बड़ी संख्या में कंपनियों के लिए दृष्टिकोण में सुधार का पता चलता है (चार्ट 4)। लॉकडाउन से बहुत अधिक प्रभावित ऑटो और कैपिटल गुड्स जैसे क्षेत्रों में भविष्य में कमायी में फिर से बेहतरी की उम्मीद की जाने लगी थी। हेल्थकेयर, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और अतिशय बिक्री वाली उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) की उत्पादक कंपनियां और अधिक आय की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसके अलावा, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को भीतर से मजबूत किया जा रहा है क्योंकि ऋण चुकौती क्षमता बेहतर हो रही है और कर्ज-पोषित आस्तियों की मात्रा को कम किया जा रहा है। विपणन के क्षेत्र में किए जा रहे नवोन्मेषी सुधार भारत के कृषि क्षेत्र को भी आगे ले जाने में सहयोगी बन रहे हैं। यह स्वीकार करना होगा कि भारत के समक्ष ऐसी अनेक बाधाएं अभी भी हैं जो बेहतर कल के

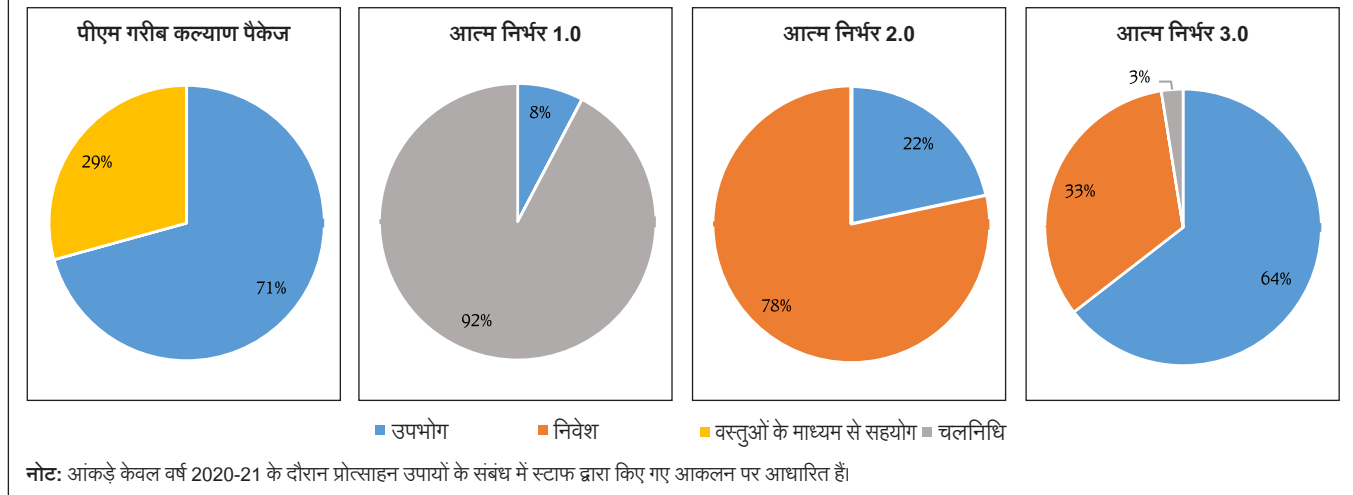
सारणी 1: कोविड-19 के टीके

कंपनी	प्रकार	खुराक	कितना प्रभावी	भंडारण
ऑक्सफोर्ड यूनी-एस्ट्राजेनेका	वायरल वेक्टर (आनुवंशिक रूप से संशोधित वायरस)	2	62-90%	सामान्य फ्रिज के तापमान पर
मॉडर्ना	आरएनए (वायरस आनुवंशिक कोड का हिस्सा)	2	95%	-20 डिग्री सेल्सियस, 6 महीने तक
फाइजर-बायोएनटेक	आरएनए	2	95%	-70 डिग्री सेल्सियस
गमलेया (स्पुतनिक वी)	वायरल वेक्टर	2	92%	सामान्य फ्रिज के तापमान पर
कैनसिनोबायो (ऐड5-एनकोव)	रिकॉम्बिनेंट एडेनोवायरस टाइप 5 वेक्टर			
सिनोफार्म: बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स	निष्क्रिय सार्स-कोव-2 (वेरो सेल)			
कोरोनावैक सिनोवैक	निष्क्रिय सार्स-कोव-2			
बीबीवी152 (कोवेक्सीन) भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च	निष्क्रिय सार्स-कोव-2			
एनवीएक्स-कोव2373(145) नोवावैक्स	सार्स-कोव-2 रिकॉम्बिनेंट स्पाइक प्रोटीन नैनोपार्टिकल्स			

स्रोत: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

¹ रिकवरी दर कुल संक्रमित व्यक्तियों की तुलना में संक्रमण मुक्त हो चुके रोगियों की संख्या के रूप में पारिभाषित की जाती है।

चार्ट 3: प्रोत्साहन उपायों का असफल होना, सहयोग की प्रकृति के आधार पर

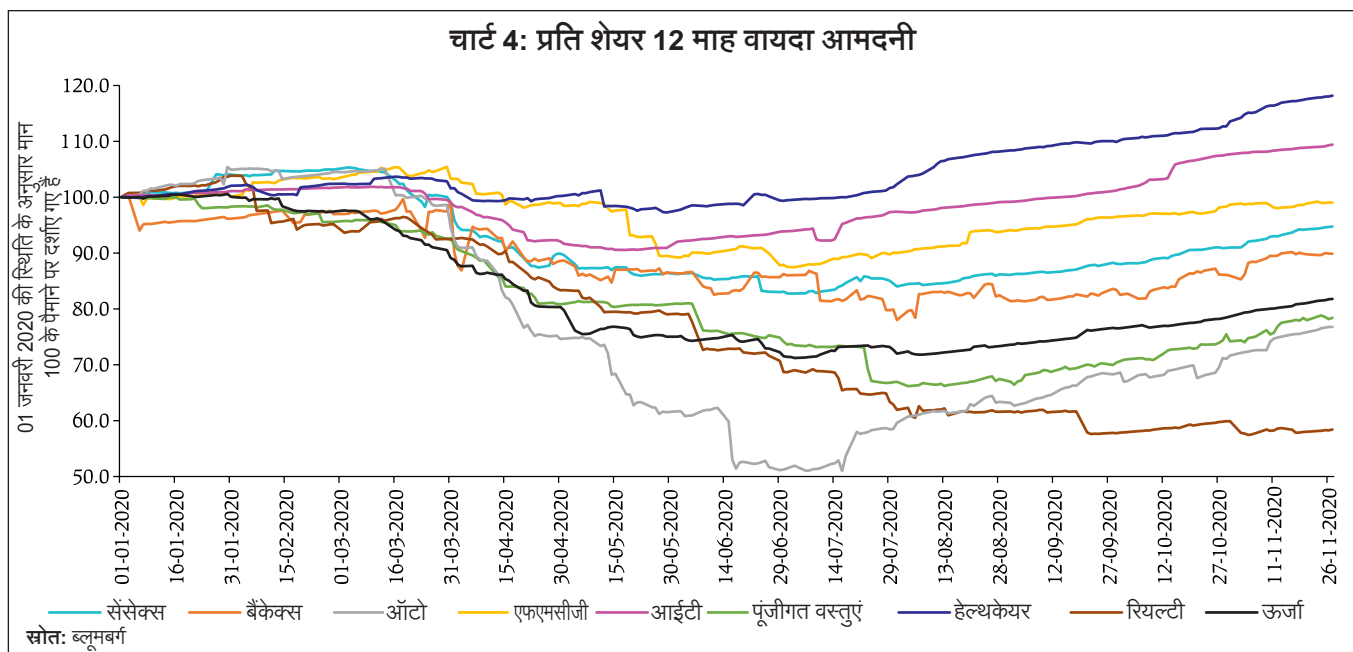


निर्माण के हमारे संकल्प में बाधक हैं, लेकिन अब हम उच्च आवृत्ति संकेतकों की ओर बढ़ रहे हैं और यह निश्चय ही एक आशा की किरण है। यह लेख पाँच खंडों में व्यवस्थित है। खंड II वर्तमान वैश्विक आर्थिक और वित्तीय बाजार की गतिविधियों का आकलन करता है। खंड III उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित रुझानों का निचोड़ प्रस्तुत करता है। खंड IV में वित्तीय बाजार की बदलती स्थितियों की समीक्षा की गयी है, और अंतिम खंड निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

II. वैश्विक परिदृश्य

हालांकि वायरस के प्रकोप की दूसरी लहरों ने वैश्विक बहाली की दर पर रोक लगा दी, फिर भी यूएस में आए चुनाव परिणाम तथा काफी आगे के स्तरों तक पहुंच चुके क्लीनिकल परीक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन आ जाने की खबरों ने वैश्विक बाजारों में सरगर्मी ला दी। जोखिम लेने की क्षमता फिर से काफी बढ़ गयी दिखती है जिससे आस्तियों का प्रवाह जोखिम मुक्त निवेशों से बाहर आकर स्टॉक बाजार और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की ओर हो रहा है। यह विश्वास

चार्ट 4: प्रति शेयर 12 माह वायदा आमदनी













बढ़ता जा रहा है कि स्वास्थ्य से जुड़ी इस महामारी का अंत निकट है और आखिरकार वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं साकार होती दिख रही हैं। परंतु साथ ही, दुनिया भर में व्यापक रूप से वैक्सीन पहुंचाने के लिए अपेक्षित तैयारियों से जुड़ी चुनौतियों के कारण वैक्सीन आ जाने की खबर से निकली आशा की किरण मद्धिम पड़ती नज़र आ रही है। 19 नवंबर को, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) ने चेतावनी भरे स्वर में कहा – वैक्सीन के आ जाने के बाद भी अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान पर विराम नहीं लगाया जा सकेगा और इसका प्रभाव भविष्य में लंबे समय तक महसूस किया जाएगा, विशेष रूप से सबसे गरीब और सबसे कमजोर तबके द्वारा, क्योंकि अत्यधिक गरीबी में गुजर बसर कर रहे लोगों की संख्या में 130 मिलियन लोग और जुड़ जाएंगे।

यह मानते हुए कि नए सिरों से बढ़ते वायरस के प्रकोप पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, और 2021 के अंत तक वैक्सीन व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाने की संभावना के मद्देनज़र उत्पन्न आत्मविश्वास के आधार आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने दिसंबर 2020 में व्यक्त अपने आर्थिक दृष्टिकोण में वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक जीडीपी में 4.2 प्रतिशत की गिरावट और उसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे परंतु असमान बहाली दिखने और वैश्विक जीडीपी वर्ष 2021 में 4.2 प्रतिशत और वर्ष 2022 में 3.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया गया है (सारणी 2)। 2021 के अंत तक, वैश्विक जीडीपी अपने महामारी-पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएगी, लेकिन इसके प्रदर्शन में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में स्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा। भारत के बारे में, ओईसीडी की टिप्पणी है कि दुनिया के सबसे शुरुआती और सख्त लॉकडाउन के कारण वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद मिली। वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी में 10 प्रतिशत की कमी आने और इसके बाद वापसी की उम्मीद है, लेकिन जीडीपी को महामारी-पूर्व का स्तर हासिल करने में लगभग दो साल लग सकते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उज्ज्वल पक्ष के रूप में देखा जा रहा है।

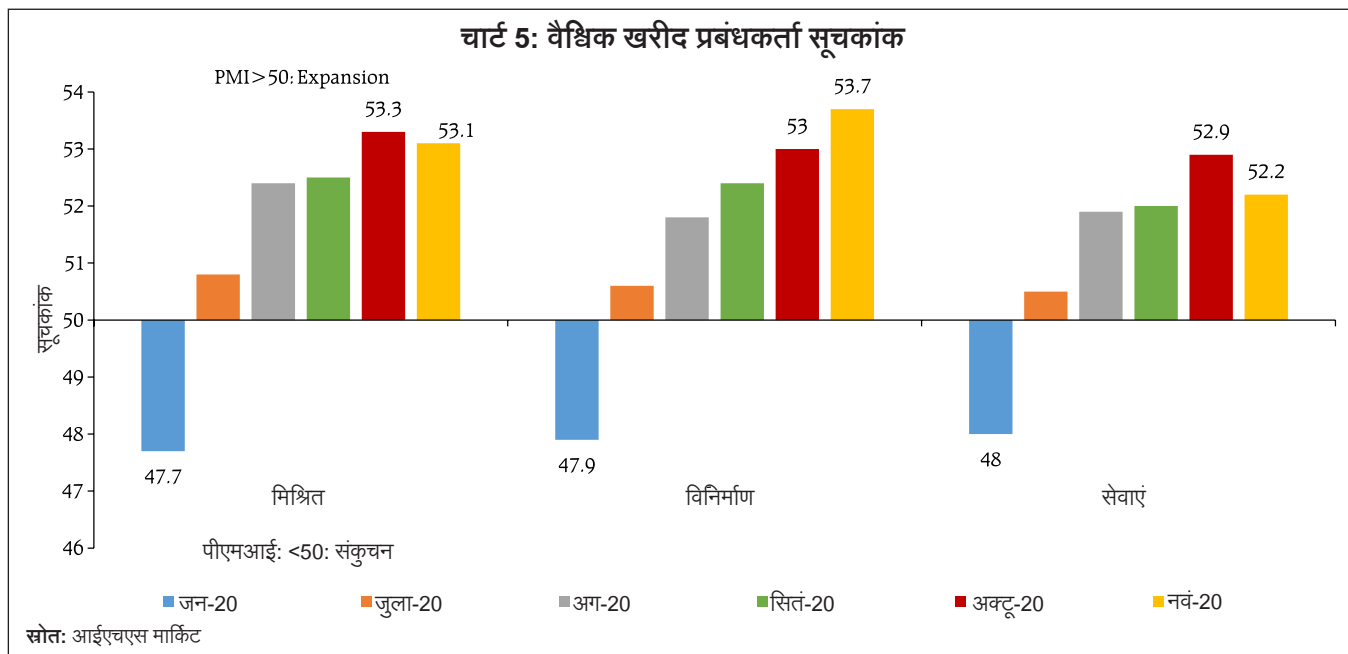
कुल मिलाकर, आर्थिक गतिविधियों में आए संकुचन के कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। इन उलटफेरों को दर्शाते हुए, ग्लोबल कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) नवंबर 2020 में घटकर 53.1 पर आ गया, जो एक महीने पहले (चार्ट 5) के दो साल के उच्चतम स्तर 53.3 पर था। नवंबर में लगातार पांचवें महीने विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा। वैश्विक सेवा क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी

सारणी 2: ओईसीडी आर्थिक परिदृश्य पूर्वानुमान दिसंबर 2020 – चुनिंदा आई और ईएमई

देश	2019	2020	2021	2022
 विश्व	2.7	-4.2	4.2	3.7
अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं				
 यूएस	2.2	-3.7	3.2	3.5
 यूके	1.3	-11.2	4.2	4.1
 यूरो क्षेत्र	1.3	-7.5	3.6	3.3
 जापान	0.7	-5.3	2.3	1.5
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं				
 चीन	6.1	1.8	8.0	4.9
 ब्राजील	1.1	-6.0	2.6	2.2
 रूस	1.3	-4.3	2.8	2.2
 दक्षिण अफ्रीका	0.2	-8.1	3.1	2.5
 भारत	4.2	-9.9	7.9	4.8

स्रोत: ओईसीडी आंकड़े

अक्टूबर की तुलना में थोड़ी मंद रही। उपभोक्ता सेवाओं में लगातार दसवें महीने सुस्ती आयी। संक्रमण की दूसरी लहर से उत्पन्न व्यवधानों और मांग पर पड़ी मार के कारण वैश्विक व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अंकटाड के अनुसार, वैश्विक व्यापार, जिसमें 2020 की दूसरी तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 19 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आयी थी, तीसरी तिमाही में भी संकुचन जारी रहा और लगभग 4.5 प्रतिशत की गिरावट आयी। इस गिरावट के दोगुना हो जाने की व्यापक आशंका के मद्देनज़र यदि आर्थिक गतिविधि और खराब नहीं हो जाती, तो चौथी तिमाही में संकुचन अपेक्षाकृत कम होगा और समान आधार पर गिरावट लगभग 3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। सितंबर से ही घटती मांग की संभावनाओं के मद्देनज़र कच्चे तेल की टूटती कीमतें, 'वैक्सीन से जुड़ी आशाओं' के आधार पर तथा पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा उत्पादन में की गयी कटौती को आगे भी



जारी रखने के फैसले के कारण नवंबर माह में बढ़ने लगीं। नवंबर 2020 में उसकी औसत कीमत यूएस डालर \$43.23 प्रति बैरल रही जो कि एक माह पहले की उनकी कीमत से 6.8% अधिक थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से जुड़ी अनिश्चितताओं और संक्रमण में वृद्धि के कारण नवंबर की शुरुआत में सोने की कीमतों में थोड़ी तेजी आई। महीने के बाकी दिनों में, कीमतों में संशोधन हुआ और महीने भर में कुल मिलाकर 5.4 प्रतिशत की गिरावट आई जिसका कारण था वैक्सीन परीक्षण और अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र के आशावादी आंकड़े जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक भावनाओं को गति मिली। पूरे वर्ष की तुलना में अद्यतन आधार पर अर्थात दिसंबर 2019 के अंत तक स्वर्ण की कीमतों में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

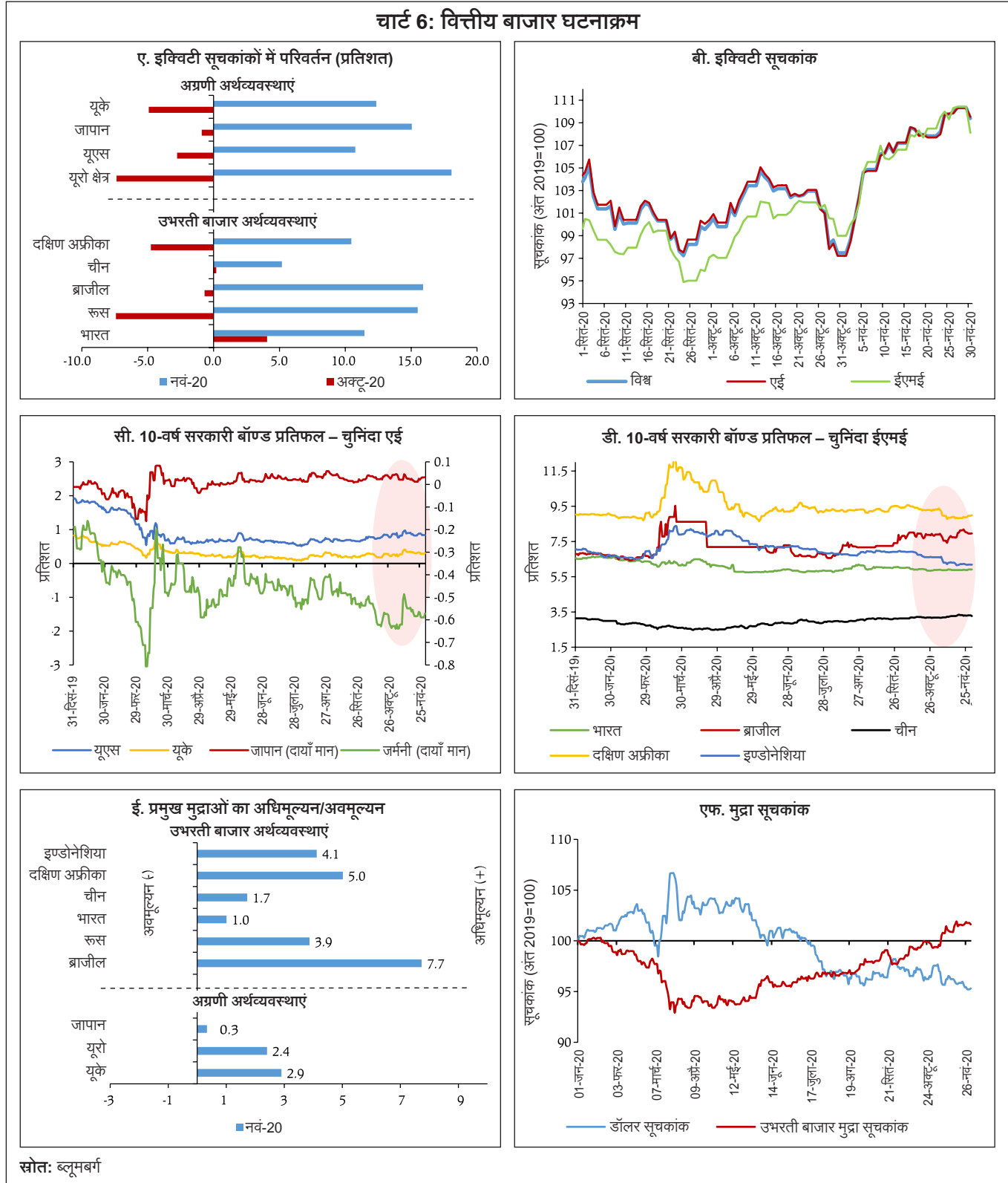
इक्विटी बाजार, जिनमें नवंबर की शुरुआत तक उतार-चढ़ाव जारी था- कभी थोड़े समय के लिए उछाल रहा तो कभी तेज बिकवाली दिखी वैक्सीन में हुई प्रगति के बल पर तीव्र उछाल देखने को मिला जिसने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिए क्योंकि निवेशकों का विश्वास उन क्षेत्रों की ओर फिर से लौटने लगा था जिन पर महामारी की मार सबसे ज्यादा पड़ी थी और इस सबके ऊपर वह उत्साह तो था ही जो कारोबारी स्थितियों को बेहतर बनाये जाने के प्रयासों का नतीजा था (चार्ट 6)। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पूरे माह चलती रही और यह अंतर्निहित व्यापक आर्थिक स्थितियों तथा कॉर्पोरेट वित्त के हालात से बेमेल थी। कॉर्पोरेट बाजार के क्षेत्रों में क्रेडिट स्प्रेड और कम हुआ तथा थोड़ी बहुत

अस्थिरता के बीच महामारी-पूर्व के स्तर को छूने लगा। दूसरी ओर, बैंकों ने ऋण देने के मानकों को कड़ा कर दिया। केंद्रीय बैंक से प्राप्त हो रहा समर्थन जारी रहने के कारण, सरकारी बॉन्ड प्रतिफल असामान्य रूप से कम रहा, हालांकि दीर्घकालिक आधार पर अमेरिकी प्रतिफल में वृद्धि देखने को मिली। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि, अधिकांश ईएमई में प्रतिफल कम रहा। अधिक प्रतिफल की तलाश जैसे-जैसे जोर पकड़ती गयी, ईएमई के प्रति नज़रिए में सुधार हुआ और इन अर्थव्यवस्थाओं में आने वाला पोर्टफोलियो निवेश बढ़ा। अमेरिकी डॉलर नवंबर में कमजोर हुआ, जिससे विशेष रूप से ईएमई मुद्राओं की कीमतें बढ़ीं, हालांकि इसमें कुछ अंतर देखा गया और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाएं तैयार करने में ज्यादा शिद्धत के साथ जुटी ईएमई में यह वृद्धि अधिक रही। इसके विपरीत, कमोडिटी निर्यात पर अधिक निर्भर देशों की मुद्राओं में यह बदलाव सीमित रहा। कुल मिलाकर, नवंबर में अमेरिकी डॉलर 2.3 प्रतिशत कमजोर पड़ा, जिससे उसका संचयी ईयर-टु-डेड मूल्यहास 4.7 प्रतिशत हो गया। मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट्स (एमएससीआई-ईएम) इंडेक्स द्वारा प्रस्तुत ईएमई मुद्राओं की कीमतों में 1.6 प्रतिशत की ईयर-टु-डेड वृद्धि हुई जबकि अकेले नवंबर माह में ही यह वृद्धि 2.2 प्रतिशत रही। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस (आईआईएफ) के अनुसार, ईएमई में पोर्टफोलियो का प्रवाह नवंबर में 76.5 बिलियन डॉलर था, जिसमें इक्विटी और कर्ज की लगभग समान भागीदारी

(यूएस \$39.8 बिलियन और यूएस \$36.7 बिलियन, क्रमशः) थी। वर्ष 2013 की पहली तिमाही, अर्थात टेपर टैंट्रम से ठीक पहले,

के बाद से 2020 की चौथी तिमाही ही वह अवधि रही है जब ईएमई इनफ्लो सबसे अधिक रहा है।

चार्ट 6: वित्तीय बाजार घटनाक्रम

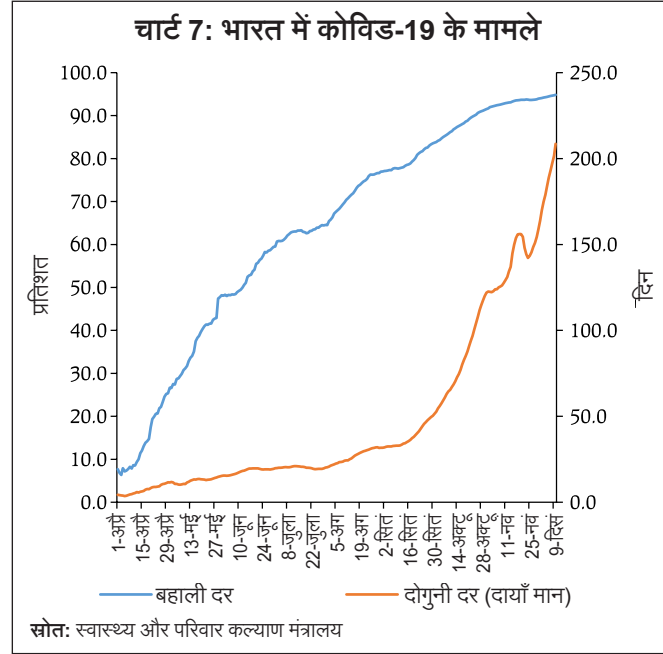


स्रोत: ब्लूमबर्ग

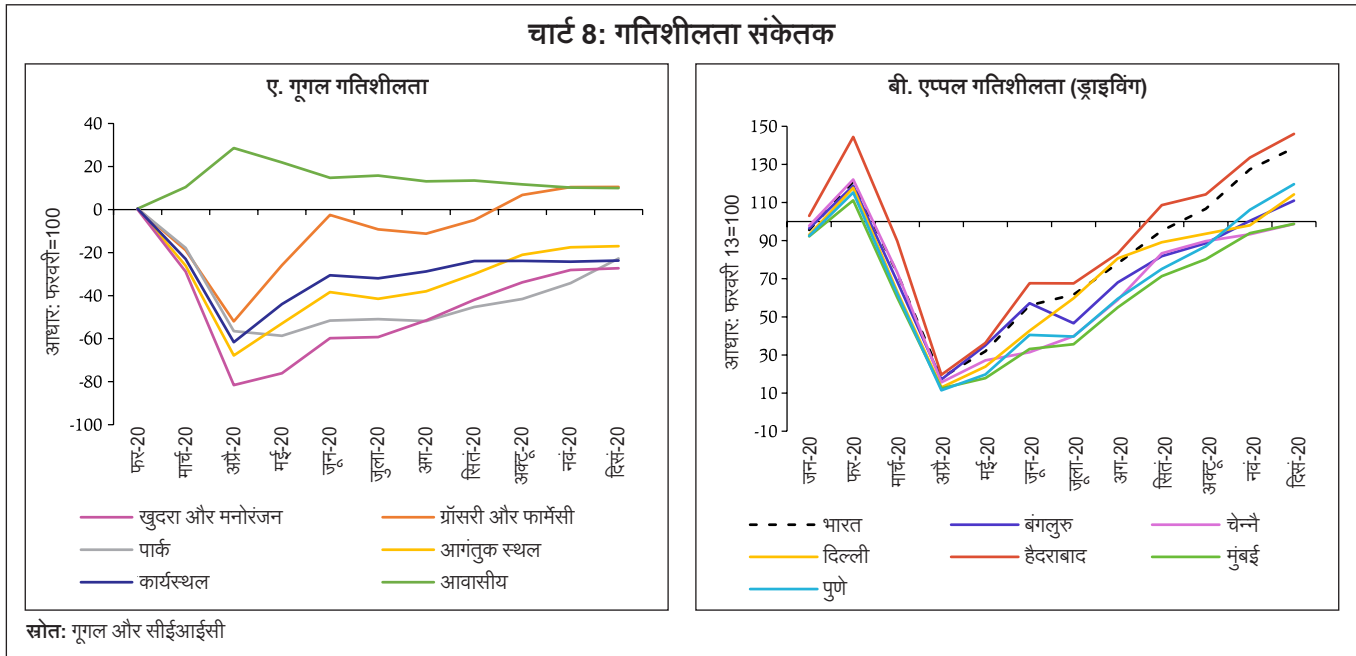
III. घरेलू क्षेत्र की गतिविधियाँ

भारत में विकास कई दृष्टियों से वैश्विक स्थितियों से भिन्न दिखायी पड़ता है। 10 दिसंबर, 2020 तक कुल संक्रमणों की संख्या 97,96,769 थी, जबकि कुल मौतों की संख्या 1,42,186 थी, लेकिन 92,90,834 व्यक्तियों का इलाज करके उन्हें ठीक किया गया। मामलों के दोगुना होने की दर² घटकर 208.6 दिन हो गई है जो कि 25 मार्च यानी लॉकडाउन लगाए जाने की तारीख को 3.5 दिन थी (चार्ट 7)। मृत्यु दर 1.5 प्रतिशत है, जो कि वैश्विक मृत्यु दर (2.2 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम है। ठीक होने की दर में भी बहुत सुधार हुआ है जो लॉकडाउन की शुरुआत के 5% से बढ़कर 10 दिसंबर को 94.8% हो गयी है। इस लेख को प्रिंट करने के लिए दिए जाने के समय तक, सक्रिय मामलों की संख्या 4 लाख से भी कम हो गई थी और ऐसा जुलाई से लेकर अभी तक में पहली बार हुआ था। हालांकि अभी भी काफी खतरा बना हुआ है, फिर भी भारत अर्जेंटीना के अलावा एकमात्र ऐसा देश है, जिसे 'दूसरी लहर' का प्रकोप नहीं झेलना पड़ा है।

गतिशीलता का अपनी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ना जारी है - गूगल मोबिलिटी इंडेक्स से संकेत मिलता है कि नवंबर में किराने के सामान और फार्मेशियों के कारोबार में वृद्धि जारी रही है और इसने फरवरी में निर्धारित बेसलाइन स्तर को पार कर लिया है। आवासीय स्थानों से जुड़े कारोबार की गतिशीलता में



गिरावट जारी है, जबकि यह गतिशीलता कार्यस्थलों के मामले में स्थिर रही और मनोरंजन और खुदरा दुकानों के क्षेत्रों में अधिक हो गयी हालांकि महामारी पूर्व के बेसलाइन की तुलना में कम स्तर पर। इन संकेतों की पुष्टि ऐपल मोबिलिटी इंडेक्स द्वारा भी की गयी है, जिसने 13 जनवरी 2020 में तय अपने बेसलाइन स्तर को पीछे छोड़ दिया और इसमें मुख्य भूमिका पुणे, हैदराबाद और बेंगलूर शहरों ने निभाई। दिसंबर के अब तक (6 दिसंबर तक) के



² दोहराव दर को $\ln 2 / \ln (1 + r)$ के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां r संचयी मामलों में पिछले सात दिनों में हुई वृद्धि का औसत है।

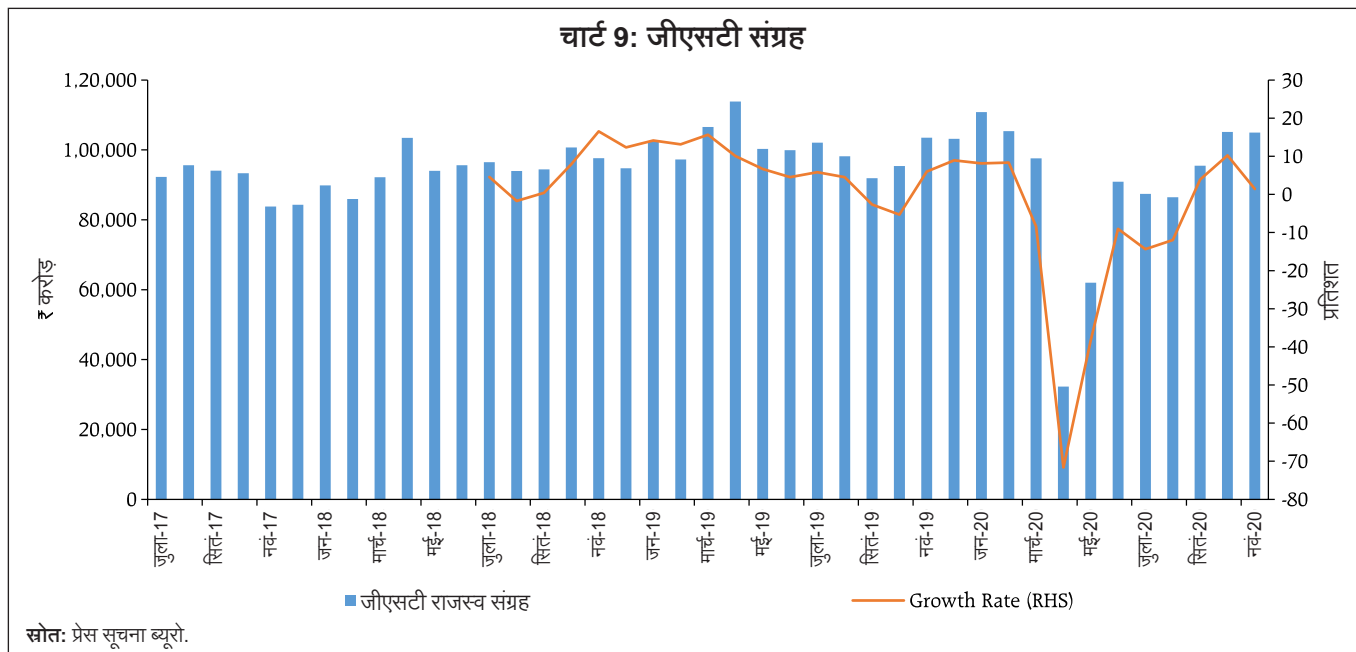
शुरुआती आंकड़े सभी शहरों में गतिशीलता सामान्य के आसपास आती दिखाते हैं (चार्ट 8)। नवंबर में सामानों की आवाजाही में भी तेजी आयी, जो कि ई-वे बिल जारी करने में हुई 8.1 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि से परिलक्षित होता है- अंतः-राज्यीय 9.6 प्रतिशत; और अंतर-राज्यीय 6.0 प्रतिशत - हालांकि पेंट-अप मांग कम हो जाने तथा त्योहारों से जुड़ा उत्पादन घटने के कारण कुछ मंदी देखी गयी।

कुल मांग

उच्च आवृत्ति संकेतक, जो तात्कालिक गतिविधियों को समझने के लिए कतिपय उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करते हैं, उनका ग्राफ पिछले माह की तुलना में नवंबर माह में पठारी आकार का हो गया लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने यही दर्शाया कि समग्र माँग में वृद्धि का रुख बना रहा। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, 2020-21 के दौरान नवंबर 2020 में बिजली की खपत लगातार तीसरे महीने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर पिछले महीने के 11.1 प्रतिशत के अतिरिक्त 3.5 प्रतिशत और बढ़ी। पेट्रोल की खपत में जहाँ 5.0 प्रतिशत की तेजी आई, वहीं डीजल की खपत में संकुचन आना शुरू हो गया परंतु इसका कारण था - प्रतिकूल बेस प्रभावा अक्टूबर-मध्य से नवंबर-मध्य के बीच के त्यौहारी मौसम में, ई-विक्रेताओं – जिनमें फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन अग्रणी थे- का सकल कारोबार 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹58,000

करोड़ रहा। घरेलू खर्च को पूर्ववत बनाए रखते हुए, इस वित्त वर्ष में नवंबर माह में ऐसा दूसरी बार हुआ जब वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत संग्रह ₹1 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (चार्ट 9)। रिजर्व बैंक द्वारा करवाए गए उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के नवंबर 2020 चरण में उपभोक्ताओं की धारणा में सुधार दिखा जबकि पिछले चरण में यह अब तक के निम्नतम स्तर पर था। आर्थिक स्थिति, रोजगार की स्थिति, आय के परिदृश्य और व्यय-क्षमता में आम तौर पर सुधार आने की आशा से हाउसहोल्ड्स अब आगामी वर्ष को लेकर अधिक आश्वस्त हैं। इसकी पुष्टि रिफाइनिटिव-इम्प्रेस प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट द्वारा भी की गयी है, जिसमें नवंबर 2020 के दौरान 2.6 प्रतिशत का तीव्र उछाल आया है जिसका कारण है रोजगार के प्रति विश्वास, आर्थिक प्रत्याशाओं, व्यक्तिगत वित्तीय स्थितियों और निवेश के माहौल में आया सुधारा

नवंबर के दौरान रोजगार की स्थितियों में भी सुधार हुआ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने अपने हाउसहोल्ड्स सर्वेक्षण से बताया कि भारत की 40.03 प्रतिशत कामकाजी उम्र वाली आबादी ने श्रम बाजार में भागीदारी की, चाहे वह रोजगार करते हुए या रोजगार की तलाश में कार्य करते हुए। नतीजतन, बेरोजगारी की दर नवंबर 2020 में घटकर 6.51 हो गई, जो अक्टूबर 2020 में 6.98 थी, जो क्रमिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयी गिरावट थी। इस सकारात्मक

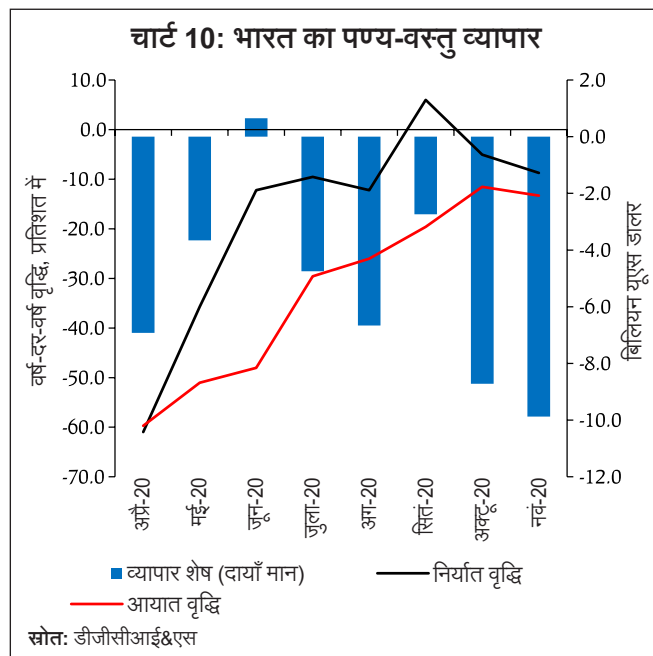


उतार-चढ़ाव को दर्शाते हुए, सेवाओं के लिए पीएमआई रोजगार सूचकांक नौ महीनों में पहली बार नवंबर 2020 में 50.4 पर पहुंचा (अक्टूबर 2020 में 46.8)। वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए जारी टीमलीज एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, किराए पर लेने के लिए समग्र इरादा रखने वालों में बड़े और मध्यम आकार के व्यवसाय अग्रणी बने रहे; हालांकि, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, वे हैं छोटे आकार के व्यवसाय, यानी, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत, नवंबर 2020 में 25 प्रतिशत हाउसहोल्ड्स की रोजगार से जुड़ी मांग पूरी नहीं हो सकी जो इस बात का परिचायक है कि उनमें पुनः आजीविका प्राप्त करने की इच्छा है।

बाहरी मांग की ओर रुख करें तो, हालांकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों में नवंबर में कुल व्यापारिक निर्यात 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो वर्ष-दर-वर्ष 8.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है, तेल से इतर निर्यात ने लगातार तीसरे माह कोविड-19 पूर्व के स्तर को बनाए रखा (चार्ट 10)। दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और लौह अयस्क जैसे क्षेत्रों में मजबूती दिखायी पड़ी। आयात में एक के बाद एक नौवें महीने गिरावट आई, हालांकि हाल के महीनों में इस संकुचन की गति कम हुई है। नवंबर 2020 में तेल आयात में 43.4 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन यह मूल रूप से कच्चे तेल की नरम पड़ी अंतरराष्ट्रीय कीमतों से प्रेरित है। दूसरी ओर, गैर-तेल आयात मोटे तौर पर कोविड-पूर्व स्तरों पर लौट आया है क्योंकि घरेलू मांग सामान्य होने लगी है। व्यापार घाटा नवंबर 2020 में बढ़कर 9.9 बिलियन यूएस डालर हो गया, जो चालू वित्त वर्ष का सर्वाधिक स्तर है। भविष्य की बात करें तो, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत दस उभरते क्षेत्रों यथा- फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स / प्रौद्योगिकी उत्पादों, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों और सौर कोशिकाओं-को भी शामिल कर लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए कि व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में तेजी आएगी और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी।

सकल आपूर्ति

कृषि और विनिर्माण गतिविधि में तेजी आने के कारण नवंबर 2020 तक सकल आपूर्ति की स्थिति में सुधार जारी



रहा। सेवा क्षेत्र के भीतर भी, निर्माण क्षेत्र ने वापसी की, लेकिन संपर्क-केंद्रित सेवाएं कोविड-पूर्व स्तरों से कम और नीचे ही बनी रहीं।

महामारी के माहौल में भी कृषि क्षेत्र में मजबूती और तेजी बनी हुई है। इस साल 4 दिसंबर, 2020 तक 430.6 लाख हेक्टेयर या सामान्य बुआई क्षेत्र के 69.4 प्रतिशत भाग पर रबी की बुआई की जा चुकी है, जो एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 3.9 प्रतिशत अधिक है (सारणी 3)। जलाशयों में पानी के पर्याप्त स्तर की मौजूदगी से बुआई में सहायता मिली है- 3 दिसंबर की स्थिति के अनुसार, जलाशयों का जल-स्तर अपनी पूरी क्षमता के 80 प्रतिशत के बराबर था, जबकि पिछले दशक में औसतन जल-स्तर 66 प्रतिशत रहा था। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखें तो गेहूं की बुआई में लगभग 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश (14.9 प्रतिशत) और पंजाब (3.2 प्रतिशत) में। इस वर्ष दलहन और तिलहन की बुआई में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस बीच, खरीफ के चावल की खरीद एक साल पहले की तुलना में 22.1 प्रतिशत अधिक की गयी, जिसके कारण अनाज (चावल और गेहूं) का बफर स्टॉक 1 दिसंबर 2020 तक सामान्य से 2.4 गुना हो गया था।

औद्योगिक गतिविधियों की बात करें तो, विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में नवंबर के दौरान वृद्धि जारी

सारणी 3: फसल की अखिल भारतीय स्थिति - रबी (2020-21), 4 दिसंबर 2020 की स्थिति

(लाख हेक्टेयर में)

फसल का नाम	सामान्य क्षेत्रफल		उक्त तारीख तक बुवाई की स्थिति		प्रतिशत भिन्नता	
	पूरे सीजन में	उक्त तारीख तक	इस वर्ष (2020)	विगत वर्ष (2019)	सामान्य की तुलना में	पिछले वर्ष की तुलना में
1. गेहूं	303.3	198.8	204.4	202.7	2.8	0.8
2. चावल	41.8	9.8	9.6	10.0	-2.6	-4.0
3. मोटे अनाज	57.1	41.2	33.0	35.6	-19.9	-7.2
ए. ज्वार	33.4	26.1	20.9	21.2	-19.7	-1.1
बी. जौ	6.4	5.7	4.9	5.8	-13.3	-14.8
सी. मक्का	17.4	8.9	6.6	8.1	-25.0	-18.0
4. कुल दलहन	144.9	114.3	116.6	103.0	2.0	13.2
ए. चना	92.8	78.3	82.2	70.7	5.0	16.2
बी. मसूर	14.2	13.1	13.1	12.1	-0.3	8.4
सी. मटर	8.8	7.5	8.2	7.2	10.2	14.7
डी. कुलथी (हॉर्स ग्राम)	2.2	3.7	3.1	3.9	-15.6	-19.5
ई. उड़द	8.9	3.8	3.4	3.5	-10.3	-3.0
एफ. मूंग	9.9	1.4	0.9	0.9	-38.6	-2.2
जी. खेसारी (लैथाइरस)	4.0	2.8	2.4	2.1	-15.5	11.4
आई. कुल खाद्यान्न (1+2+3+4)	547.1	364.1	363.5	351.3	-0.2	3.5
5. तिलहन	73.2	66.7	67.1	63.2	0.5	6.2
ए. राई और सरसों	59.4	59.5	61.8	57.4	3.9	7.7
बी. मूंगफली	7.3	2.6	2.1	2.3	-18.0	-8.1
सी. सूरजमुखी	2.4	1.2	0.6	0.6	-54.6	-9.9
डी. तिल	0.0	0.2	0.2	0.3	-19.6	-26.2
ई. कुसुम	1.2	0.6	0.4	0.3	-26.9	35.0
एफ. अलसी	2.7	2.3	1.8	2.1	-22.8	-12.4
सभी- फसलें (1+2+3+4+5)	620.3	430.8	430.6	414.4	-0.1	3.9

उक्त दिनांक को सामान्य क्षेत्रफल: 2014-15 से 2018-19 तक की इसी अवधि के दौरान औसत क्षेत्रफल।

सामान्य क्षेत्रफल: 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान औसत क्षेत्रफल।

नोट: क्षेत्रफल के आंकड़े राज्यों के कृषि विभागों द्वारा देखकर किए गए आकलन के अनुसार दिए गए हैं।

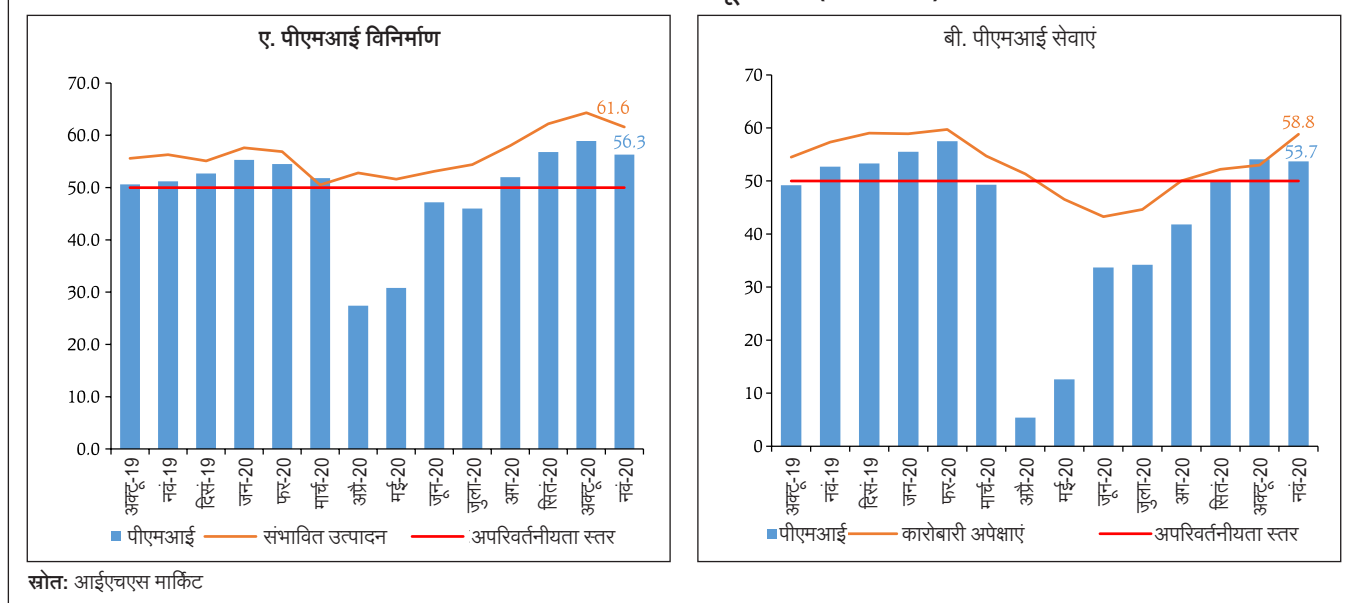
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

रही, हालांकि पिछले माह यह अपने एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच कर नीचे फिसला और 56.3 पर आ गया (चार्ट 11)। अक्टूबर माह के लिए 12 दिसंबर को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ने इस ओर संकेत किया कि चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरे महीने औद्योगिक गतिविधियों की वृद्धि की रफ्तार अपने उच्चतम स्तर पर बनी रहेगी। रिजर्व बैंक के औद्योगिक परिदृश्य

सर्वेक्षण (आईओएस) के 91वें दौर पर फर्मों से प्राप्त प्रतिसाद में यह देखा गया कि वे इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि 2020-21 की दूसरी तिमाही से फिर से जो तेजी दिखनी शुरू हुई थी, वह और जोर पकड़ेगी। इस आशा का आधार था- वित्त की उपलब्धता और साथ ही बाहरी मांग में सुधार एवं नौकरियों के मामले में जारी सुधारात्मक कार्रवाई।

सेवा क्षेत्र के भीतर, एक उल्लेखनीय सुधार चल रहा है, और कई संकेतक इसमें तेज वृद्धि दर्शाते हैं। घरेलू क्षेत्र में नये कार्यों के आने से सेवाओं का पीएमआई लगातार दूसरे महीने बढ़ते हुए नवंबर में 53.7 हो गया। विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में 2020-21 की तीसरी तिमाही में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखे। निर्माण गतिविधि का एक महत्वपूर्ण संपाती सूचक - स्टील की खपत - में अक्टूबर में आए 2.6 प्रतिशत के संकुचन के बिलकुल विपरीत नवंबर में 11.0 प्रतिशत की तेजी आयी। इसी तर्ज पर चलते हुए, अक्टूबर 2020 में सीमेंट उत्पादन ने संकुचन के दौर से बाहर निकलते हुए 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और नवंबर में इसमें और अधिक वृद्धि की उम्मीद है। जैसा कि ई-वे बिलों से संकेत मिलता है, नवंबर में व्यापार गतिविधि में वृद्धि का रुख रहा, लेकिन पिछले महीने में त्योहारों के कारण रहे उच्च स्तर की तुलना में ये गतिविधियाँ धीमी रहीं। यातायात सेवा क्षेत्र में अगस्त 2020 में वृद्धि का जो दौर शुरू हुआ था, उसे रेलवे माल ढुलाई में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि के कारण समर्थन मिला। यात्री यातायात क्षेत्र अच्छा रहा और इसमें लॉकडाउन लगाए जाने के कारण आए संकुचन के बाद माह-दर-माह सुधार हुआ। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) के अनुसार, घरेलू हवाई यात्रा की मांग फिर से बढ़ी क्योंकि यात्री यातायात में 19 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि हुई और यह नवंबर 2020 में 62.0 लाख हो गया। संपर्क से बचने के लिए लोगों द्वारा व्यक्तिगत वाहनों को तरजीह दिए जाने के साथ-ही-साथ लगातार चौथे महीने नवंबर में भी यात्री वाहन बिक्री में तेजी दर्ज की गई। यात्री कारों के अग्रणी निर्माताओं को छोड़कर, अन्य सभी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) ने महीने के दौरान उच्च वृद्धि दर्ज की जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नवंबर में हुआ वाहन पंजीकरण, हालांकि, अधिक सतर्क आशावाद को दर्शाता है।

चार्ट 11: खरीद प्रबंधकर्ता सूचकांक (पीएमआई)



मुद्रास्फीति

सीपीआई मुख्य मुद्रास्फीति एक महीने पहले 6.9 प्रतिशत से घटकर नवंबर में 7.6 प्रतिशत हो गयी, जो मुख्य रूप से क्रमिक आधार पर खाद्य स्फीति 1.3 प्रतिशत अंकों की गिरावट के कारण थी; हालाँकि, मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही और यह ऊपरी सहनीय सीमा के ऊपर रही। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलों के विभाग) से प्राप्त

दिसंबर माह में अब तक (16 दिसंबर 2020 तक) के उच्च आवृत्ति खाद्य कीमत आंकड़े प्याज, आलू, टमाटर, अरहर, मसूर, चावल और गेहूं की कीमतें कुछ कम होने का संकेत देते हैं। खाद्य तेलों में मूल्य वृद्धि पूरे दिसंबर माह में निरंतर जारी रही है। कुल मिलाकर, डीसीए डेटा के आधार पर, आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में दिसंबर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि नवंबर में यह वृद्धि 2.0 प्रतिशत थी (तालिका 4)।

सारणी 4: डीसीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

क्र. सं.	वस्तुएं	सीपीआई में भारिता	₹ प्रति कि.ग्रा.			माह-दर-माह (प्रतिशत)		
			दिसं-19	नवं.20	दिसं.20*	अक्टू.-20	नवं.-20	दिसं.20*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	अनाज (चावल + गेहूं)	6.9	31.8	32.9	32.7	-0.2	0.5	-0.8
	चावल	4.4	33.5	35.0	34.8	0.4	0.4	-0.7
	गेहूं और आटा	2.6	29.0	29.3	29.1	-1.2	0.5	-0.9
II	दलहन	2.0	83.0	97.4	97.1	5.8	1.9	-0.3
	तूर / अरहर दाल	0.8	88.4	106.6	105.6	10.2	2.0	-0.9
	उड़द दाल	0.3	96.4	106.4	107.3	5.0	2.4	0.8
III	खाद्य तेल	3.0	106.6	124.6	128.8	1.7	2.6	3.3
	सरसों का तेल	1.3	113.7	132.7	137.0	1.7	3.1	3.3
	रिफाईंड तेल	1.3	93.0	109.9	114.5	1.8	2.5	4.1
IV	सब्जियां (पीओटी)	2.2	46.6	48.0	42.7	12.9	8.6	-11.0
	आलू	1.0	25.4	44.6	41.7	7.7	12.8	-6.4
	प्याज	0.6	95.0	59.3	48.1	59.0	18.0	-18.9
	टमाटर	0.6	29.0	41.2	38.3	-12.4	-9.3	-7.0
V	सुगर	1.1	39.2	40.0	40.0	-0.4	-0.4	0.0
VI	दूध	6.4	44.9	47.1	47.3	0.1	0.4	0.5
VII	भारित औसत मूल्य	22.9	59.2	64.8	65.1	2.1	2.0	0.5

*: 1 दिसंबर से 16 दिसंबर 2020 के दौरान रही कीमतों के आधार पर।

नोट: भारित औसत मूल्य से अभिप्राय 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों के औसत मूल्य से जिनकी भारिता सीपीआई बास्केट में उनकी हिस्सेदारी से निर्धारित होती है।

स्रोत: उपभोक्ता मामले, भारत सरकार तथा आरबीआई स्टाफ के अनुमान

पेट्रोलियम उत्पादों की श्रेणी में, उत्पाद शुल्क और राज्य करों ने पंप की कीमतों को ऊंचा बनाए रखा। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण 20 नवंबर 2020 से घरेलू पंप की कीमतों में तेजी आना शुरू हो गयी है। दिसंबर माह में अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 2.4 फीसदी और 3.6 फीसदी बढ़ोतरी देखी गयी। एलपीजी की कीमतें जुलाई-नवंबर 2020 के दौरान स्थिर बने रहने के बाद दिसंबर में ₹100 प्रति सिलेंडर बढ़ गयीं, जिसने लोगों का चैन छीन लिया और पहले से दबावग्रस्त घरेलू बजट की स्थिति और भी बिगड़ गयी। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के परिणामस्वरूप दिसंबर में केरोसीन की कीमतों में भी लगभग ₹1 प्रति लीटर और इजाफा हुआ (तालिका 5)।

वस्तुओं की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों और घरेलू क्षेत्र द्वारा निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर इसके बढ़ते प्रभाव के कारण ऐसी फर्में जो मार्जिन को बढ़ाते हुए और मांग के सामान्य स्थिति में आने के कारण मुख्य मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ रहा है। नवंबर के लिए विनिर्माण पीएमआई में, इनपुट कीमतों में और वृद्धि हुई है तथा जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में गिरावट की दर कम होगी और मांग में वृद्धि आएगी, इसका असर निश्चित रूप से बिक्रय मूल्यों पर पड़ेगा। नतीजतन, उत्पाद-कीमतों में अब तक हो रही मामूली वृद्धि और मौजूदा कमजोर पड़ी हुई मूल्य निर्धारण शक्ति में कहीं अधिक इजाफा होगा। यह नवंबर की सीपीआई में भी देखा गया जहाँ खाद्य और ईंधन से इतर

मुद्रास्फीति नवंबर में भी 5.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रही जो अक्टूबर में 5.9 प्रतिशत थी।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण बढ़कर ₹5,63,589 करोड़ हो जाने के कारण नवंबर 2020 में प्रणालीगत चलनिधि का और अधिक विस्तार हुआ बावजूद इसके कि त्यौहारों के कारण बढ़ी हुई मुद्रा की मांग के चलते संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में अच्छी-खासी वृद्धि हुई थी। अधिशेष चलनिधि रात्रिपर्यंत रिवर्स रिपो के माध्यम से अवशोषित कर ली गयी थी और 30 नवंबर 2020 तक कुल मिलाकर ₹6,76,413 करोड़ का चलनिधि अवशोषण हुआ था। जैसा कि 9 अक्टूबर को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, जिन बैंकों ने पहले लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (TLTRO और TLTRO 2.0) के तहत निधि प्राप्त की थी, उन्हें इस राशि को परिपक्वता से पहले लौटाने का विकल्प दिया गया। तदनुसार, बैंकों ने ₹37,348 करोड़ रुपये लौटाए। रिज़र्व बैंक ने 5 नवंबर 2020 को राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में एकमुश्त खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के जरिये खरीद की और ₹10,000 करोड़ की टिकाऊ चलनिधि का अंतर्वेशन किया। प्रतिफल वक्र के सभी परिपक्वता स्पेक्ट्रम में चलनिधि वितरित करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने खुले बाजार परिचालन (विशेष ओएमओ) के तहत 12, 19 और 26 नवंबर, 2020 को प्रतिभूतियों की खरीद और

सारणी 5: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें (चार बड़े महानगरों का औसत)

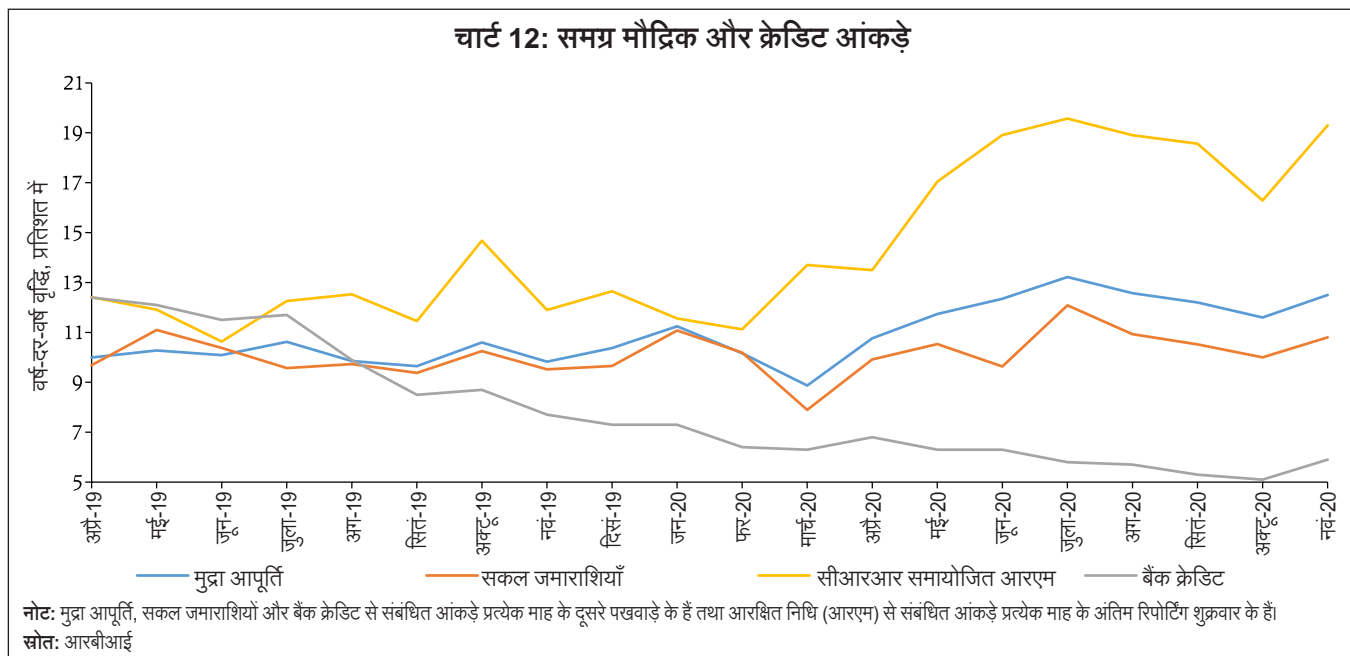
उत्पाद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		दिसं.-19	नव.-20	दिसं.-20	नव.-20	दिसं.-20
पेट्रोल	₹/लीटर	77.64	84.13	86.12 ^	0.3	2.4
डीजल	₹/लीटर	68.77	74.73	77.43 ^	0.6	3.6
केरोसीन	₹/लीटर	28.80	22.17	23.21	3.3	4.7
एलपीजी	₹/लीटर	699.88	604.63	704.63*	0.0	16.5

^: 1-16 दिसंबर 2020 के दौरान मौजूद कीमतों पर आधारित।

*: दिसंबर, 2020 से लागू

नोट: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) द्वारा चार प्रमुख महानगरों (चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में प्रभारित कीमतों का औसत।

स्रोत: आईओसीएल, पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ, (पीपीएसी), भारत सरकार और भारिबैं स्टॉफ का अनुमान।



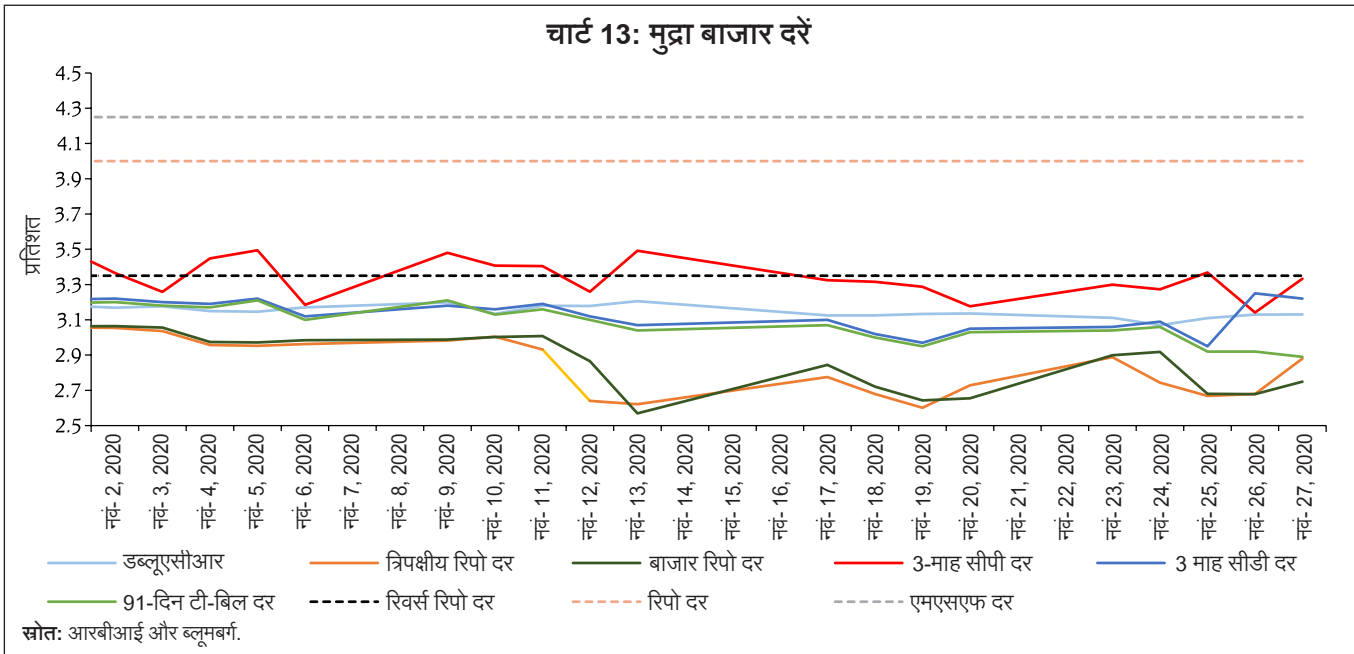
बिक्री के तीन परिचालन साथ-साथ किए जिनमें से प्रत्येक ₹10,000 करोड़ रुपये का था।

वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक मौद्रिक और ऋण की स्थितियाँ सुगम हुई हैं और इससे आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवन प्रदान करने में सहायता मिलेगी। 27 नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में प्रथम चरण के प्रभाव के लिए समायोजित रिजर्व मनी (आरएम) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (जो एक साल पहले 11.9 प्रतिशत थी)। 20 नवंबर 2020 को समाप्त पखवाड़े के लिए कुल जमा राशि में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि होने के साथ, मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (जो एक साल पहले 9.8 प्रतिशत थी) [चार्ट 12]।

वाणिज्यिक क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का क्रेडिट 20 नवंबर 2020 तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.8 प्रतिशत बढ़ा, जो कि पूर्ववर्ती महीने के अंतिम पखवाड़े में हुई 5.1 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि से अधिक था जिसका प्रमुख कारण था उत्साहजनक माहौल। टीएलटीआरओ का ही प्रभाव था कि वाणिज्यिक पत्र, बॉन्ड / डिबेंचर और कॉरपोरेट निकायों

के शेयरों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश में वर्ष 2020-21 (20 नवंबर तक) के दौरान ₹850 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में उनके इस निवेश में ₹24,611 करोड़ की गिरावट आयी थी।

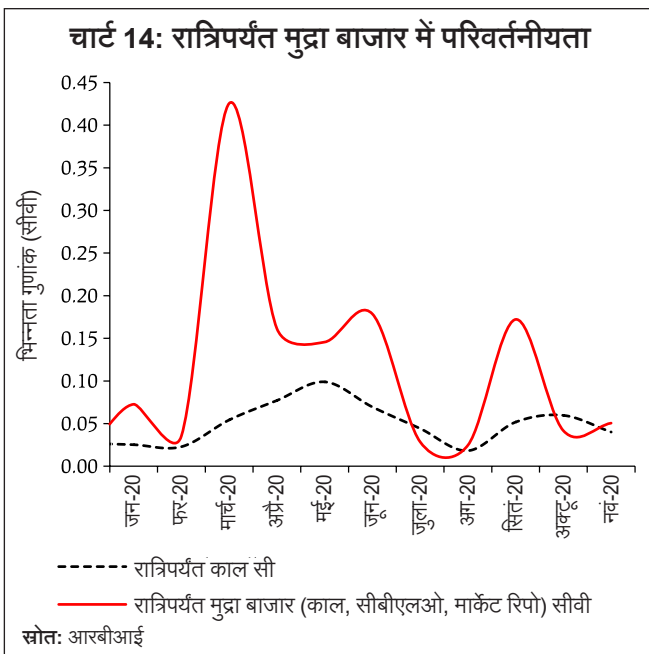
बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि की स्थिति ने नवंबर में मुद्रा बाजार की दरों को और नीचे धकेल दिया है। रात्रिपर्यंत संपार्श्विक-मुक्त ऋण संविभाग में, भारत औसत कॉल दर डब्ल्यूएसीआर) अक्टूबर 2020 के अंतिम सप्ताह से रिवर्स रिपो दर से नीचे आ गई है। संपार्श्विक आधारित ऋण संविभाग में - मार्केट रिपो और त्रि-पक्षीय रिपो - दरें कॉल दर से क्रमशः 29 आधार अंक (बीपीएस) और 32 बीपीएस कम रहीं। निकट अवधि संविभाग, यानि जमा प्रमाण-पत्रों और 91-दिवसीय ट्रेजरी बिलों, में दरें रिवर्स रिपो दर से कम बनी रहीं। वाणिज्यिक पत्र पर बट्टाकरण की दर कई मौकों पर एलएएफ रिवर्स रिपो दर से नीचे आ गई और 26 नवंबर 2020 को घटकर 3.14 प्रतिशत के स्तर को छूने लगी (चार्ट 13)। रात्रिपर्यंत मनी मार्केट में मौजूद अस्थिरता, जो मार्च 2020 के महीने में चरम पर थी, पिछले कुछ महीनों में कम हुई है (चार्ट 14)।



अधिशेष चलनिधि के परिणामस्वरूप सभी वित्तीय बाजारों के प्रतिफल में वृद्धि हुई, विशेष रूप से मुद्रा और कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों में (सारणी 6)। 27 नवंबर, 2020 को 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क (5.77 जीएस 2030) का प्रतिफल 5.91 प्रतिशत पर पहुंच गया। 27 नवंबर 2020 को की गयी प्राथमिक बाजार नीलामी में नए 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क का कट ऑफ

प्रतिफल 5.85 प्रतिशत तय किया गया, जो 10-वर्षीय बेंचमार्क पर कारोबार के उस समय के मौजूदा प्रतिफल से कम था।

रिजर्व बैंक द्वारा किए गए चलनिधि संबंधी और अन्य उपायों के कारण वित्तीय स्थितियों में हुए निरंतर सुधार के चलते, कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड लगभग सभी रेटिंग श्रेणियों में घटकर कोविड-पूर्व के स्तर पर पहुंच गया (सारणी 7)।



सारणी 6: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संगत जोखिम-मुक्त दरों के ऊपर)		
	29 अक्टू 2020 की स्थिति	27 नव 2020 की स्थिति	भिन्नता (बीपीएस में)	29 अक्टू 2020 की स्थिति	27 नव 2020 की स्थिति	भिन्नता (बीपीएस में)
(1)	(2)	(3)	(4 = 3-2)	(5)	(6)	(7 = 6-5)
सीपी (3 माह)	3.89	3.33	-56	71	44	-27
कॉर्पोरेट बॉण्ड						
एए (1 वर्ष)	4.00	3.86	-14	36	30	-6
एए (3 वर्ष)	4.90	4.64	-26	28	17	-11
एए (5 वर्ष)	5.60	5.59	-1	22	28	6
ए (3 वर्ष)	5.84	5.50	-34	122	103	-19
बीबीबी-माइन्स (3 वर्ष)	9.79	9.47	-32	517	500	-17
10-वर्ष जी-सेक	5.88	5.91	3	-	-	-

स्रोत: सीसीआईएल: एफ-ट्रैक:एफआईएमडीए; और ब्लूमबर्ग

सारणी 7: कॉर्पोरेट बॉण्ड स्प्रेड

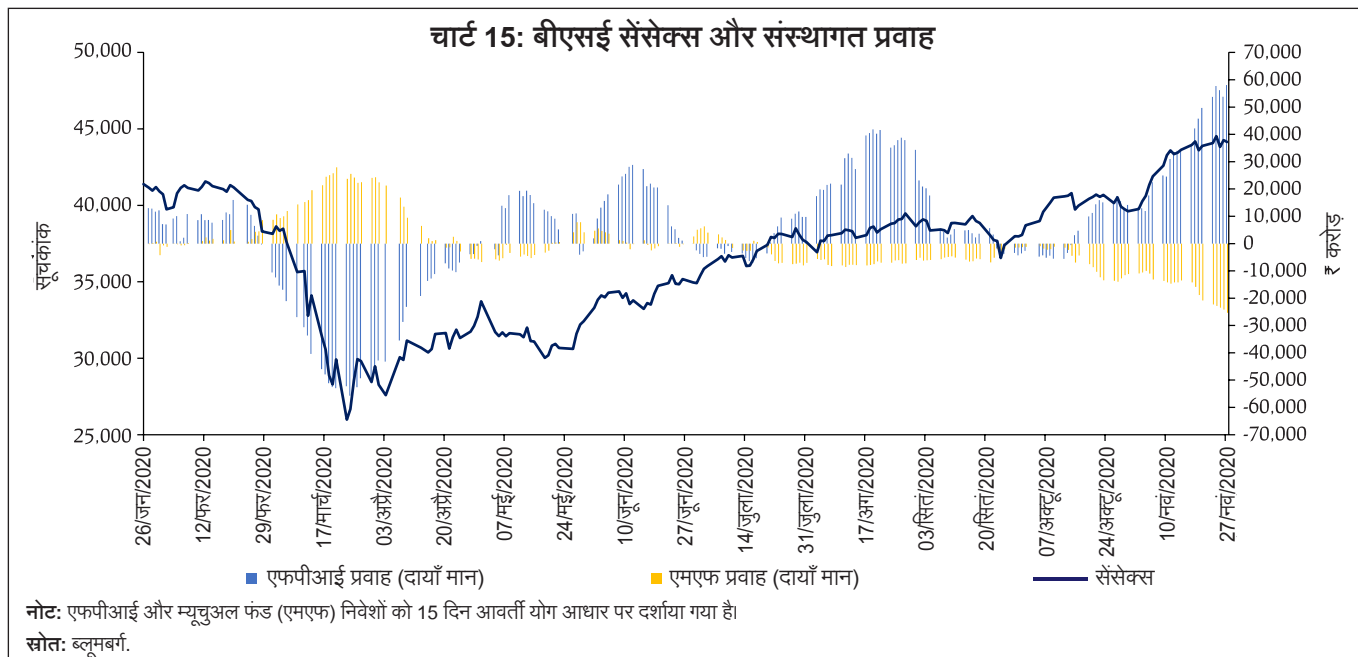
रेटिंग	3-वर्ष कॉर्पोरेट बॉण्ड स्प्रेड				भिन्नता		
	कोविड-पूर्व			कोविड- पश्चात	5= (4-1)	6= (4-2)	7= (4-3)
	31-दिसं-19	31-जन-20	28-फर-20	27-नव-20			
	1	2	3	4	(आधार अंक)		
एएए	59	60	90	17	-42	-43	-73
एए	103	104	128	69	-34	-35	-59
एए	136	140	167	103	-33	-37	-64
एए	175	178	207	150	-25	-28	-57
ए	315	278	307	300	-15	22	-7
ए	345	328	357	325	-20	-3	-32
ए	425	378	407	400	-25	22	-7
बीबीबी+	475	403	432	425	-50	22	-7
बीबीबी	500	428	457	450	-50	22	-7
बीबीबी	550	453	482	500	-50	47	18

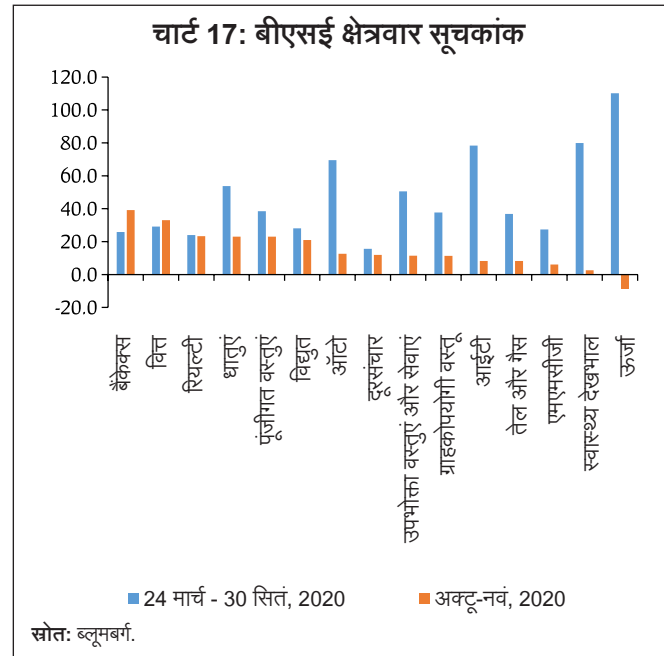
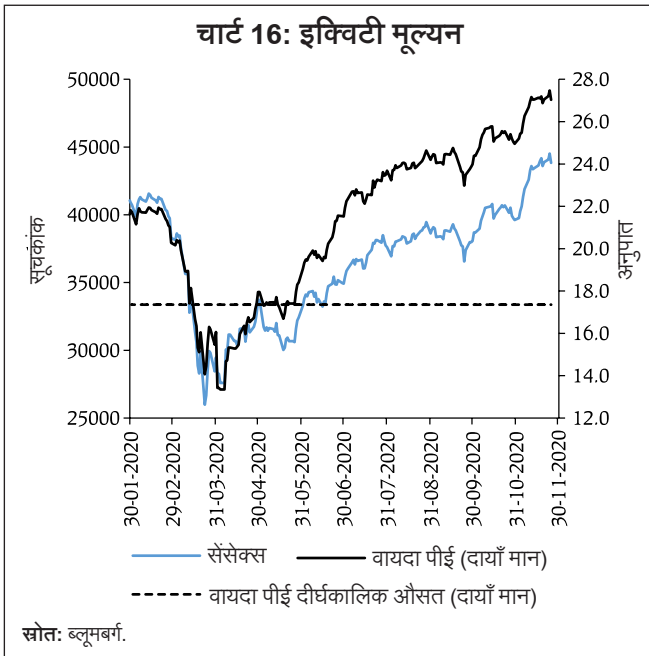
नोट: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एचओ) द्वारा 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने के बाद की अवधि को कोविड-पश्चात अवधि के रूप में माना जाता है।
 स्रोत: एफआईएमएमडीए

मार्च 2020 के बाद से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा और उधार दरों में नीतिगत रिपो दर में परिवर्तन के संचरण में सुधार आया है, जो अधिशेष चलनिधि, निभावकारी मौद्रिक नीति रुख, ऋणों के बाह्य बेंचमार्क-आधारित मूल्य निर्धारण, कमजोर पड़ी ऋण की मांग और नीतिगत दरों में कटौती के विलंबित असर के सम्मिलित प्रभाव का परिचायक है। माध्य सावधि जमा दर, जो मौजूदा कार्ड दरों को दर्शाती है, में मार्च से नवंबर 2020 के दौरान 143 आधार अंकों की भारी गिरावट

आयी है। इसी अवधि में 1-वर्ष माध्य एमसीएलआर में 90 बीपीएस की गिरावट आई है।

23 मार्च 2020 को बीएसई सेंसेक्स में 69.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारतीय इक्विटी बाजार में 25,981 के निचले स्तर से 27 नवंबर 2020 को 44,150 पर बंद हुआ। वैक्सिन से जुड़ी खबरों, अमेरिकी चुनावों के परिणाम और सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपायों के कारण घरेलू इक्विटी बाजारों ने नई उंचाइयाँ



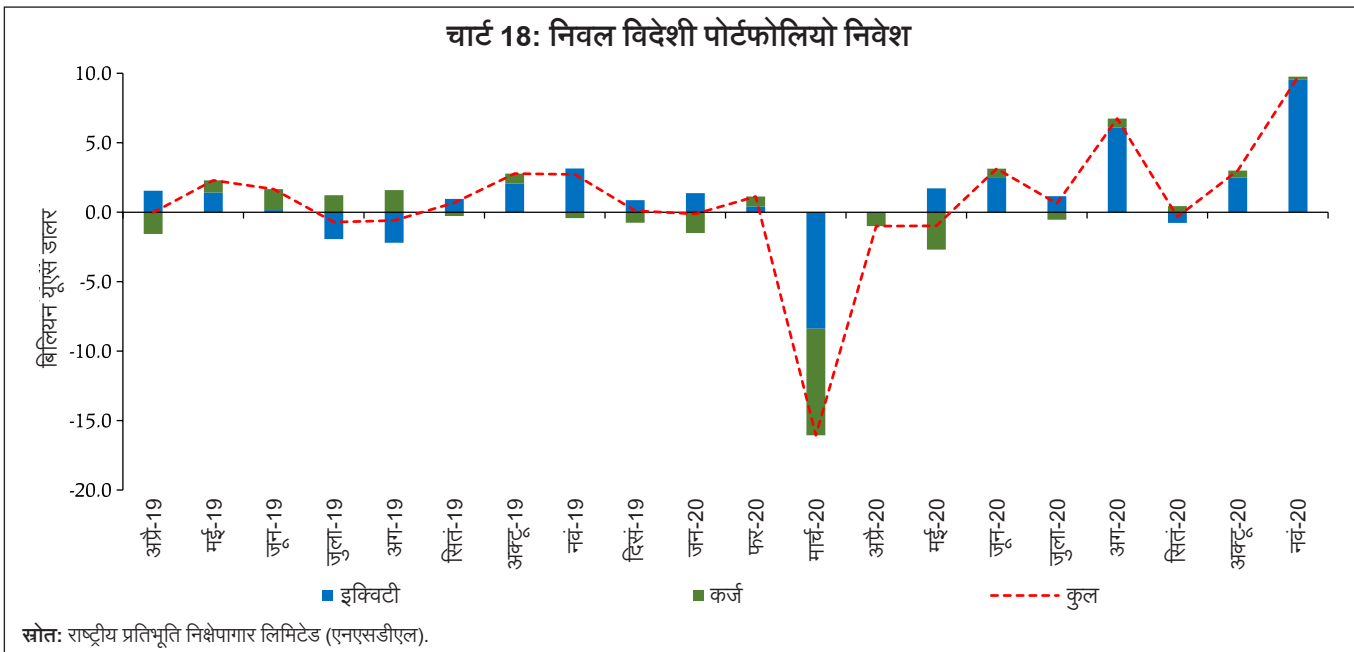


छुई (चार्ट 15)। इसने मूल्य-आय अनुपात (पीई) को नवंबर 2020 के अंत में इसके दीर्घकालिक औसत 17.4 से बढ़ाकर 27.2 कर दिया (चार्ट 16)।

इक्विटी बाजारों में आयी अचानक तेजी का कारण बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में आया उछाल भी था जिनकी आय में 2020-21 की दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर परिणाम आए थे और तेजी से वापसी की संभावनाएं भी बढ़ी थीं

(चार्ट 17)। नवंबर 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) की आमद सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी, जिसका प्रमुख कारण था 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इक्विटी खरीद जो कि पिछले महीने की गयी 2.5 बिलियन यूएस डालर से बहुत अधिक थी (चार्ट 18)।

विदेशी मुद्रा बाजार में, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये (INR) में अक्टूबर 2020 की तुलना में नवंबर 2020 के



दौरान 1.0 प्रतिशत की मामूली गिरावट आयी, हालांकि, यह मार्च 2020 के अंत में अपने प्रारंभिक स्तर से 2.2 प्रतिशत ऊपर रहा। 36-मुद्रा व्यापार-भारित प्रभावी विनिमय दर के दोनों सूचकांकों- नाममात्र और वास्तविक- की दृष्टि से आईएनआर में इसके एक महीने पहले के स्तर से नवंबर 2020 में 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई।

पूँजी प्रवाह बहुत अच्छा रहने और साथ ही, व्यापार घाटे में पहले की तुलना में संकुचन आने से मार्च 2020 के अंत से आरक्षित निधि के भंडार में 97.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर अभिवृद्धि हुई है। नवंबर 2020 के अंत में, यह भंडार 574.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था, जो 16.8 के आयात के समतुल्य था, या यूँ कहें कि यह जून 2020 के अंत में भारत के कुल मौजूदा बकाया बाह्य ऋण को पूरी तरह से कवर करने हेतु आवश्यक निधि से अधिक था (चार्ट 19)।

डिजिटल लेनदेन में निरंतर वृद्धि हुई और नवंबर 2020 के दौरान इसमें और अधिक गति आयी जिसमें थोक और खुदरा लेनदेन दोनों का योगदान रहा (तालिका 8)। खुदरा खंड में, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) लेनदेन की मात्रा में नवंबर 2020 में 24.6 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गयी, जो एक महीने पहले दर्ज की गई वृद्धि (13.9 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है। नवंबर 2020 में एनईएफटी लेनदेन के मूल्य में

सारणी 8: 2020-21 में भुगतान लेनदेन

	(₹ करोड़ में)			
	आरटीजीएस	एनईएफटी	यूपीआई	आईएमपीएस
अप्रै.-20	64,43,653	13,06,406	1,51,141	1,21,141
मई-20	70,41,869	14,81,750	2,18,392	1,69,402
जून -20	86,51,978	19,06,586	2,61,835	2,06,951
जुला -20	83,35,279	19,63,113	2,90,538	2,25,775
अग-20	72,92,380	19,30,552	2,98,308	2,35,137
सितं-20	94,89,066	21,65,515	3,29,032	2,48,662
अक्टू-20	84,96,046	22,35,389	3,86,107	2,74,645
नवं-20	79,87,655	22,18,252	3,90,999	2,76,459

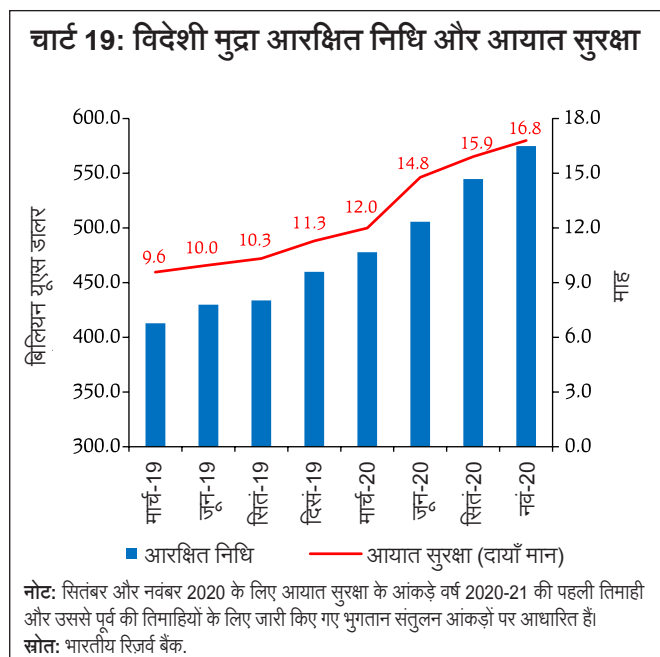
स्रोत: भारिबैंक

वृद्धि (27.9 प्रतिशत) अक्टूबर 2020 में दर्ज की गई वृद्धि (20.1 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी। नवंबर 2020 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) लेनदेन तेजी से बढ़ता हुआ लगभग 2.2 बिलियन हो गया, और इसमें मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टियों से वृद्धि हुई। डिजिटल लेनदेन के अन्य प्रकारों में भी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) में अत्यधिक तेजी का रुख देखा गया और तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) में पिछले माह की तुलना में नवंबर 2020 में तीव्र वृद्धि देखी गई। थोक भुगतान खंड में, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) लेनदेन में मात्रात्मक रूप से तेजी दर्ज की गयी।

V. निष्कर्ष

उच्च आवृत्ति संकेतकों में निहित उतार-चढ़ाव का सारांश यह है कि इस अंतर्निहित प्रवृत्ति से पता चलता है कि 2020-21 की दूसरी छमाही की शुरुआत ही आर्थिक गतिविधियों में जो तेजी आनी प्रारंभ हुई थी, वह बनी हुई है। इस भयानक महामारी की जिस दूसरी लहर के प्रकोप की आशंका थी, वह अभी भारत में नहीं देखी जा रही है, जिसके कारण समर्थनकारी समष्टि आर्थिक नीतियों वाले वातावरण में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ गयी है और अब अनलॉक की प्रक्रिया तेज होने से अर्थव्यवस्था अपनी सामान्य स्थिति में लौट रही है।

विभिन्न एजेंसियों द्वारा इस पूरे वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में संकुचन के पूर्वानुमानों में कमी आनी पहले से ही शुरू हो चुकी है, और यदि बहाली की वर्तमान गति बनी रहती है, तो वर्ष की अंतिम तिमाही में अपेक्षित उछाल आधारभूत आकलन से भी अधिक होने की संभावना है। वर्तमान में नीतिगत जोर अर्थव्यवस्था के अधिक टिकाऊ वाहकों पर होने के कारण ड्राइवर्स की ओर बढ़



रहा है, निजी निवेश के लिए यह उपयुक्त अवसर है कि वह कैपेक्स के प्रति एहतियाती और डीलीवरेजिंग वाली धारणा को छोड़कर अपना ध्यान वर्तमान क्षमता के उपयोग और नई क्षमताओं के निर्माण की ओर लगाए। अनुभव और अनुभवजन्य साक्ष्य दोनों ने यह दिखाया है कि निवेश की वजह से आयी बहाली टिकाऊ होती है और इससे उपभोग व्यय और निर्यात दोनों में वृद्धि होती है। कृषि विपणन और श्रम-संहिताओं के क्षेत्र में हुए सुधारों से दक्षता और उत्पादकता लाभ में वृद्धि को सहारा मिलेगा।

वित्तपोषण की स्थिति अच्छी है। इस महामारी के दौरान, हाउसहोल्ड्स और निगमों की वित्तीय बचत में तेजी आई है, लेकिन इस बात का इंतजार है कि उन्हें उत्पादक निवेशों के रूप में रखा जाए न कि सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और गैर-एसएलआर पेपर जैसे निष्क्रिय निवेशों के रूप में। आर्थिक गतिविधियों के पुनः पटरी पर आने के साथ ही, अब बैंक ऋणों में धीरे-धीरे तेजी आ रही है। आगे कंपनियों की कमाई बेहतर रहने के आसार हैं। विदेशी बचत की आपूर्ति बढ़ रही है, और भारत विदेशी निवेश को लेकर आशान्वित है। वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार की विजेता 'इन्वेस्ट इंडिया' रही है जो राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। इसके अलावा, ब्याज दरों की दृष्टि से देखें तो वित्तीय स्थितियां इतनी अनुकूल हैं

जितनी कई दशकों में नहीं थीं। महामारियों से भय का वातावरण बन जाता है और ऐसे में जोखिम विमुखता आ जाती है, लेकिन वे अपने साथ कई अवसर भी लेकर आती हैं और जिंदादिली दिखाने के नये द्वार खोलती हैं।

साथ ही, इस बात के दोगुने प्रयास करने की आवश्यकता है कि महँगाई- जो दूध में मक्खी के समान है- उसे निकाल फेंका जाए इससे पहले कि संवृद्धि की दिशा में बनते संवेग को यह मंद कर दे। अनियंत्रित रिटेलर मार्जिन पर लगाम और उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाने की घटनाओं को कम करने सहित कुशल, प्रभावी और समयबद्ध आपूर्ति प्रबंधन से ही, बढ़ती महँगाई की कमर तोड़ी जा सकती है इससे पहले कि उसका प्रभाव और व्यापक हो जाए और वह राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहनों के इच्छित प्रभाव के विरुद्ध कार्य करने लगे। अच्छे समन्वय के साथ रसद अंतिम मील तक टीकों के देश-व्यापी भली-भांति और तेजी से वितरण के लिए बेहतर समन्वय के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं ताकि देश के आखिरी व्यक्ति तक उन्हें पहुंचाया जा सके। हालांकि, टिकाऊ बहाली के मार्ग में अभी भी कई बाधाएं हैं, तथापि यदि सभी हितधारकों द्वारा लगातार प्रयास किया जाएगा तो खोई हुई आय को फिर से हासिल किया जा सकेगा और/अथवा भारत को तीव्रतर संवृद्धि पथ पर अग्रसर करना संभव होगा।

तत्काल स्थानिक गति संकेतक आर्थिक गतिविधि*

चार दैनिक संकेतकों पर निर्मित संपाती संकेतक (सीआई)¹ राष्ट्रीय व उप राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक गतिविधि में तत्काल गति की सूचना देता है। मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधि में तीव्र गिरावट के बाद सभी क्षेत्रों में सीआई बड़ी तेजी से नीचे गए जो आर्थिक गतिविधि में तेज गिरावट का प्रतिबिंब है। सीआई की गति दर्शाती है कि जून 2020 से प्रारंभ क्रमिक अनलॉकिंग के साथ विभिन्न क्षेत्रों में समुत्थान की अलग-अलग गति रही। अक्टूबर में सभी क्षेत्रों में सीआई उल्लेखनीय रूप से ऊपर गए। यद्यपि नवंबर के प्रथमार्ध में कुछ नरमी देखी गई अपितु गति धनात्मक बनी रही और उत्तरार्ध में अधिकांश राज्यों में उलट गई। इसके अलावा, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ अखिल-भारतीय सीआई का एक सुदृढ़ धनात्मक और सांख्यिकीय दृष्टि से उल्लेखनीय संबंध है।

भूमिका

विगत वर्षों में अग्रसक्रिय लोकनीति के लिए उच्च आवृत्ति संकेतकों के जरिये आर्थिक गतिविधि की निगरानी सर्वोपरि हो गई है। सामान्य समय में, औद्योगिक गतिविधि, मोटर वाहन (ऑटोमोबाइल) बिक्री, माल उतारने चढ़ाने एवं हवाई यात्री यातायात (ट्रैफिक) आदि जैसे आर्थिक संकेतकों का मासिक व त्रैमासिक आवृत्ति के साथ प्रयोग कर तत्संबंधी उभरते आर्थिक आवेगों को समझा जाता है। लेकिन मासिक व त्रैमासिक आवृत्ति संकेतक तेजी से उभरते आर्थिक समीकरणों पर बारीक तत्काल सूचना उस अवधि के लिए नहीं दे पाते जो बड़ी अनिश्चितता और द्रुत परिवर्तनों से भरी है। हाल में, कोविड-19 महामारी की अवधि एक प्रपाती घटना की साक्षी रही जिसमें लॉकडाउन व कड़े प्रतिबंधात्मक कदमों के कारण हर ओर तीव्र संकुचन हुआ। यहाँ

* यह आलेख मौद्रिक नीति विभाग (एमपडीडी) के सार्थक गुलाटी, बिपुल कुमार घोष और सुनील कुमार द्वारा तैयार किया गया है। आलेख के ड्राफ्ट पर मूल्यवान टिप्पणियों के लिए डॉ राजीव रंजन और मनीष कपूर के प्रति लेखक आभारी हैं। लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और आरबीआई का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

¹ संपाती सूचकांक और सूचक का प्रयोग इस आलेख में विनिमेयता के अनुसार किया गया है।

तक कि नियमित डेटा प्रकाशित करना भी कोविड-19 महामारी के दौरान तकनीकी व्यवस्थात्मक कारणों के चलते एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया। अतः कोविड-19 महामारी ने आर्थिक डेटा की निगरानी की पद्धति को पूरी तरह बदल दिया है जिसका कारण है तेजी से उभरती आर्थिक गतिविधि जिसमें नीतिगत प्रतिसाद के लिए समय कम एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रवृत्तियों में विभिन्नता है। चूंकि कोविड-19 महामारी में आर्थिक परिवर्तन तेज और गहरे रहे हैं, इसलिए आर्थिक गतिविधि पर तत्काल स्थानिक सूचना महत्वपूर्ण हो जाती है जिनके आधार पर त्वरित नीतिगत निर्णयों के लिए उपयुक्त निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकें। इस संदर्भ में, कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधि की गति मापने के लिए उच्च आवृत्ति डेटा पर आधारित संपाती सूचकांक (सीआई) उपयोगी सिद्ध हुए हैं (फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ़ फिलाडेल्फिया² और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ़ न्यू यॉर्क³)। समय व स्थान के संकेतकों को मिलाकर सीआई की गणना की जाती है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ़ न्यूयॉर्क साप्ताहिक आवृत्ति के दस संकेतों का प्रयोगकर साप्ताहिक आर्थिक सूचकांक (डबल्यूईआई) बनाता है जबकि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ़ फिलाडेल्फिया चार राज्य स्तरीय परिवर्तियों को मिलाकर 50 राज्यों में से प्रत्येक के लिए एक मासिक संपाती सूचकांक (सीआई) निर्मित करता है।

मार्च के अंतिम सप्ताह में लागू कड़े राष्ट्रव्यापी तालाबंदी (लॉकडाउन), जिसे बाद में बढ़ाया गया, के कारण 2020-21 की पहली तिमाही (ति1) में भारत में आर्थिक गतिविधि तेजी से नीचे गई। परिणामस्वरूप ति1: 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वास्तविक जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की तीव्रतम गिरावट दर्ज की। जून 2020 के पहले सप्ताह में क्रमिक अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद आर्थिक गतिविधियों में कुछ गति आई। ति2: 2020-21 में, राज्यों ने भी स्थानीय लॉकडाउन लगाए जिसमें आर्थिक गतिविधि को नियंत्रित करने वाले नियमों में व्यापक भिन्नता थी। तथापि वास्तविक जीडीपी ने एक तेज क्रमिक सुधार दर्ज किया और ति2 में संकुचन घटकर 7.5 प्रतिशत पर आ गया।

² <https://www.philadelphiafed.org/research-and-data/regional-economy/indexes/coincident>

³ <https://www.newyorkfed.org/research/policy/weekly-economic-index#/>

गति के बने रहने को देखते हुए, सुधार की गति प्रत्याशा से अधिक होने की आशा है। ऐसी परिस्थितियों में, आर्थिक संकेतकों की उच्च आवृत्ति पर और एक स्थानिक वितरण के साथ निगरानी केंद्रीय बैंक व अन्य नीति निर्माताओं के लिए बहुत महत्व रखती है। इस संदर्भ में, इस अध्ययन का उद्देश्य दैनिक उच्च आवृत्ति चरों (वेरिएबल्स) वाले एक संपाती संकेतक (सीआई) का निर्माण करके भारत में राज्य स्तर पर आर्थिक गतिविधि के गतिमान आयामों को दर्ज करना है। मांग और आपूर्ति के गतिमान आयामों के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले और दैनिक आवृत्ति पर राज्य स्तरीय डेटा की उपलब्धता के आधार पर चार संकेतकों से सीआई निर्मित है: (i) कुल वाहन पंजीकरण; (ii) बिजली की खपत; (iii) वायु गुणवत्ता सूचकांक; तथा (iv) गूगल और एपल गतिशीलता डेटा। खंड II मौजूदा साहित्य से इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन प्रदान करता है। डेटा और कार्यप्रणाली का विवरण खंड III में है, जबकि खंड IV क्षेत्र-वार सीआई में गति पर विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अखिल भारतीय सीआई और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के बीच संबंध की जांच खंड V में की गई है। खंड VI में समापन निष्कर्ष शामिल हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, इस अध्ययन की नवीनता दैनिक आवृत्ति डेटा के साथ उप-राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधि में गति को दर्ज करने में है।

II. साहित्य से मार्गदर्शन

कई अध्ययनों ने उप-राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी सीआई के निर्माण के लिए प्रतिनिधि/प्रमुख कारकों (प्राइम फैक्टर्स) को निकालने के लिए डायनेमिक फैक्टर मॉडल (डीएफएम) का उपयोग किया है (गेवेक, 1977; सीआई; सार्जेंट एंड सिम्स, 1977)।

डीएफएम का उपयोग करते हुए, अध्ययनों ने युद्धोपरांत अमेरिका में समग्र व्यापार चक्र और विभिन्न मैक्रोइकॉनॉमिक चर, अर्थात्, उत्पादन, ब्याज दरों, कीमतों, उत्पादकता, क्षेत्रीय रोजगार, निवेश, आय और खपत के बीच अनुभवजन्य संबंधों की जांच की है (स्टॉक और वाटसन, 1998)। यह कार्य वे समग्र चक्र और व्यक्ति समय शृंखला के चक्रीय घटकों के बीच संबंधों की मजबूती की जांच द्वारा करते हैं कि कोई व्यक्ति समय शृंखला चक्र

के आगे चल रही है या अंतराल से और कि क्या व्यक्ति समय शृंखला समग्र उतार-चढ़ाव का पूर्वानुमान लगाने में सहायक है।

फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया राज्य और क्षेत्र संबंधी कई मुद्दों की जांच हेतु आर्थिक गतिविधि के मासिक माप के रूप में अमेरिका के 50 राज्यों के लिए सीआई के एक सेट का आकलन करता है। वे तीन मासिक चरों (कृषि से इतर पेट्रोल रोजगार, बेरोजगारी दर और विनिर्माण में किए गए कार्य के औसत घंटे) और एक तिमाही चर - वास्तविक मजदूरी और वेतन संवितरण के साथ डीएफएम का आकलन करते हैं। इन सूचकांकों का उपयोग राज्य व्यापार चक्रों के समय की तुलना करने, बैंक के प्रदर्शन पर क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि के प्रभाव का अनुमान लगाने और कर राजस्व पर राज्य की आर्थिक गतिविधि के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया गया है। मासिक राज्य स्तरीय जीडीपी के अभाव में, ये सूचकांक राज्य स्तर की आर्थिक गतिविधि (क्रोन और मैथ्यू, 2005) को ट्रैक करने में मदद करते हैं। दूसरी ओर, वास्तविक गतिविधि की गति, जिसे मासिक और त्रैमासिक संकेतक नहीं बता पाते, को जानने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यू यॉर्क मोटे तौर पर तीन श्रेणियों - उपभोक्ता-केंद्रित, श्रम बाजार और औद्योगिक शृंखला - में विभाजित साप्ताहिक आवृत्ति वाली 10 शृंखलाओं का प्रयोग करते हुए साप्ताहिक आर्थिक सूचकांक (डबल्यूआईआई) तैयार करता है (लुईस व अन्य, 2020)। चूंकि डबल्यूआईआई वास्तविक आर्थिक गतिविधि में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) प्रतिशत परिवर्तन को लक्ष्य बनाता है, उन्होंने शृंखला को 52-सप्ताह प्रतिशत परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष) में बदल दिया है, जिससे मौसमीपन को समाप्त करने में भी मदद मिली जो काफी हद तक साप्ताहिक शृंखला में व्याप्त होता है। डबल्यूआईआई के निर्माण हेतु पहला प्रमुख घटक निकालने के लिए वे डीएफएम का उपयोग करने से पहले वे सभी शृंखलाओं का मानकीकरण करते हैं। पूर्वानुमान शक्ति और तत्कालिक अनुमान की क्षमता को मापने के लिए, वे त्रैमासिक डबल्यूआईआई पर त्रैमासिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) वृद्धि का और साथ ही मासिक डबल्यूआईआई पर मासिक औद्योगिक उत्पादन (आईपी) में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) वृद्धि का प्रतीपगमन (रिग्रेसन) करते हैं और उन्हें परिणाम बहुत उत्साहजनक मिलते हैं।

डीएफएम के प्रयोग से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऐसा डेटाबेस बनाने का भी प्रयास किया गया है जो निजी कंपनियों के

अनाम डेटा का उपयोग करके तत्काल बारीक स्तर पर आर्थिक गतिविधि को ट्रैक करता है (चेट्टी व अन्य, 2020)। पिन (ज़िप) कोड, उद्योग, आय समूह और व्यापार के अनुसार उपभोक्ता खर्च, व्यवसाय राजस्व, रोजगार दर और अन्य संकेतकों पर लेखक दैनिक आँकड़े रिपोर्ट करते हैं। इन आँकड़ों को लेकर, वे विश्लेषण करते हैं कि कोविड-19 ने अर्थव्यवस्था को विविध स्तरों पर कैसे प्रभावित किया। वे देखते हैं कि उच्च आय वाले व्यक्तियों ने मार्च 2020 के मध्य में विशेष रूप से कोविड -19 संक्रमण की उच्च दर वाले क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में खर्च में कटौती की, जिनमें आमने-सामने आदान-प्रदान या व्यवहार की आवश्यकता होती है। खर्च में इस कटौती के कारण उच्च आय वाले गृहस्थों की जरूरतों को पूरा करने वाले छोटे व्यवसायों के राजस्व में गिरावट आई। इसके चलते कम मजदूरी पाने वाले वैसे श्रमिकों की नौकरियां गईं जो संपन्न क्षेत्रों में काम करते थे।

III. डेटा और पद्धति

डेटा

हम 14 प्रमुख राज्यों से जुड़े दैनिक आवृत्ति वाले 4 चरों का उपयोग करते हैं, जो कुल राष्ट्रीय सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) में लगभग 82 प्रतिशत का योगदान करते हैं। लिए गए चर हैं: (i) कुल वाहन पंजीकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का वाहन डैशबोर्ड); (ii) पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) में उपलब्ध बिजली की मांग; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दिया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक; और (iv) गूगल मोबिलिटी डेटा। गूगल मोबिलिटी (जो जनवरी 2020 से उपलब्ध है) को छोड़कर सभी चरों की नमूना अवधि 1 जनवरी, 2018 से 1 दिसंबर, 2020 तक है। (अनुबंध 1)। चर उच्च आवृत्ति पर उपलब्ध हैं, इसके अलावा वे, मांग और आपूर्ति दोनों स्थितियों का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्ता मांग का एक संकेतक होने के साथ वाहन पंजीकरण, सेवा क्षेत्र के व्यापार और परिवहन उप-खंड में आर्थिक गतिविधि को भी दर्शाते हैं। बिजली की खपत वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधि का एक संकेत देती है, तथापि कुछ हद तक इससे कृषि और घरेलू ऊर्जा की मांग का भी पता चलता है। ट्रैफिक डेटा और

वायु गुणवत्ता को मिलाकर देखने पर विनिर्माण गतिविधि के साथ-साथ श्रमिकों की आवाजाही का पता चलता है जो सेवाओं की गतिविधि का एक संकेतक है। राज्यों के चयन का आधार डेटा उपलब्धता है और केवल वे राज्य लिए गए हैं जहां सभी चार चरों के लिए डेटा उपलब्ध है (सारणी 1)।

चूँकि अंतर्निहित डेटा में उच्च स्तर का मौसमीपन है, पहले तीन चर को 1 जनवरी से साप्ताहिक आधार पर वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन में बदल दिया गया है (1-7 जनवरी को सप्ताह 1, जनवरी 8-14 को सप्ताह 2 इत्यादि) के रूप में निरूपित किया जाता है (लेविस व अन्य की पद्धति, 2020 के अनुसार)। साप्ताहिक डेटा का प्रयोग सप्ताह का दिन के प्रभाव के नियंत्रण में भी सहायक

सारणी 1: डेटा और जीवीए शेयर ⁴

राज्य	जीवीए शेयर (प्रतिशत)	वाहन रजिस्ट्रेशन	बिजली	वायु गुणवत्ता	गूगल मोबिलिटी
आंध्र प्रदेश	4.8	×	✓	✓	✓
असम	1.8	✓	✓	✓	✓
बिहार	3.1	✓	✓	✓	✓
छत्तीसगढ़	1.8	✓	✓	×	✓
दिल्ली	4.0	✓	✓	✓	✓
गुजरात	7.8	✓	✓	✓	✓
हरियाणा	3.6	✓	✓	✓	✓
झारखंड	1.6	✓	✓	×	✓
कर्नाटक	8.0	✓	✓	✓	✓
केरल	4.2	✓	✓	✓	✓
महाराष्ट्र	13.8	✓	✓	✓	✓
ओडिशा	2.6	✓	✓	✓	✓
पंजाब	2.8	✓	✓	✓	✓
राजस्थान	5.2	✓	✓	✓	✓
तमिलनाडु	8.8	✓	✓	✓	✓
उत्तराखंड	1.3	✓	✓	×	✓
उत्तर प्रदेश	8.8	✓	✓	✓	✓
पश्चिम बंगाल	6.2	✓	✓	✓	✓
हिमाचल प्रदेश	0.8	✓	✓	×	✓
तेलंगाना	4.5	×	✓	✓	✓
मध्य प्रदेश	4.5	×	✓	✓	✓

स्रोत: एमओएसपीआई, वाहन डैशबोर्ड, पोसोको, सीपीसीबी, गूगल.

⁴ कुछ राज्यों के आँकड़े वाहन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हैं जबकि सीपीसीबी द्वारा जारी दैनिक एक्ज्यूआई बुलेटिन में कुछ राज्यों में नगर (सिटीज) नहीं हैं। डेटा की ऐसी अनुपलब्धता दर्शाने के लिए के लिए (x) चिह्न का प्रयोग किया गया है। 2019 के लिए गूगल गतिशीलता (मोबिलिटी) डेटा की अनुपलब्धता के कारण आलेख में आगे चलकर 3-परिवर्तनशील संकेतक निर्मित किए गए हैं।

है। गूगल गतिशीलता (मोबिलिटी) डेटा बेसलाइन से विचलन के रूप में उपलब्ध है (5-सप्ताह की अवधि 3- जनवरी 6 फरवरी, 2020)। इसके अलावा, मानक पद्धति का प्रयोग करते हुए सभी शृंखलाओं को सामान्य किया गया है – औसत (मीन) से घटाना और मानक विचलन द्वारा विभाजित करना⁵।

पद्धति

डायनामिक फैक्टर मॉडल (डीएफएम) का उपयोग मुख्य रूप से उन प्रमुख कारकों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो अंतर्निहित चर में अधिकतम भिन्नता का कारण बताते हैं। हम स्टॉक और वॉटसन (1998) द्वारा प्रचलित पद्धति के आधार पर इन चार उच्च आवृत्ति चरों में निहित सूचना का सारांश प्रस्तुत करने के लिए भी डीएफएम का प्रयोग करते हैं। फैक्टर एनालाइजर पाइथन मॉड्यूल का उपयोग करते हुए, डेटा सेट को प्रत्येक राज्य के लिए एक कारक (फैक्टर) में संक्षेपित किया गया है।

डीएफएम में N चर (x_{it}) ($i = 1, \dots, N$) को दो अलक्ष्य आयतीय घटकों (अनऑब्जर्वेबल ऑर्थोगोनल कॉम्पोनेंट्स) का योग माना गया है अर्थात् चरों के सेट में प्रत्येक अवधि ($t=1, \dots, T$) में कॉमन कारक (फैक्टर) (y_{it}) और एक अनूठा घटक (z_{it})

$$x_{it} = y_{it} + z_{it}$$

घटक (y_{it}) को डेटा सेट में मौजूद सभी चरों से r कॉमन कारक (F_{jt}), $j = 1, \dots, r$ निकालकर प्राप्त किया गया है जबकि अनूठा घटक (z_{it}) प्रत्येक चर के प्रति विशिष्ट आघात को कवर करता है।

$$x_{it} = \lambda_{i1}F_{1t} + \dots + \lambda_{ir}F_{rt} + z_{it}$$

$i = 1, \dots, N$ और $j = 1, \dots, r$, के लिए (λ_{ij}) लोडिंग कारक (फैक्टर) (F_j) चर के योगदान को दर्शाता है।

प्रारंभ में हम बारलेट के गोलाई परीक्षण और नमूने की पर्याप्तता के कैसर-मेयर-ओल्किन (केएमओ) माप द्वारा यह जाँचते हैं कि हमारा डेटासेट एक तत्समक आव्यूह (आइडेंटिटी मैट्रिक्स) नहीं है (डजुबन और शिकि, 1974; कैसर, 1970)। 1 प्रतिशत महत्व के स्तर पर खारिज निराकरणिय परिकल्पना (नल

हाइपोथेसिस)⁶ के साथ बारलेट परीक्षण महत्वपूर्ण है और 0.5 से अधिक के केएमओ मान से पता चलता है कि डेटा का उपयोग गतिशील कारक (डायनामिक फैक्टर) विश्लेषण के लिए किया जा सकता है।

हम देखे गए डेटा में कारकों को फिट करने के लिए अधिकतम संभावना (एमएल) पद्धति का प्रयोग करते हैं। एमएल उस कारक (फैक्टर) लोडिंग और अनूठे विचरण/प्रसरण आकलनों (वैरिएंस एस्टिमेट) का निर्धारण करता है जो देखे गए डेटा का सर्वाधिक संभावित कारण है (विंटर और डोडो, 2012)। हमारे डेटा के लिए रखे जाने वाले कारकों की संख्या पर निर्णय लेने के लिए विजुअल स्क्रि प्लॉट विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है (जोस्की और जर्स, 1996) (अनुबंध 2)। एकरूपता बनाए रखते हुए स्क्रि प्लॉट का प्रयोग करते हुए, सभी राज्यों के लिए एकल कारक (सिंगल फैक्टर) डीएफएम का उपयोग इस आलेख में किया गया है। सारणी 2 प्रत्येक राज्य के डेटा के लिए केएमओ मान और डीएफएम मॉडल में प्रयुक्त चर के लिए कारक लोडिंग देती है।

सभी राज्यों के लिए डीएफएम में बिजली की मांग और गूगल गतिशीलता शृंखला की सकारात्मक लोडिंग्स हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत स्थिर हैं। वाहन पंजीकरण और वायु गुणवत्ता शृंखला, बहुत अस्थिर हैं जिसके कारण अलग-अलग राज्यों हेतु अलग डीएफएम के लिए इनकी लोडिंग में उच्च विचलन है।

सारणी 2: कारक (फैक्टर) लोडिंग

राज्य	केएमओ वैल्यू	वाहन रजिस्ट्रेशन	बिजली	वायु गुणवत्ता	गूगल मोबिलिटी
असम	0.6	0.75	0.33	-0.09	0.78
बिहार	0.53	0.61	0.35	-0.13	0.67
दिल्ली	0.71	0.81	0.5	-0.02	0.88
गुजरात	0.6	-0.09	0.69	0.93	0.13
हरियाणा	0.7	-0.07	0.69	0.82	0.25
कर्नाटक	0.6	0.81	0.6	0	0.88
केरल	0.6	0.52	0.73	0.07	0.8
महाराष्ट्र	0.64	0.67	0.78	0.06	0.93
ओडिशा	0.6	0.68	0.39	0.02	0.66
पंजाब	0.56	-0.13	0.86	0.87	0.38
राजस्थान	0.57	-0.07	0.8	0.71	0.41
तमिलनाडु	0.71	0.84	0.75	0.08	0.87
उत्तर प्रदेश	0.59	-0.05	0.81	0.73	0.48
पश्चिम बंगाल	0.57	0.52	0.36	-0.07	0.69

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

⁶ टेस्ट स्टैटिस्टिक X^2 को बार्टलेट (1951) में $X^2 = -[n(n-1) - (2k+5)/6] \cdot \log(|R|)$ के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ n प्रेक्षणों की संख्या है, k चरों की संख्या और x में दिए गए डेटा का सहसंबंध ढाँचा R है। R का निर्धारक तत्व $|R|$ है।

बार्टलेट का χ^2 निराकरणिय परिकल्पना (नल हाइपोथेसिस) के अंतर्गत $df = k(k-1)/2$ द्वारा वितरित अनंतस्पर्शी (ऐसिम्पटोटिक) χ^2 है।

⁵ $Z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$

जहाँ

x_i एक डेटा प्वाइंट है (x_1, x_2, \dots, x_n) , \bar{x} नमूना माध्य और s नमूना मानक विचलन

इसके अलावा, 2019 हेतु संकेतक को पश्चगामी विस्तार (बैकवर्ड एक्सटेंशन) देकर राज्यों के लिए मॉडल के 3 परिवर्ती विनिर्देशन (वेरिएबल स्पेसिफिकेशन) भी बनाए गए हैं। गूगल गतिशीलता डेटा की अनुपलब्धता के कारण, अन्य 3 वेरिएबल्स के प्रयोग से आर्थिक गतिविधि के वास्तविक संकेतक की दीर्घतर शृंखला उत्पन्न की जाती है।

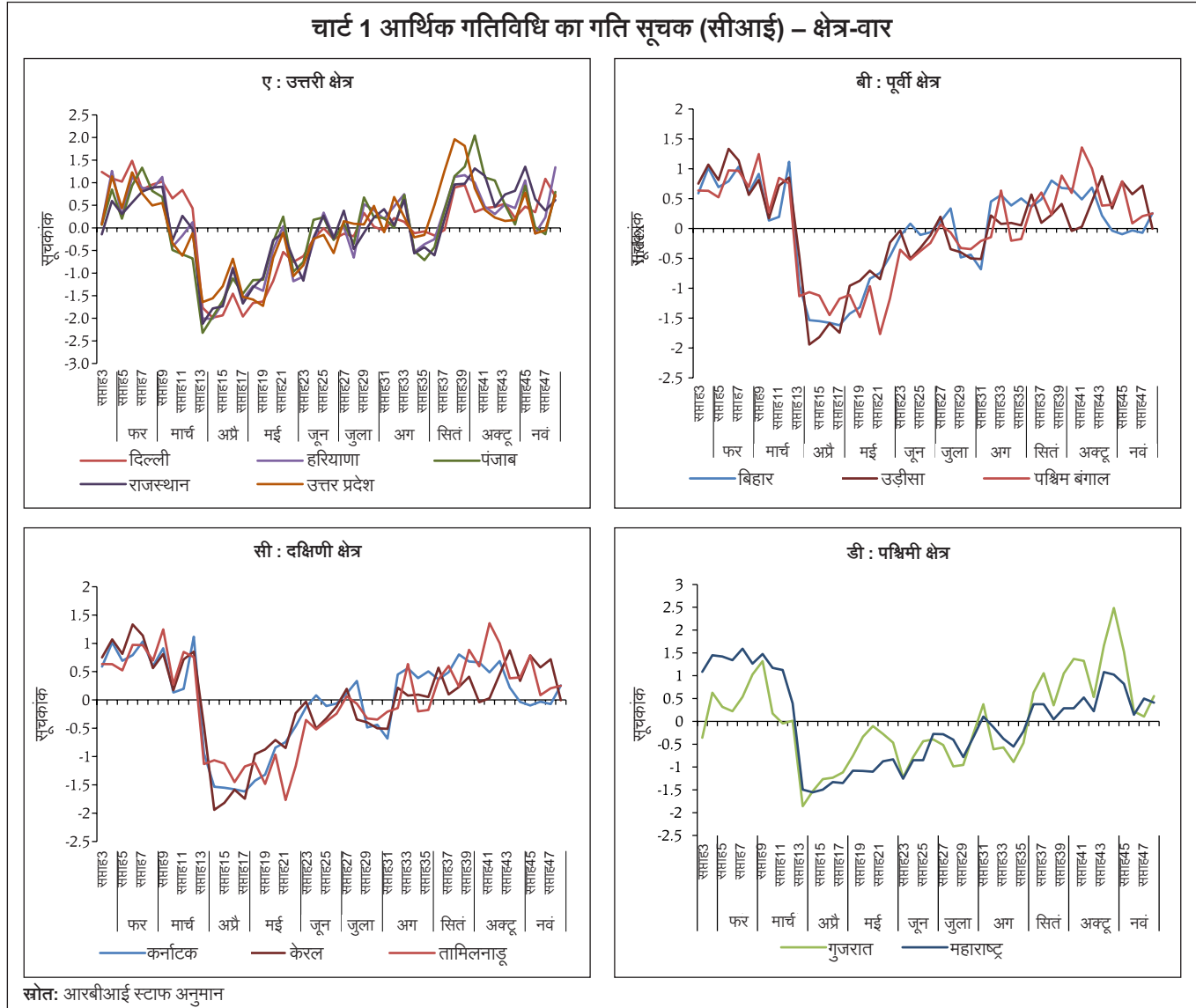
IV. प्रायोगिक (एम्पिरीकल) परिणामों का विश्लेषण

सीआई का निर्माण 14 राज्यों में से प्रत्येक के लिए एकल-कारक (सिंगल फैक्टर) डीएफएम के प्रयोग द्वारा किया गया है। चार इनपुट वेरिएबल्स द्वारा राज्यों के लिए आर्थिक गतिविधि का एकल सुगम संकेतक बनाना डीएफएम के प्रयोग से सीआई के निर्माण का आधार है। भार के रूप में फैक्टर लोडिंग के प्रयोग द्वारा

बनाई गई सिंगल-फैक्टर आधारित सीआई को उस राज्य में आर्थिक गतिविधि के प्रतिनिधि के रूप में लिया गया है। इसके बाद राज्यों के जीवीए शेरों को भार के रूप में उपयोग करके राज्य-वार सीआई का भारित औसत निकालकर अखिल भारतीय सीआई की गणना की जाती है। राज्यों को भौगोलिक रूप से चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राज्यों का क्षेत्र-वार सीआई नीचे चार्ट 1 में दर्शाया गया है। सीआई के अनुसार, मार्च के अंतिम सप्ताह में देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद सभी क्षेत्रों के राज्यों ने आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट देखी। इसके बाद, सभी क्षेत्रों के सीआई ने सुधार (रिकवरी) दर्शाया प्रदर्शन किया, पर रह-रहकर अधोमुखी गति के साथ।

विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ सुधार (रिकवरी) की अलग-अलग गति देखी गई है, उत्तरी क्षेत्र ने सकारात्मक गति के पहले संकेत जुलाई

चार्ट 1 आर्थिक गतिविधि का गति सूचक (सीआई) – क्षेत्र-वार



में दर्शाए और उसके बाद सितंबर में पुनः तीव्र वृद्धि दर्ज की। अक्टूबर और नवंबर के पहले सप्ताह तक उत्तरी क्षेत्र में गति में वृद्धि बनी रही। नवंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान कुछ उत्तरी राज्यों में सीआई में नरम पड़ा और अंतिम सप्ताह में फिर से उठा। पूर्वी क्षेत्र का सीआई अगस्त और सितंबर के दौरान धीमी और स्थिर सुधार दर्शाता है। पूर्वी राज्यों में, पश्चिम बंगाल ने अक्टूबर में तेज वृद्धि दर्ज की है और नवंबर में सकारात्मक गति बनाए रखी। नवंबर की पहली छमाही में बिहार में जहाँ कुछ नरमी दर्ज हुई, उड़ीसा में गति मजबूत रही।

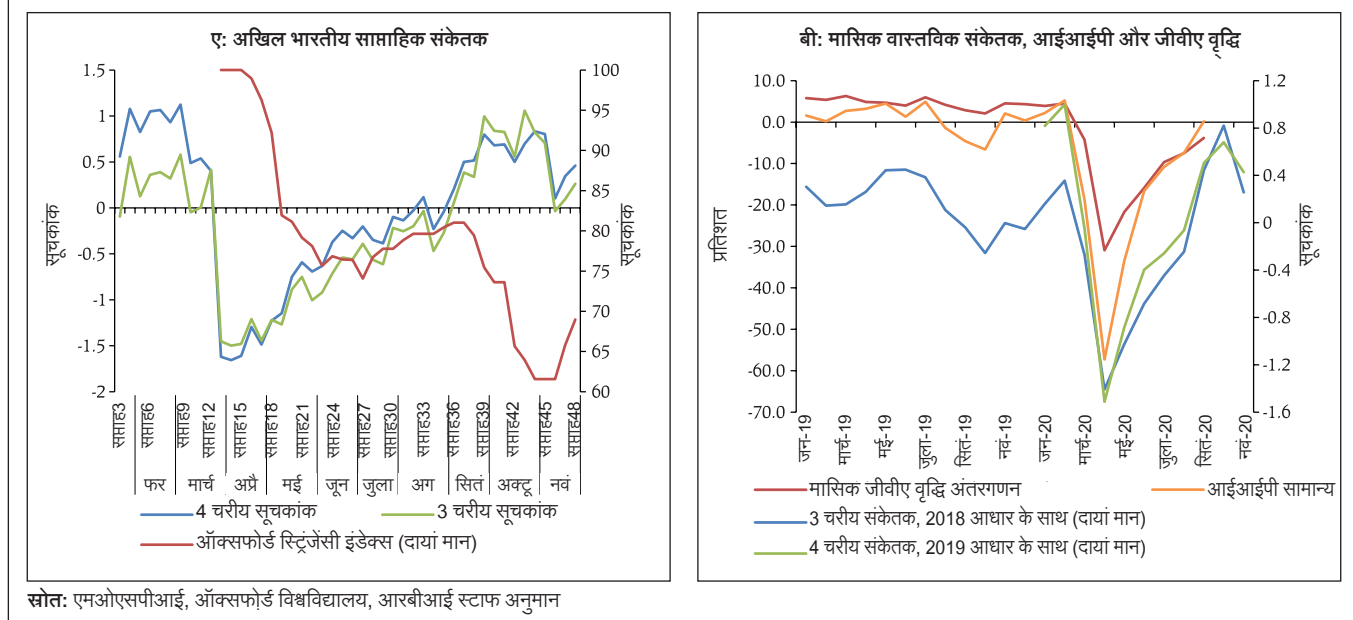
दक्षिणी क्षेत्र, जिसने अगस्त में सकारात्मक गति का पहला संकेत दिया था, सितंबर में कुछ नरम पड़ा और अक्टूबर में फिर से बढ़ा। नवंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान गति में आई एक अल्पकालिक गिरावट महीने की उत्तरार्ध में तेजी से उलट गई। अन्य क्षेत्रों से पिछड़ रहे पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों ने सितंबर के दौरान सीआई में सकारात्मक गति की निरंतरता का पहला संकेत देखा, जो अक्टूबर और नवंबर में जारी रहा। उल्लेखनीय है कि, अक्टूबर में सभी क्षेत्रों में राज्यों के सीआई ने तेज वृद्धि दर्ज की। यद्यपि नवंबर में कुछ गिरावट दर्ज की गई, लेकिन गति सकारात्मक रही और अधिकांश राज्यों में उत्तरार्ध में उलट गई।

समग्र जीवीए में भार के रूप में राज्यों के अंश के प्रयोग द्वारा राज्य सीआई के भारत औसत के रूप में निर्मित अखिल भारतीय

सीआई, ति1 (तिमाही 1) में गतिविधि में गिरावट और बाद में सुधार को दर्शाता है (चार्ट 2.ए)। अखिल भारतीय संयुक्त संकेतक भी अर्थव्यवस्था के क्रमशः खोले जाने को प्रतिबिंबित करता है जैसा कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स ने दर्शाया है और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधि का सुसंगत तत्काल आकलन प्रदान करता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में उँचाई पर जाने के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में साप्ताहिक अखिल भारतीय संकेतक ने नवंबर के दूसरे सप्ताह में कुछ सुधार दिखाया है। तथापि, कुछ राज्यों द्वारा रात के कर्फ्यू जैसे नए प्रतिबंधों (ऑक्सफोर्ड स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स में वृद्धि द्वारा प्रतिबिंबित) के बावजूद, गति में यह कमी नवंबर के दूसरे पखवाड़े में वृद्धि में बदल गई।

जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में वृद्धि के साथ तुलना करने के लिए, हमने सीआई के 3-चरों वाले विनिर्देशन का प्रयोग किया (2020 से पहले गूगल गतिशीलता पर डेटा की अनुपलब्धता के कारण) और अपने विश्लेषण की अवधि को पीछे जनवरी 2019 तक बढ़ाकर ले गए (अर्थात् जनवरी 2019 से नवंबर 2020 तक की नमूना अवधि)। यह पाया गया कि 3-चरों वाले विनिर्देशनों पर आधारित सीआई 2020 के लिए मोटे तौर पर से एक जैसा रुझान दिखाता है (चार्ट 2बी)। इसके अलावा, दोनों 3-चरों वाले और 4-चरों वाले संकेतक आईआईपी वृद्धि के साथ सह-गति दर्शाते हैं।

चार्ट 2: आर्थिक गतिविधि का गति सूचक (सीआई)



V. समष्टि-आर्थिक चरों के साथ संबंध

इसके अलावा हमने 3-चरों और प्रमुख समष्टि-आर्थिक वृद्धि चरों पर आधारित सीआई के बीच प्रायोगिक/अनुभवजन्य संबंधों के परीक्षण का प्रयास किया है ताकि लोक नीति के उद्देश्यों के लिए सीआई की उपयोगिता का पता लग सके। डेटा सीमा के मद्देनजर, हमने आईआईपी में वृद्धि के साथ सीआई के संबंध की अनुभवजन्य जांच की। पहले कदम के रूप में, सहसंबंध की गणना द्वारा आईआईपी (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि) में 12 महीने के प्रतिशत परिवर्तन के साथ सीआई के संबंध को मापा गया और यह देखा जा सकता था कि जनवरी 2019 से सितंबर 2020 की नमूना अवधि में चरों के दो सेट के बीच उच्च स्तर का सहसंबंध है (सारणी 3)। चार्ट 2बी भी 3-चरों वाले सीआई और आईआईपी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के बीच एक स्पष्ट संबंध प्रदर्शित करता है।

$$IIP_t = C + \beta CI_t + Dummy + \varepsilon_t$$

जहां आईआईपी, आईआईपी में 12 महीने का प्रतिशत परिवर्तन है और सीआई अखिल भारतीय सीआई का औसत है। प्रतिगमन की दो विशिष्टताओं के परिणाम नीचे तालिका 4 में दिए गए हैं। परिणाम दर्शाते हैं कि आईआईपी वृद्धि और 3-चरों वाले सीआई संकेतक के बीच सकारात्मक संबंध है तथा दोनों विनिर्देशों में 1 प्रतिशत के स्तर पर गुणांक महत्वपूर्ण (कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट) है। विनिर्देश 1 में, हमने न्यूई-वेस्ट एस्टिमेटर का प्रयोग किया है जो हेटरोस्केडास्टिसिटी और ऑटोकोरिलेशन – कनसिस्टेंट (एचएसी) स्टैंडर्ड एरर्स प्रदान करता है। विनिर्देश II में, अप्रैल 2020 में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण तेज नकारात्मक झटकों के लिए एक प्रतिरूपी (डमी) को शामिल किया गया है। इसके अलावा, दोनों प्रतिगमनों के परिणाम दर्शाते हैं कि

सारणी 3: सहसंबंध ढाँचा

	आईआईपी वृद्धि (जनवरी 2019-सितंबर 2020)	आईआईपी वृद्धि (जनवरी 2019-मार्च 2020)	आईआईपी वृद्धि (जनवरी 2019-सितंबर 2020 अप्रैल 2020 छोड़कर)
3 चरों वाले संकेतक	0.93	0.79	0.92

सारणी 4: ओएलएस प्रतिगमन (रिग्रेसन) (आश्रित चर /डिपेंडेंट वेरिएबल – आईआईपी वृद्धि)

	(1)	(2)
स्थिरांक (कॉन्स्टैंट)	-4.54*** (1.32#)	-3.81*** (0.93)
3 चरों वाले संकेतक	28.62*** (4.02#)	22.59*** (2.39)
प्रतिरूपी (डमी)		-21.96***
समायोजित आर ²	0.87	0.93

टिप्पणियां: 1. ***, **, & * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, और 10 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्त्व दर्शाते हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए अंक मानक त्रुटियां हैं।

एचएसी मानक त्रुटियां दर्शाते हैं (न्यूई- वेस्ट फिक्सस्ड बैंडविड्थ = 3.00)

आईआईपी वृद्धि में क्रमशः 87 प्रतिशत और 93 प्रतिशत परिवर्तन पर सीआई प्रकाश डालता है (समायोजित R² = 0.87 और 0.93)।

VI. निष्कर्ष

चार दैनिक संकेतकों पर निर्मित संपाती संकेतक (सीआई)1 राष्ट्रीय व उप राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक गतिविधि में तत्काल गति की सूचना देता है। मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधि में तीव्र गिरावट के बाद सभी क्षेत्रों में सीआई बड़ी तेजी से नीचे गए जो आर्थिक गतिविधि में तेज गिरावट का प्रतिबिंब है। सीआई की गति दर्शाती है कि जून 2020 से प्रारंभ क्रमिक अनलॉकिंग के साथ विभिन्न क्षेत्रों में समुत्थान की अलग-अलग गति रही। उभरते कोविड-19 संक्रमणों के चलते लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में ढील और कसाव के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र ने रह-रहकर उतार-चढ़ाव का अनुभव किया है। उत्तरी क्षेत्र ने जुलाई और अगस्त में समुत्थान की अगुवाई की और उसके बाद दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में गति के कुछ संकेत मिले। कुल मिलाकर, अखिल भारतीय सीआई ने सितंबर और अक्टूबर में निरंतर क्रमिक सुधार जारी रखा, जो मजबूत समुत्थान (रिकवरी) दर्शाता है। नवंबर में नरमी के बावजूद, उत्तरार्ध में आर्थिक गतिविधियों की गति पलट गई और धनात्मक बनी रही।

इसके अलावा, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ सीआई का एक सुदृढ़ धनात्मक और सांख्यिकीय दृष्टि से उल्लेखनीय संबंध है। चूंकि निर्मित सीआई राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों

स्तरों पर आर्थिक गतिविधि का तत्काल आकलन दे रहा है, यह तत्काल नीति-निर्माण हेतु महत्तर अंतर्दृष्टि दे सकता है।

संदर्भ

Chetty, R., Friedman, John N., Hendren, N., Stepner, M. and Team (2020), "How Did COVID-19 and Stabilization Policies Affect Spending and Employment? A New Real-Time Economic Tracker Based on Private Sector Data", *Working Paper 27431, National Bureau of Economic Research Working Paper series*.

Crone, T.M. and Alan Clayton Matthews (2005), "Consistent Economic Indexes for the 50 States", *Review of Economics and Statistics*, MIT Press.

Dziuban, C. D., and Shirkey, E. C. (1974, March 1), "On the Psychometric Assessment of Correlation Matrices", *American Education Research Journal*, 2(2), 211-216. <https://doi.org/10.3102/00028312011002211>

Geweke (1977), "The dynamic factor analysis of economic time-series models", *Latent Variables in Socio-Economic Models* (D. Aigner and A. Goldberger, eds.), North-Holland, New York.

Kaiser, H. F. (1970), "A second generation little jiffy" *Psychometrika*, 401-415, <https://doi.org/10.1007/BF02291817>

Lewis, Daniel J., Karel Mertens James H. Stock and Mihir Trivedi (2020), "Measuring Real Activity Using a Weekly Economic Index", *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports*, no. 920.

Sargent, T., and Sims, C. (1977), "Business cycle modeling without pretending to have too much a priori economic theory", *Working Papers 55*, Federal Reserve Bank of Minneapolis.

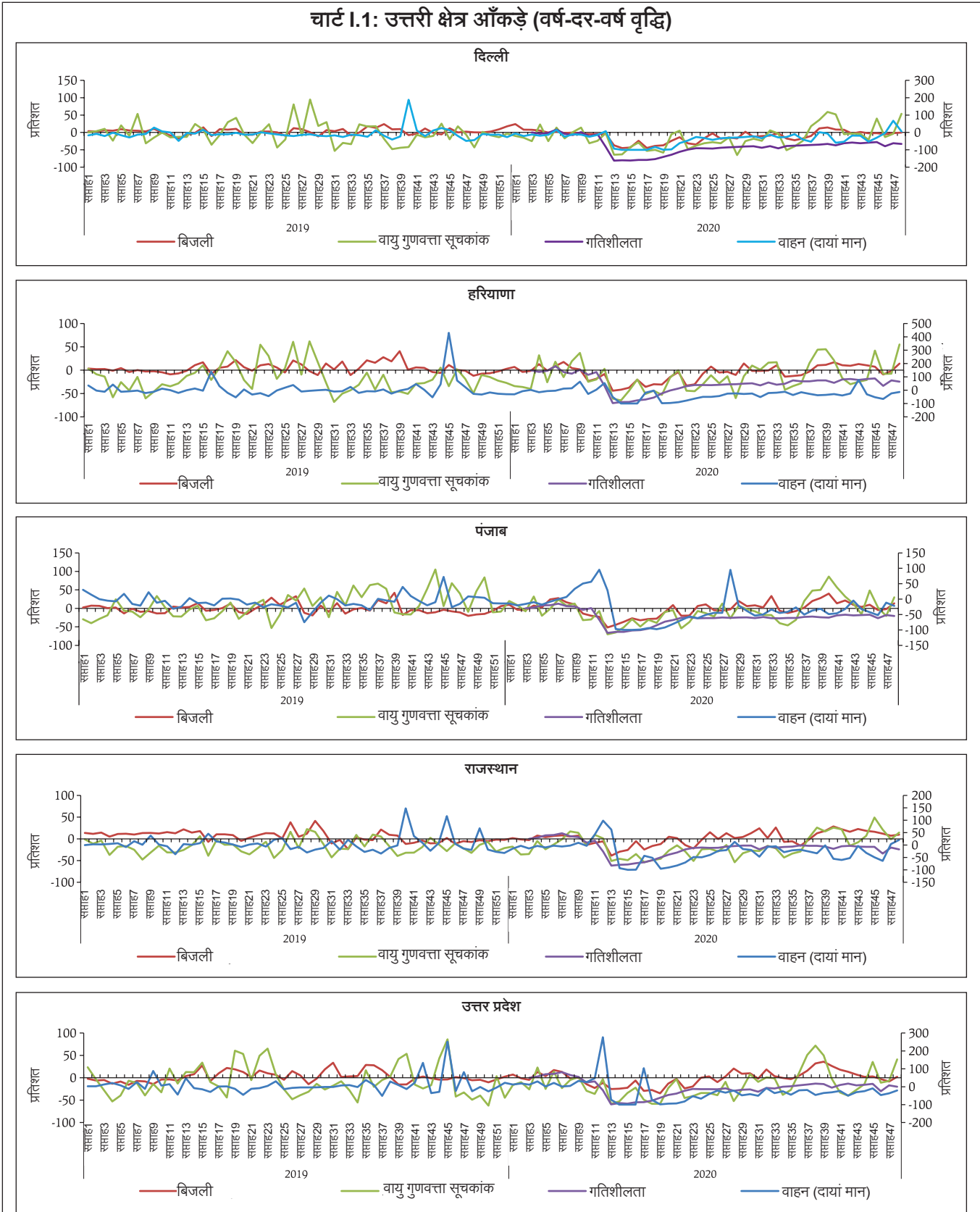
Stock, J. H., and Watson, M. w. (1998), "Business Cycle Fluctuations in US Macroeconomic Time Series", *NBER Working Paper series*, <https://www.nber.org/papers/w6528.pdf>

Winter, J., and Dodou, D. (2012), "Factor recovery by principal axis factoring and maximum likelihood factor analysis as a function of factor pattern and sample size", *Journal of Applied Statistics*, 39(4), 695-710.

Zoski, K. W., and Jurs, S. (1996), "An Objective Counterpart to the Visual Scree Test for Factor Analysis: The Standard Error Scree", *Educational and Psychological Measurement*, 56(3), 443-451, <https://doi.org/10.1177/0013164496056003006>.

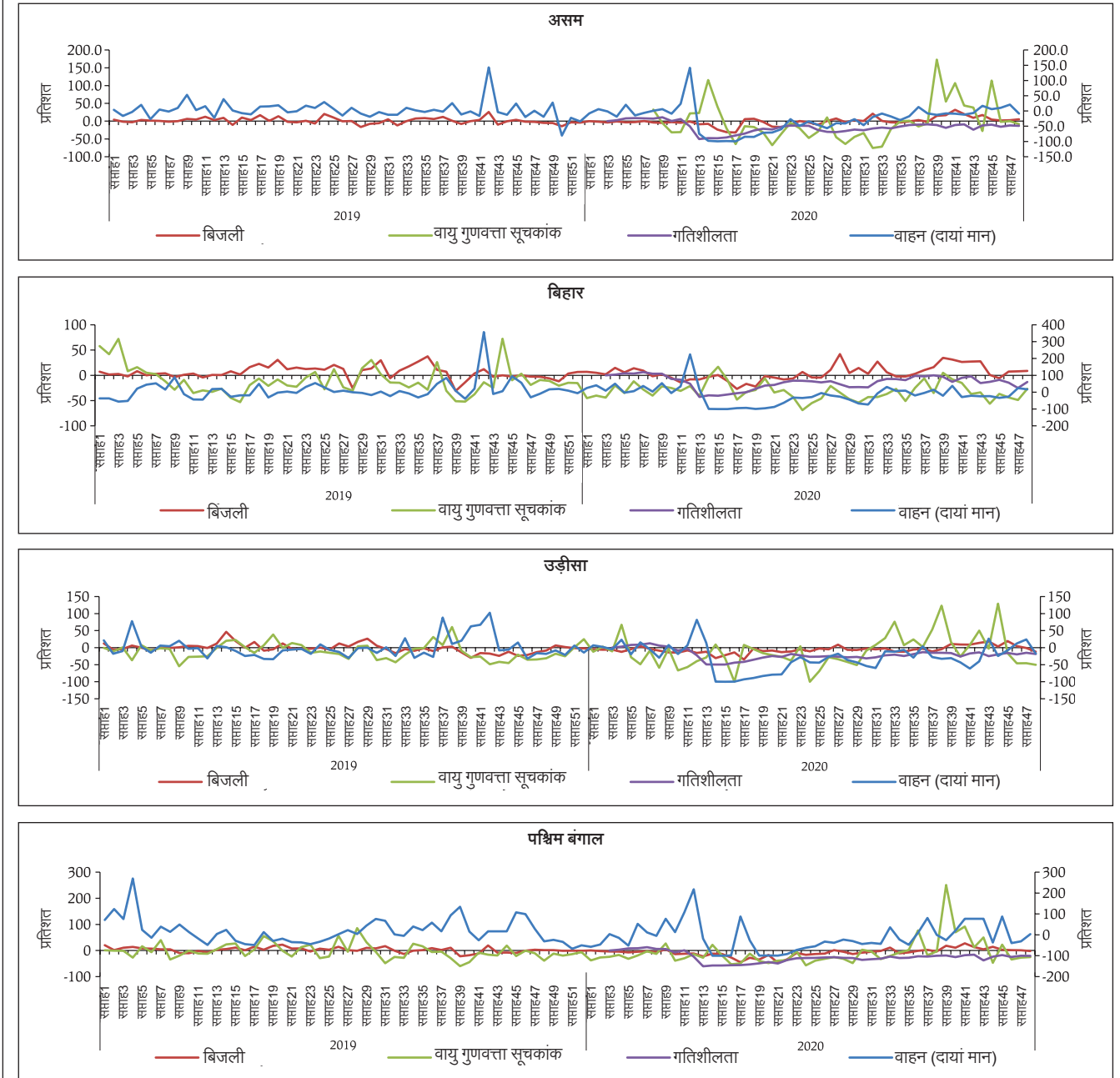
अनुबंध 1

चार्ट I.1: उत्तरी क्षेत्र आँकड़े (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)



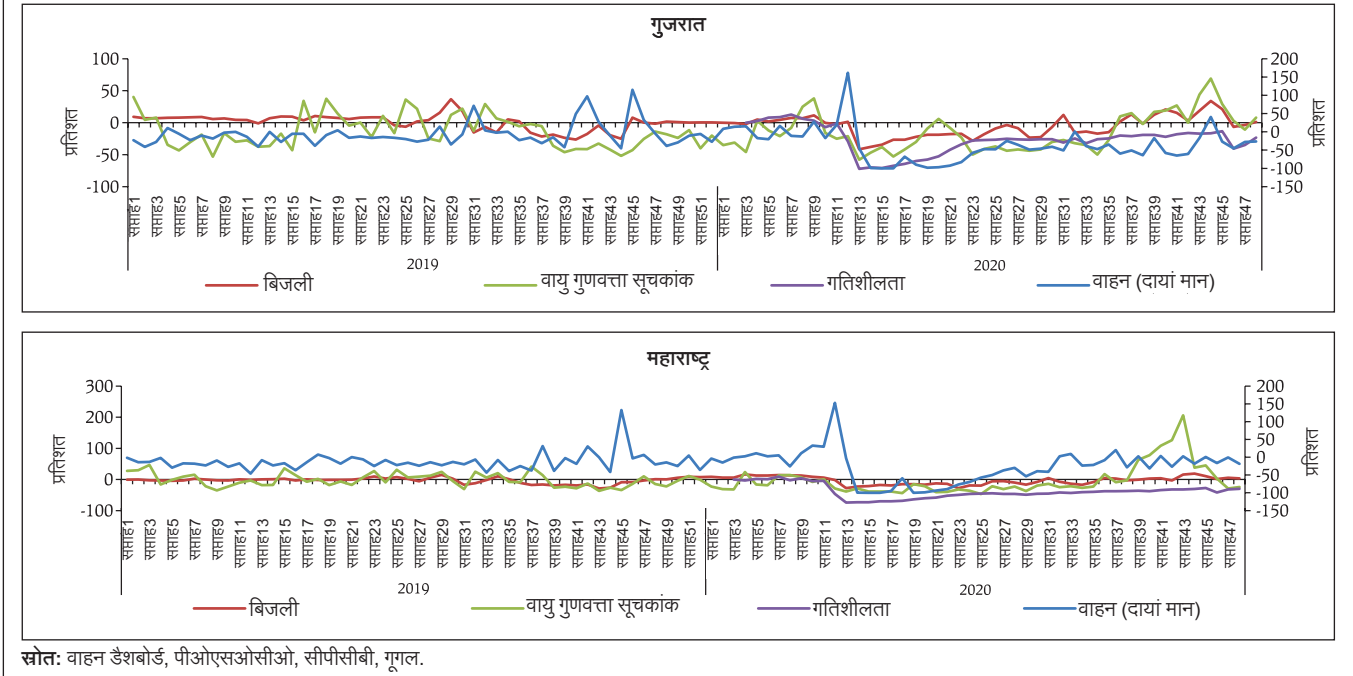
स्रोत: वाहन डैशबोर्ड, पीओएसओसीओ, सीपीसीबी, गुगल.

चार्ट 1.2: पूर्वी क्षेत्र आँकड़े (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)



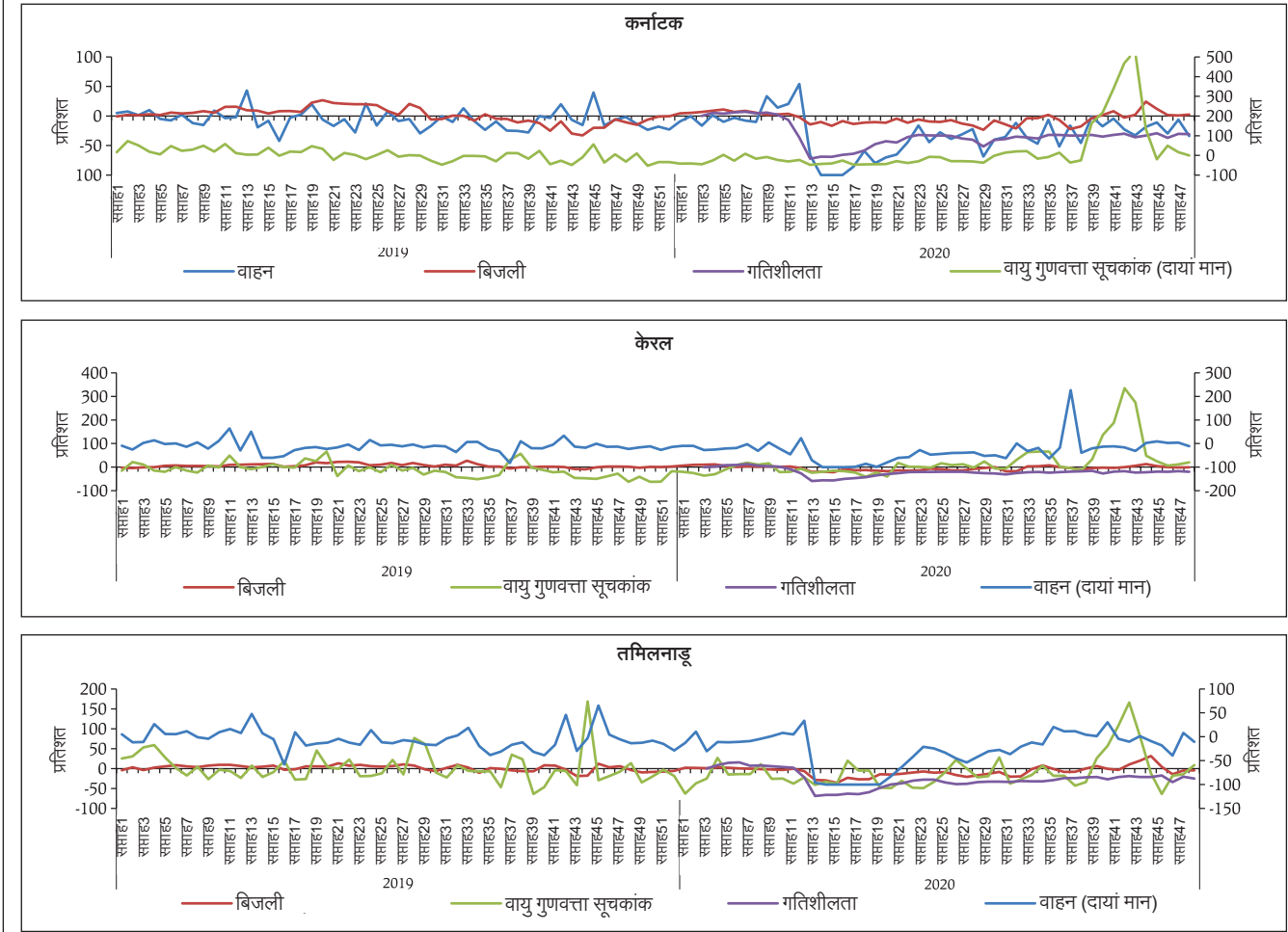
स्रोत: वाहन डैशबोर्ड, पीओएसओसीओ, सीपीसीबी, गूगल.

चार्ट 1.3: पश्चिमी क्षेत्र आँकड़े (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)



स्रोत: वाहन डैशबोर्ड, पीओएसओसीओ, सीपीसीबी, गूगल.

चार्ट 1.4: दक्षिणी क्षेत्र आँकड़े (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)



स्रोत: वाहन डैशबोर्ड, पीओएसओसीओ, सीपीसीबी, गुगल.

सरकारी वित्त 2020-21 : अर्धवार्षिक समीक्षा*

सरकार के वित्त की छमाही समीक्षा की श्रृंखला में यह तीसरा लेख है, सरकारी बजट के राजकोषीय गणित की जांच करता है और आर्थिक गतिविधि में संकुचन के प्रभाव और 2020-21 की पहली छमाही में प्रमुख राजकोषीय मापदंडों पर कोविड-19 के राजकोषीय प्रतिसाद की व्याख्या करता है। 2020-21 की पहली छमाही में संयुक्त वित्तीय घाटा तेजी से बढ़ा है लेकिन पहली तिमाही की गतिविधियां इसके लिए ज्यादातर जिम्मेदार हैं। इसके आगे, सरकारी वित्त पर कोविड-19 का गंभीर प्रभाव पहली तिमाही से ही पडने के कारण अब केंद्र तथा राज्य सरकारों को बहाली गति बनाए रखने के लिए प्रति चक्रिय राजकोषीय समर्थन देना जारी रखना जरूरी है।

परिचय

वर्ष 2020-21 का यूनियन बजट, कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन के पहले प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य धीमी अर्थव्यवस्था को एक प्रतिचक्रिय वित्तीय समर्थन प्रदान करना था। हालांकि, राजकोषीय रुख के कारण राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के बचाव खंड [धारा 4 (2)] का सहारा लेते हुए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त राजकोषीय घाटे की अनुमति देना आवश्यक हो गया। इसके परिणाम स्वरूप 2020-21 में प्रतिशत के अनुपात में सकल घरेलू उत्पाद (जीएफडी-जीडीपी) की तुलना में 3.0 प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करने का राजकोषीय समेकन लक्ष्य 2022-23 (3.1 प्रतिशत) तक आगे बढ़ाया गया। केंद्र के विपरीत, राज्यों ने हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का पालन किया है, जो ज्यादातर खर्च में कटौती के द्वारा प्राप्त किया गया है जिसका वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2020-21 में सभी राज्यों को मिलाकर, जीडीपी के 2.8 प्रतिशत जीएफडी का बजट

* यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) के राजकोषीय प्रभाग में राहुल अग्रवाल, इप्सिता पाठी, सुधांशु गोयल, समीर रंजन बेहरा और संगीता मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। डॉ. देबा प्रसाद रथ के बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए टीम उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और यह भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

किया गया है, हालांकि उन राज्यों के बीच एक अंतर है जिन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन से पहले अपना बजट प्रस्तुत किया है [उनके संयुक्त सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2.4 प्रतिशत] और जिन्होंने लॉकडाउन के बाद प्रस्तुत किया है (उनके संयुक्त जीएसडीपी के 4.6 प्रतिशत)।

कोविड-19 के साथ मुकाबले में सामान्य जीवन और आर्थिक गतिविधि पर कठोर पाबंदियां लगाना आवश्यक हुआ। जिसका सरकारी वित्त पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। घाटे के संतुलन में वृद्धि और विश्व उत्पादन (आईएमएफ 2020 ए) में कमी के संयुक्त प्रभाव के कारण वैश्विक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वैश्विक सामान्य सरकार राजकोषीय घाटा 2019 के 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 12.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि भारत का सामान्य सरकार राजकोषीय घाटा जीडीपी के 8.2 प्रतिशत से बढ़कर 13.1 प्रतिशत होगा। आर्थिक गतिविधि में संकुचन का सरकारी वित्त पर बुरा असर पड़ा जो राजस्व और व्यय के विषम प्रतिसादों से स्पष्ट है, राजस्व प्रवाह आर्थिक चक्र से है और व्यय स्थिर है। अधिक व्यय और कम करों के रूप में प्रतिचक्रिय प्रोत्साहन आर्थिक चक्र के अंतर्जनित प्रभाव से ज्यादा राजकोषीय घाटे के आकार को और अधिक बढ़ा सकता है। सरकारी वित्त पर भारत के उच्च-आवृत्ति आंकड़े बताते हैं कि जब जीडीपी में संकुचन के साथ राजस्व गिर गया है, प्रोत्साहनों को समायोजित करने के लिए सरकारी व्यय को आस्थगित किया गया / गैर-आवश्यक व्यय में कटौती की गयी जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ गया और परिणामस्वरूप सरकार का उधार अप्रत्याशित स्तर तक बढ़ गया।

सरकार के वित्त की छमाही समीक्षा की श्रृंखला में यह तीसरा लेख, अप्रत्याशित वर्ष की कुछ प्रमुख राजकोषीय चुनौतियों को परखता है, कोविड -19 के राजकोषीय प्रतिसाद तथा प्रमुख राजकोषीय मानदंडों पर इसके प्रभाव की जानकारी देता है। पहले, वर्तमान और अगले राजकोषीय वर्ष में वृद्धि और इसके विभिन्न घटकों पर प्रोत्साहक पैकेज के प्रभाव को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर, अब तक के परिणामों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य सरकार के संभाव्य राजकोषीय शेष का अनुमान लगाया गया है।

यह लेख निम्नानुसार विभाजित किया गया है। भाग II में तिमाही अंतरालों पर वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में केंद्र और सभी राज्यों की प्राप्तियों और व्यय परिणामों का विश्लेषण किया गया है। भाग III में घाटे के प्रमुख संकेतक और उनके वित्तपोषण के संदर्भ में परिणामों से संबंधित वर्णन किया है। भाग IV में केंद्र और राज्य सरकारों के बाजार उधार शामिल किए गए हैं। भाग V में वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए सामान्य सरकार के वित्त पर अनुमान के साथ-साथ वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही के लिए पूर्वानुमानों को प्रस्तुत किया है। भाग VI में निष्कर्ष दिया गया है तथा निकटवर्ती राजकोषीय परिदृश्य दिया गया है।

II. तिमाही परिणाम : 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही

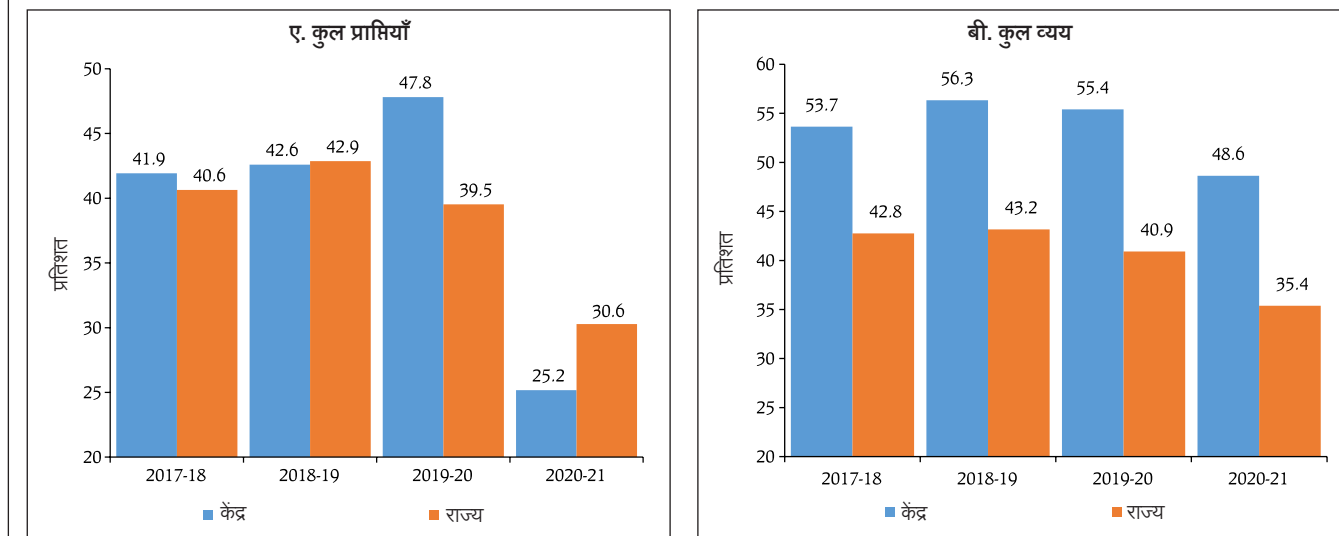
केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक आम तौर पर वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में जुटाया जाता है, जबकि इसी अवधि के दौरान कुल व्यय का लगभग 55 प्रतिशत खर्च होता है। इस पैटर्न से हटकर 2020-21 की पहली छमाही में बजट किए गए कुल प्राप्तियों के केवल 25.2 प्रतिशत प्राप्त किया जा सका, जबकि वर्ष के लिए बजट किए गए व्यय में से पहली छमाही

में आधे से भी कम व्यय किया जा सका। 2020-21 की पहली छमाही में, राज्य¹ अपनी बजट प्राप्तियों का केवल 30.6 प्रतिशत ही जुटा सके और पहली छमाही में उनका व्यय भी प्रत्येक वार्षिक प्राप्ति तथा व्यय के 40 प्रतिशत के सामान्य पैटर्न की तुलना में कम दिखाई दिया। (चार्ट 1)।

ए. प्राप्तियां

2020-21 की पहली तिमाही में महामारी से प्रेरित तालाबंदी के कारण केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां बुरी तरह से प्रभावित हुईं; इस अवधि के दौरान 47.3 प्रतिशत संकुचन दर्ज हुआ। जून 2020 के बाद से आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू होने के साथ, राजस्व प्राप्तियां आंशिक रूप से होने लगी, और 2020-21 की दूसरी तिमाही में 24.6 प्रतिशत संकुचन दर्ज किया गया। कर्ज से इतर पूंजी प्राप्तियों में भी इस अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि विनिवेश का कोई विशेष फायदा नहीं हुआ और बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से केवल ₹ 6,000 करोड़ से थोड़ी सी ही अधिक राशि जुटायी जा सकी (चार्ट 2)।

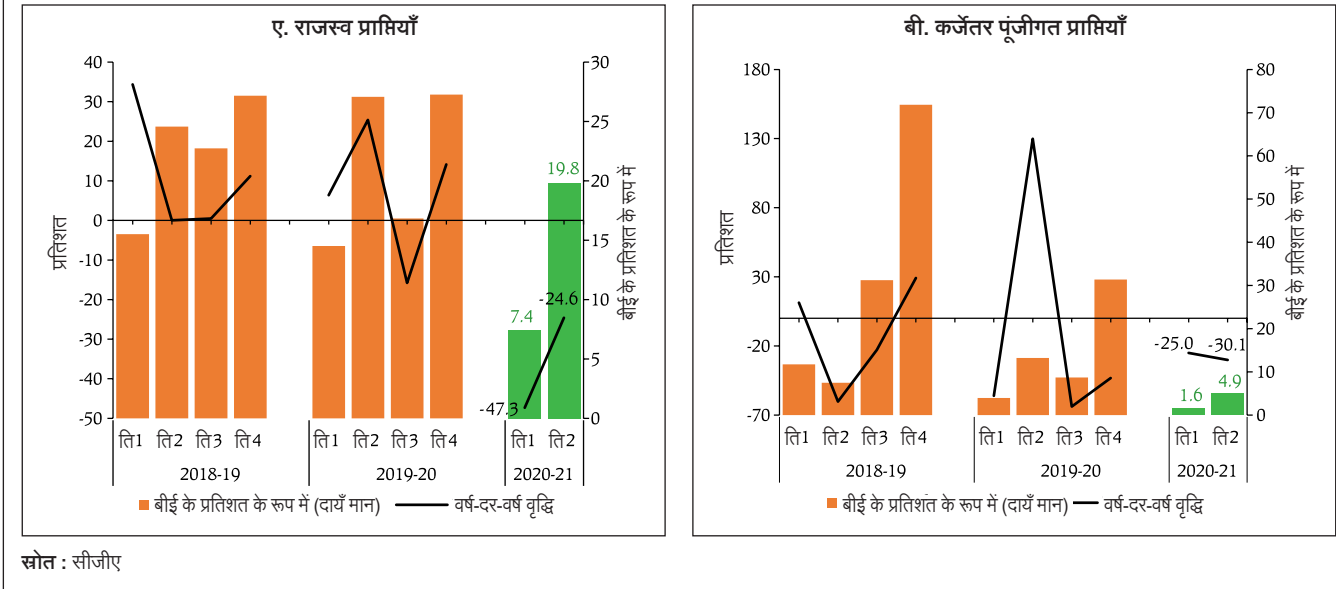
चार्ट 1 : 2020-21 की पहली छमाही के लिए कुल प्राप्तियां तथा व्यय



स्रोत: सीजीए और सीएजी

¹ 2020-21 की दूसरी तिमाही तक जिन राज्यों का ऐतिहासिक और अद्यतन डेटा उपलब्ध है ऐसे 21 राज्यों के कुल आंकड़ों के आधार पर।

चार्ट 2 : वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए केंद्र की प्राप्ति

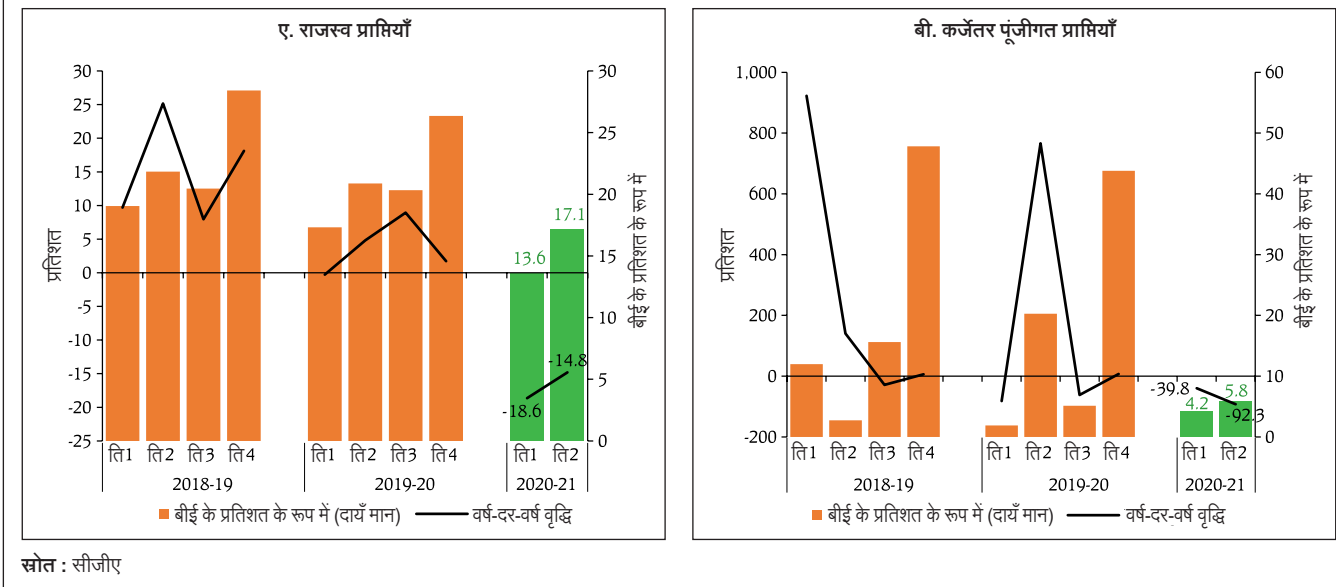


राज्यों के संबंध में भी मोटे तौर पर इसी तरह का पैटर्न देखा गया, उनकी राजस्व प्राप्ति में 2020-21 की पहली तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) 18.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई लेकिन दूसरी तिमाही में संकुचन कम हुआ। राज्यों की कर्ज से इतर पूंजी रसीदें, जो काफी अस्थिर होती हैं, में भी 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में संकुचन देखा गया, परिणामस्वरूप कर्ज से इतर पूंजी प्राप्ति (बीई के प्रतिशत के रूप में) 2020-21

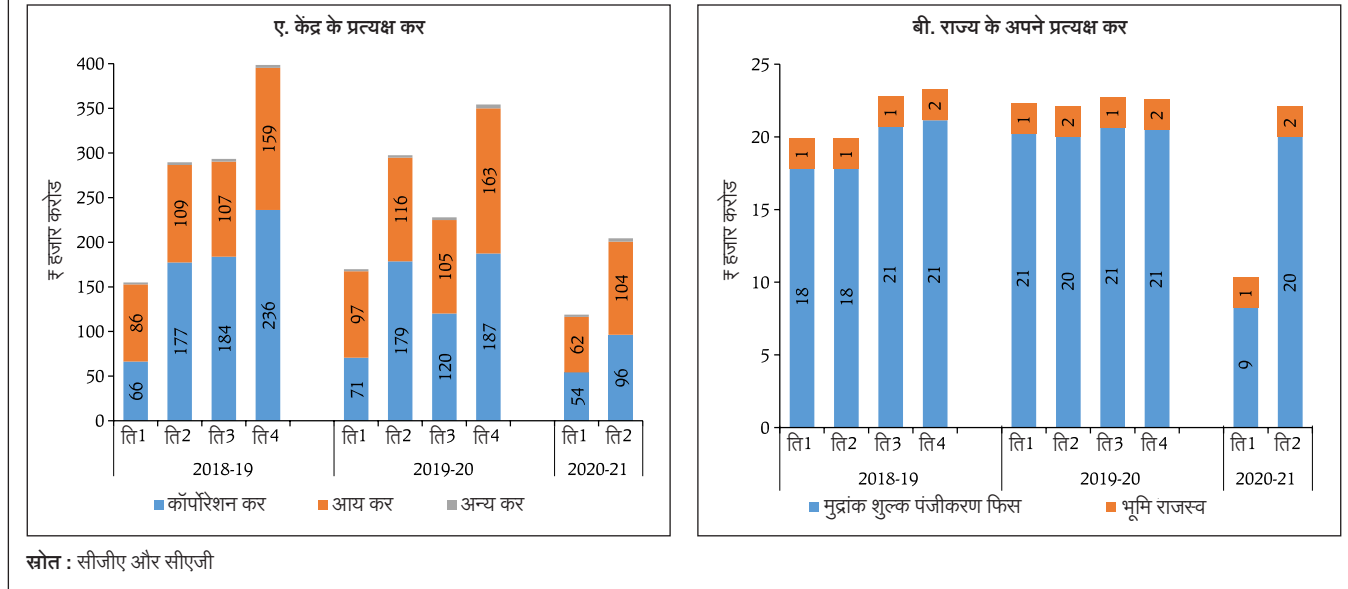
की पहली छमाही में पूर्ववर्ती दो वर्षों के औसत से कम रही (चार्ट 3)।

आर्थिक गतिविधि में चक्रीय संकुचन और कर दाखिल करने के लिए विभिन्न छूटों से संबंधित सरकार के विवेकाधीन नीतिगत कार्यों के कारण केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रहण, आयकर और निगम दोनों कर में 2020-21 की पहली छमाही के दौरान बड़ी गिरावट आई। केंद्र सरकार के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, इन

चार्ट 3 : वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए राज्यों की प्राप्ति



चार्ट 4 : वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में प्रत्यक्ष कर



संभव है कि दोनों² ने वृद्धि को प्रति चक्रीय समर्थन प्रदान किया हो। राज्यों के लिए, प्रत्यक्ष कर राजस्व में 85 प्रतिशत से अधिक स्टांप शुल्क का हिस्सा हैं तथा निर्माण गतिविधि में संकुचन के कारण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2020-21 की पहली तिमाही में इसमें 57.2 प्रतिशत की तेज गिरावट देखी गई। अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे फिर से बहाल होने के साथ 2020-21 की दूसरी तिमाही में स्टांप शुल्क संग्रहण में तेजी आई, जिससे केवल 1 प्रतिशत से कम वर्ष-दर-वर्ष संकुचन दर्ज किया गया (चार्ट 4)।

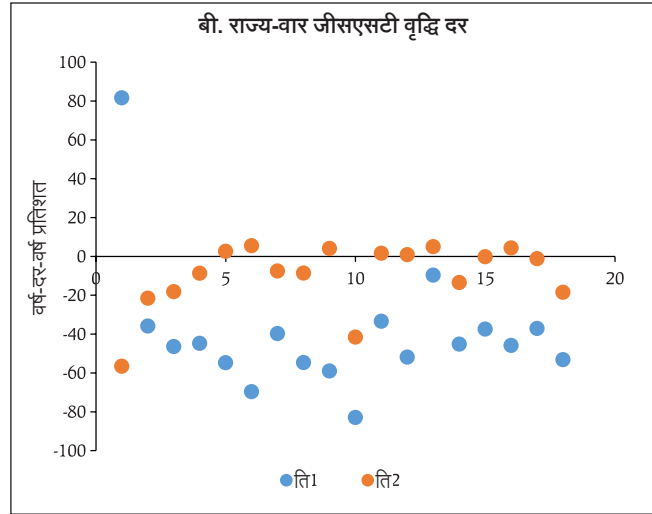
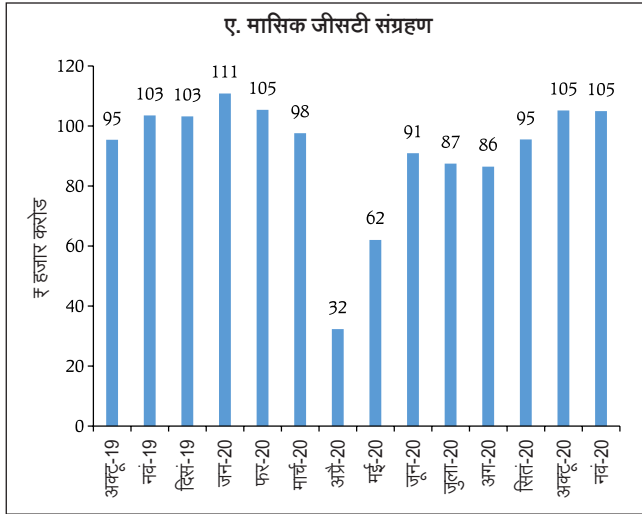
अवधि के दौरान केंद्र के अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में भी संकुचन पाया गया, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के खुलने के बाद वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व की वसूली में बढ़ोतरी तथा संघ उत्पाद शुल्क के संग्रहण में वृद्धि की पृष्ठभूमि में प्रत्यक्ष करों की तुलना में वह कम था। लॉकडाउन के कारण 2020-21 की पहली तिमाही में जीएसटी संग्रहण (केंद्र और राज्य दोनों) गंभीर रूप से बाधित हुआ, लेकिन जून-नवंबर 2020 के दौरान तेजी से बरामद भी हुआ, क्योंकि उपभोग खर्च पुनर्जीवित हुआ, मांग में वृद्धि हुई और उत्सव के कारण खर्चों में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में बीई के 31.6 प्रतिशत जीएसटी मुआवजा उपकर जुटाया गया, हालांकि, राज्यों की जीएसटी

मुआवजे की आवश्यकता पूरी करने के लिए यह अपर्याप्त था। तदनुसार, केंद्र सरकार ने एक विशेष विंडो का संचालन किया है, जिसके तहत भारत सरकार (जीओआई) जीएसटी उपकर संग्रहण में ₹1.1 लाख करोड़ (यह मानकर चलते हुए कि इसमें सभी राज्य शामिल होंगे) की अनुमानित कमी का उचित किशतों में उधार लेगा, जिसे जीएसटी मुआवजा उपकर रिलीज के रूप में बैंक-टू-बैंक ऋण के बदले में राज्यों को दिया जाएगा (चार्ट 5)। अब तक, सभी राज्यों और विधान सभा वाले सभी 3 संघ शासित प्रदेशों ने इस विकल्प को चुना है। भारत सरकार ने पहले ही राज्यों की ओर से ₹ 36,000 करोड़ की राशि उधार ली है और इसे उन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दिया है जिन्होंने इस विकल्प को चुना था (9 दिसंबर 2020 तक)।

इस अप्रत्याशित समय में कुछ अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए, केंद्र ने मार्च-मई 2020 के दौरान दो बार पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ाया, परिणामस्वरूप 2020-21 की पहली छमाही में युनियन उत्पाद शुल्क संग्रहण में 34.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 22 राज्यों / संघशासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल शुल्क में ₹ 1 से 5 रुपये की बढ़ोतरी की है, जबकि 25 राज्यों / संघशासित प्रदेशों में

² सामान्य समय के दौरान प्रत्यक्ष कर प्रत्यास्थता 1 (2 के करीब) से अधिक होने और विभिन्न कारणों से इस तरह की अप्रत्याशित मंदी के दौरान बढ़ने की संभावना है (आईएमएफ 2020 बी; मिश्रा और त्रिवेदी, 2016) ; करों में गिरावट आय में गिरावट की तुलना में अनुपातिक रूप से अधिक हो सकती है, डिस्पोजेबल आय को बढ़ाने का वृद्धि पर वास्तविक प्रभाव टैक्स मल्टीप्लायर और अन्य आपूर्ति पक्ष बाधाओं के आकार पर निर्भर करेगा।

चार्ट 5 : जीएसटी प्रदर्शन

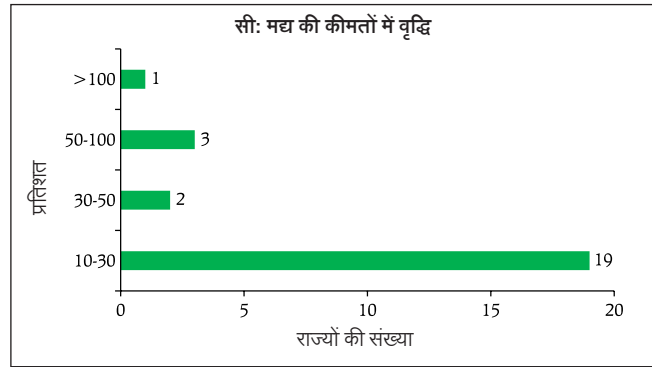
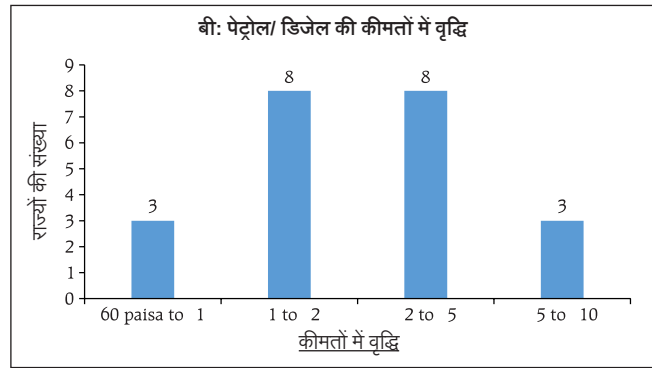
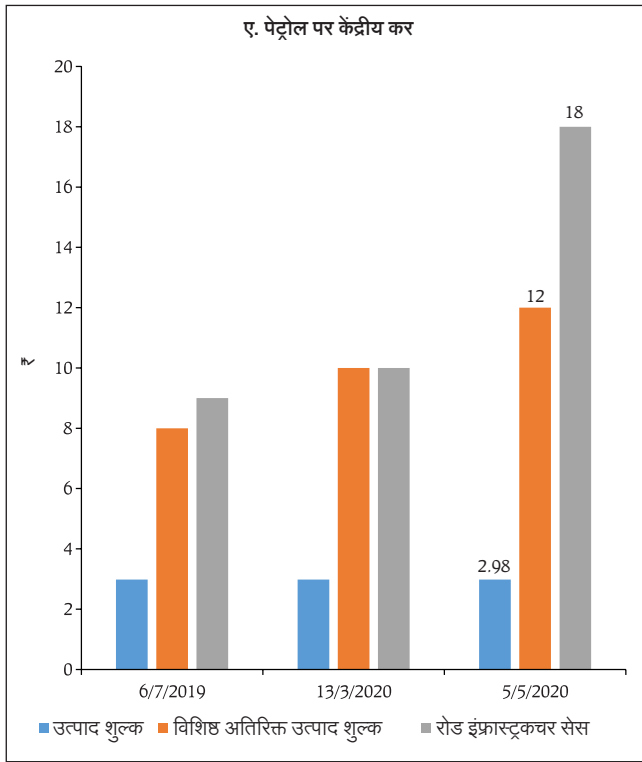


टिप्पणी: जीएसटी के आंकड़े उन राज्यों के हैं जिन्होंने ये आंकड़े रिपोर्ट किए हैं।
 स्रोत: पीआईबी; ई-स्टेट्स डेटाबेस

शराब पर औसतन 10-30 प्रतिशत तक शुल्क में बढ़ोतरी की है। हालांकि मंदी के दौरान शुल्क बढ़ोतरी को प्रचक्रिय माना जा सकता है, लेकिन संभव है कि इन वस्तुओं की कीमतों के

मूल्यनिरपेक्ष स्वरूप ने इसे राजस्व वृद्धि के लिए एक उपयोगी साधन बना दिया है, भले ही शुरू में लॉकडाउन अवधि के दौरान खपत में गिरावट आई (चार्ट 6)।

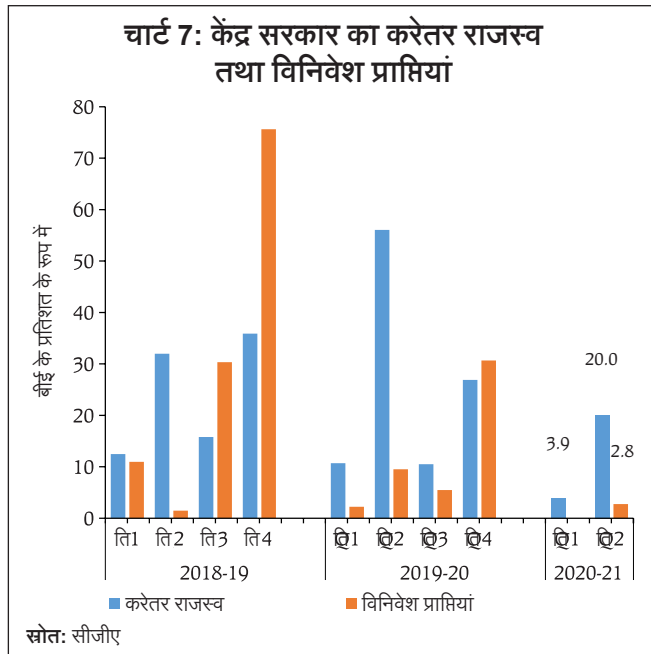
चार्ट 6: उत्पाद शुल्क में वृद्धि



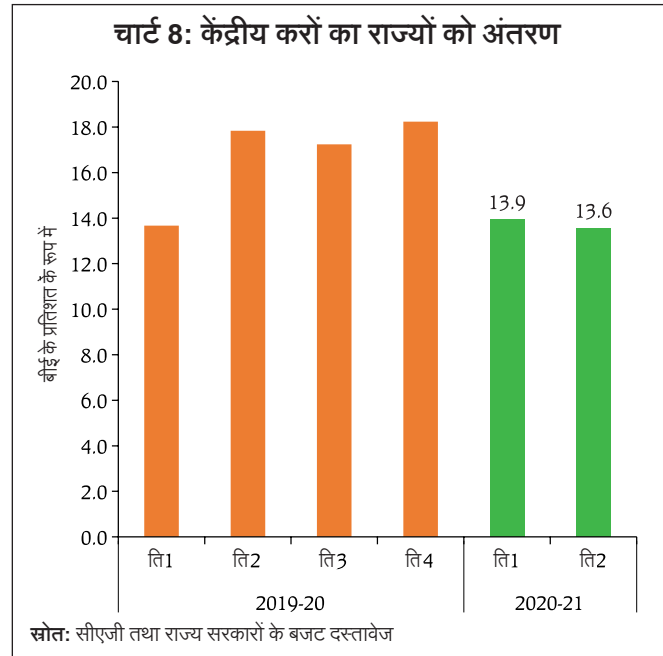
स्रोत: ई-स्टेट्स डेटाबेस; सीबीआईसी तथा राज्य सरकार

कराधान के अलावा, केंद्र अपने राजस्व के लिए गैर-कर स्रोतों पर भी काफी निर्भर रहता है, जिसने 2020-21 की पहली छमाही में, मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम बिक्री से बजट किए गए राजस्व में कमी के कारण भारी गिरावट आई। कर्ज से इतर पूंजी प्राप्तियों के संबंध में, 2020-21 के लिए सरकार द्वारा ₹2.1 लाख करोड़ बजट किया गया विनिवेश लक्ष्य संकट के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका, जबकि वर्तमान में शेयर बाजारों में उछाल देखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने हाल ही में विनिवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें आस्ति मुद्रीकरण के लिए सलाहकार सेवाएं हेतु विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसके परिणाम अगले वित्तीय वर्ष से पहले मिलने की संभावना नहीं है (चार्ट 7)।

पहली तिमाही में राज्यों को केंद्रीय कर अंतरणों में कोई पर्याप्त गिरावट नहीं देखी गई थी - ज्यादातर बजट अनुमानों के अनुसार अंतरण किए गए हैं, 2020-21 की दूसरी तिमाही में बड़ी गिरावट हुई: (चार्ट 8), संभवतः पहली तिमाही में केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रहण में कमी दर्शाता है, जो विभाज्य पूल³ का एक हिस्सा है (यह एक तिमाही अंतराल में राज्यों की प्राप्तियों में परिलक्षित होता है)।



³ विभाज्य पूल सकल कर राजस्व का वह हिस्सा है जो केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। इसमें विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिभार और उपकर, निवल संग्रहण शुल्क को छोड़कर सभी कर शामिल हैं।



बी. व्यय

केंद्र सरकार ने कोविड-19 संकट के बाद कई उपायों के लिए खर्च किया, शुरुआत में गरीब और कमजोर वर्गों को लक्षित नकदी अंतरण के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक सहायता, मुफ्त खाद्यान्न वितरण, स्वास्थ्य कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा, आदि तथा इसके बाद आर्थिक बहाली को प्रोत्साहित करने के लिए आत्म निर्भर भारत पैकेज के विभिन्न भागों में अधिक व्यापक उपाय किए गए। प्रोत्साहन का स्वरूप और मात्रा के साथ-साथ, खपत से तरलता, तरलता से निवेश में सावधानीपूर्वक अपने फोकस में परिवर्तन करना यह दर्शाता है कि यह निवेश पुनरुत्थान चैनल के माध्यम वृद्धि दे रहा है जिसका अधिक प्रभाव वर्ष की दूसरी छमाही में प्राप्त होना अपेक्षित है (बॉक्स I)।

अतिरिक्त आवश्यक व्यय की पूर्ति, अन्य व्यय शीर्षों के अंतर्गत राशि को पुनः आबंटित कर पूरा की गयी है। सरकार ने 2020-21 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही में परिहार्य व्यय के स्थान पर प्राथमिकता क्षेत्रों में खर्च करने के लिए व्यय के युक्तिसंगत उपाय (विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के इन

बॉक्स I – राजकोषीय प्रोत्साहन का वृद्धि पर प्रभाव

महामारी से उत्पन्न अप्रत्याशित आघात के जवाब में, दुनिया भर की सरकारों ने बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया है। भारत में, सरकार ने राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक नपा-तुला दृष्टिकोण लिया है जिसमें प्रारंभिक चरण में गरीबों को सामाजिक सहायता शामिल थी जिसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (सारणी.1 और परिशिष्ट सारणी 7) में समर्थन प्रदान करने के लिए एक व्यापक पैकेज (आत्म निर्भर भारत) के साथ दिया गया था। विचाराधीन व्यय उपायों तथा उसके तदनुसूची गुणक के आकार की मात्रा और संरचना के आधार पर वृद्धि पर राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। इस प्रयोजन से, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) और आत्म निर्भर 1.0, 2.0 और 3.0 के तहत प्रदान किए गए प्रत्येक प्रोत्साहन उपायों की जीडीपी के तदनुसूची मांग-पक्ष घटकों- सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई), निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)- के साथ अलग-अलग मैपिंग की जाती है। इसके बाद वृद्धि पर हुए असर को देखने के लिए संबंधित राजकोषीय गुणकों पर परस्पर प्रभाव को देखा गया है क्योंकि व्यय का स्वरूप आम तौर पर आर्थिक विकास पर किसी भी राजकोषीय प्रोत्साहन के प्रभाव को निर्धारित करता है।

राजकोषीय गुणक, जो राजकोषीय चर (अर्थात्, सरकारी व्यय / कराधान या दोनों) में एक बहिर्जात परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, उत्पादन पर विवेकाधीन राजकोषीय नीति के तत्काल प्रभाव को मापता है। राजकोषीय गुणकों के सही आकार के बारे में सार्थक अनिश्चितता होते हुए भी गुणक दृष्टिगोचर नहीं होने के कारण, उन्हें अनुमानित मापदंडों द्वारा नापा जाता है। अनुभवजन्य अनुमान बताते हैं कि राजकोषीय गुणक व्यापार चक्र की स्थिति और दूसरों (आईएमएफ, 2020 ए) के बीच मौद्रिक नीति के रुख के आधार पर

समय के साथ बदलते हैं।

भारतीय संदर्भ में, इस बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार से संबंधित राजस्व व्यय गुणक उनके यूनिटी से कम होते हैं। जब राजस्व व्यय में एक रुपये की वृद्धि होती है, तब जीएफसीई में एक रुपये की वृद्धि होती है, जबकि पूंजीगत व्यय अक्सर कम हो जाता है जिससे उत्पादन में कुछ वांछित वृद्धि का समंजन होता है और अतः अवधि टी में उत्पादन में केवल 45 पैसे की वृद्धि होती है और अवधि टी + 1 में लगभग 10 पैसे की वृद्धि होती है। इसके विपरीत, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पूंजीगत व्यय गुणक उनके योग से काफी ऊपर है - केंद्र सरकार के लिए, यह अवधि टी में 2.45 और अवधि टी + 1 में 3.14 है, जबकि राज्य सरकारों के लिए यह 2 (आरबीआई, 2019) के करीब है। यह इस बात को दर्शाता है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय में प्रति एक रुपये की वृद्धि निजी निवेश का अंतर्गमन करती है, अर्थव्यवस्था में निवेश में आनुपातिक वृद्धि से अधिक वृद्धि लाती है जिसके लाभ कुछ वर्ष तक उपचित होते हैं। इन गुणकों का उपयोग करते हुए और अब तक घोषित राजकोषीय प्रोत्साहन के उपायों के आधार पर, यह अनुमान है कि सरकारी व्यय द्वारा वृद्धि में वर्ष 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 159 बीपीएस और 158 बीपीएस को जोड़ा जाएगा। यहां पर यह फिर से संभव है कि सरकार के प्रोत्साहन उपायों का प्रभाव वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में मुख्य रूप से निवेश पुनरुत्थान चैनल के माध्यम से दिखाई देगा (चार्ट I.1)।

अनुभवजन्य अनुमान बताते हैं कि सार्वजनिक निवेश अत्यधिक अनिश्चितता, जो वर्तमान संकट की एक प्रमुख विशेषता है, के दौरान जीडीपी विकास और रोजगार पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है (रेचल और समर्स, 2019; एगर्ट्सन और अन्य, 2019)। भारत में भी, यह निवेश वृद्धि है जिसने 2000 के दशक में पुनरुत्थान चरण के दौरान, विशेष रूप से 2001 के मध्य से 2003 के दौरान और फिर से वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) की अवधि के तुरंत बाद खपत की तुलना में बड़ी भूमिका निभाई है (चार्ट II.2ए)। इस प्रयोजन के लिए निवेश पुनरुत्थान पर सरकार द्वारा दिया गया ध्यान समय पर उठाया गया कदम है, हालांकि कुल जीएफसीएफ पर सामान्य सरकार निवेश (पीएसई सहित) की हिस्सेदारी लगभग 24 प्रतिशत रही है (चार्ट II.2 बी)।

वृद्धि पर प्रोत्साहन के इन अनुमानित प्रभावों के साथ सकारात्मक तथा नकारात्मक, दोनों तरफ, कुछ अनिश्चितताएं भी जुड़ी हैं। पहला, यह देखते हुए कि उपयोग किए गए गुणकों की गणना सामान्य समय के लिए की गयी है, वर्तमान महामारी की स्थिति में वास्तविक प्रभाव

(जारी....)

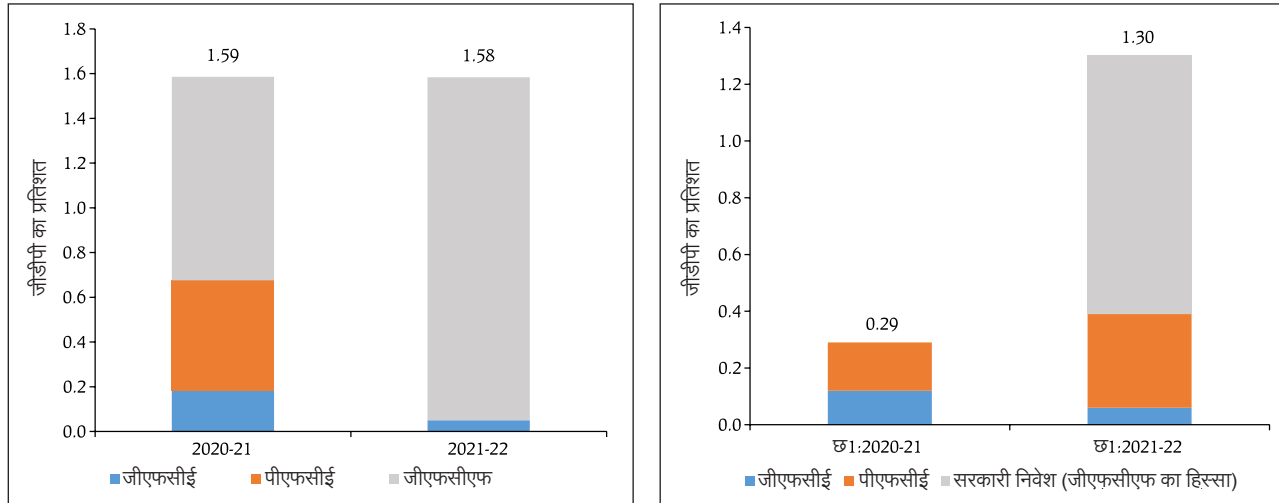
सारणी I.1: घोषित प्रोत्साहन उपायों का सारांश (30 नवंबर 2020)

क्रम सं.	मद	₹ करोड़
1.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) +	1,92,800
2.	आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0	11,02,650
3.	पीएमजीकेपी अन्न योजना – नवंबर तक बढ़ायी गयी	82,911
4.	आत्म निर्भर भारत अभियान	73,000
5.	आत्मनिर्भर भारत अभियान	2,65,080
6.	31 अक्टूबर 2020 तक आरबीआई द्वारा घोषित उपाय	12,71,200
कुल		29,87,641

स्रोत: प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) इंडिया

⁴ जीएफसीई में अंतर्गत भुगतान को छोड़कर केंद्र सरकार के सभी राजस्व व्यय शामिल हैं (यानी सब्सिडी), जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) महिलाओं / वरिष्ठ नागरिकों और खाद्य सब्सिडी, जो पीएफसीई में शामिल हैं।

चार्ट I.1: जीडीपी पर प्रोत्साहन का प्रभाव

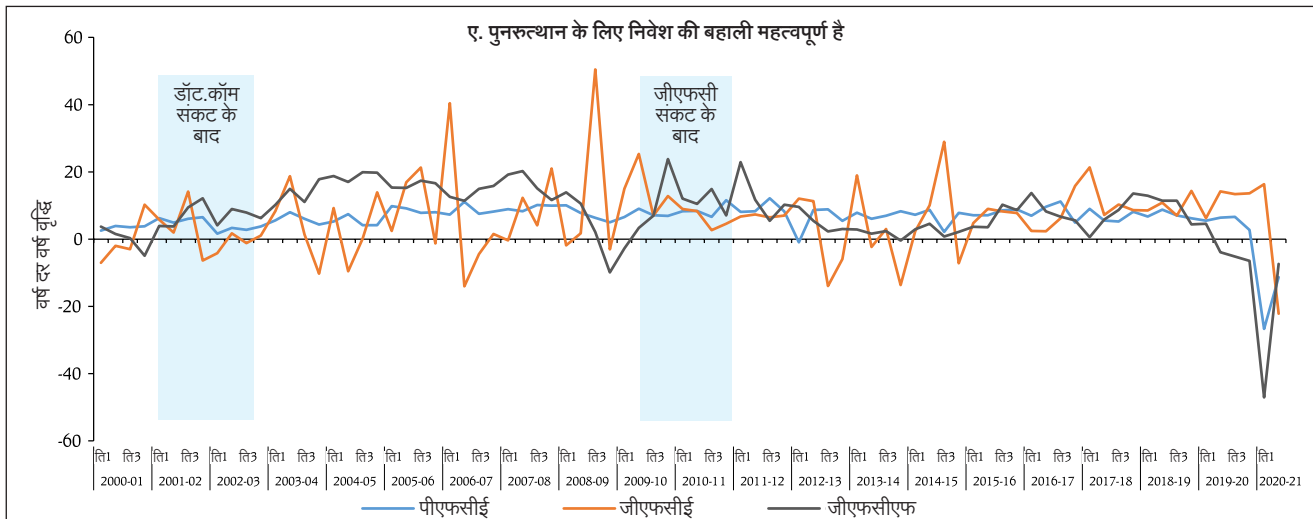


स्रोत: आरबीआई स्टाफ प्राकलन

भिन्न हो सकते हैं। जबकि अब यह पाया गया है आर्थिक मंदी और मौद्रिक नीति का अत्यधिक उदार रुख यह दर्शाता है कि गुणक अपेक्षाकृत अधिक हो सकते हैं, महामारी से संबंधित आपूर्ति की

कमी ने हो सकता है कि विपरीत दिशा में योगदान दिया है (आईएमएफ, 2020ए)। दूसरा, केंद्र द्वारा दिया गया गारंटी समर्थित चलनिधि समर्थन, जो कि वास्तव में आपूर्ति-पक्ष समर्थन प्रदान

चार्ट II.2: निवेश का स्वरूप और हिस्सा



टिप्पणी: 1 वर्ष 2000-01 से 2005-06 की वृद्धि दर की गणना 1999-00 के आधार जीडीपी श्रृंखला के आधार पर की गयी है। वर्ष 2006-07 से 2011-12 की वृद्धि दर की गणना 2004-05 के आधार जीडीपी श्रृंखला के आधार पर की गयी है। वर्ष 2012-13 से आगे 2011-12 आधार जीडीपी श्रृंखला के आधार पर की गयी है।

स्रोत: नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) तथा आरबीआई स्टाफ प्राकलन

बी. सामान्य सरकार (पीएसई सहित) कैपेक्स

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 E
कुल जीएफसीएफ में हिस्सा	20.5	22.1	23.0	25.7	24.3	23.4	23.7	23.5
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.1	9.2	6.9	19.0	2.9	3.1	11.2	-3.7

ई: प्राकलित

(जारी....)

⁵ वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान राजकोषीय गुणकों को कम आंकने का वृद्धि पूर्वानुमान त्रुटियों में इसका महत्वपूर्ण योगदान प्रतीत हो रहा है (ब्लॉगार्ड और लेह, 2013)।

करने वाले लाभ निकालने के बाद के उपाय हैं, मांग-पक्ष उपायों के अतिरिक्त विशेष रूप से कुछ बुरी तरह से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों को एक सकारात्मक गति भी प्रदान करेंगे। तीसरा, एक दृष्टिकोण यह भी है कि आर्थिक सहायता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से निजी खपत में संभावित वृद्धि, लगाए गए उच्च अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्रतिसंतुलित की जा सकती है, हालांकि वास्तविक प्रभाव विभेदक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। चौथा, जैसा कि पिछली घटनाओं के दौरान देखा गया था, राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय (केपैक्स) में कोई भी संभावित कटौती, प्रोत्साहन विस्तार के प्रभाव को भी कम कर सकती है।

संदर्भ:

Baker, S., R. A. Farrokhnia, M. Pagel, S. Meyer, and C. Yannelis. 2020. "Income, Liquidity, and the Consumption

Response to the COVID-19 Pandemic and Economic Stimulus Payments." VoxEU (blog), Centre for Economic Policy Research, June 17.

Eggertsson, G. B., N. R. Mehrotra, and J. A. Robbins. 2019. "A Model of Secular Stagnation: Theory and Quantitative Evaluation." *American Economic Journal: Macroeconomics* 11 (1): 1-48

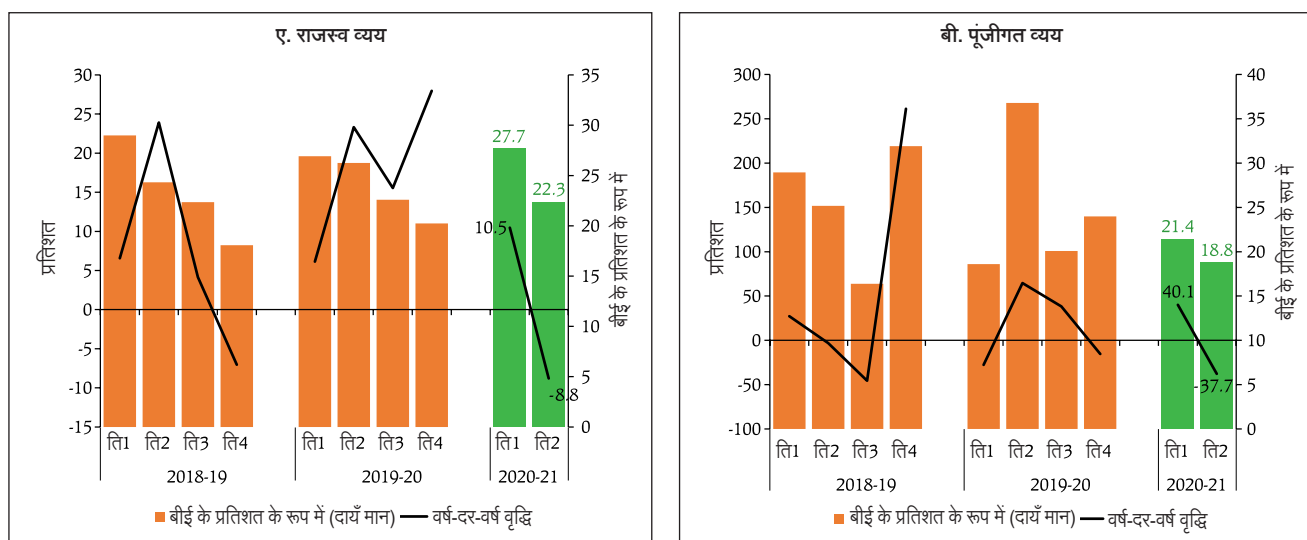
IMF Fiscal Monitor. 2020a, International Monetary Fund, October.

Rachel, L., and L. H. Summers. 2019. "On Falling Neutral Real Rates, Fiscal Policy, and the Risk of Secular Stagnation." *Brookings Papers on Economic Activity* (Spring): 1-76.

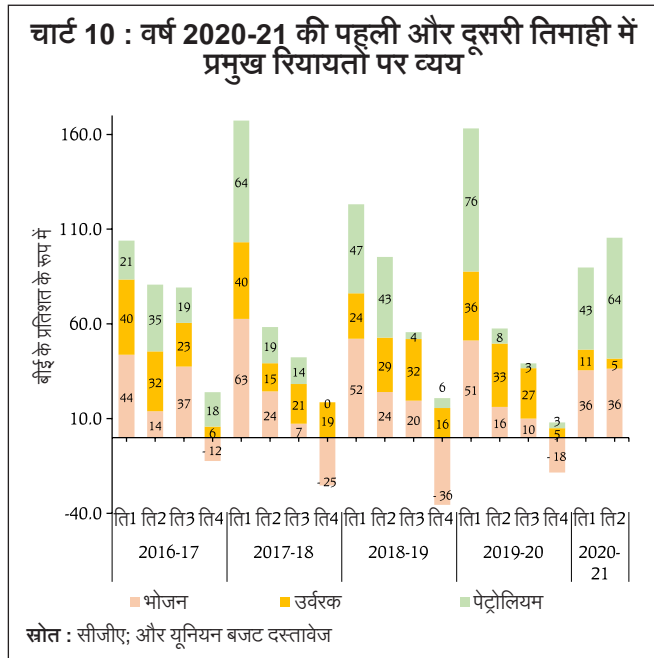
खर्चों में अब ढील दी गई है)⁶ किए। परिणामस्वरूप, 2020-21 की पहली छमाही में महामारी संबंधी विस्तारक उपायों के बावजूद कुल व्यय बीई के 48.6 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 53.4 प्रतिशत था। निरपेक्ष रूप से, 2020-21 की पहली छमाही में राजस्व व्यय लगभग पिछले वर्ष के स्तर पर था, प्राप्तियों में गिरावट के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में 1.0 प्रतिशत

की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, पहली तिमाही में तेज पिकअप दर्ज करना तथा इसकी फ्रंट-लोडिंग महामारी से संबंधित राजस्व व्यय को दर्शाता है और दूसरी तिमाही में तेज गिरावट देखी गई है। दूसरी ओर, पहली तिमाही में लॉकडाउन तथा दूसरी तिमाही में वर्षा के कारण 2020-21 की पहली छमाही में पूंजीगत व्यय 11.6 प्रतिशत संकुचित हुआ है (चार्ट 9)।

चार्ट 9 : वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में केंद्र का व्यय



⁶ कार्यालय ज्ञापन: वित्त वर्ष 2020-21, की शेष अवधि के लिए नकदी प्रबंधन दिशानिर्देश 29 अक्टूबर 2020.



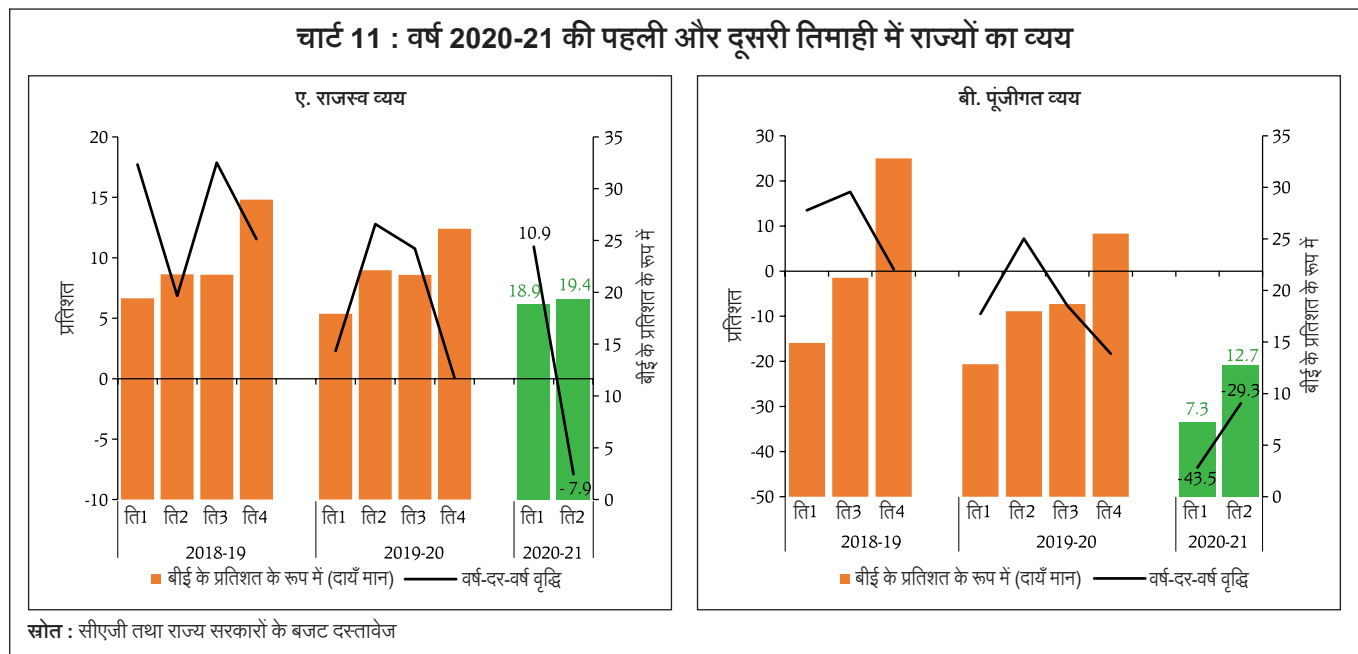
केंद्र सरकार का अनुदान भुगतान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2020-21 की पहली तिमाही में कम था लेकिन 2019-20 की दूसरी तिमाही में उच्च खाद्य और पेट्रोलियम अनुदान (बीई के प्रतिशत के रूप में) के कारण 2020-21 की दूसरी तिमाही में अधिक रहा है (चार्ट 10)।

2020-21 की पहली छमाही में राज्यों के राजस्व व्यय में भी पिछले वर्षों की तुलना में कोई तेज वृद्धि नहीं देखी गई है, इस

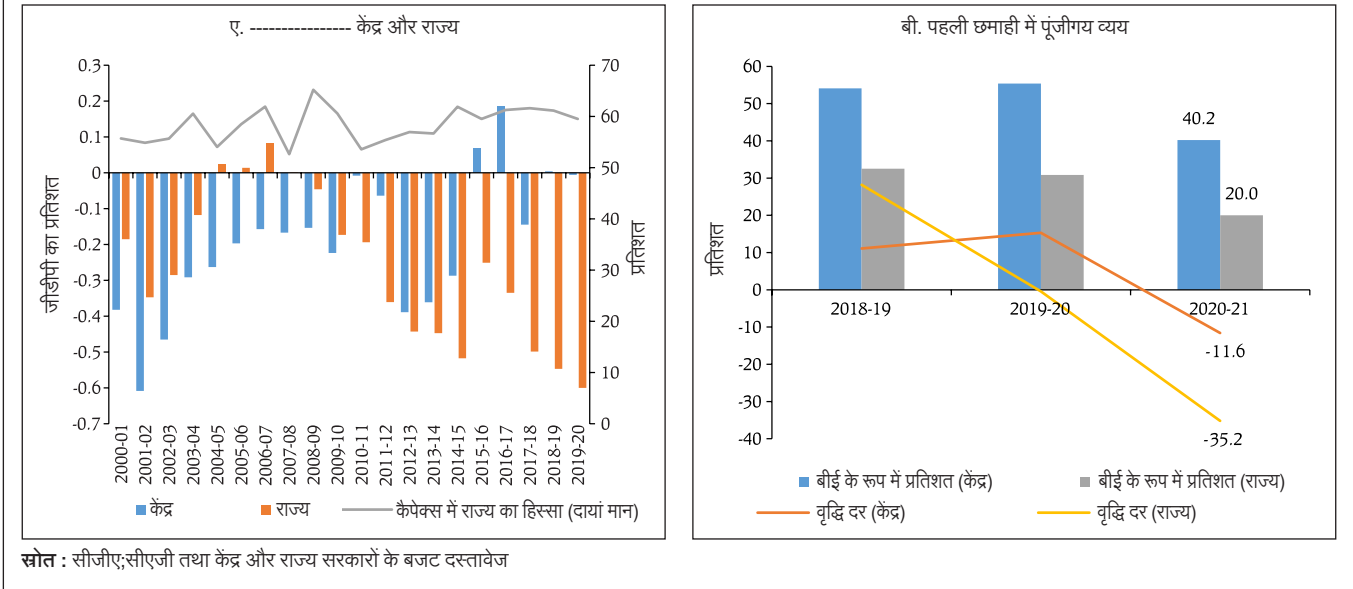
तथ्य के बावजूद कि महामारी का मुकाबला करने में राज्य सबसे आगे रहे हैं, मुख्य रूप से महंगाई भत्ता (डीए) फ्रीज, पूर्ण वेतन के भाग का स्थगन, यात्रा और वाहन खर्चों को युक्तिसंगत करना (आरबीआई, 2020) जैसे तरीकों से खर्च को पुनः प्राथमिकता देने को, इसका श्रेय दिया जा सकता है। दूसरी तिमाही से पहली तिमाही तक सभी तिमाहियों में राजस्व व्यय में एक बदलाव हुआ है। पूंजीगत व्यय के संबंध में 2020-21 की पहली तिमाही में तेज गिरावट देखी गयी, जो कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2020-21 की दूसरी तिमाही में थोड़ी कम हुई। पिछले दो वर्षों की तुलना में 2020-21 की पहली छमाही में राज्य सरकारों का पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों से काफी कम अनुपात में है (चार्ट 11)।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण से पूंजीगत व्यय को देखने से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में संघ और राज्यों ने क्रमशः 17 और 16 वर्षों में कैपेक्स कटौती का सहारा लिया है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र ने व्यापक रूप से अपने कैपेक्स की तुलना में बीई को बनाए रखा है, विशेष रूप से राज्यों के लिए कटौती की गई है (चार्ट 12 ए)।

केंद्र सरकार द्वारा आत्म निर्भर भारत 2.0 और 3.0 के तहत कई मंत्रालयों के लिए घोषित कैपेक्स की वृद्धि के साथ, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजीगत व्यय की भी समीक्षा की जा रही है और उनसे इस वित्तीय वर्ष की तीसरी



चार्ट 12 : केंद्र और राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय का स्वरूप



तिमाही तक उनके पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। हालाँकि, यह संकेत है कि राज्य, जो 2 से अधिक राजकोषीय गुणक के साथ सामान्य सरकार कैपेक्स का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है, 2020-21 में कैपेक्स कटौती का सहारा ले सकता है, जो निवेश के पुनर्प्रवर्तन और समग्र वृद्धि पर रोक लगा सकता है। (चार्ट 12 बी)।

राजकोषीय संतुलन के अनुपात में सामान्य सरकार के पूंजीगत व्यय की तुलना, कैपेक्स के लिए दिए जा रहे वित्तपोषण के लिए बाहरी उधार का कितना हिस्सा जा रहा है यह संकेत देता है, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं यह दर्शाती है कि भारत का यह अनुपात उसके कई साथियों से कम है (चार्ट 13)।

III. राजकोषीय घाटा और उसका वित्तपोषण

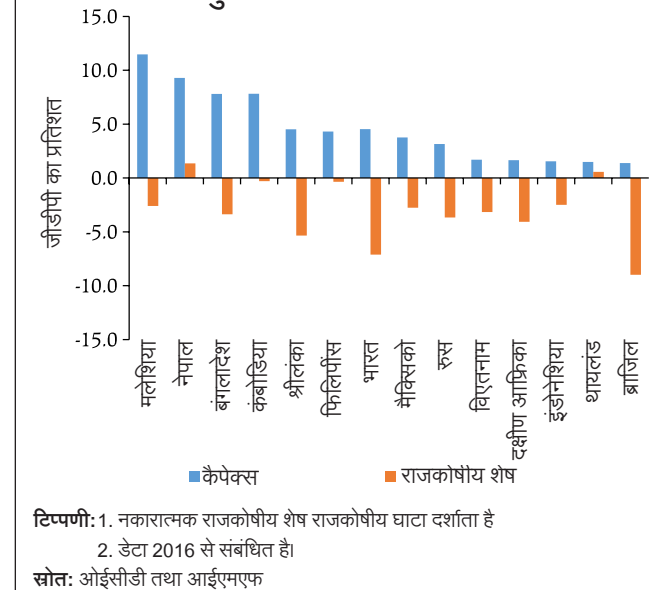
ए. राजकोषीय घाटा

केंद्र सरकार

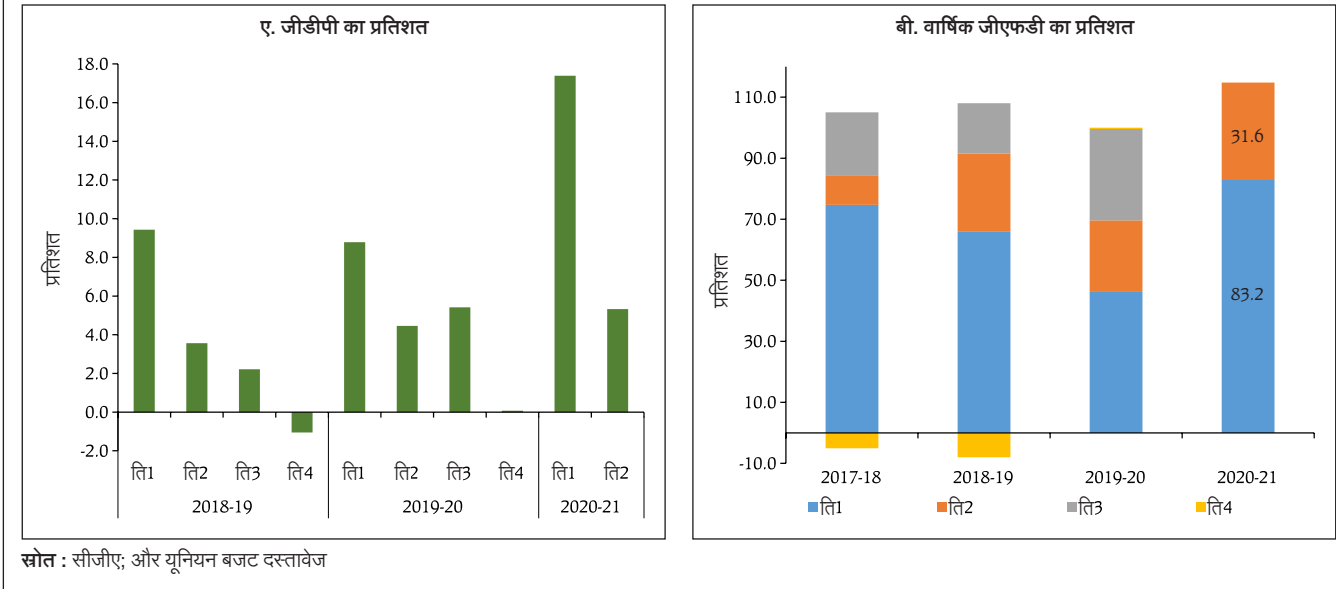
2019-20 में केंद्र सरकार जीएफडी-जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से बाहर चले जाने से, सरकार ने 2020-21 के लिए इस उद्देश्य से थोड़ेसे अधिक राजकोषीय घाटा अनुपात का बजट प्रावधान किया, कि एफआरबीएम अधिनियम के निर्धारित

लक्ष्य का पालन करते हुए वृद्धि को प्रतिचक्रिय सहायता प्रदान की जा सके। हालाँकि, यह राजकोषीय अंकगणित आर्थिक गतिविधियों में तेज संकुचन के कारण राजस्व में भारी गिरावट से बदल गया है। 2020-21 के पहली और दूसरी तिमाही में, राजकोषीय घाटा

चार्ट 13: सामान्य सरकार के कैपेक्स की तुलना में राजकोषीय शेष



चार्ट 14 : केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा



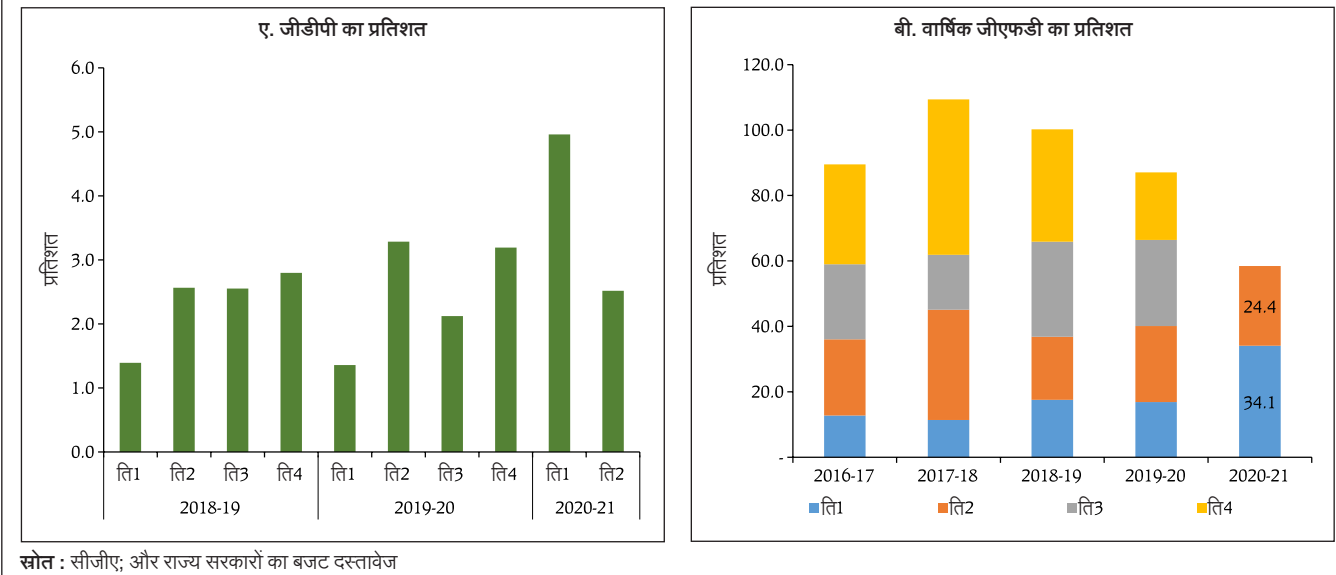
तिमाही जीडीपी के क्रमशः 17.4 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत था, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अधिक था (चार्ट 14)।

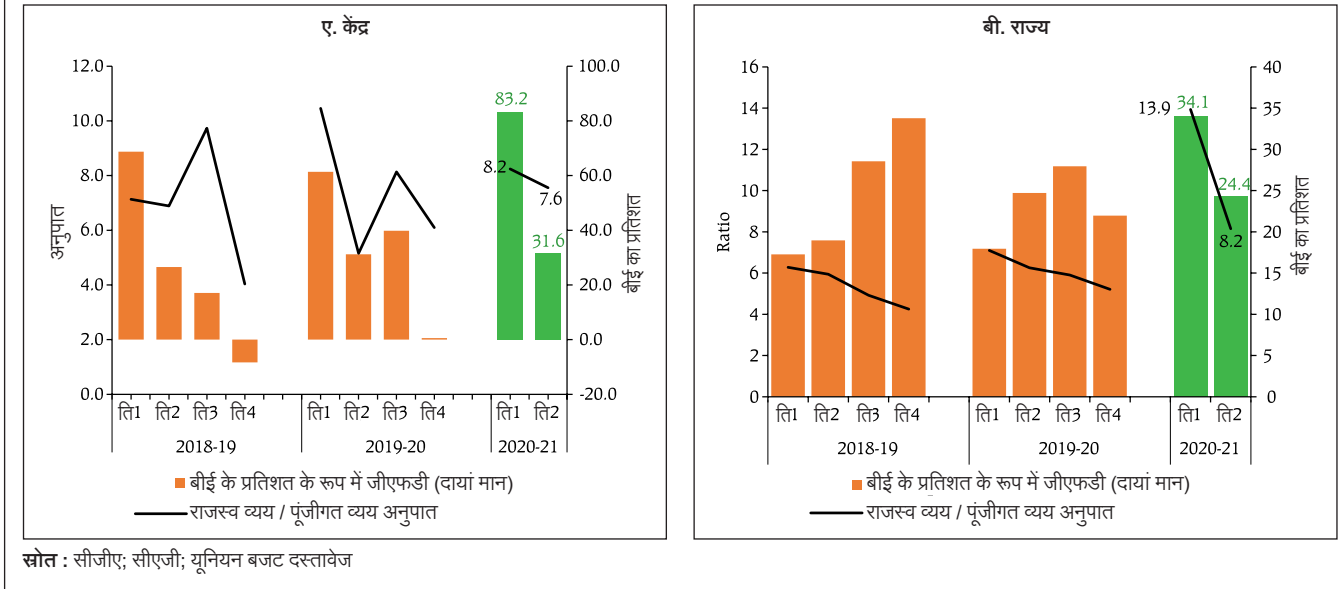
राज्य सरकारें

जबकि राज्यों ने 2020-21 के लिए जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2.8 प्रतिशत का बजट रखा है यह संख्या और अधिक होने के कगार पर है क्योंकि अधिकांश राज्यों ने कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले अपने बजट प्रस्तुत किए थे। यह

इस तथ्य से स्पष्ट है कि जिन राज्यों ने महामारी प्रकोप के बाद बजट प्रस्तुत किया है, उनका औसत जीएफडी, जीएसडीपी का 4.6 प्रतिशत है इसकी तुलना में महामारी प्रकोप से पहले बजट प्रस्तुत करने वाले राज्यों के लिए 2.4 प्रतिशत है (आरबीआई, 2020)। 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में, राज्यों का राजकोषीय घाटा तिमाही जीडीपी के क्रमशः 5.0 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत था, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अधिक है (चार्ट 15)।

चार्ट 15 : राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा



चार्ट 16 : सकल राजकोषीय घाटा और केंद्र एवं राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का स्वरूप

व्यय की गुणवत्ता के हास के साथ राजकोषीय गिरावट तथा 2020-21 की पहली छमाही में केंद्र और राज्यों के राजस्व व्यय के साथ पूंजीगत व्यय अनुपात में पिछले वर्ष की इसी अवधि के सापेक्ष वृद्धि हो रही है (चार्ट 16)। केंद्र द्वारा 2020-21 की पहली छमाही में कुल राजस्व व्यय का एक तिहाई से अधिक कृषि, ग्रामीण विकास, रक्षा और उपभोक्ता मामलों, खाद्य

और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों द्वारा खर्च किया गया (सारणी 1)।

मंत्रालय-वार, रक्षा, रेलवे, और सड़क परिवहन मंत्रालय ने अवधि के दौरान किए गए कुल पूंजी व्यय का 75 प्रतिशत से अधिक खर्च किया है (सारणी 2)।

सारणी 1: पहली छमाही में केंद्र सरकार का मंत्रालय-वार राजस्व व्यय

मद	₹ हजार करोड़			कुल राजस्व व्यय का प्रतिशत		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	3	4	5	6	7	8
रक्षा मंत्रालय	175	195	175	15.4	15.0	13.3
ग्रामीण विकास मंत्रालय	74	72	125	6.5	5.5	9.5
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	131	126	88	11.5	9.7	6.7
कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	37	56	72	3.2	4.3	5.5

स्रोत: सीजीएम

सारणी 2: पहली छमाही में केंद्र सरकार का मंत्रालय-वार पूंजीगत व्यय

मद	₹ हजार करोड़			कुल राजस्व व्यय का प्रतिशत		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	3	4	5	6	7	8
रक्षा मंत्रालय	55	67	58	33.9	35.8	34.8
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	44	45	41	27.4	24.1	24.5
रेल मंत्रालय	29	35	29	17.7	18.5	17.2
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	0	0	11	0.1	0.0	6.7

स्रोत: सीजीएम

सारणी 3 : केंद्र सरकार के सकाल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

वर्तमान कीमत पर पहली छमाही के जीडीपी का प्रतिशत

घटक	अप्रैल -सितंबर 2015-16	अप्रैल -सितंबर 2016-17	अप्रैल -सितंबर 2017-18	अप्रैल -सितंबर 2018-19	अप्रैल -सितंबर 2019-20	अप्रैल -सितंबर 2020-21
बाहरी वित्तपोषण	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.4
बाजार उधार	4.0	4.0	4.3	3.6	4.9	13.0
लघु बचत की तुलना में प्रतिभूतियां	0.0	-0.0	0.2	0.3	0.6	0.6
राष्ट्रीय लघु बचत कोष	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5	0.9
कैश बैलेंस {घट (+) / बढ़ (-)}	0.1	-0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
अधिशेष नकद का निवेश (-) / विनिवेश (+)	1.4	2.0	0.8	1.8	0.9	-3.0
अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	0.3	-	-
अन्य	-0.4	-0.7	-0.1	-0.1	-0.4	-1.3
कुल जीएफडी/ वित्त पोषण	5.7	6.1	6.1	6.5	6.6	10.7

स्रोत : सीजीए; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई); और आरबीआई

बी. राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

पिछले वर्षों की तुलना में बाजार उधारियों की अधिक हिस्सेदारी, विशेष रूप से प्राप्तियों में कमी की भरपाई करने के लिए, केंद्र के जीएफडी के वित्तपोषण पैटर्न में 2020-21 की पहली छमाही में काफी बदलाव आया है। वास्तव में, बाजार उधारियां (जीडीपी का 13.0 प्रतिशत) जीएफडी की तुलना में काफी अधिक है (जीडीपी के 10.7 प्रतिशत), जो अधिशेष नकदी शेष के रूप में उपलब्ध है और दूसरी छमाही में खर्च पूरा करने के लिए अतिरिक्त उधार की आवश्यकता को कम कर सकता है (सारणी 3)।

IV. बाजार उधारियां

2020-21 में अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त पर कोविड-19 के विनाशकारी प्रभाव के कारण केंद्र और राज्यों दोनों की बाजार उधारियां अप्रत्याशित स्तर तक बढ़ गयी है (सारणी 4)। महामारी के कारण, केंद्र का उधार कैलेंडर वित्तीय वर्ष में अब तक दो बार बढ़ाकर संशोधित किया गया है, आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मई 2020 में राज्यों को जीएसडीपी के अतिरिक्त 2 प्रतिशत (आंशिक रूप से सशर्त और आंशिक रूप से बिना शर्त) उधार सीमा बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।

राज्य स्तर पर एक विश्लेषण में 2020-21 के पूरे वर्ष के जीएफडी के प्रतिशत के रूप में 2019-20 के स्तरों की तुलना में पहली छमाही के बाजार उधारियों में सामान्य बढ़ोतरी दर्शाता है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर (कई वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं रेखा से ऊपर) सभी राज्यों में संवृद्धि दर्ज हुई है, और कुछ अपवादों के

सारणी 4 : केंद्र और राज्य सरकारों की बाजार उधारियां

(रु करोड़ में)

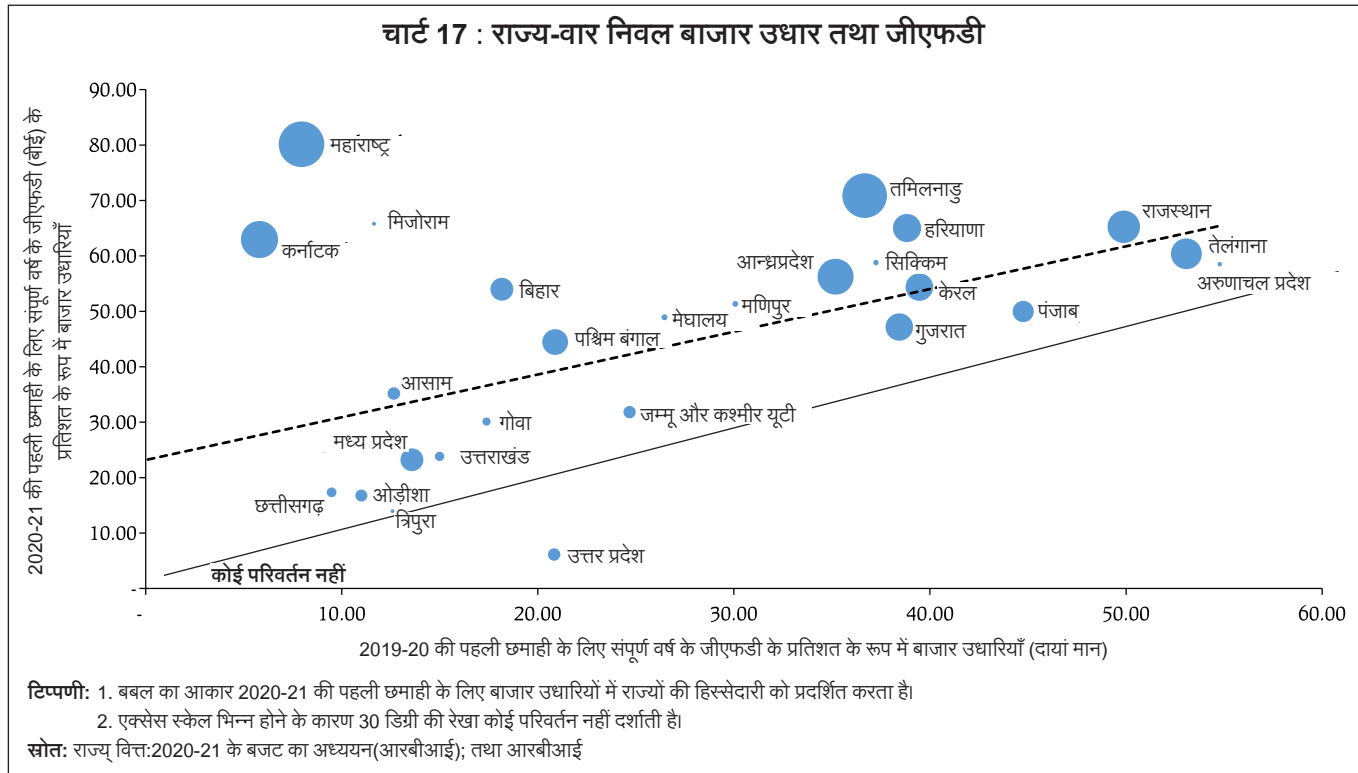
मद	2020-21 (April - November 13, 2020)	2019-20 (अप्रैल 1 से नव.15, 2020)	2020-21 छमा.1 (अप्रैल से अक्टू.2, 2020)	2019-20 छमा.1 (अप्रैल से सित 2019)
केंद्र सरकार				
सकल बाजार उधारियां	9,05,000 (116.0)	5,22,000 (73.5)	7,66,000 (98.2)	4,42,000 (62.3)
निवल बाजार उधारियां	7,74,428 (142.1)	4,20,972 (89.0)	6,35,428 (116.6)	3,40,972 (72.1)
राज्य सरकार				
सकल बाजार उधारियां	4,64,132 (65.6)	3,07,306 (49.3)	3,53,596 (50.0)	2,25,445 (36.2)
निवल बाजार उधारियां	3,81,077 (68.0)	2,18,254 (44.9)	2,98,989 (53.3)	1,56,447 (32.2)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े बीई का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक, भा.रि.बैंक

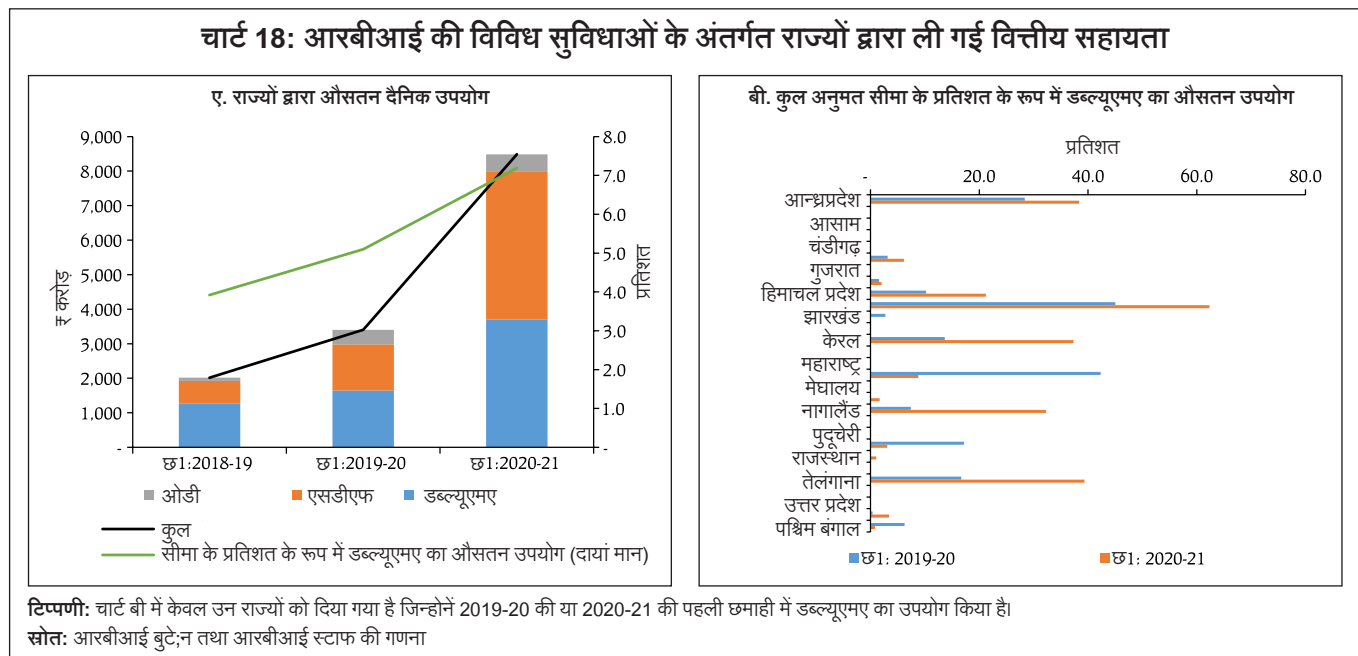
साथ, 2020-21 और 2019-20 के स्तरों में एक मजबूत सहसंबंध पाया गया जो यह दर्शाता है कि मोटे तौर पर संवृद्धि सभी राज्यों में समान है। राज्य सरकार के वित्त पर कोविड-19 प्रकोप का स्थानिय आयाम बाजार उधारियों की मात्रा में बढ़ोतरी से स्पष्ट है - तीन राज्यों जिसमें अत्यधिक बढ़ोतरी हुई (महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु) कोविड-19 मरिजों की अत्यधिक संख्या वाले 4 राज्यों में भी शामिल है (चार्ट 17)।

रिजर्व बैंक की विभिन्न सुविधाओं के तहत राज्यों द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में 2020-21 की पहली छमाही में विशेष रूप से उच्चतर अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) (जो सामान्य डब्ल्यूएमए के अतिरिक्त एक विशेष डब्ल्यूएमए के रूप में)

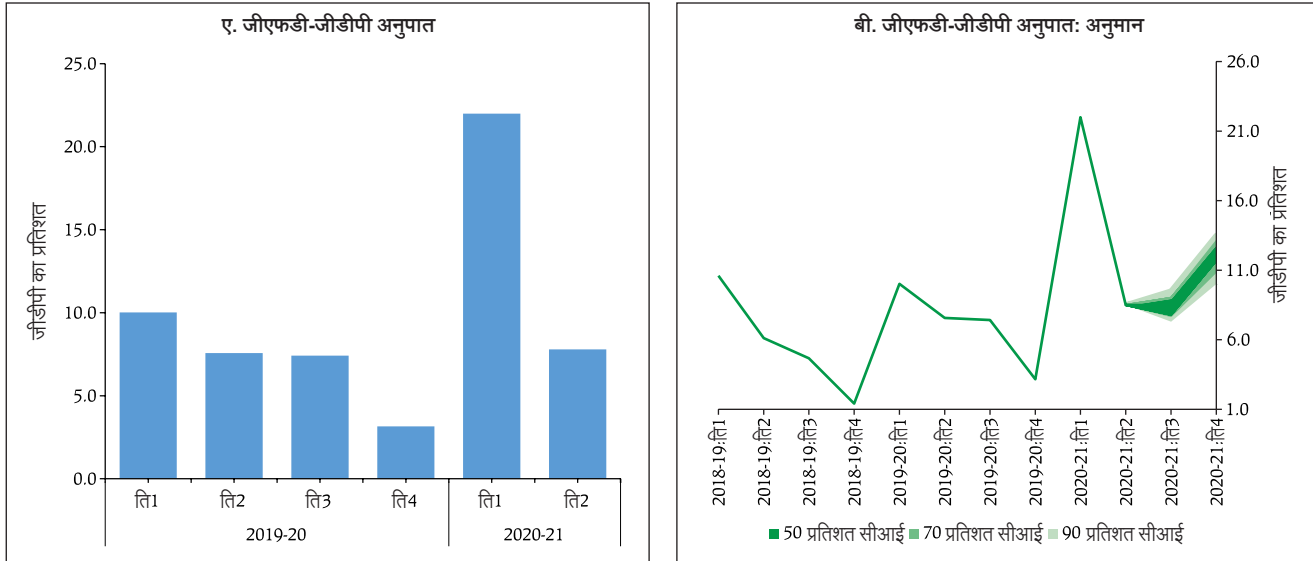


की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गयी हैं (चार्ट 18ए)। वर्ष के दौरान, वित्तीय दबाव कम करने और राज्यों के उधार कैलेंडर को सुचारु करने के उपाय के रूप में, रिजर्व बैंक ने राज्यों के डब्ल्यूएमए सीमा 60 प्रतिशत से बढ़ायी। अप्रैल - सितंबर 2020 के दौरान, तेरह राज्यों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया, जबकि छह राज्यों ने

ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया। राज्य-वार, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड और तेलंगाना ने उपलब्ध डब्ल्यूएमए सीमा का प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक उपयोग किया, जबकि मणिपुर, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 18 बी)।



चार्ट 19: संयुक्त सरकारी वित्त: वास्तविक और अनुमान



टिप्पणी: 1. गाढ़ा हरे रंग से छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल (सीआई) का प्रतिनिधित्व करता है जिसका अर्थ है कि 50 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम गाढ़े हरे छायांकित क्षेत्र द्वारा दी गई सीमा के भीतर होगा। इसी तरह 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत विश्वास अंतराल के लिए, क्रमशः 70 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्रों द्वारा दी गई सीमा में होगा।

2. रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 2020 की मौद्रिक नीति समीक्षा में वर्ष 2020-21 के लिए घोषित अनुमानित जीडीपी वृद्धि का उपयोग किया गया है।

3. वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक संयुक्त जीएफडी-जीडीपी अनुपात केंद्र तथा 27 राज्यों के लिए है, ति1: 2020-21 तक केंद्र तथा 24 राज्यों और ति2: 2020-21 के लिए जीएफडी-जीडीपी अनुपात केंद्र तथा 21 राज्यों के लिए के लिए है। जीएफडी-जीडीपी का अनुमान केंद्र और 24 राज्यों के लिए है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन

V. सामान्य सरकार वित्त

"सरकारी वित्त 2019-20: छमाही समीक्षा" पर बुलेटिन लेख दिसंबर 2019 में प्रकाशित हुआ, जिसने जी -20 डेटा गैप पहल की दिशा में भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सामान्य सरकार के वित्त आंकड़ों को तिमाही आधार पर संकलन और रिपोर्ट करने पहला कदम उठाया। राजकोषीय डेटा समय पर प्रदान करने के इस प्रयास को जारी रखते हुए, सामान्य सरकार वित्त को तिमाही आधार पर 2020-21 की दूसरी तिमाही तक संकलित किया गया है (परिशिष्ट सारणी 5)। विश्लेषण से पता चलता है कि संयुक्त जीएफडी प्रदर्शन 2020-21 की पहली छमाही में खराब था, क्योंकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएफडी में 2020-21 की पहली तिमाही में तेजी से वृद्धि हुई थी, मुख्य रूप से सामान्य सरकार प्राप्ति में कमी और समय से पहले खर्च के साथ जीडीपी में संकुचन होने के कारण (चार्ट 19 ए)।

इसके अलावा, 2020-21 की दूसरी छमाही में, जबकि आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने के कारण बेहतर प्रतियों से राजकोष को लाभ होने की संभावना है, सरकार द्वारा विभिन्न व्यय उपायों, विशेष रूप से बजट के आधार पर आत्म निर्भर 2.0 तथा 3.0 के माध्यम से दी गयी सहायता मूर्त रूप लेने की संभावना है। इन विकासों को ध्यान में रखते हुए और प्रमुख व्यय सहायता- आंशिक रूप से तीसरी तिमाही में और अधिकतर चौथी तिमाही में, रिजर्व बैंक की दिसंबर 2020 की मौद्रिक नीति समीक्षा में अनुमानित जीडीपी वृद्धि के आधार पर, तीसरी और चौथी तिमाही में संयुक्त राजकोषीय घाटा तदनु रूप 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल 7.8-8.8 प्रतिशत और 11.6-12.9 प्रतिशत अनुमान के साथ क्रमशः जीडीपी के 8.3 और 12.4 प्रतिशत पर अनुमानित हैं (चार्ट 19 बी)। तदनुसार, जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2020-21 की पहली छमाही में जीडीपी के 14.5 प्रतिशत से घटकर 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का 10.4 प्रतिशत होने की संभावना है।

VI. भावी दिशा

2020-21 में केंद्र सरकार का जीएफडी वित्त वर्ष के चौथे महीने (अर्थात् जुलाई 2020) तक ही निर्धारित बजट राशि का 100 प्रतिशत पार करते हुए अक्टूबर 2020 तक 119.7 प्रतिशत तक पहुंच गया, राजस्व घाटा अक्टूबर 2020 तक बजट राशि के 126.7 प्रतिशत था, जो व्यय की गुणवत्ता में गिरावट दर्शाता है। हालांकि, केंद्र सरकार के घाटे के फ्रंट-लोडिंग में मौसमीयता ने भी भूमिका निभाई है, इस साल सामान्य से अधिक राजकोषीय घाटा राजस्व में गिरावट के कारण है (विशेष रूप से पहली तिमाही में जीडीपी में 22.6 प्रतिशत संकुचन के परिणामस्वरूप)। 2020-21 की पहली छमाही में राज्यों का जीएफडी 58.4 प्रतिशत था, जो वर्ष में सामान्यतः देखे गए जीएफडी से 35-40 प्रतिशत से अधिक है। सरकार के दोनों स्तरों पर राजकोषीय संतुलन में गिरावट के साथ, 2020-21 की पहली छमाही में संयुक्त जीएफडी (केंद्र और राज्यों) बीई के 85.9 प्रतिशत था, जो 2019-20 की पहली छमाही के 70.0 प्रतिशत से काफी अधिक है।

छमाही रुझान राजकोषीय संतुलन के क्रमिक विकास में अंतर-तिमाही भिन्नता को आच्छादित करती है क्योंकि 2020-21 की पहली छमाही में उच्च जीएफडी के लिए पूरी तरह से 2020-21 की पहली तिमाही जिम्मेदार है, 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीएफडी (बीई के प्रतिशत में) पिछले दो वर्षों के समान स्तरों पर रहा। जीएफडी एक व्युत्पन्न आंकड़ा होने के कारण, यह प्राप्तियों और व्यय दोनों निर्भर है। 2020-21 की पहली तिमाही में, राजस्व प्राप्तियों में गिरावट आई, व्यय स्तर पिछले वर्ष की तुलना में केवल मामूली अंतर आया, जिसके परिणामस्वरूप जीएफडी बढ़ गया। जबकि राजस्व अंतर, कुछ हद तक कम था, दूसरी तिमाही में, विवेकपूर्ण व्यय के कारण जीएफडी में सुधार हुआ। जैसे कि व्यय के युक्तिसंगत करने से राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त वसूली हुई 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीएफडी अपने सामान्य स्तर (बीई के एक प्रतिशत के रूप में) पर प्रत्यावर्तित हुआ। हालांकि, सरकार के दोनों स्तरों पर पूंजीगत व्यय में कटौती से व्यय युक्तिसंगत किया गया जो वृद्धि में बहाली को निरुत्साहित

कर सकता है। 2020-21 की दूसरी तिमाही में मौसमीयता और इसके सामान्य स्तर पर जीएफडी के प्रत्यावर्तन को देखते हुए, संयुक्त जीएफडी में निम्न अभिवृद्धि होने की संभावना है।

पहले से ही पहली छमाही में महसूस किए गए सरकारी वित्त पर कोविड -19 के गंभीर प्रभाव के बावजूद बहाली की गति को बनाए रखने के लिए प्रतिचक्रिय राजकोषीय उपाय जारी रखना केंद्र और राज्यों के लिए अनिवार्य है। वंचितों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए और श्रम बाजार की अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए राजस्व व्यय के उपायों को जारी रखने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि सभी क्षेत्रों में असमान बहाली होने की संभावना है। 2020-21 की पहली छमाही में पूंजीगत व्यय जो तेजी से नीचे गिरा, को प्राथमिकता से बढ़ाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक आवास, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण में सार्वजनिक निवेश एक अधिक आघात सहनीय और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए समय की आवश्यकता है।

सरकारों को राजकोषीय रिपोर्टिंग में अच्छी आंतरिक व्यवस्था और पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ कमजोर बहाली प्रक्रिया के लिए जारी राजकोषीय समर्थन और मध्यम अवधि के ऋण-घाटे के असंतुलन को दूर करने के बीच प्रभावी ढंग से संतुलन बनाना होगा।

संदर्भ

Baker, S., Farrokhnia, R. A., Pagel, M., Meyer, S., and Yannelis, C. 2020. "Income, Liquidity, and the Consumption Response to the 2020 Economic Stimulus Payments." National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 27097.

Eggertsson, G. B., Mehrotra, N. R., and Robbins, J. A. 2019. "A Model of Secular Stagnation: Theory and Quantitative Evaluation." American Economic Journal: Macroeconomics 11 (1): 1-48.

IMF (2020a). IMF Fiscal Monitor. 2020, International Monetary Fund, October 2020.

IMF (2020b). "Challenges in Forecasting Tax revenue." IMF Special Series on COVID-19. April 20.

Misra, S. and Trivedi P. (2016). Structural fiscal balance: An empirical investigation for India. RBI Occasional Papers Vols. 35 and 36, Vols. 1 and 2, 2014 and 2015.

Rachel, L., and Summers L. H.. 2019. "On Falling Neutral Real Rates, Fiscal Policy, and the Risk of Secular Stagnation." Brookings Papers on Economic Activity (Spring): 1-76.

Reserve Bank of India (2019). "Monetary Policy Report". April 2019.

Reserve Bank of India (2020). "State Finances A Study of Budgets of 2020-21".

Websites

The office of the Comptroller and Auditor General of India. <https://cag.gov.in/>

The Office of Controller General of Accounts. <http://www.cga.nic.in/>

परिशिष्ट

सारणी 1 : अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के बजट की स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वास्तविक		बजट अनुमान		बीई का प्रतिशत		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	550.8	816.5	2020.9	1962.8	27.3	41.6	-32.5	18.0
1.1. कर राजस्व (निवल)	458.5	607.4	1635.9	1649.6	28.0	36.8	-24.5	4.2
1.2. करेतर राजस्व	92.3	209.0	385.0	313.2	24.0	66.7	-55.9	91.8
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	5.7	6.5	11.0	13.7	52.1	47.3	-11.3	10.9
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ	14.6	20.6	225.0	119.8	6.5	17.2	-28.9	16.2
2.1. ऋणों की वसूली	8.9	8.2	15.0	14.8	59.2	55.6	7.5	5.8
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	5.8	12.4	210.0	105.0	2.8	11.8	-53.2	24.3
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)	565.4	837.1	2245.9	2082.6	25.2	40.2	-32.5	18.0
4. राजस्व व्यय	1313.6	1301.1	2630.1	2447.8	49.9	53.2	1.0	14.0
जिसमें से								
(i) ब्याज भुगतान	305.7	270.7	708.2	660.5	43.2	41.0	12.9	6.0
5. पूंजीगत व्यय	165.8	187.5	412.1	338.6	40.2	55.4	-11.6	15.3
जिसमें से								
(i) ऋण और अग्रिम	17.4	14.8	31.8	27.8	54.7	53.4	17.1	40.8
6. कुल व्यय (4+5)	1479.4	1488.6	3042.2	2786.3	48.6	53.4	-0.6	14.1
7. राजस्व घाटा (4-1)	762.8	484.6	609.2	485.0	125.2	99.9	57.4	7.7
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	914.0	651.6	796.3	703.8	114.8	92.6	40.3	9.6
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4(i)}	608.3	380.9	88.1	43.3	690.2	879.8	59.7	12.2

स्रोत : महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 2 : केंद्र सरकार के वित्त की तिमाही स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	ति1		ति2		बजट अनुमान का प्रतिशत				वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर	
					ति1		ति2		2020-21	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	Q1	Q2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	150.0	284.9	400.8	531.6	7.4	14.5	19.8	27.1	-47.3	-24.6
1.1. कर राजस्व (निवल)	134.8	251.4	323.7	356.0	8.2	15.2	19.8	21.6	-46.4	-9.1
1.2. करेतर राजस्व	15.2	33.5	77.1	175.6	3.9	10.7	20.0	56.1	-54.6	-56.1
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	1.6	3.3	4.1	3.2	14.8	23.8	37.3	23.5	-50.0	27.9
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ	3.6	4.8	11.1	15.8	1.6	4.0	4.9	13.2	-25.0	-30.1
2.1. ऋणों की वसूली	3.6	2.4	5.3	5.8	23.9	16.2	35.3	39.3	48.4	-9.4
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	0.0	2.4	5.8	10.0	0.0	2.2	2.8	9.5	-100.0	-42.2
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)	153.6	289.7	411.8	547.4	6.8	13.9	18.3	26.3	-47.0	-24.8
4. राजस्व व्यय	727.7	658.7	585.9	642.4	27.7	26.9	22.3	26.2	10.5	-8.8
जिसमें से										
(i) ब्याज भुगतान	160.5	141.8	145.2	128.9	22.7	21.5	20.5	19.5	13.2	12.6
5. पूंजीगत व्यय	88.3	63.0	77.6	124.5	21.4	18.6	18.8	36.8	40.1	-37.7
जिसमें से										
(i) ऋण और अग्रिम	13.9	6.0	3.4	8.8	43.9	21.7	10.8	31.7	131.4	-61.1
6. कुल व्यय (4+5)	815.9	721.7	663.5	766.9	26.8	25.9	21.8	27.5	13.1	-13.5
7. राजस्व घाटा (4-1)	577.7	373.8	185.1	110.8	94.8	77.1	30.4	22.8	54.5	67.1
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	662.4	432.1	251.6	219.5	83.2	61.4	31.6	31.2	53.3	14.6
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4(i)}	501.9	290.3	106.5	90.6	569.4	670.6	120.8	209.2	72.9	17.6

स्रोत : महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 3 : अप्रैल से सितंबर 2020-21 के दौरान राज्य सरकारों के बजट की स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)			(प्रतिशत)			
	अनंतिम वास्तविक डेटा			बीई का प्रतिशत		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर	
	2018-19	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8
1. राजस्व प्राप्तियाँ	834.9	855.4	713.9	38.2	30.7	2.5	-16.5
1.1. कर राजस्व (निवल)	628.2	633.4	496.6	39.5	30.6	0.8	-21.6
1.2. करेतर राजस्व	63.6	61.8	45.8	31.2	20.9	-2.8	-25.9
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	143.1	160.2	171.5	36.5	35.7	12.0	7.0
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ	6.9	12.1	1.5	22.2	10.0	76.0	-87.8
2.1. ऋणों की वसूली	6.8	12.1	1.4	22.8	13.0	77.4	-88.2
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	0.1	0.1	0.1	3.1	1.4	-32.5	-11.3
3. राजस्व व्यय	840.8	906.7	911.5	40.1	38.3	7.8	0.5
जिसमें से							
(i) ब्याज भुगतान	84.7	103.8	113.9	40.1	39.6	22.6	9.8
4. पूंजीगत व्यय	137.8	137.2	88.9	30.8	20.0	-0.4	-35.2
4.1. पूंजीगत परिव्यय	122.6	119.6	80.1	29.1	19.7	-2.4	-33.1
4.2. संवितरित ऋण और अग्रिम	15.3	17.6	8.8	52.1	22.6	15.3	-49.8
5. राजकोषीय घाटा [(3+4) - (1+2)]	136.8	176.4	285.0	42.6	58.4	29.0	61.6
6. राजस्व घाटा (3-1)	5.9	51.3	197.6	212.7	340.9	775.8	285.1

स्रोत : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

सारणी 4 : राज्य सरकार के वित्त की तिमाही स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	अनंतिम वास्तविक डाटा				बजट अनुमान का प्रतिशत				वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर	
	ति1		ति2		ति1		ति2		2020-21	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	ति1	ति2
1. राजस्व प्राप्तियाँ	315.6	388.0	398.2	467.4	13.6	17.3	17.1	20.9	-18.6	-14.8
1.1. कर राजस्व	200.9	299.3	295.7	334.1	12.4	18.7	18.2	20.8	-32.9	-11.5
1.2. करेतर राजस्व	19.8	28.4	26.0	33.4	9.0	14.4	11.8	16.9	-30.3	-22.1
1.3. सहायता-अनुदान और अंशदान	94.9	60.3	76.6	99.9	19.8	13.7	16.0	22.8	57.4	-23.4
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.6	1.0	0.9	11.1	4.2	1.9	5.8	20.3	-39.8	-92.3
2.1. ऋणों की वसूली	0.6	1.0	0.8	11.1	5.5	1.9	7.5	21.0	-39.6	-92.6
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	0.9	1.5	-44.2	25.0
3. राजस्व व्यय	450.1	405.8	461.3	500.9	18.9	17.9	19.4	22.1	10.9	-7.9
जिसमें से										
(i) ब्याज भुगतान	51.7	42.8	62.2	61.0	18.0	16.5	21.6	23.6	20.9	2.0
4. पूंजीगत व्यय	32.3	57.2	56.6	80.0	7.3	12.8	12.7	18.0	-43.5	-29.3
4.1. पूंजीगत परिव्यय	29.8	52.8	50.3	67.1	7.4	12.9	12.4	16.3	-43.6	-25.1
4.2. संवितरित ऋण और अग्रिम	2.5	4.7	6.3	12.9	6.5	13.9	16.2	38.3	-46.1	-51.2
5. राजकोषीय घाटा [(3+4)-(1+2)]	166.2	74.0	118.9	102.4	34.1	17.9	24.4	24.7	124.6	16.0
6. राजस्व घाटा (3-1)	134.5	17.8	63.1	33.5	232.0	74.0	108.9	138.8	653.8	88.6

स्रोत : महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 5: संयुक्त सरकारी वित्त (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

मद	2019-20				2020-21		2019-20	2020-21
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	छ1	छ1
कर राजस्व	13.1	16.0	14.9	17.5	9.9	13.1	14.6	11.7
करेतर राजस्व	3.0	7.1	4.0	6.4	3.9	3.8	5.0	3.9
पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.1	0.6	0.3	1.2	0.1	0.3	0.3	0.2
कुल प्राप्तियाँ	16.1	23.7	19.2	25.1	14.0	17.2	19.9	15.7
कुल व्यय	26.2	31.3	26.6	28.2	36.0	24.9	28.7	29.9
राजस्व व्यय	23.7	26.9	23.4	23.9	33.1	22.2	25.3	27.1
पूंजीगत व्यय	2.5	4.4	3.2	4.3	2.9	2.8	3.4	2.8
सकल राजकोषीय घाटा	10.0	7.6	7.4	3.2	22.0	7.8	8.8	14.1
राजस्व घाटा	7.6	3.8	4.5	0.0	19.2	5.3	5.7	11.5

टिप्पणी : आंकड़े केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अनंतिम वित्त के अनुसार दिए गए हैं।
आंकड़े केंद्र सरकार और 23 राज्यों से संबन्धित हैं।

सारणी 6: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	भारत सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा
14 मार्च 2020	राज्य आपदा प्रतिसाद निधि (एसडीआरएफ) से सहायता के लिए मानदंड जारी किए गए।
24 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> सांविधिक और अनुपालन मामलों में छूट दी गयी जैसे आयकर/जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करने, <i>विवाद से विश्वास</i> योजना के अंतर्गत भुगतान और विभिन्न कॉर्पोरेट मामलों, की समय सीमा बढ़ाना। व्यापार वित्त उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल व्यापार लेनदेन पर बैंक प्रभारों को कम कर दिया गया। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को प्रवृत्त करने से रोकने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 4 के अंतर्गत चूक की प्रारंभिक सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ रुपये कर दिया गया। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर एटीएम से नकद आहरण के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों में तीन महीने के लिए छूट। सैनिटाइजर्स के निर्यात पर प्रतिबंध।
26 मार्च 2020 (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना)	<ul style="list-style-type: none"> प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं/चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रति माह 3 महीने के लिए निशुल्क प्रदान की जाएंगी। जन धन महिला खाता धारकों को तीन महीने के लिए ₹500 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गरीब <i>दिव्यांग</i>, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ (डीबीटी) हस्तांतरित किए जाएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की मजदूरी में ₹20 रुपये की वृद्धि की जाएगी। गरीब परिवारों को 3 माह तक गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत 2020-21 में देय ₹2,000 की पहली किस्त अप्रैल 2020 में उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकारों को कोविड-19 स्वास्थ्य प्रतिसाद के लिए जिला खनिज निधि के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा। निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण निधि का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए संपार्श्विक मुक्त उधार सीमा ₹10 लाख रुपये से बढ़ाकर ₹20 लाख रुपये की जाएगी। 100 से कम श्रमिकों वाले कम वेतन अर्जक व्यवसायों के लिए अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान, तीन महीने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ईपीएफ विनियमों में संशोधन किया जाएगा ताकि खातों से 75 प्रतिशत राशि या तीन महीने की मजदूरी, जो भी कम हो, अप्रतिदेय अग्रिम लेने के लिए महामारी को कारण के रूप में शामिल किया जा सके।
30 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों द्वारा दिए गए ₹3 लाख रुपये तक के सभी फसल ऋण जो 1 मार्च से 31 मई 2020 के दौरान देय हैं, के लिए बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान और सभी किसानों के लिए 3 प्रतिशत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन लाभ 31 मई 2020 तक बढ़ाया गया।
31 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट) अध्यादेश 2020 में बहुतायत आर्थिक कानूनों के अनुपालन और प्रवर्तन में छूट प्रदान की गयी। विदेश व्यापार नीति 2015-20 को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और निर्यात और आयात पद्धति के क्षेत्र में अन्य छूट प्रदान की गयी।

सारणी 6: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम (जारी)

घोषणा की तारीख	भारत सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा
3 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों के पास उपलब्ध धन को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि की वर्ष 2020-21 के लिए ₹11,092 करोड़ रुपये की पहली किस्त अग्रिम रूप से जारी की गयी।
8 अप्रैल 2020	यह घोषणा की गयी कि ₹5 लाख तक के सभी लंबित आयकर रिफंड, और सभी लंबित जीएसटी और कस्टम रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे, जिसकी कुल राशि ₹18,000 करोड़ रुपये है।
9 अप्रैल 2020	'कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेडनेस पैकेज' के लिए ₹15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी।
18 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों की अवसरवादी खरीद/अधिग्रहणों को रोकने के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन किया गया।
13 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान-भाग I)	<ul style="list-style-type: none"> • 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवर के साथ ₹3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त ऋण, मानक व्यवसायों/एमएसएमई को प्रदान किया जाएगा। • आंशिक ऋण गारंटी सहायता के साथ ₹20,000 करोड़ रुपये गौण ऋण, अनर्जक आस्ति (एनपीए) /दबावग्रस्त एमएसएमई को प्रदान किया जाएगा। • विकासक्षम और अर्थक्षम एमएसएमई के इक्विटी वित्तपोषण के लिए ₹10,000 करोड़ रुपये राशि से निधियों का कोष बनाया जाएगा। • बड़ी संख्या में फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा। • मेक इन इंडिया समर्थन करने और एमएसएमई के लिए ई-मार्केट संपर्कों को बढ़ाने के लिए ₹200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। • सरकार/केंद्र सरकार के लोक उद्यमों (सीपीएसई) से एमएसएमई को प्राप्य राशियों को 45 दिनों में जारी किया जाएगा। • पात्र व्यवसायों और कामगारों के लिए ₹2,500 करोड़ रुपये की ईपीएफ सहायता को और 3 महीने (जून से अगस्त 2020 तक) के लिए विस्तारित किया जाएगा। • अन्य व्यवसायों और कामगारों के संबंध में, हर एक के ईपीएफ अंशदान को 3 महीने के लिए घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जिससे ₹6,750 करोड़ रुपये चलनिधि उपलब्ध होगी। • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) /आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) /सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के लिए ₹30,000 करोड़ रुपये की विशेष चलनिधि योजना शुरू की जाएगी। • आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना को कम रेटिंग वाले एनबीएफसी/ एचएफसी/ एमएफआई के उधार को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। • बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में ₹90,000 करोड़ रुपये चलनिधि लगायी जाएगी। • केंद्र सरकार की विद्युत उत्पादन कंपनियां डिस्कॉम को छूट देंगी, जिसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं (उद्योगों) को दिया जाएगा। • स्थावर संपदा और निर्माण का दबाव कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे, केंद्र सरकारी एजेंसियों द्वारा संविदाओं को 6 महीने तक बढ़ाया जाएगा। • स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) /स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) की दरें वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में 25 प्रतिशत कम की जाएंगी। • विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत आयकर रिटर्न फ़ाइल करने और भुगतान करने की तारीखें और आगे बढ़ाई गईं।

सारणी 6: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम (जारी)

घोषणा की तारीख	भारत सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा
14 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान-भाग II)	<ul style="list-style-type: none"> • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/राज्य कार्ड के जो लाभार्थी नहीं हैं, उन प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की 83 प्रतिशत आबादी को अगस्त 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभों की राष्ट्रीय पोर्टबिलिटी के लिए 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा (मार्च 2021 तक 100 प्रतिशत)। • प्रवासी कामगारों/शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों (एआरएचसी) को विकसित और प्रोत्साहित किया जाएगा। • मुद्रा-शिशु ऋणों के त्वरित भुगतान कर्ताओं को 12 महीने की अवधि के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। • फेरीवालों को ₹5,000 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। • आवास क्षेत्र को ₹70,000 करोड़ रुपये प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिट लिंकड आर्थिक सहायता योजना मार्च 2021 तक बढ़ायी जाएगी। • रोजगार के अवसर निर्माण करने हेतु वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यों के लिए क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) निधियों का उपयोग किया जाएगा। • नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता के माध्यम से किसानों को ₹30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। • किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ₹2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण दिया जाएगा।
15 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान-भाग III)	<ul style="list-style-type: none"> • फार्म-गेट और समूह स्थानों पर कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ₹1,00,000 करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा प्रदान की जाएगी। • सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) के औपचारीकरण के लिए ₹10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की जाएगी। • प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिए ₹20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। • डेयरी में निजी निवेश को समर्थन देने के लिए ₹15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कोष स्थापित किया जाएगा। • औषधिक खेती और मधुमक्खी पालन की पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। • ऑपरेशन ग्रीन, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) के साथ-साथ सभी फल और सब्जियों (टीओटीएएल) के लिए प्रदान किया जाएगा। • कुछ खाद्य पदार्थों को अविनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाएगा। • बिना अवरोध अंतरराज्यीय व्यापार के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाएगा। • जोखिम कम करने, आश्वासित प्रतिफल, और गुणवत्ता मानकीकरण को शामिल करते हुए सुविधाजनक कानूनी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि किसानों को प्रोसेसर/ एग्रीगेटर्स/ बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ा जा सके।

सारणी 6: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम (जारी)

घोषणा की तारीख	भारत सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा
16 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान - भाग IV)	<ul style="list-style-type: none"> वाणिज्यिक कोयला उत्पादन और अन्वेषण में निजी क्षेत्र की सहभागिता को अनुमति दी जाएगी; कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा; कारोबारी सुगमता के लिए उपाय किए जाएंगे; कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन अधिकारों की, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की कोयला खदानों से नीलामी की जाएगी; सीआईएल के उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक शर्तों में रियायतें दी जाएंगी। कोयला क्षेत्र में ₹50,000 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। खनिज क्षेत्र में निजी निवेशों को बढ़ाने के लिए निर्बाध समग्र अन्वेषण-सह-खनन सह-उत्पादन व्यवस्था शुरू की जाएगी; 500 खनन ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी; बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त रूप से नीलामी की जाएगी; कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव खानों के बीच भेद हटा दिया जाएगा; विभिन्न खनिजों के लिए खनिज सूचकांक विकसित किया जा रहा है; खनन पट्टे के लिए देय स्टांप ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया जाएगा। आयात पर प्रतिबंध वाले हथियारों/ प्लेटफार्मों की एक सूची अधिसूचित की जाएगी; आयातित कलपुर्जों को स्वदेशीकृत किया जाएगा; आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा; स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा; समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हवाई क्षेत्र का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाएगा, जिससे उड़ान लागत में प्रति वर्ष ₹1,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी; सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से विश्व स्तरीय हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा; चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टरों, खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी की स्थापना हेतु पीपीपी को प्रोत्साहित किया जाएगा; और प्रौद्योगिकी विकास सह इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की मात्रा ₹8,100 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ बढ़ायी जाएगी। बिजली क्षेत्र के लिए नई टैरिफ नीति जारी की जाएगी और संघ शासित प्रदेशों में पॉवर युटिलिटीज का निजीकरण किया जाएगा। निजी क्षेत्र को अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी; उदार भू-अंतरिक्ष डेटा नीति तकनीकी उद्यमियों को रिमोट-सेंसिंग डेटा प्रदान करेगी; ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा निजी क्षेत्र के लिए खुली की जाएगी।
17 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान - भाग V)	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को बढ़ाया जाएगा; सभी जिलों में संक्रामक रोग अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे; प्रयोगशाला और निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा; और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम, मन:सामाजिक समर्थन के लिए मनोदर्पण, नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक फ्रेमवर्क, और राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और न्यूमेरसी मिशन शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के लिए विशेष दिवाला समाधान फ्रेमवर्क अधिसूचित किया जाएगा; एक वर्ष तक कोई भी नयी दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी; आईबीसी के अंतर्गत दिवाला कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रयोजन के लिए जो "चूक" की परिभाषा दी गयी है उसमें कोविड-19 संबंधित ऋण शामिल नहीं किया जाएगा; निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) सूचीबद्ध करती हैं, उन्हें सूचीबद्ध नहीं माना जाएगा; छोटी कंपनियों/ एक-व्यक्ति कंपनियों/ निर्माता कंपनियों/ स्टार्ट-अप के सभी चूक के लिए दंड कम किया जाएगा। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों (तकनीकी और प्रक्रियात्मक स्वरूप की अल्प चूकों के लिए) को गैरआपराधिक माना जाएगा।

सारणी 6: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम (जारी)

घोषणा की तारीख	भारत सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा
	<ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक हित में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की उपस्थिति अनिवार्य होने वाले कार्यनीतिक क्षेत्रों की सूची अधिसूचित की जाएगी; कार्यनीतिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्र में कम से कम एक उद्यम रहेगा लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी; अन्य क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा; और व्यर्थ की प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए, कार्यनीतिक क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या केवल एक से चार होगी। वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी जाएगी, जो विशिष्ट सुधारों से आंशिक रूप से जुड़ी रहेगी तथा इससे ₹4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा आवंटन में ₹40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाएगी।
12 जून 2020	छोटे कर दाताओं को विलंब शुल्क में कमी के माध्यम से जीएसटी छूट प्रदान की जाएगी, और पंजीकरण के निरसन का प्रतिसंहरण करने की मांग की अवधि में एक बार विस्तार दिया जाएगा।
30 जून 2020	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की निशुल्क व्यवस्था नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दी गयी।
6 अगस्त 2020	भारत सरकार द्वारा 22 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को कोविड-19 आपातकालीन प्रतिसाद और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज की दूसरी किस्त ₹ 890.3 करोड़ राशि जारी की गई थी।
12 अक्टूबर 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान 2.0)	<ul style="list-style-type: none"> सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) नकद वाउचर योजना और त्यौहार अग्रिम विशेष योजना दी जाएगी। पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों 50 साल का ऋण ₹ 12,000 करोड़ का विशेष ब्याज रहित जारी किया जाएगा। सड़कों, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू रूप से उत्पादित पूंजी उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 25,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाएगा।
23 अक्टूबर 2020	निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के राशि के अंतर का अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान किया गया था।
12 नवंबर 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान 3.0)	<ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 रिकवरी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान रोजगार योजना शुरू की गई। एमएसएमई, व्यवसाय, मद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया। घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजना के तहत 10 और चैंपियन सेक्टर को कवर किया जाएगा। पीएम आवास योजना - शहरी के लिए ₹18,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया गया। सरकारी निविदाओं पर अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी और कार्य निष्पादन जमानत में रियायत प्रदान की गई ताकि व्यवसाय करने में आसानी हो और ठेकेदारों को राहत मिले। डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए आयकर राहत प्रदान की गई। राष्ट्रीय निवेश और अवसरचना निधि (एनआईआईएफ) के कर्ज प्लेटफॉर्म में ₹ 6,000 करोड़ का इक्विटी निवेश किया जाएगा।

सारणी 6: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम (समाप्त)

घोषणा की तारीख	भारत सरकार द्वारा नीतिगत घोषणा
	<ul style="list-style-type: none"> • सब्सिडी वाले उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ₹ 65,000 करोड़ प्रदान किए जाएंगे। • ग्रामीण रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को ₹10,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च प्रदान किया जाएगा। • भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस योजना) के तहत निर्यात परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एक्विजि बैंक को ₹3,000 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। • ₹10,200 करोड़ प्रोत्साहन राशि का अतिरिक्त बजट घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हरित ऊर्जा पर पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए प्रदान किया जाएगा। • भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को ₹900 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।

भारत में ग्रामीण – शहरी मुद्रास्फीति के आयाम*

यह आलेख इस पर प्रकाश डालता है कि बावजूद यत्र-तत्र विचलन के, जो कि लंबे समय तक नहीं चलते, भारत में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के गतिमान आयाम- प्रवृत्ति, चक्र, सातत्य और अस्थिरता के मामले में – एक जैसे हैं। अल्पकालिक छिटपुट एक सदृश गति दिखलाती है। उनके बीच दीर्घावधि सहएकीकारी संबंध की उपस्थिति पर प्रायोगिक निष्कर्ष, सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण एक त्रुटि सुधार प्रक्रिया द्वारा संरेखण की बहाली, और राज्यों में अभिसरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि राज्यों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सांकेतिक स्थिरक/अधिकीलक (नॉमिनल एंकर) के रूप में मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रासंगिक है।

भूमिका

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जिसकी एक प्रमुख विशेषता ग्रामीण आबादी का एक बड़े हिस्से (जनगणना 2011 के अनुसार 68.8 प्रतिशत) का होना और जीविका के लिए कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों पर अत्यधिक निर्भरता है (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सामान्य स्थिति में ग्रामीण कामगारों का 57.8 प्रतिशत), वहाँ ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के व्यवहार का परीक्षण जरूरी हो जाता है ताकि नीति निर्माण के निमित्त उनके निहितार्थ को समझा जा सके। मुद्रास्फीति के क्षेत्रीय आयाम को अनदेखा करना सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समान और पर्याप्त रूप से पूरा करने में एकल मौद्रिक नीति के प्रभाव को सीमित कर सकता है (वेबर एंड बेक, 2005: वेयरस्ट्रास 2011) और आर्थिक परिणामों के बारे में इसके निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं (ब्रान्ट एंड होल्ज, 2006)।

ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति में बड़े और लगातार अंतर के कारण वास्तविक मजदूरी दरों, वास्तविक ब्याज दरों और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में अंतर हो सकता है जो कि मौद्रिक नीति के लिए चुनौतियां पेश कर सकता है। परिचालनात्मक दृष्टिकोण से, ऐसा विचलन, यदि बना रहे तो, मुद्रास्फीति के विश्वसनीय मॉडल-आधारित पूर्वानुमान को और पेचीदा बना सकता है जो कि

* यह आलेख भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के बिनोद बी भोई, हिमानी शेखर और इप्सिता पादी, द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

लचीली मुद्रास्फीति फ्रेमवर्क (एफआईटी) के अंतर्गत मौद्रिक नीति के मध्यवर्ती लक्ष्य के रूप में कार्य करता है। इस पृष्ठभूमि में, ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के गतिमान आयामों का - उनकी प्रवृत्ति, चालकों, अस्थिरता, सातत्य और अभिसरण के संदर्भों में - मौद्रिक नीति के लिए उनके निहितार्थों को समझने के लिए परीक्षण इस आलेख का मुख्य उद्देश्य है।

इस आलेख के शेष भाग की संरचना इस प्रकार है: मुद्रास्फीति की विविधता/ अभिसरण की प्रकृति और स्वरूप को समझने के लिए खंड II ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति का एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। खंड III क्षेत्रीय मुद्रास्फीति विचलन पर चुनिन्दा साहित्य की समीक्षा करता है और मौद्रिक नीति के लिए उनकी प्रासंगिकता और आशय पर निष्कर्ष निकालता है। समग्र (अखिल भारत) स्तर पर ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के सह-संचरण के साथ राज्य स्तर पर ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के अभिसरण की प्रकृति का परीक्षण खंड IV में किया गया है। खंड V में निष्कर्षात्मक टिप्पणियां दी गई हैं।

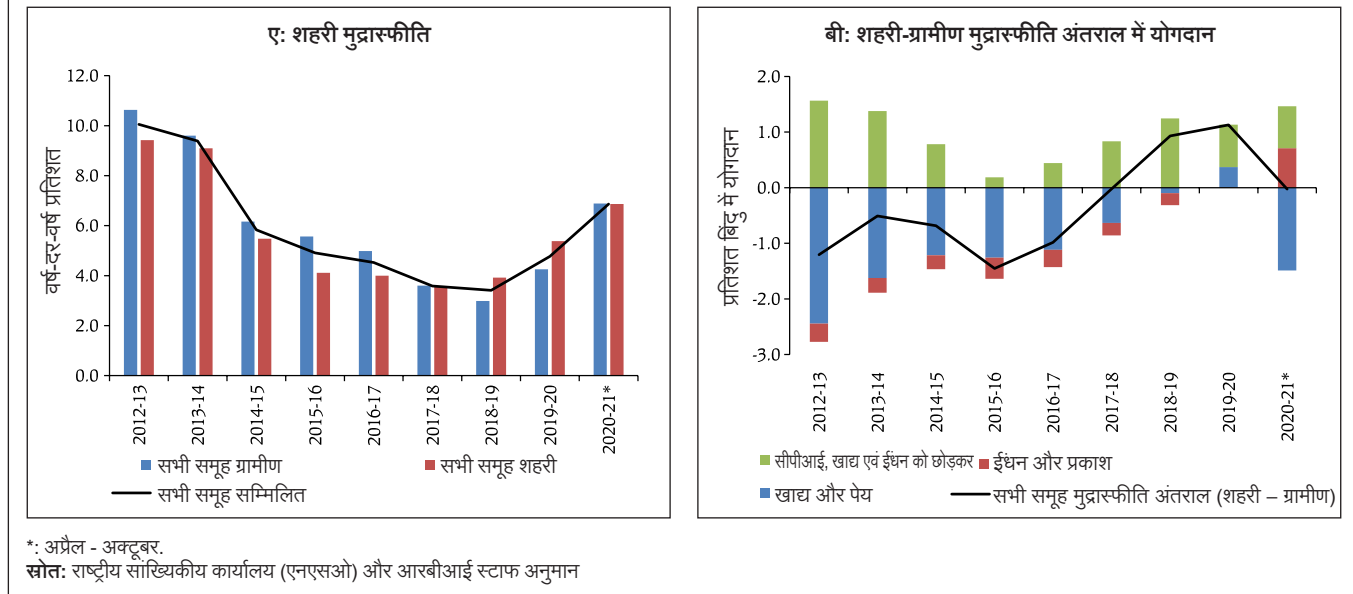
II. सरलीकृत तथ्य

वर्ष 2012-13 से 2018-19 के दौरान हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति¹ में महत्वपूर्ण और लगातार कमी और उसके बाद वृद्धि देखने को मिली ग्रामीण और शहरी- दोनों मुद्रास्फीति में एक जैसी प्रवृत्ति दिखी और इसमें एकमात्र अंतर यही रहा कि 2018-19 से शहरी मुद्रास्फीति बढ़ने लगी। इसके अतिरिक्त, वार्षिक औसत शहरी मुद्रास्फीति जो 2017-18 तक ग्रामीण मुद्रास्फीति से कम थी, वह वर्ष 2018-19 और 2019-20 में इससे अधिक हो गई (चार्ट 1ए)। शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति के बीच अंतर में खाद्य और खाद्येतर दोनों प्रकार की मुद्रास्फीति का हाथ रहा (चार्ट 1बी)।

वार्षिक मुद्रास्फीति में बड़े समूहों के योगदान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में होने वाली गतियों को ढंक देते हैं क्योंकि सीपीआई समूहों की संरचना में विभिन्नता है।

¹ भारत में, आधार वर्ष 2012=100 लेकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसो), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (एमओएसपीआई), भारत सरकार मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) शृंखला में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन के आधार पर हेडलाइन मुद्रास्फीति मापी जाती है और अगस्त 2016 से लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे के तहत इसका उपयोग मुद्रास्फीति लक्ष्य को परिभाषित करने के लिए किया गया है। सीपीआई-सी, उध्वगामी पद्धति पर बनता है जिसमें पहले आइटम स्तर और फिर राज्यों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उप-समूह / समूह स्तर पर मूल्य सूचकांक का संकलन होता है जिसके बाद उनको तत्संबंधी निर्धारित भार का प्रयोग करके संयुक्त किया जाता है।

चार्ट 1 : ग्रामीण – शहरी मुद्रास्फीति अंतर



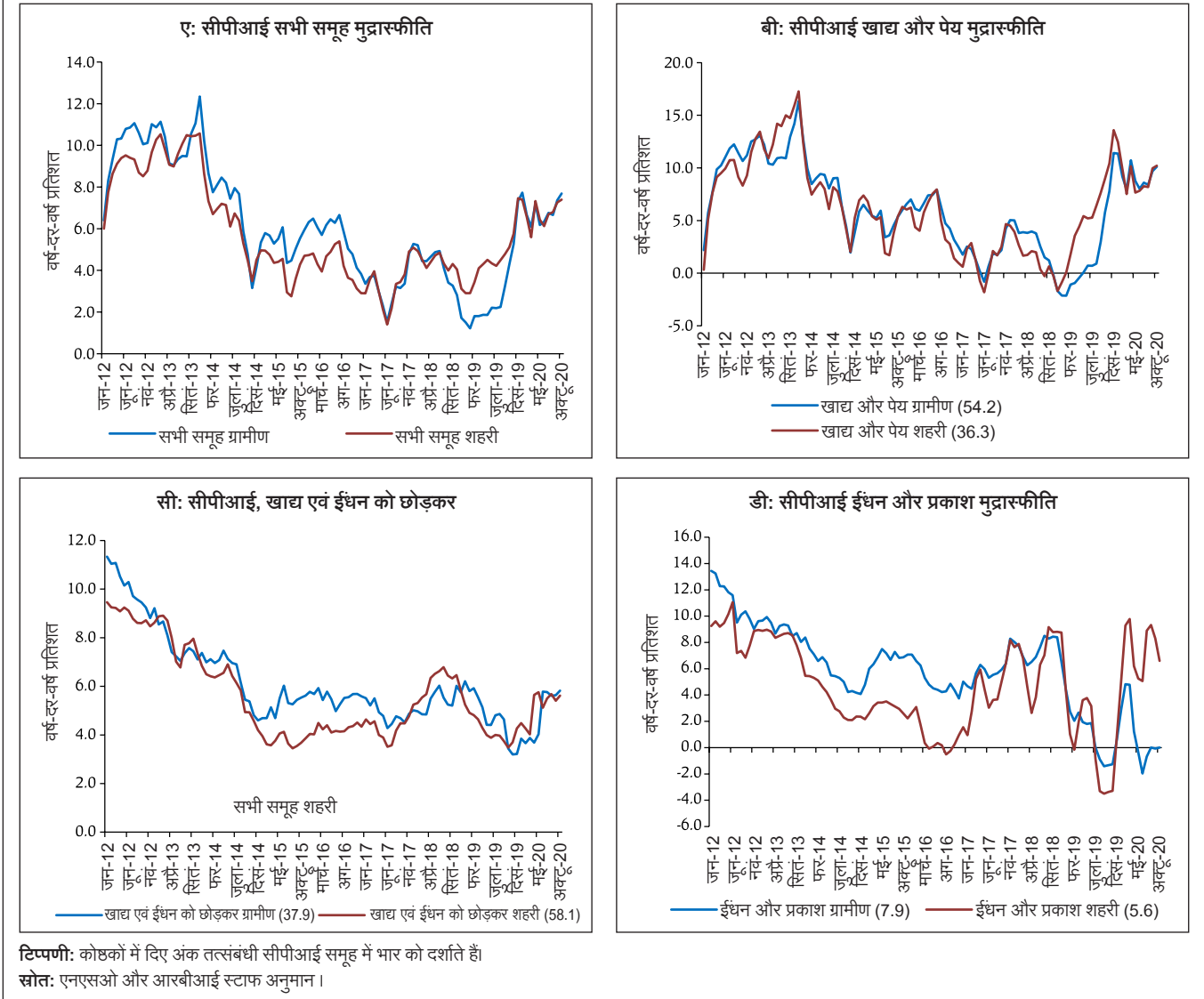
मासिक डाटा से यह समझा जा सकता है कि वर्ष 2012-20 के दौरान ग्रामीण और शहरी सभी समूहों की मुद्रास्फीति में प्रायः अंतर रहा है लेकिन अंतर का लंबे समय तक न बने रहना उनके बीच एक दीर्घावधि संबंध की ओर इंगित करता है (चार्ट 2ए)। आगे इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि इस अवधि में यह विचलन सीपीआई के किसी एक घटक से चालित न होकर विभिन्न अवधियों में इसके विभिन्न घटकों- जैसे खाद्य, ईंधन और खाद्य व ईंधन आइटमों से इतर - का परिणाम है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2018-19 के दौरान ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच देखा गया अंतर मुख्यतः आपूर्ति आघातों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में आए फर्क के कारण था (चार्ट 2बी), जबकि वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान यह विचलन खाद्य और ईंधन से इतर मुद्रास्फीति के कारण हुआ (चार्ट 2सी)। दूसरी ओर, ईंधन मुद्रास्फीति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कभी-कभी बड़े अंतर देखने को मिलते हैं जिसका कारण है खपत के स्वरूप में अंतर, जीवाश्म ईंधनों के मूल्य निर्धारण का उत्तरोत्तर बाजार से जुड़ा होना और पारंपरिक ईंधन वस्तुओं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों जलाऊ लकड़ी और चिप्स और गोबर के उपलों में के दबे हुए मूल्य दबाव (चार्ट 2डी)। (चार्ट 2डी). वर्ष 2021-21 में अभी तक, कोविड-19 के कारण तालाबंदी (लॉकडाउन) कार्रवाइयों और और संबन्धित आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति को मजबूती मिली है। तथापि ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति ने

महत्वपूर्ण अभिसरण दर्शाया है जो मुख्यतः अप्रैल-मई 2020 के बाद खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के रुझानों को प्रतिबिंबित करता है। इसका कारण कोविड-19 के प्रसार - बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में पर पहले शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित - का स्वरूप और उसे रोकने हेतु लागू किए गए विभिन्न लॉकडाउन उपाय हो सकते हैं।

खाद्य मुद्रास्फीति की गतिमान आयामों की गहन जांच से यह पता चलता है कि खाद्य मूल्यों में वृद्धि के दौरान आम तौर पर शहरी खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति ग्रामीण खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक होती है, जबकि गिरावट के समय इसकी स्थिति विपरीत होती है। यह घटना दोनों में देखी जाती है - सब्जियों (विकारियों) और अन्य खाद्य उत्पादों, अर्थात् सब्जियों से इतर खाद्य पदार्थों में। ऐसे विषम व्यवहार का आंशिक कारण आपूर्ति शृंखला के व्यवधान जैसे बाढ़, गैर-मौसमी वर्षा या ट्रांसपोर्टों की हड़ताल हो सकती है जिसके कारण खाद्य उत्पादों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवहन मुश्किल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य निर्धारण अवसरवादी हो जाता है और इसलिए शहरी खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। हालांकि, जैसे ही आपूर्ति की स्थिति सामान्य होती है और सुगमता का चक्र प्रारम्भ होता है, शहरी कीमत तेजी से गिरती है क्योंकि विक्रेता अपने स्टॉक्स बेचकर साफ कर देना चाहते हैं।

ईंधन समूह में, वर्ष 2018-19 तक उच्च स्तर पर रहने के बाद ग्रामीण ईंधन मुद्रास्फीति नरम पड़ने लगी क्योंकि स्वच्छ

चार्ट 2: सीपीआई मुद्रास्फीति – ग्रामीण बनाम शहरी



ईंधन जैसे एलपीजी [प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के कारण] और बिजली [दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)] एवं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य के कारण], के प्रसार से जलाऊ लकड़ी और चिप्स जैसे मदों में मूल्य दबाव कम हुआ। खाद्य और ईंधन के अतिरिक्त वर्ग में, विगत तीन वर्षों में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के मध्य अंतर में काफी कमी आयी है, जिसमें मुख्यतः वस्त्र और जूते-चप्पल, स्वास्थ्य, निजी देखभाल एवं संबंधित वस्तुएं, घरेलू सामान और सेवाओं का योगदान है। सरकार द्वारा वित्तपोषित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं [यथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और अन्य राज्य स्तरीय

स्वास्थ्य बीमा योजनाओं] के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार ने भी इस अंतर को कम करने में योगदान दिया होगा।

इस प्रकार, विभिन्न प्रकरणों में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच फर्क जहाँ विभिन्न घटकों के कारण रहा, यह फर्क अधिक समय तक एक ही दिशा में कायम नहीं रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य मुद्रास्फीति की तुलना का आधार दो मूल्य सूचकांक हैं (न कि कच्ची कीमतें), यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि सूचकांकों के निर्माण के तरीके से भी कुछ विचलन / फर्क आ सकता है, अर्थात कवरेज, नमूना चयन (सैंपलिंग), मूल्य संग्रह प्रणाली (प्राइस कलेक्शन मेकानिज्म), और संबन्धित सीपीआई बास्केट

में मदों/ सह-समूहों/ समूहों के भार में अंतर के कारण। उदाहरण स्वरूप, खाद्य समूह का शहरी सीपीआई (36.3%) की तुलना में ग्रामीण सीपीआई में भार अधिक (54.2%) है, जबकि ग्रामीण सीपीआई में कोई आवासीय घटक नहीं है (तालिका 1)। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर मूल्य संग्रह प्रणाली में था - अक्टूबर 2018 तक

सारणी 1: सीपीआई-ग्रामीण और सीपीआई-शहरी समूह संघटन की तुलना

	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
विश्व (यूनिवर्स)	अखिल भारत ग्रामीण घर (हाउसहोल्ड्स)	अखिल भारत शहरी घर (हाउसहोल्ड्स)	
केंद्र/कीमत दर (सेंटर/प्राइस कोटेशनस)	268351 दर (कोटेशन) के साथ देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1181 ग्रामीण बाजार	281001 कोटेशन के साथ देश के 310 शहरों में फैले हुए 1114 शहरी बाजार	
ली गई वस्तुएं	225	250	299
प्रमुख समूहों व उप-समूहों के भार			
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
अनाज और अनाज के उत्पाद	12.4	6.6	9.7
मांस और मछली	4.4	2.7	3.6
अंडा	0.5	0.4	0.4
दूध एवं दुग्ध-उत्पाद	7.7	5.3	6.6
तेल एवं वसा	4.2	2.8	3.6
फल	2.9	2.9	2.9
सब्जियां	7.5	4.4	6.0
दालें और उत्पाद	3.0	1.7	2.4
चीनी और मिष्ठान	1.7	1.0	1.4
मसाले	3.1	1.8	2.5
मादकेतर पेय पदार्थ	1.4	1.1	1.3
तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाइयां आदि	5.6	5.5	5.6
खाद्य और पेय पदार्थ	54.2	36.3	45.9
पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	3.3	1.4	2.4
वस्त्र	6.3	4.7	5.6
जूते-चप्पल	1.0	0.9	1.0
कपड़े और जूते-चप्पल	7.4	5.6	6.5
आवास	-	21.7	10.1
ईंधन और प्रकाश	7.9	5.6	6.8
घरेलू सामान और सेवाएं	3.8	3.9	3.8
स्वास्थ्य	6.8	4.8	5.9
परिवहन और संचार	7.6	9.7	8.6
मनोरंजन और मनोविनोद	1.4	2.0	1.7
शिक्षा	3.5	5.6	4.5
निजी देखभाल एवं संबंधित वस्तुएं	4.3	3.5	3.9
विविध	27.3	29.5	28.3
खाद्य और ईंधन को छोड़कर सभी समूह	37.9	58.1	47.3
	100.0	100.0	ग्रामीण:53.5 शहरी:46.5

टिप्पणी : आवास समूह ग्रामीण सीपीआई का हिस्सा नहीं है।

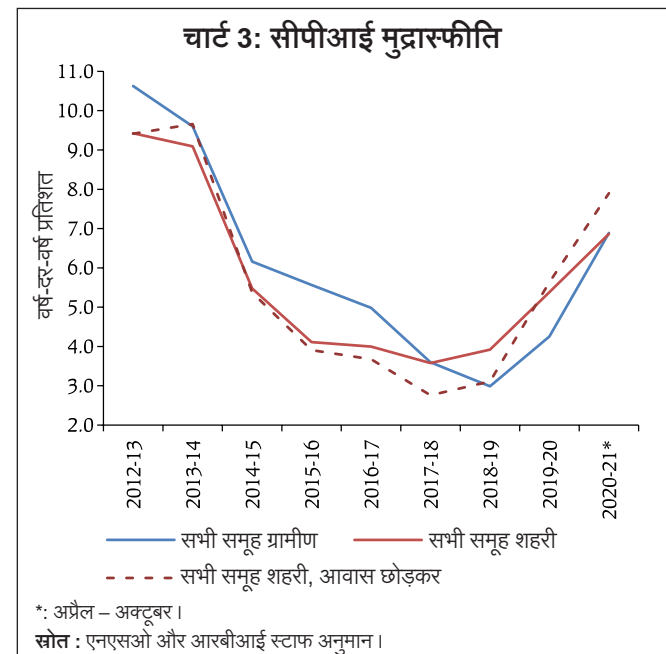
स्रोत : एनएसओ और डीएस व अन्य., 2017

शहरी क्षेत्रों में मूल्य संकलन का कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) और ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस कर रहे थे, उसके बाद से ग्रामीण और शहरी सीपीआई, दोनों के लिए यह जिम्मेदारी एनएसओ को सौंप दी गई।

ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति को और अधिक तुलनीय बनाने हेतु आवासीय क्षेत्र को और अधिक समायोजन (एडजस्टेबल) के बावजूद भी, पूरी अवधि के दौरान 2017-18 तक वार्षिक औसत सीपीआई शहरी मुद्रास्फीति ग्रामीण सीपीआई मुद्रास्फीति से नीचे रही; और 2019-20 (चार्ट 3) के बाद से यह ऊपर अधिक रही।

प्रमुख सारांश सांख्यिकी एक विश्लेषण से यह पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति का आचरण सीपीआई-सी (हेडलाइन) के समान है, विशेषतः, माध्य (मीन) और अस्थिरता (वोलेटिलिटी) के संदर्भ में (जैसा कि मासिक वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति के मानक विचलन द्वारा मापा गया) (सारणी 2)। इन दो क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति के माध्य और अस्थिरता और भी करीब हैं।

उप राष्ट्रीय नीति में परिवर्तनों के साथ-साथ राष्ट्रीय नीति में बदलाव के असममित प्रभाव भी क्षेत्रीय मुद्रा स्थिति में अंतर उत्पन्न कर सकते हैं। चीन में नीतिगत बदलावों ने कुछ समय तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मूल्य सूचकांक के अंतर को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (झेंग सूचन, 2010)। भारत



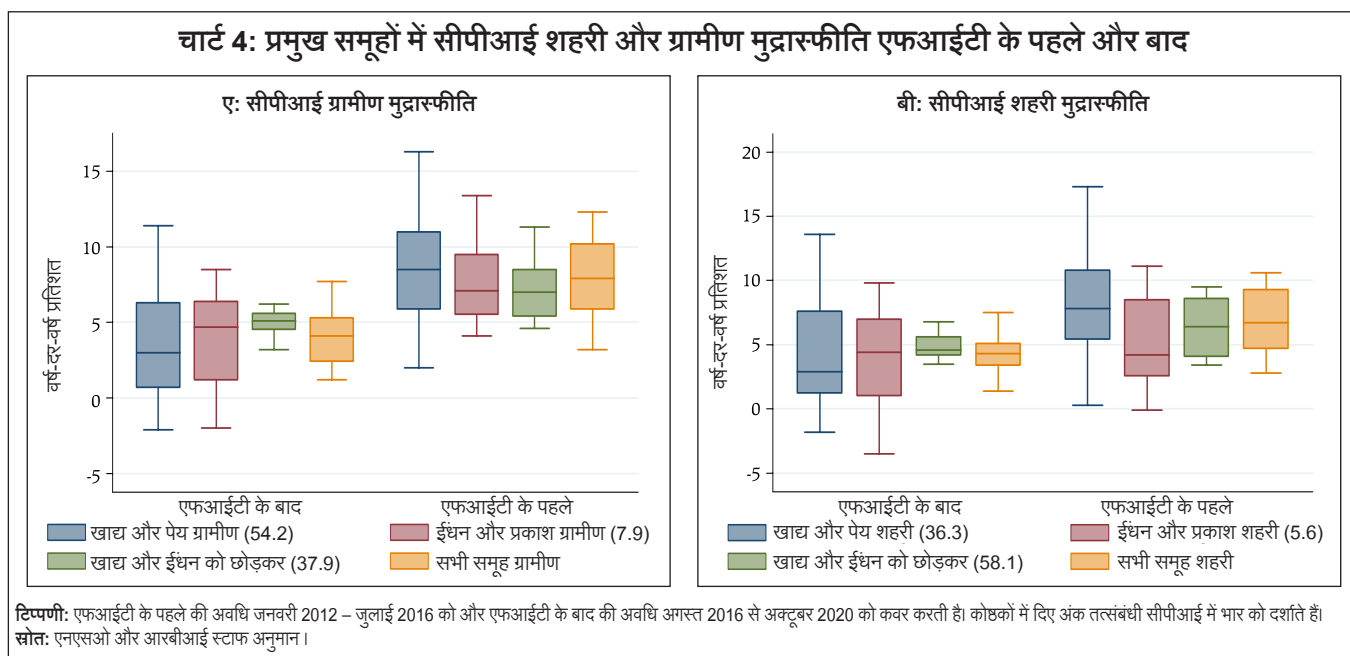
सारणी 2: अखिल भारत, ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति – सारांश सांख्यिकी

	तत्संबंधी सीपीआई में भार	जनवरी 2012-अक्टूबर 2020 (पूरा सैंपल)						
		माध्य (मीन)	माध्यिका (मीडियन)	अधिकतम	न्यूनतम	मानकविचलन	वैषम्य (सक्यूनेस)	ककुदता (कर्टोसिस)
सीपीआई – सी मुद्रास्फीति	100.0	5.9	5.4	11.5	1.5	2.6	0.5	2.1
खाद्य	45.9	6.2	6.2	16.7	-1.7	4.2	0.1	2.2
ईंधन	6.8	5.4	5.4	11.9	-2.2	3.1	-0.1	2.9
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	47.3	5.8	5.1	10.3	3.4	1.7	1.0	3.0
ग्रामीण मुद्रास्फीति	100.0	6.1	5.9	12.3	1.2	2.8	0.3	2.1
खाद्य	54.2	6.2	6.0	16.3	-2.1	4.2	0.0	2.1
ईंधन	7.9	5.9	6.3	13.4	-2.0	3.4	-0.3	2.9
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	37.9	6.1	5.6	11.3	3.2	1.8	1.2	3.9
शहरी मुद्रास्फीति	100.0	5.8	4.9	10.6	1.4	2.4	0.6	2.2
खाद्य	36.3	6.2	6.2	17.3	-1.8	4.3	0.3	2.4
ईंधन	5.6	4.6	4.4	11.1	-3.5	3.5	-0.2	2.3
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	58.1	5.6	4.9	9.5	3.4	1.8	0.8	2.3

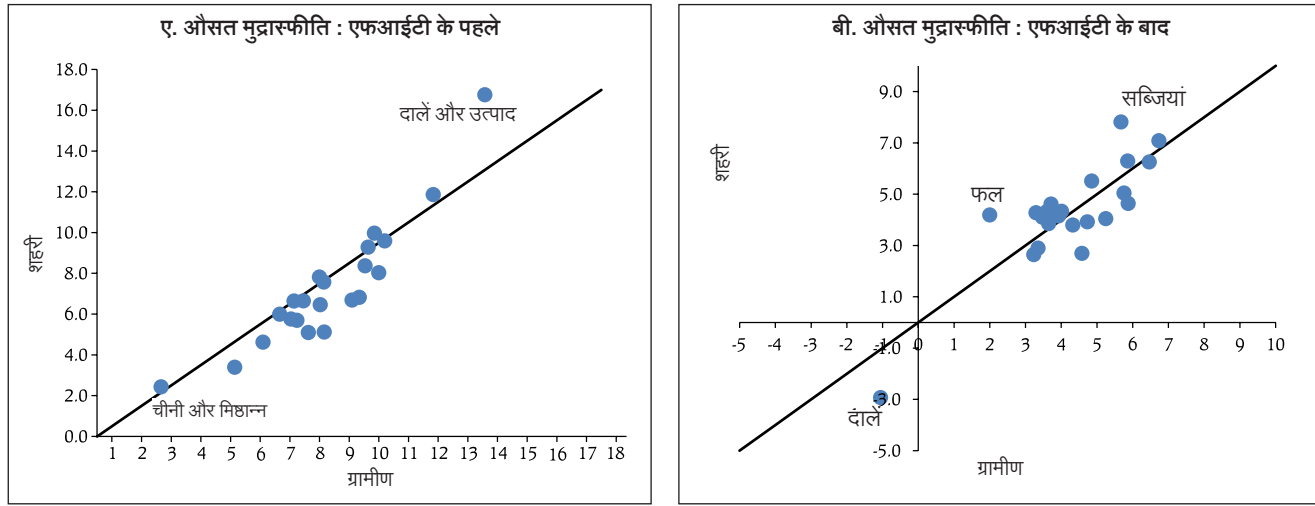
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान

में कर, सब्सिडी, कृषि विपणन सुधार और लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के रूप में नीतिगत हस्तक्षेप ने भी क्षेत्रीय मूल्य अंतरों में योगदान दिया होगा, मुख्यतः कवरेज/ अभिगम के अनुसार असममित प्रभाव के कारण। वास्तव में वर्ष 2016-2020 के दौरान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रमुख समूहों की मुद्रास्फीति और समग्र मुद्रास्फीति उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, यद्यपि कुछ अंतरों के साथ जो कि भारत में एफआईटी फ्रेमवर्क या ढांचे को अपनाए जाने के समय घटित हुए (चार्ट 4)।

उप समूह स्तर पर अधिकांश घटकों के लिए एफआईटी अपनाए जाने से पहले ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से अधिक थी। एफआईटी के बाद, उप समूहों में मुद्रास्फीति करीब 4 प्रतिशत के आसपास घूमती प्रतीत होती है, जो कि घटकों के बीच मुद्रास्फीति के फैलाव में सामान्य कमी को दर्शाती है, कुछ को छोड़कर यथा फल व सब्जियों जैसे विकारी पदार्थ और दालें (चार्ट 5)।



चार्ट 5: सीपीआई – ग्रामीण और सीपीआई शहरी उप समूह मुद्रास्फीति : एफआईटी के पहले और बाद (उस अवधि के लिए मासिक औसत)



टिप्पणी: एफआईटी के पहले की अवधि जनवरी 2012 – जुलाई 2016 को और एफआईटी के बाद की अवधि अगस्त 2016 से अक्टूबर 2020 को कवर करती है।

मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय परिवर्तन के साथ 2018 तक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति निरंतरता या पश्चमुखी कीमत निर्धारण व्यवहार में कमी भी सामने आई, अलबत्ता कुछ अंतर के साथ (चार्ट 6 ए)। फसलों और आपूर्ति पर दुष्प्रभाव डालने वाले वाले बेमौसम और अत्यधिक बारिश से खाद्य कीमतों को लगे आघातों के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति आग्रह बढ़ा और बाद में आपूर्ति श्रृंखला के क्रमिक सामान्यीकरण के साथ पुनः घटा ²। हेडलाइन मुद्रास्फीति का प्रवृत्ति और चक्र में विश्लेषण दर्शाता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रवृत्ति मुद्रास्फीति का आचरण समान है, यद्यपि ग्रामीण मुद्रास्फीति की तुलना में शहरी मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रवृत्ति का अपेक्षाकृत पहले विपर्यय दिखाई देता है (चार्ट 6.बी)। हालांकि यह देखना दिलचस्प है कि शहरी और ग्रामीण दोनों मुद्रास्फीति में चक्रीय घटकों ने काफी हद तक एक जैसा व्यवहार किया है।

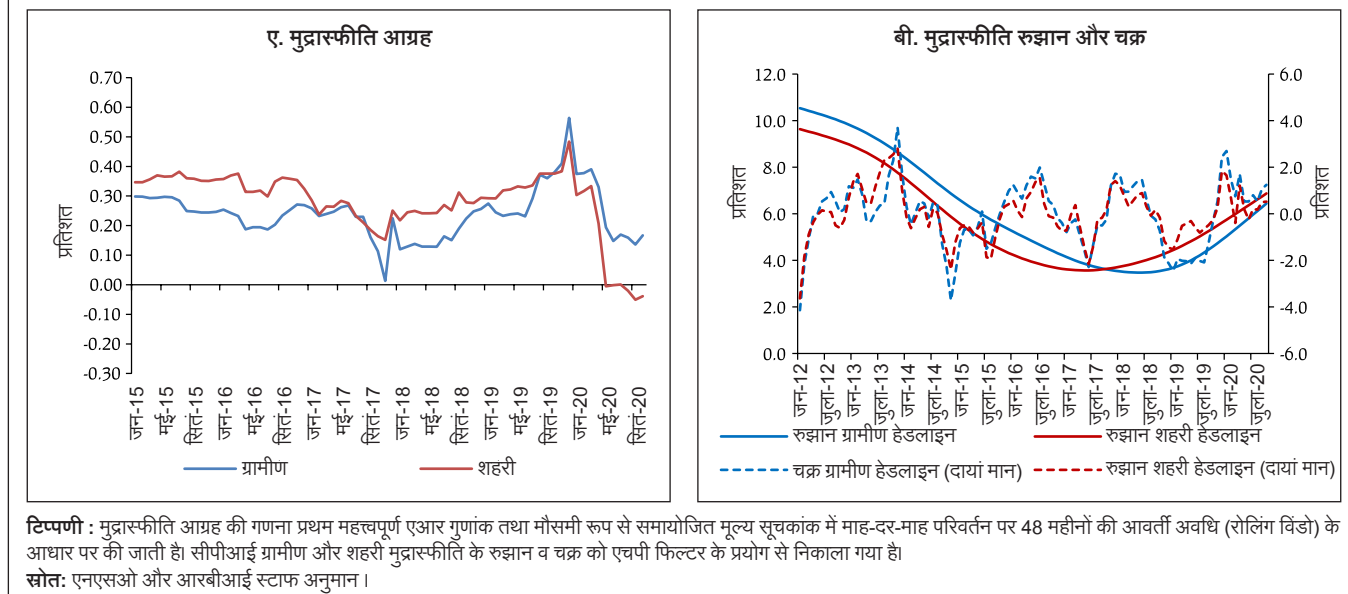
III. साहित्य समीक्षा

यूरो क्षेत्र में यूरो मुद्रा को अपनाए जाने के बाद क्षेत्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति के गतिमान आयामों ने साहित्य में विशेष महत्व प्राप्त किया (वेबर एंड बेक, 2005 और बेक व अन्य. 2009)। हार्मोनाइज्ड इंडेक्स ऑफ़ कन्ज्यूमर प्राइसेज (एचआईसीपी)

के आधार पर पूरे यूरो क्षेत्र के औसत मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए प्रासंगिक सबक हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भी क्षेत्रीय मूल्य के समीकरणों का विश्लेषण किया गया है (सेसचेटी व अन्य. 2002)। यह देखते हुए कि पूरे देश/ समान मुद्रा क्षेत्र (सीसीए) के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण तभी तर्कसंगत है जब सीसीए/ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति की दर एक-दूसरे से बहुत भिन्न नहीं होती है, मुद्रास्फीति के अंतर के कारणों पर नीति निर्माता अक्सर ध्यान देते हैं। मुद्रास्फीति में अंतर अर्थव्यवस्था में रुद्धियों का द्योतक हो सकते हैं और वास्तविक ब्याज दरों में अंतर के कारण इनसे प्रतिस्पर्धा को हानि हो सकती है (अलबेरोला, 2000) तथा इससे अस्थिरकारी असममित प्रभाव की संभावना बनती है (बेक व अन्य. , 2009)। मुद्रास्फीति में देखे गए अंतर के कारणों का परीक्षण कई अध्ययनों में किया गया है (हेंड्रिक्स एंड चैपल, 2002; ईसीबी, 2003; ईसीबी, 2005)। यूरोपीय संघ के देशों के बीच मुद्रास्फीति की दरों में अंतर के कुछ कारणों में विनिमय दर की गति के विभेदक प्रभाव (होनोहन एंड लेन, 2003, 2004), मुद्रास्फीति आग्रह (एंजीलोनी एंड इहरमान, 2004) और मांग के आघातों के मुकाबले आपूर्ति आघातों की भूमिका (डुआर्टे एंड वोलमन, 2002) शामिल हैं। उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में, ग्रामीण-शहरी मूल्य के अंतर को समझने हेतु चीन के लिए किया गया एक अध्ययन नीतिगत बदलावों, उपभोक्ता वस्तुओं

² हाल की अवधि यानी मई-अक्टूबर 2020 के लिए एआर गुणांक 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं हैं, विशेषतः शहरी मुद्रास्फीति के लिए।

चार्ट 6: सीपीआई ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति – आग्रह और रुझान



की शहरी-ग्रामीण खुदरा बिक्री, शहरीकरण के स्तर और स्थिर आस्तियों के निवेश की भूमिका पर प्रकाश डालता है (झांग ज्यूशन, 2010)। विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में व्यवस्थित अंतर निर्वाह-व्यय में अंतर के संकेत दे सकते हैं; अतः आर्थिक परिणामों की व्याख्या में स्थानिक कीमत के अंतर को अनदेखा करना भ्रामक हो सकता है (ब्राण्ट एंड होल्त्ज, 2006)।

साहित्य की एक जुड़ी हुई धारा ने माध्य विपर्यय (मीन रिवर्टिंग) व्यवहार और मुद्रास्फीति दरों के समग्र अंतर क्षेत्रीय फैलाव की जाँच की है। बारो और सला-ई मार्टिन के कार्य के आधार पर यूरोपीय संघ के अलग-अलग क्षेत्रों की मुद्रास्फीति की दरों पर किए गए एक अध्ययन से एक निश्चित समय अवधि के दौरान मुद्रास्फीति फैलाव (डिस्पर्सन) में गिरावट और महत्वपूर्ण माध्य विपर्यय (मीन रिवर्टिंग) व्यवहार, भले ही अपेक्षाकृत कम दर पर, का पता चलता है (वेबर एंड बेक, 2005)। संयुक्त राज्य के शहरों में कीमतों के अभिसरण में एक धीमी गति भी देखी गई है (सेसचेटी व अन्य, 2002)। इसी की तर्ज पर सह-एकीकरण और त्रुटि सुधार तकनीक का प्रयोग करते हुए चीन के लिए हुए एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्रामीण कीमत स्तर शहरी कीमत के स्तर की ओर अभिसरित होता है (झांग ज्यूशन, 2010)। अर्जेंटीना के छः क्षेत्रों में वर्ष 2016-2019 की अवधि के लिए लॉ ऑफ वन प्राइस (एलओपी) के अनुपालन की पड़ताल से सभी क्षेत्रों में कीमतों

और सह-एकीकरण में अभिसरण के अस्तित्व पता चलता है (गोंजलेज, 2020)।

भारत के मामले में अधिकांश साहित्य ने क्षेत्रीय मुद्रास्फीति के गतिमान आयामों को प्रभावित करने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित किया है जिनमें परिवहन लागत, राज्यों की प्राकृतिक धरोहर, कारक गतिशीलता पर प्रतिबंध, क्षेत्र-विशेष में खपत की वस्तुएं, मुद्रास्फीति सातत्य, राज्य सरकारों की व्यय व कर नीतियां, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि तथा अन्य आपूर्ति पक्ष एवं संरचनात्मक कारकों को सम्मिलित किया गया है (दास एंड भट्टाचार्य, 2008; झा एंड ढल, 2019; पटनायक, 2016)। ग्रामीण मुद्रास्फीति के शहरी मुद्रास्फीति से अधिक पाए जाने पर पर भंडारी और श्रीनिवास (2015) ने यह निष्कर्ष निकाला कि संरचनात्मक अड़चनों के चलते ग्रामीण भारतीय वैश्विक अवस्फीति का लाभ पूरी तरह नहीं ले पा रहे हैं। राज्यों के मध्य मुद्रास्फीति के अंतर को कीमतों के अभिसरण और आगे चलकर राज्य स्तर पर मुद्रास्फीति के बराबरी पर आने से समझा जा सकता है (पटनायक, 2016)। खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के कारण राज्यों में मुद्रास्फीति में व्यापक अंतर के बावजूद, राज्य स्तर की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति समय के साथ राष्ट्रीय मुद्रास्फीति की ओर अभिसरित होने की होती है, जो भारत में मौद्रिक नीति के लिए सांकेतिक अधिकालक/स्थिरक (नॉमिनल एंकर) के रूप में राष्ट्रीय स्तर की सीपीआई मुद्रास्फीति के चयन का दृढ़ आधार बनती है (कुंडू व अन्य 2018)।

IV. सह-एकीकरण और अभिसरण

समय के साथ ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति (अखिल भारतीय स्तर पर) के बीच घनिष्ठ सह-संचरण को देखते हुए, दोनों के बीच दीर्घवाधि संतुलन संबंध के अस्तित्व का परीक्षण करने के लिए जनवरी 2012-अक्टूबर 2020 के लिए मुद्रास्फीति के मासिक आंकड़े पर पूर्णतः संशोधित साधारण न्यूनतम वर्ग (एफएमओएलएस) (फिलिप्स और हैन्सन, 1990) द्वारा एकल समीकरण ढाँचे में एक प्रयोग किया गया। चूँकि दोनों ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति श्रृंखलाएं स्तर पर अनप्रगामी पाई गई, अपितु एकीकरण के एक ही स्तर के साथ (यानी, $I(1)$), एफएमओएलएस का उपयोग करके निम्नलिखित एकल समीकरण सहएकीकारी प्रतीपगमन (अर्थात्, दीर्घवाधि समीकरण) का आकलन किया गया था:

$$urban\ inflation_t = \alpha + \beta rural\ inflation_t + \gamma_1 DUM\ 2013 + \gamma_2 DUM\ 2018 + u_t \dots (1)$$

जहाँ डीयूएम 2013 (मई-अगस्त 2013 = 1, अन्यथा '0') ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच विचलन की दिशा में टेपर टैंट्रम प्रभाव और अस्थायी विपथन को पकड़ने के लिए लाया गया है, जबकि डीयूएम 2018 (अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 = 1, अन्यथा '0') अक्टूबर 2018 में, डाकघरों से लेकर एनएसओ क्षेत्र (फील्ड) स्टाफ तक, ग्रामीण सीपीआई हेतु डेटा संग्रह प्रणाली में बदलाव के लिए लाया गया है।

अगले चरण में, व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले एंगल-ग्रेंजर (1987) टू-स्टेप एप्रोच (गेरार्ड और गॉडफ्रे, 1998) की तरह, समीकरण (1) से ओएलएस का उपयोग करते हुए त्रुटि सुधार प्रणाली (ईसीएम) के आकलन हेतु वन पीरियड-लैंग्ड इक्विलिब्रियम एरर (\hat{u}_{t-1}) का इस प्रकार प्रयोग किया गया:

$$\Delta urban\ inflation_t = \alpha + \beta_1 \Delta rural\ inflation_t + \beta_2 \hat{u}_{t-1} + \epsilon_t \dots (2)$$

जहाँ Δ अंतर परिचालक (डिफरेंस ऑपरेटर) है और β_2 त्रुटि सुधार अवधि (एरर करेक्शन टर्म) का गुणांक है। एक ऋणात्मक और महत्वपूर्ण β_2 दीर्घवाधि संतुलन की ओर समायोजन की गति को दर्शाता है।

अनुमानित समीकरण (1) से एंगल-ग्रेंजर ताऊ-स्टेटिस्टिक और जेड-स्टेटिस्टिक (1) ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति (तालिका 3) के बीच एक दीर्घवाधि सह-एकीकारी संबंध होने की पुष्टि करता है (सारणी 3)। इसके अलावा, समीकरण (2) में त्रुटि

सारणी 3: सह-एकीकरण परिणाम

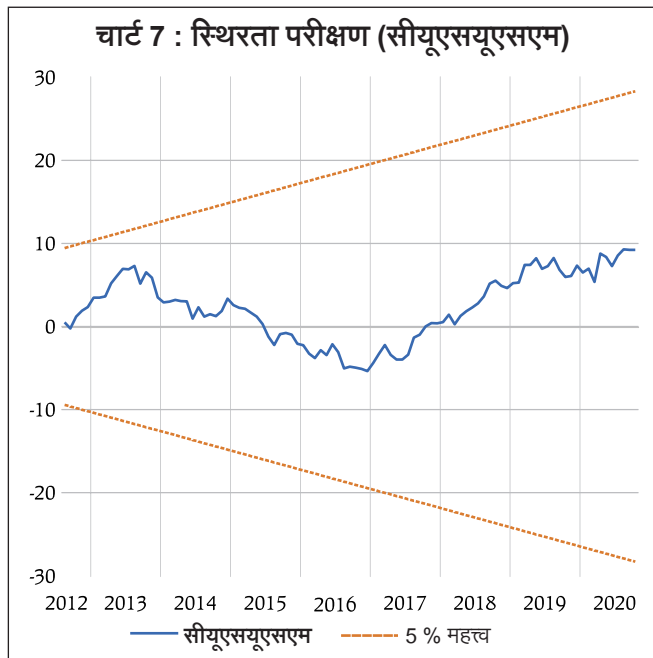
	गुणांक	पी-वैल्यू
दीर्घकालिक अनुमान (आश्रित चर: Δ शहरी मुद्रास्फीति)		
ग्रामीण मुद्रास्फीति	0.88***	0.00
डीयूएम 2013	1.60***	0.01
डीयूएम 2018	1.88***	0.00
स्थिरांक	0.12	0.71
नैदानिकी (डायग्नोस्टिक्स)		
एडीजे.आर ²	0.93	
एंगल – ग्रेंजर ताऊ-स्टेटिस्टिक	-3.76**	0.02
एंगल – ग्रेंजर जेड-स्टेटिस्टिक	-25.39***	0.01
(एचओ: श्रृंखलाएं सह-एकीकृत नहीं हैं)		
अल्पकालिक अनुमान (आश्रित चर: Δ शहरी मुद्रास्फीति)		
Δ ग्रामीण मुद्रास्फीति	0.78***	0.00
Δ ग्रामीण मुद्रास्फीति	-0.18**	0.04
Δ शहरी मुद्रास्फीति	0.19*	0.06
ईसीएम (-1)	-0.12**	0.03
स्थिरांक	0.00	0.99
नैदानिकी (डायग्नोस्टिक्स)		
एडीजे.आर ²	0.77	
आनुक्रमिक सहसंबंध के लिए ब्रेस्क-गॉडफ्रे एलएम परीक्षण (एफ-स्टेटिस्टिक) (एचओ: कोई आनुक्रमिक सहसंबंध नहीं)	1.75	0.18
हेट्रोस्केडेस्टिसिटी के लिए ब्रेस्क-पैगन-गॉडफ्रे परीक्षण (एफ-स्टेटिस्टिक) (एचओ: होमोस्केडेस्टिसिटी)	1.58	0.19

नोट: ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व के स्तर दर्शाते हैं।

सुधार अवधि का गुणांक [$\beta_2 = (-) 0.12$] भी प्रत्याशित ऋणात्मक संकेत के साथ सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया, जो बताता है कि पिछली अवधि के असंतुलन (अर्थात्, वास्तविक और लंबे समय के बीच विचलन) का 12 प्रतिशत हर महीने सुधारा जा रहा है। अवशिष्ट निदान परीक्षण आनुक्रमिक सहसंबंध (सीरियल कोरिलेशन) और विषम विचालिता (हेटरोसेडास्टिसिटी) की अनुपस्थिति दर्शाते हैं जिससे आकलनों के अच्छे होने का संकेत है। पैरामीटर आकलनों की स्थिरता भी वर्गों के संचयी योग (सीयूएसयूएम) परीक्षण द्वारा भी वैध सिद्ध होता है (चार्ट 7)।

चूँकि अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी सीपीआई को राज्य स्तरीय ग्रामीण और शहरी मूल्य सूचकांकों की भारित योग के रूप में संकलित किया जाता है, इसलिए राज्य स्तर पर ग्रामीण

³ दीर्घवाधि संतुलन में समायोजन द्विदिशात्मक पाया गया।

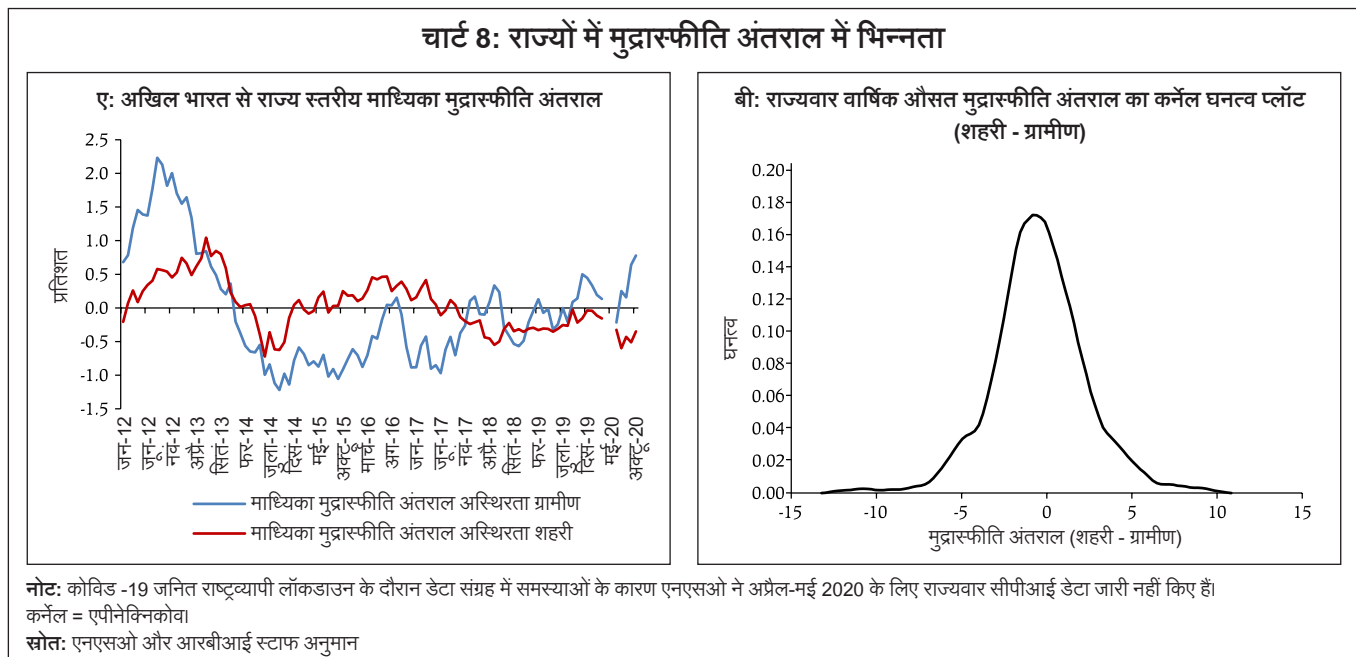


और शहरी मुद्रास्फीति की प्रकृति परीक्षण रोचक है। अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के संबंध में राज्य-स्तरीय औसत ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति अंतर, क्रमशः, समय के साथ घटे हैं, जो राज्यवार ग्रामीण (शहरी) मुद्रास्फीति के अखिल भारतीय ग्रामीण (शहरी) मुद्रास्फीति की ओर अभिसरण का

सूचक है (चार्ट 8.ए)। जैसा कि 2012-13 से 2019-20 के दौरान शहरी ग्रामीण मुद्रास्फीति के बीच राज्यवार वार्षिक औसत अंतर के अनुमानित कर्नेल डेंसिटी प्लॉट के कम या अधिक सममित प्रकृति से जाहिर है, राज्यों में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति अभिसरित होती या एक बिंदु की ओर जाती प्रतीत हो रही है (चार्ट 8.बी)। मुद्रास्फीति के अंतर का दायरा व्यापक है और वितरण भी तुंगककुदी (लेप्टोकर्टिक) है जो बताता है कि ग्रामीण-शहरी जुड़ाव की हदों में फर्क है।

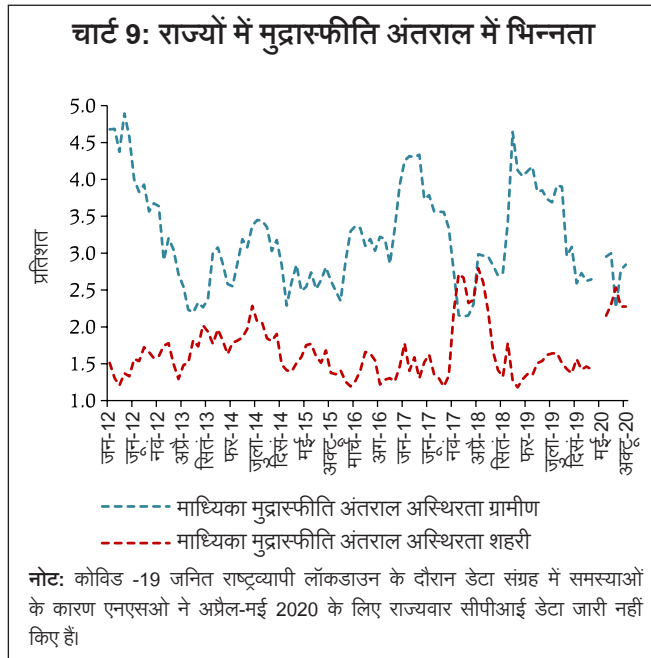
राज्यों में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति का राष्ट्रीय औसत से भिन्न होना किसी विशेष रुझान की अनुपस्थिति दर्शाता है, जो राज्यों में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच संबंध में तुलनात्मक स्थिरता का द्योतक है (चार्ट 9)। इस प्रकार मुद्रास्फीति की वर्तमान क्षेत्रीय भिन्नता राष्ट्रीय स्तर की मुद्रास्फीति मीट्रिक पर आधारित निष्कर्षों और विश्लेषणों को कमजोर नहीं करती।

इस पृष्ठभूमि में, 2012-13 से 2019-20 की अवधि के लिए 35⁴ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को लेकर यादृच्छिक प्रभाव पैनल प्रतिगमन मॉडल में राज्यों में शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति के बीच अभिसरण (कनवर्जेंस) का एक औपचारिक परीक्षण किया गया। साहित्य (वेबर और बेक, 2005), की सहायता से, बिना शर्त अभिसरण की गति की पहचान करने देने वाले



नोट: कोविड -19 जनित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान डेटा संग्रह में समस्याओं के कारण एनएसओ ने अप्रैल-मई 2020 के लिए राज्यवार सीपीआई डेटा जारी नहीं किए हैं।
कर्नेल = एपीनेकिनकोवा
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान

⁴ अरुणाचल प्रदेश को नहीं लिया गया है क्योंकि इस राज्य के लिए सीपीआई शहरी नियमित रूप से प्रकाशित नहीं की जाती।



β अभिसरण का परीक्षण निम्नलिखित समीकरण के आकलन द्वारा किया गया:

$$\Delta(\pi_{i_{ut}} - \pi_{i_{rt}}) = \alpha + \beta(\pi_{i_{ut-1}} - \pi_{i_{rt-1}}) + \epsilon_{it} \quad \dots (3)$$

जहां, Δ अंतर परिचालक (डिफरेंस ऑपरेटर) है, i राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, $\pi_{i_{ut}}$ और $\pi_{i_{rt}}$ क्रमशः राज्य वार शहरी और ग्रामीण वार्षिक औसत मुद्रास्फीति हैं, और ϵ_{it} त्रुटि अवधि है। β^5 का ऋणात्मक संकेत बताता है कि अभिसरण है और इसका (पूर्ण) आकार अभिसरण की गति को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, β के ऋणात्मक संकेत का अर्थ यह होगा कि एक प्रारंभिक अपेक्षाकृत उच्च शहरी-ग्रामीण मुद्रास्फीति अंतराल वाले राज्य प्रारंभिक अपेक्षाकृत कम शहरी-ग्रामीण मुद्रास्फीति अंतराल वाले राज्यों की तुलना में बाद की अवधि में मुद्रास्फीति का अधिक धीमेपन से (या मुद्रास्फीति में कमी का तेजी से) अनुभव करेंगे। इस प्रकार, राज्यों में शहरी-ग्रामीण मुद्रास्फीति दर का मौजूदा अंतराल कम हो जाएगा। हमारे विश्लेषण के परिणाम β अभिसरण के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, अर्थात्, राज्यों में ग्रामीण शहरी मुद्रास्फीति का अभिसरण और यह कि राज्य स्तर पर मुद्रास्फीति के प्रति किसी भी आघात का प्रभाव यथोचित गति से घटता जाता है (सारणी 4)। ब्रेच-पैगन लैंगरेंज मल्टीप्लायर (एलएम) परीक्षण से पता चलता है

⁵ जैसा कि वेबर और बेक, 2005 में बताया गया है; यह ध्यान दिया जा सकता है कि – वृद्धि संबंधी साहित्य के विपरीत - समायोजन गति के लिए बताए गए उपायों में सुदृढ़ सैद्धांतिक नींव का अभाव है। फिर भी, वे कुछ विचार दे सकते हैं कि कितनी तेजी से अभिसरण होता है।

सारणी 4: बीटा अभिसरण परीक्षण के परिणाम⁶ (ओएलएस परिणाम)

निरूपक चर	आश्रित चर: Δ मुद्रास्फीति गैप (शहरी ग्रामीण)	
	(35 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र; अवधि: 2012-13 से 2019-20) #	
	गुणांक	जेड - वैल्यू
$\pi_{i_{ut-1}} - \pi_{i_{rt-1}}$ (Inflation Gap _{i,t-1})	-0.64	-9.63***
स्थिरांक	-0.27	-2.68***
प्रेक्षणों की संख्या	245	
वाल्ड ची ² (1)	92.66***	
आर- वर्गीकृत (आर - स्क्वायर्ड)	अंतर्गत = 0.3062, के बीच = 0.2982, समग्र = 0.3044	

नोट: ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व के स्तर दर्शाते हैं।

#: कोविड -19 जनित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान डेटा संग्रह में समस्याओं के कारण एनएसओ ने अप्रैल-मई 2020 के लिए राज्यवार सीपीआई डेटा जारी नहीं किए हैं और इसलिए यह कार्य (एक्सरसाइज़) 2019-20 में बंद है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान

कि ओएलएस प्रतिगमन एक यादृच्छिक प्रभाव पैनल प्रतिगमन की तुलना में बेहतर है और इसलिए, ओएलएस परिणामों को एक मजबूती जाँच के रूप में भी रिपोर्ट किया जाता है (सारणी 5)।

प्रायोगिक तौर पर देखे गए समग्र स्तर पर ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के सह-संचरण और साथ ही राज्य स्तर पर अभिसरण से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्रास्फीति दर भारत

सारणी 5: बीटा अभिसरण परीक्षण के परिणाम (ओएलएस परिणाम)

निरूपक चर	आश्रित चर: Δ मुद्रास्फीति गैप (शहरी ग्रामीण)	
	(35 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र; अवधि: 2012-13 से 2019-20) #	
	गुणांक	टी - वैल्यू
$\pi_{i_{ut-1}} - \pi_{i_{rt-1}}$ (Inflation Gap _{i,t-1})	-0.64	-6.20***
स्थिरांक	-0.27	-1.63
प्रेक्षणों की संख्या	245	
एफ (1, 243)	38.46***	
आर- वर्गीकृत (आर - स्क्वायर्ड)	0.3045	

नोट: ***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर महत्व के स्तर दर्शाते हैं।
#: कोविड -19 जनित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान डेटा संग्रह में समस्याओं के कारण एनएसओ ने अप्रैल-मई 2020 के लिए राज्यवार सीपीआई डेटा जारी नहीं किए हैं और इसलिए यह कार्य (एक्सरसाइज़) 2019-20 में बंद है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान

⁶ एक यादृच्छिक प्रभाव सामान्यीकृत न्यूनतम वर्ग प्रतिगमन (रैंडम जेनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर्स रिसेशन) किया गया। यादृच्छिक प्रभाव और निश्चित प्रभाव पैनल आकलन के बीच चयन हॉसमैन परीक्षण पर आधारित था।

में समग्र मुद्रास्फीति के गतिमान आयामों को अच्छी तरह से दर्शाती है।

V. निष्कर्ष

भारत में ग्रामीण शहरी मुद्रास्फीति के गतिशील आयामों में विभिन्न घटकों - भोजन, ईंधन या खाद्य और ईंधन से इतर - जो लंबे समय तक नहीं टिकते, द्वारा चालित भिन्नता के प्रकरणों के साथ घनिष्ठ सह-संचरण देखने को मिलते हैं। शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति के लिए प्रवृत्ति और चक्रीय घटक दोनों समान पाए गए हैं। पूर्व कोविड-19 अवधि (2018 तक) में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के मामले में मुद्रास्फीति सातत्य में क्रमिक गिरावट भी देखी गई।

प्रायोगिक आकलन बताते हैं कि ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच देखा गया अंतर अस्थायी है और दोनों एक दीर्घावधि संतुलन संबंध दर्शाते हैं, जिसमें अल्पावधि में एक महत्वपूर्ण त्रुटि सुधार है। राज्य स्तर पर भी शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति दरें समय के साथ अभिसरित होती हैं। ये निष्कर्ष राज्यों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सांकेतिक स्थिरक/अधिकीलक (नॉमिनल एंकर) के रूप में एक मुद्रास्फीति लक्ष्य की प्रासंगिकता का समर्थन करते हैं।

संदर्भ:

Alberola Ila, E. (2000), "Interpreting Inflation Differentials in the Euro Area", *Economic Bulletin/Banco de España*, April, pp. 61-70.

Angeloni, I. and M. Ehrmann (2004), "Euro Area Inflation Differentials", European Central Bank, *Working Paper Series* No. 388.

Barro, Robert. J. and Xavier Sala-i-Martin (1992), "Convergence", *Journal of Political Economy*, 100(2), pp. 223-251.

Beck, Guenter W., Kirstin Hubrich and Massimiliano Marcellino (2009), "Regional Inflation Dynamics Within and Across Euro Area Countries and a Comparison with the United States", *Economic Policy*, January, pp. 141-184.

Brandt, Loren and Carsten A. Holz (2006) "Spatial Price Differences in China: Estimates and Implications", *Economic Development and Cultural Change*, *University of Chicago Press*, vol. 55(1), October, pp. 43-86.

Cecchetti, S. G, N. C. Mark, and R. J. Sonora (2002), "Price Index Convergence among United States Cities", *International Economic Review*, 43(4) November, pp. 1081-1099.

Das, Praggya and Asish Thomas George (2017), "Comparison of Consumer and Wholesale Price Indices in India: An Analysis of Properties and Sources of Divergence", *RBI Working Paper Series* No. 05, March.

Das, S. and K. Bhattacharya (2008), "Price Convergence across Regions in India", *Empirical Economics*, 34(2), pp. 299-313.

Duarte, M. and A. L. Wolman (2002), "Regional Inflation in a Currency Union: Fiscal Policy vs. Fundamentals", *European Central Bank Working Paper Series* 180.

Engle, Robert F. and W. J. Granger (1987), "Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing", *Econometrica*, Vol. 55, No. 2, March, pp. 251-276.

European Central Bank (ECB) (2003), "Inflation Differentials in the Euro Area: Potential Causes and Policy Implications", Monetary Policy Committee of the European System of Central Banks, September 2003.

European Central Bank (ECB) (2005), "Monetary Policy and Inflation Differentials in a Heterogeneous Currency Area", *European Central Bank Monthly Bulletin*, May, pp. 61-77.

- Gerrard, W. J. and L.G. Godfrey (1998), "Diagnostic Checks for Single Equation Error Correction and Autoregressive Distributed Lag Models", *The Manchester School*, Vol.66, No.2, March, pp. 222-237.
- Gonzalez, Fernando. A. I. (2020), "Regional Price Dynamics in Argentina (2016–2019)", *Regional Statistics*, Vol. 10. No. 2. pp. 83–94; DOI: 10.15196/RS100205.
- Hendriks, M. and B. Chapple (2002), "Regional Inflation Divergence in the Context of EMU", *MEB Series* (discontinued) 2002-19, Netherlands Central Bank, Monetary and Economic Policy Department.
- Honohan, P. and P. R. Lane (2003), "Divergent Inflation Rates in EMU", *Economic Policy*, 18(37), pp. 357-394.
- Honohan, P. and P. R. Lane (2004), "Exchange Rates and Inflation under EMU: An Update", *The Institute for International Integration Studies Discussion Paper Series* No. 31.
- Jha, Arvind and Sarat Chandra Dhal (2019), "Spatial Inflation Dynamics in India: An Empirical Perspective", *Reserve Bank of India Occasional Papers*, Vol. 40, No. 1.
- Kundu, Sujata, Vimal Kishore and Binod B. Bhoi (2018) "Regional Inflation Dynamics in India", *RBI Monthly Bulletin*, November.
- Patnaik, Anuradha (2016), "Inflation Differential and Inflation Targeting in India", *Prajnan*, Vol-XLV, No. 1.
- Phillips, Peter C. B. and Bruce E. Hansen (1990), "Estimation and Inference in Models of Cointegration: A Simulation Study", *Advances in Econometrics*, Vol 8, pages 225-248.
- Weber, Axel A. and Guenter W. Beck (2005), "Price Stability, Inflation Convergence and Diversity in EMU: Does One Size Fit All?", *Centre for Financial Studies Working Paper* No. 2005/30, November.
- Weyerstrass, K., B. Aarle, M. Kappler and A. Seymen (2011), "Business Cycle Synchronisation within the Euro Area: In Search of a 'Euro Effect'", *Open Economies Review*, 22(3), pp. 427–446.
- Zhang Xuechun (2010), "The Urban-Rural Differences of Inflation in China", *People's Bank of China*, January.

कोविड-19 काल में विनिमय दर अस्थिरता को नियंत्रित करना*

कोविड-19 संक्रमण फैलने के परिणामस्वरूप उभरते बाज़ार की मुद्राओं में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाज़ार में मध्यक्षेप करने समेत परंपरागत और अपरंपरागत साधनों का इस्तेमाल करने के परिणामस्वरूप अस्थिरता, जिसको विभिन्न संकेतकों द्वारा मापा जाता है, मार्च में बढ़ने के बाद तुरंत सामान्य हुई और पूर्व की तनाव वाली घटनाओं की अपेक्षा कम रही।

भूमिका

कोविड-19 संक्रमण फैलने, अप्रत्याशित नीति लागू करने और विश्वभर में अत्यधिक अनिश्चितता के परिणामस्वरूप मुद्रा, बॉण्ड, इक्विटी और ऋण जैसे विभिन्न आस्ति वर्गों के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव पाए गए थे। उभरते बाज़ार की मुद्राओं में विशेष रूप से काफी अस्थिरता पाई गई जो मार्च 2020 में भारी जोखिम-मुक्त बहिर्वाहों से शुरू हुई जिससे अत्यधिक मूल्यहास दबाव, भारतीय रुपये (आईएनआर) पर भी, पैदा होता है (ओईसीडी, जून 2020) और यह वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफ़सी) के बाद से इक्विटी बाज़ारों में पाया गया सबसे बुरा अधिविक्रय है और कई उन्नत देशों में दीर्घ-कालिक बॉण्ड प्रतिफलों में अब तक सबसे कम है। वर्ष के पूर्वार्ध में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़), विश्व बैंक एवं रेटिंग एजेंसियों द्वारा वैश्विक वृद्धि में संशोधन कर उसे कम किया गया, साथ ही रोजगार व मांग की संभावना गिरी। मांग एकाएक कम होने की वजह से अप्रैल में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई जो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम थी। रुपया के विनिमय दर के संबंध में रिज़र्व बैंक की नीति उसे बाज़ार शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देती है, जिसमें किसी पूर्व-निर्धारित लक्ष्य स्तर का संदर्भ लिए बिना विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को काबू में कर बाज़ार में सुव्यवस्थित स्थितियां बनाए रखने मात्र हेतु मध्यक्षेप किया जाता है। महामारी फैलने के बाद वाले महीनों में, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता और

वित्तीय बाज़ारों में सुव्यवस्थित स्थितियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई परंपरागत व अपरंपरागत साधनों को प्रयोग में लाया। विनिमय दर में अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव संपूर्ण समष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थिरता को खतरे में डालने के अलावा व्यापार और निवेश पर प्रायः हानिकर प्रभाव डाल सकता है (जनक राज, एवं अन्य 2018)। अल्पावधि विनिमय दर परिवर्तनीयता से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) के प्रवाहों पर असर पड़ता देखा गया है (गोल्डबर्ग, 2009)। तर्क यह है कि विनिमय दर उतार-चढ़ाव से होने वाले खतरों, जिससे निवेश से होने वाली संभावित आय पर असर पड़ता है, के लिए निवेशकों को क्षतिपूर्ति करने की जरूरत है। यदि विनिमय दरें अत्यधिक अस्थिर रहती हैं तो निवेश के संभावित मूल्य घट जाते हैं, और तदनुसार एफ़डीआई घटने लगता है। वास्तविक विनिमय दर अस्थिरता के व्यापार-रोधक प्रभाव भी पाए गए हैं, क्योंकि फर्मों द्वारा किए गए निर्यातों के मूल्य के साथ-साथ निर्यात बाज़ारों में प्रवेश करने की उनकी संभाव्यता उच्च विनिमय दर अस्थिरता वाले गंतव्य-स्थानों के लिए कम होने लगती हैं (हेरिकोट एवं अन्य 2013)। एक दूसरे अध्ययन से उजागर होता है कि जब विनिमय दरों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव होता है तब निर्यातक जोखिम के स्तर में परिवर्तन के अनुसार या तो निर्यात की कीमतों को बढ़ाता है अथवा व्यापार की मात्राओं को घटाता है, लेकिन प्रायः कीमतों को बढ़ाने की अपेक्षा व्यापार की मात्राओं को सीधे घटाना उनकी पसंद होती है (चेओंग एवं अन्य, 2005)।

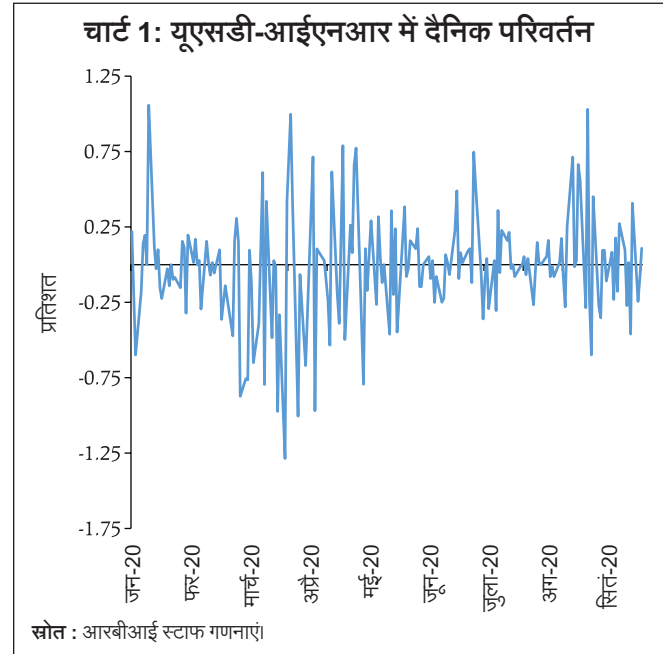
भारत के एक हाल के अध्ययन में यह पाया गया कि यूएसडी-आईएनआर में वास्तविक अस्थिरता (ऐतिहासिक अस्थिरता) वित्तीय दबाव सूचकांक (एफ़एसआई) का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के साथ सांख्यिकीय तौर पर महत्वपूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है और आईआईपी के पूर्वानुमान में एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य कर सकता है (या वास्तविक आर्थिक गतिविधि) (मंजूषा, और अन्य, 2020)। पूर्व में, 2008, 2011, 2013 आदि सर्व-विदित तनावग्रस्त घटनाओं में उच्च एफ़एसआई मूल्य पाए गए थे जिसकी एक विशेषता निम्न आईआईपी मूल्य भी थी (और वास्तविक उच्च आईएनआर अस्थिरता)। लिहाजा, यूएसडी-आईएनआर में वास्तविक अस्थिरता वास्तविक आर्थिक गतिविधि के पूर्वानुमान में अन्य संकेतकों के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकती है।

* यह लेख वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के राधा श्याम राठो, विक्रम राजपूत और सब्यासाची सारंगी द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

इस पृष्ठभूमि में, यह लेख विनिमय दर अस्थिरता को नियंत्रण में करने को लेकर रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों की क्षमता का आकलन करने का प्रयास करता है। शेष लेख को पांच भागों में विभाजित किया जाता है। भाग II यूएस डॉलर की तुलना में आईएनआर विनिमय दर पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की चर्चा करता है। भाग III आईएनआर अस्थिरता को काबू में करने को लेकर रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों से संबंधित है। भाग IV बाज़ार प्रत्याशाओं की तुलना में आईएनआर द्वारा अनुसरण किए गए वास्तविक मार्ग के संदर्भों में अस्थिरता को नियंत्रण में करने के लिए विदेशी मुद्रा बाज़ार संबंधी मध्यक्षेप उपायों की क्षमता पर विचार-विमर्श करता है। भाग V विदेशी मुद्रा बाज़ार में मध्यक्षेप की अंतर-देशीय तुलना करता है। भाग VI में निष्कर्षों का सार दिया गया है।

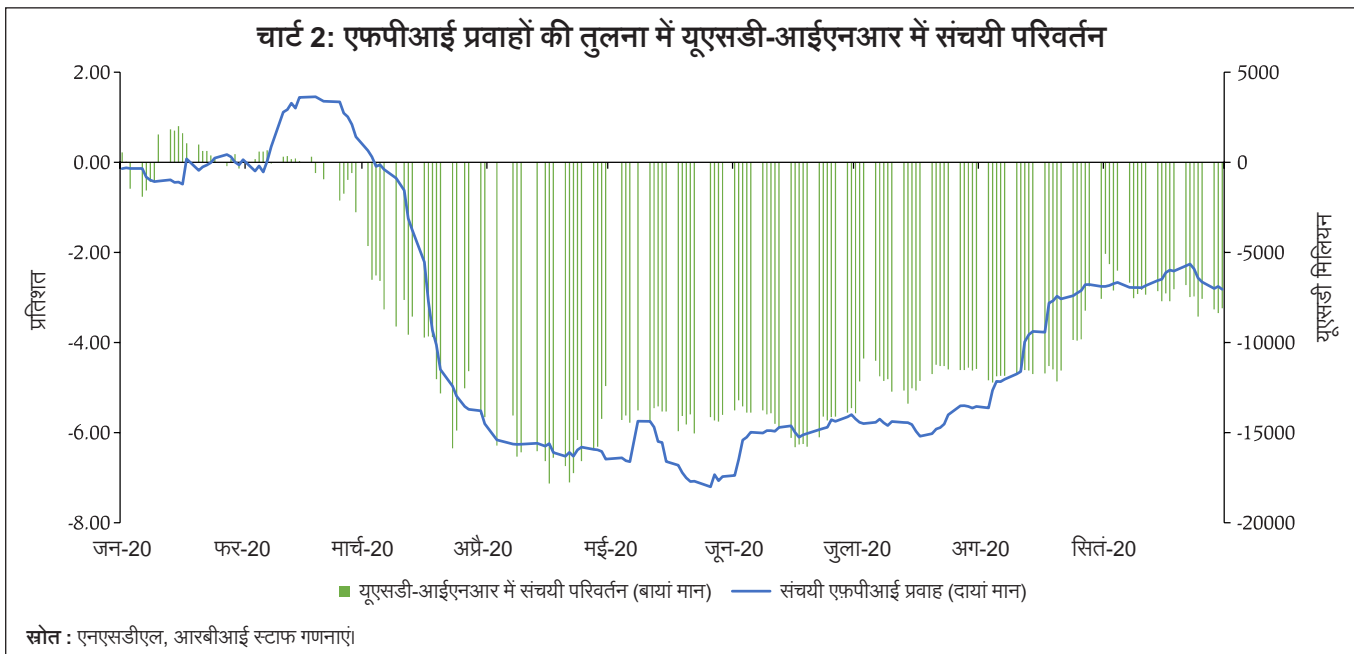
II. आईएनआर पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

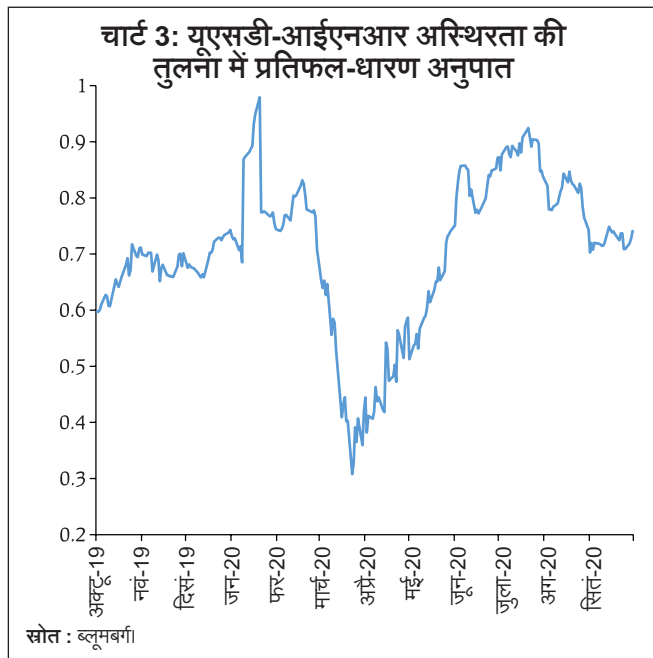
वित्त बाज़ारों में अत्यधिक अस्थिरता की पिछली वारदातों, जैसे, जीएफसी, यूरोक्षेत्र संकट और टेपर टैन्ट्रम घटना की भांति कोविड-19 के कारण सभी उभरते बाज़ारों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह हुआ। भारत ने आईएनआर में उच्च अस्थिरता के साथ जनवरी 2020 और फरवरी 2020 में 1.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी अंतर्वाह दर्ज करने के बाद मार्च 2020 में 15.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अप्रत्याशित विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) बहिर्वाह (कर्ज़ और



इक्विटी) दर्ज किया (चार्ट 1)। मार्च के दौरान एकाधिक अवसरों पर 1 प्रतिशत तक का दैनिक मूल्यहास पाया गया था, और वह भी 23 मार्च 2020 में 1.29 प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी।

साल दर साल आधार पर, आईएनआर में 7.13 प्रतिशत का संचयी मूल्यहास देखा गया, जो 16 अप्रैल 2020 को गिरकर अब तक सबसे कम अर्थात् 76.86 पर समाप्त हुआ (चार्ट 2)।





कोविड-पूर्व अवधि में उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच के संतोषजनक ब्याज दर अंतर को देखते हुए विदेशी निवेशकों ने प्रतिफल-धारक व्यापार (कैरी ट्रेड) कार्यनीतियों को सफलतापूर्वक काम में लाया। इस कार्यनीति ने, जब अस्थिरता कम थी, मुद्राओं के वित्तपोषण में बेहतर काम किया (मुख्यतः यूएसडी) (रक्षित ब्याज दर समानता के उल्लंघन में)। प्रतिफल धारण-अस्थिरता अनुपात, जो एक प्रत्याशित जोखिम समायोजित प्रतिलाभ उपाय है (अस्थिरता की तुलना में दो मुद्राओं के बीच के ब्याज अंतर का अनुपात), 0.76 के अपने 1-वर्ष के औसत के आस-

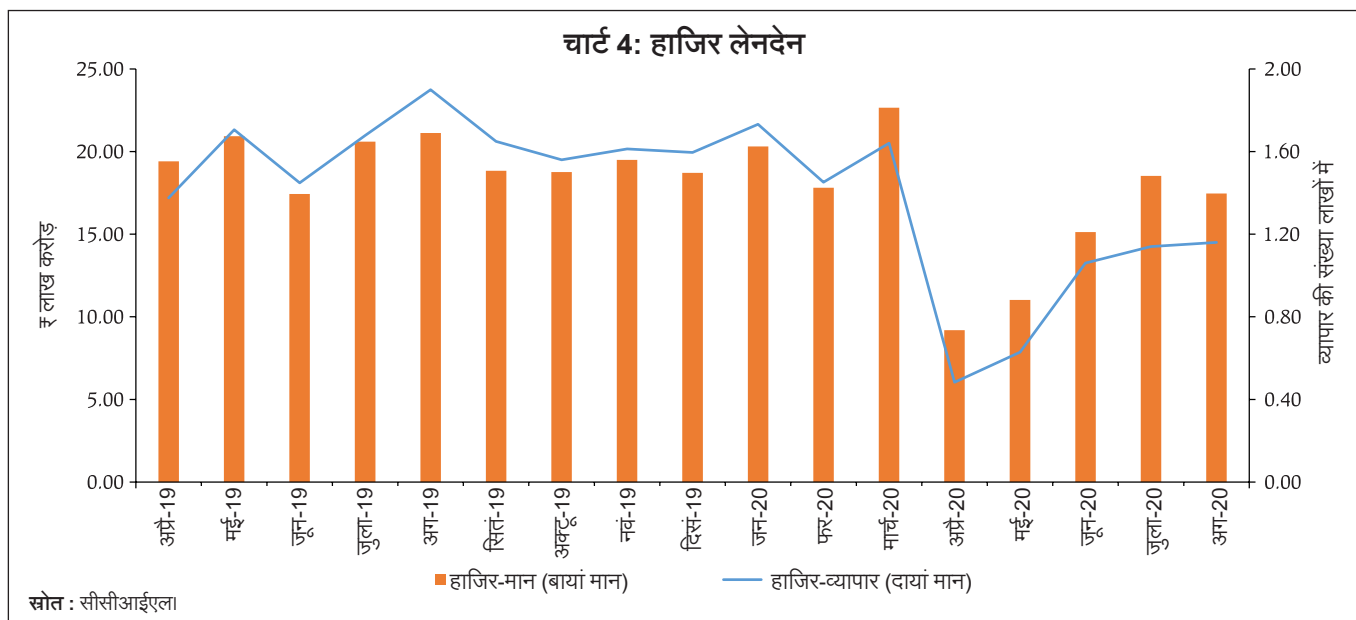
पास था (चार्ट 3)। अस्थिरता अचानक बढ़ जाने से अनुपात तेजी से घटने लगा, जो मार्च के बाद प्रतिफल-धारक व्यापार कार्यनीतियों को समाप्त न करने की उच्च संभाव्यता को दर्शाता है। फिर भी, निहित अस्थिरता घटने की वजह से अनुपात बाद में बढ़ने लगा। जब अनुपात अधिक होता है तो विदेशी निवेशक मौकों की तलाश में रहते हैं।

III आरबीआई द्वारा किए गए उपाय

III.1 अर्थव्यवस्था-व्यापी उपाय

जब महामारी के कारण वित्तीय स्थिरता और वास्तविक अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा, तब रिजर्व बैंक की सोच थी 'अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो करे' (टोबियास एड्रियन, एवं अन्य, 2020)। रिजर्व बैंक के इन उपायों ने निवेशकों के मनोभाव को बढ़ावा दिया और बाजार की परेशानियों को कम करने में मदद की (आरबीआई मौद्रिक नीति रिपोर्ट, 2020)। निवेशकों की जोखिम क्षमता में चूंकी सुधार हुआ, एफ़पाई बहिर्वाहों की तीव्रता अप्रैल और मई 2020 में पर्याप्त रूप से कम हुई (क्रमशः 1.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 0.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह), जिससे आईएनआर पर दबाव कुछ कम हुआ।

रिजर्व बैंक ने बाजार गतिविधि कम होने के परिणामस्वरूप परिचालन और लाजिस्टिक जोखिमों को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से 03 अप्रैल 2020 को अंतरबैंक विदेशी मुद्रा लेनदेनों (अन्य बाजार खण्डों के साथ) के समय में कटौती की है। नतीजतन हाजिर लेनदेनों की मात्रा में गिरावट आई, यद्यपि तब से उनमें सुधार हुआ है (चार्ट 4)।



III.2 अस्थिरता को नियंत्रण में करने के लिए विशिष्ट उपाय

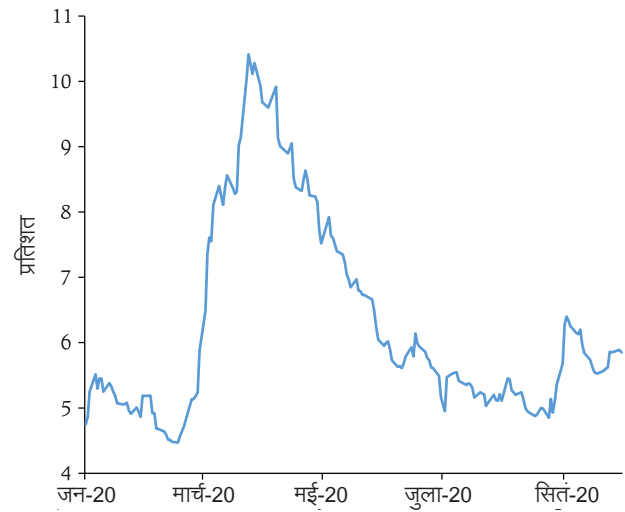
रिज़र्व बैंक ने आईएनआर में अस्थिरता को नियंत्रण में करने के लिए विशिष्ट उपाय किए। रिज़र्व बैंक ने ओवर-दि-काउंटर (ओटीसी), एक्सचेंज ट्रेड और ऑफशोर मार्केट सेगमेंट में अमेरिकी डॉलर को बेचने के जरिए मध्यक्षेप किया। रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2020 में मध्यक्षेप करने के परिणामस्वरूप बढ़ती अस्थिरता (बाज़ार भाव पर 1 माह विकल्प में निहित अस्थिरता) को काबू में किया गया और आईएनआर पर मूल्यहास का दबाव कम हुआ। इसके बाद, छिट-पुट एफपीआई अंतर्वाहों के कारण अप्रैल-अंत से क्रय-पक्ष में मध्यक्षेप किया गया, जिसकी बदौलत अस्थिरता घटकर दखल देने के पूर्व वाले स्तर पर पहुंचने में आसानी हुई (चार्ट 5)।

रिज़र्व बैंक ने बाज़ार में डॉलर में चलनिधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मार्च 2020 में प्रत्येक छह महीनों के परिपक्वता-काल के लिए दो यूएसडी-आईएनआर विक्रय-क्रय स्वैप भी किए। स्वैप से वित्त वर्ष के अंत में बाज़ार प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही डॉलर चलनिधि की कमी को दूर करने में मदद मिली।

IV. विदेशी मुद्रा बाज़ार में मध्यक्षेपों की क्षमता

यूएसडी-आईएनआर विनिमय दर के 1-माह एटीएम विकल्प में निहित अस्थिरता (आईवी) मार्च 2020 की शुरुआत से बढ़ने लगी, जो दर्शाता है कि बाज़ार प्रतिभागी उच्च अनिश्चितता होने

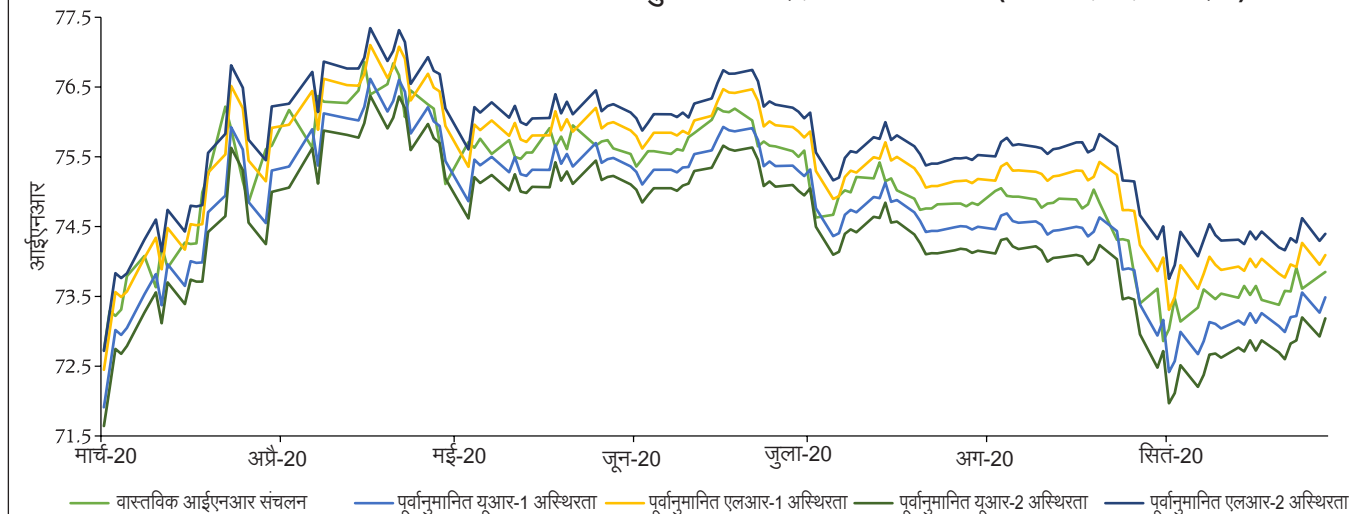
चार्ट 5: यूएसडी-आईएनआर – 1 माह बाज़ार भाव पर निहित अस्थिरता



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

की उम्मीद करते हैं (चार्ट 5)। रिज़र्व बैंक द्वारा 04 मार्च 2020 से एकाधिक मोर्चों पर मध्यक्षेप करने की बदौलत आईएनआर अधिकांश अवधि (04 मार्च-30 सितंबर) के दौरान खिसककर अस्थिरता बैंड¹ (आवश्यक रूप से संकरा 1-अस्थिरता बैंड में) के मध्य में पहुंच गया, जिसका आशय है कि आईएनआर की वास्तविक अस्थिरता प्रत्याशा आधारित आईवी की अपेक्षा काफी कम थी (चार्ट 6)।

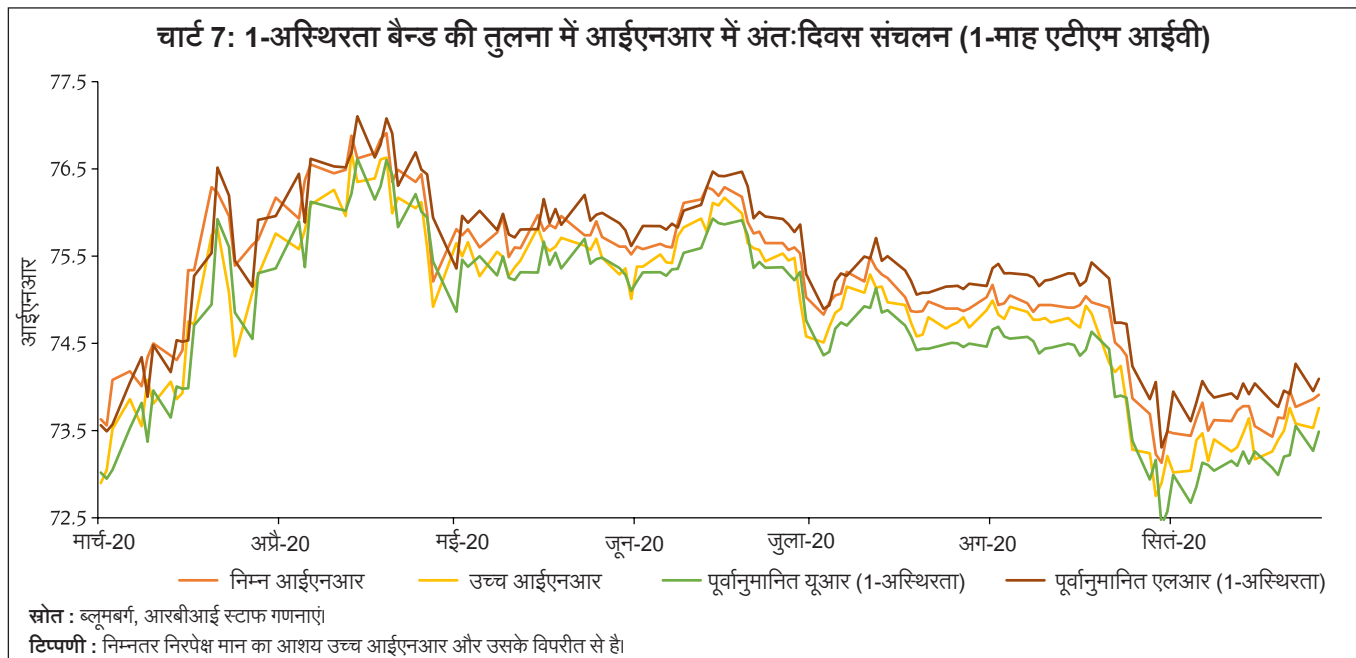
चार्ट 6: 1-अस्थिरता और 2-अस्थिरता बैंड की तुलना में आईएनआर में संचलन (1-माह एटीएम आईवी)



स्रोत : ब्लूमबर्ग, आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

टिप्पणी : निम्नतर निरपेक्ष मान का आशय उच्च आईएनआर और उसके विपरीत से है।

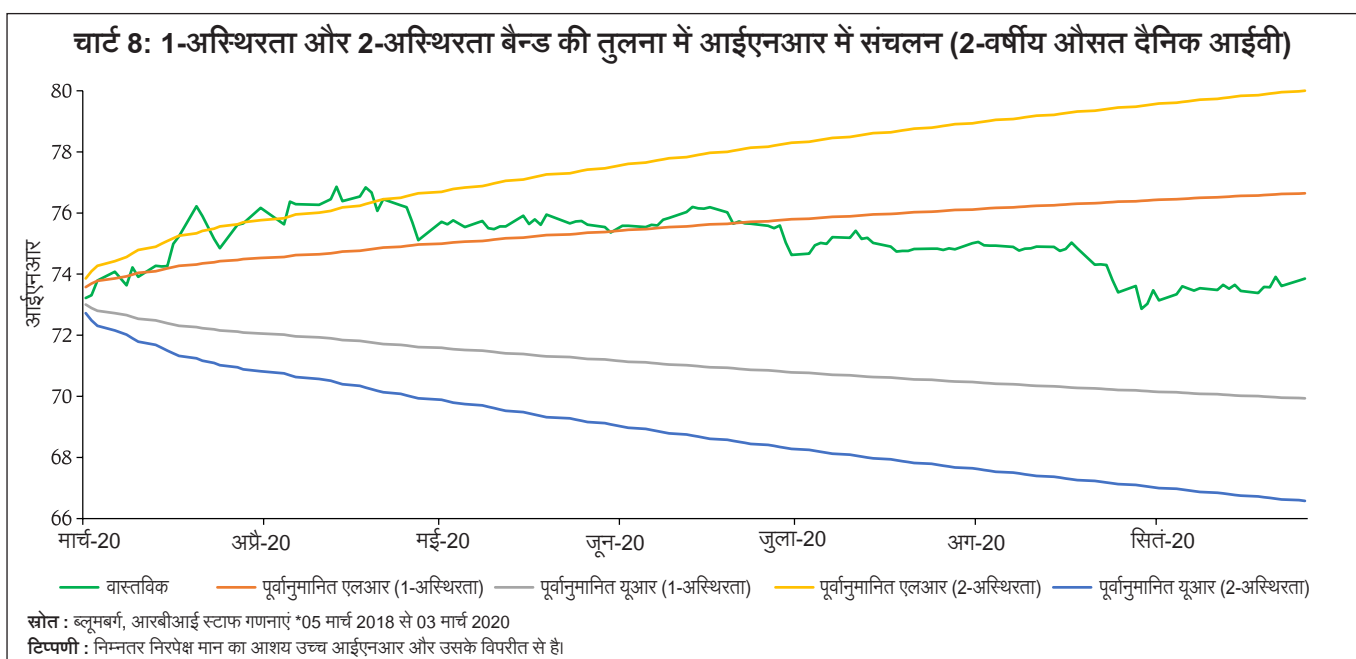
¹ दिन के अंत के आईएनआर मान (यूएसडी की तुलना में) एवं ब्लूमबर्ग में उपलब्ध निहित अस्थिरता मान के आधार पर अगले दिन के लिए पूर्वानुमानित आईएनआर मान (उच्चतम और निम्नतम मान) का उपयोग करके 1-अस्थिरता और 2-अस्थिरता आईएनआर बैंड तैयार किए गए हैं।



मार्च और अप्रैल के महीनों में आईएनआर के अंतःदिवस संचलनों में उच्च अस्थिरता भी पाई गई थी (चार्ट 7)।

मध्यक्षेपों की क्षमता को परखने का एक वैकल्पिक तरीका है आईवी के ऐतिहासिक औसत के साथ वास्तविक आईएनआर के संचलनों की तुलना करना। दैनिक 1-माह एटीएम आईवी का 2-वर्षीय औसत 6.12 प्रतिशत (05 मार्च 2018 से 03 मार्च 2020) है, जो संभावित आईएनआर संचलनों के संकरा रेंज का पूर्वानुमान करता है।

यदि आईएनआर बैंड को ऐतिहासिक आईवी मान और मार्च 03 (मात्र एक दिन पहले जब से रिज़र्व बैंक ने मध्यक्षेप करना शुरू किया) को 73.29 के समाप्त आईएनआर मान का उपयोग करके दर्शाया जाता है, तो एक रेट कारिडॉर प्राप्त होता है जिसमें आईएनआर रुढ़िवादी आईवी मान के आधार पर संचलन करने का अनुमान लगाया जाता है (चार्ट 8)। यह देखा जा सकता है कि वास्तविक आईएनआर में संचलन 2-अस्थिरता



बैंड में अवधि के दौरान अधिकांश दिनों में बैंड के उच्चतम मान (निम्नतर रेंज) के नीचे या आस-पास रहा है।

आईएनआर मार्च और अप्रैल के महीनों में अधिक रूढ़िवादी 1-अस्थिरता बैंड के निम्नतर रेंज (उच्चतर निरपेक्ष मान) के ऊपर चल रहा था। तथापि, आईएनआर मई 2020 से निम्नतर रेंज के आस-पास या नीचे स्थिर होने लगा। परिणामस्वरूप, अस्थिरता उच्च स्तर पर रही। इस परिप्रेक्ष्य में, विक्रय पक्ष के साथ-साथ क्रय पक्ष में मध्यक्षेप का न्यायपूर्ण उपयोग करने की बदौलत मई 2020 से अस्थिरता कम हुई। लिहाजा, आईएनआर रूढ़िवादी 2-वर्षीय औसत आईवी पर आधारित पथ पर चलने लगा, जो भारी मूल्यहास के भय को दूर करता है (जैसा मार्च 2020 से उच्च आईवी मान से पता चलता है)।

निकट-माह वाले परिपक्वता कालों में तेज वृद्धि के साथ मार्च अंत आते-आते विभिन्न परिपक्वता कालों में वायदा प्रीमियमों में सामान्य वृद्धि पाई गई। परिणामस्वरूप, रिजर्व बैंक ने मार्च के अंत में दो क्रय-विक्रय स्वैप किया। मार्च के बाद वायदा प्रीमियमों में गिरावट आई (चार्ट 9)।

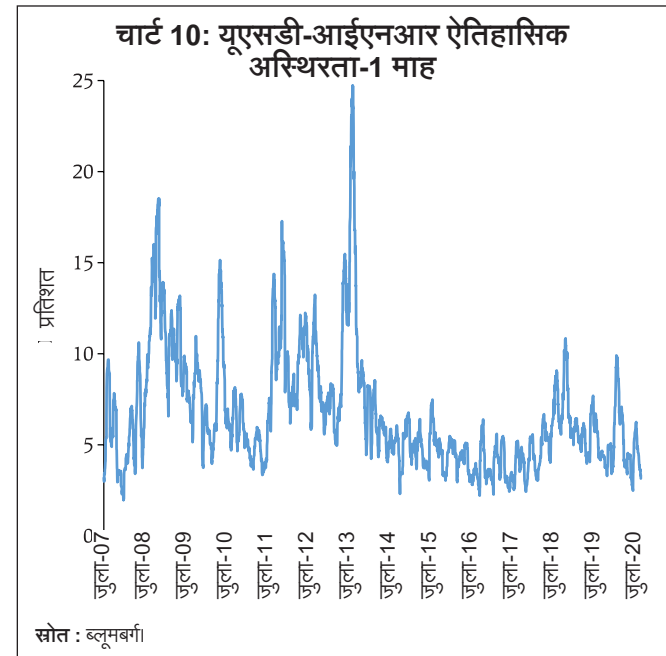
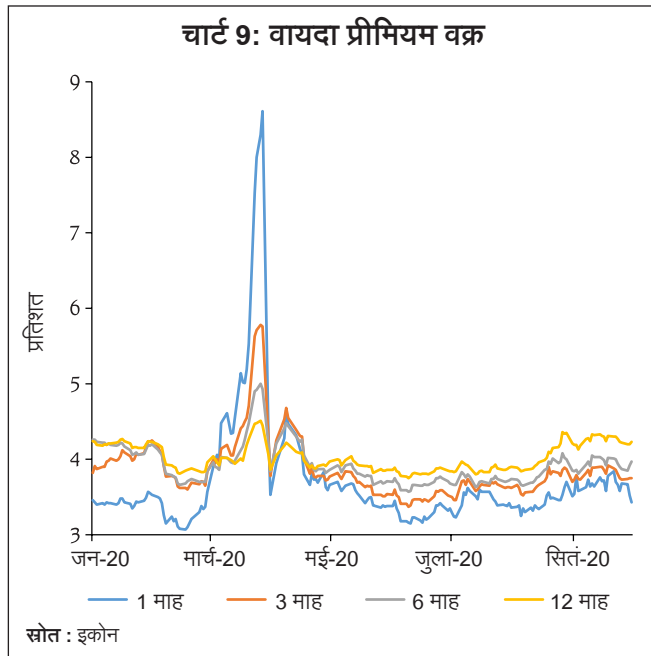
पूर्व में, आईएनआर की ऐतिहासिक अस्थिरता² (1-माह) में 2008-09, 2011-12, 2013-14 और 2018-19 में आवधिक

वृद्धि हुई। इसने सितंबर 2013 में 24.73 प्रतिशत की ऊंचाई को छुआ (चार्ट 10)। कोविड पूर्व अवधि में वास्तविक अस्थिरता की तुलना में अस्थिरता में साफ-साफ गिरावट दिखाई दी (चार्ट 11)। यदि केवल बुलंदी के दौर अर्थात, मार्च-अप्रैल 2020 पर विचार किया जाता है तो वास्तविक अस्थिरता का औसत 7.7 प्रतिशत रहा, जो उच्च अस्थिरता वाले प्रकरणों में सबसे कम भी है।

V. मध्यक्षेप की बहु-देशीय तुलना

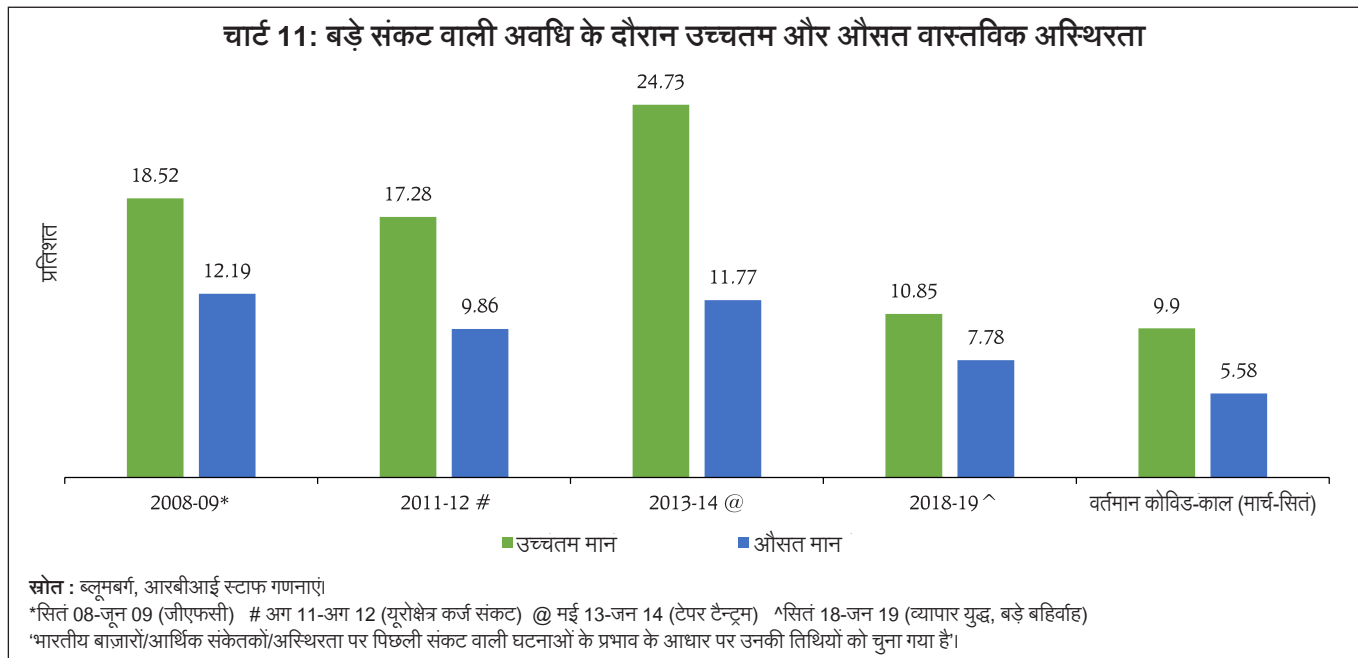
जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ तो अस्थिरता का स्तर काफी बढ़ने लगा जिस वजह से वैश्विक बाज़ार में औने-पौने दाम पर बिक्री होने लगी जिसके कारण ईएमई मुद्राएं बुरी तरह से प्रभावित हुईं और उनमें से कुछ अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। परिणामस्वरूप, अधिकांश ईएमई केंद्रीय बैंकों ने विदेशी मुद्रा बाज़ार में मध्यक्षेप किया (चार्ट 12)।

फरवरी के अंत में कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के हिस्से के रूप में भारत का मध्यक्षेप मार्च 2020 (अर्थात, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में फरवरी की तुलना में मार्च में गिरावट) में इंडोनेशिया के 7.61 प्रतिशत और दक्षिणी कोरिया के 2.19 प्रतिशत की तुलना में 1.43 प्रतिशत था।



² वास्तविक अस्थिरता की गणना करने के लिए आवधिक लॉगरिथमिक प्रतिलाभ के मानक विचलन को ऐतिहासिक समय-सीमा की तुलना में वार्षिकीकृत किया जाता है (ब्लूमबर्ग में उपलब्ध मूल्य)।

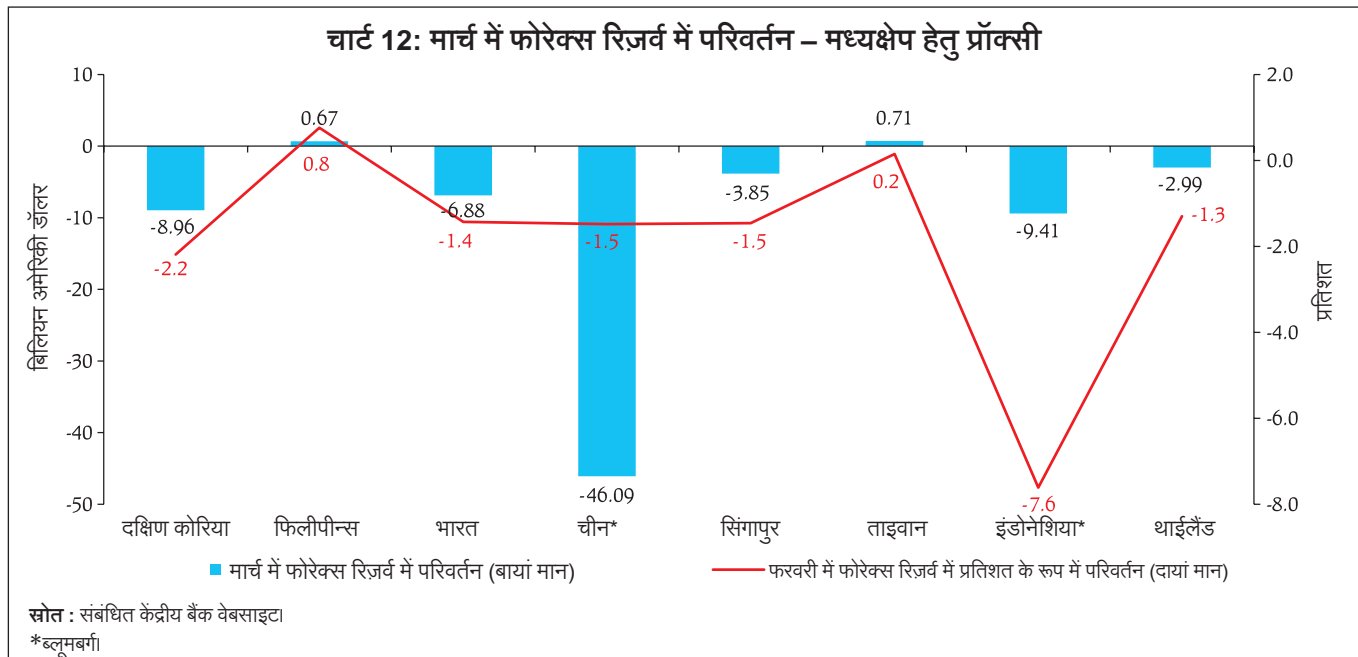
चार्ट 11: बड़े संकट वाली अवधि के दौरान उच्चतम और औसत वास्तविक अस्थिरता



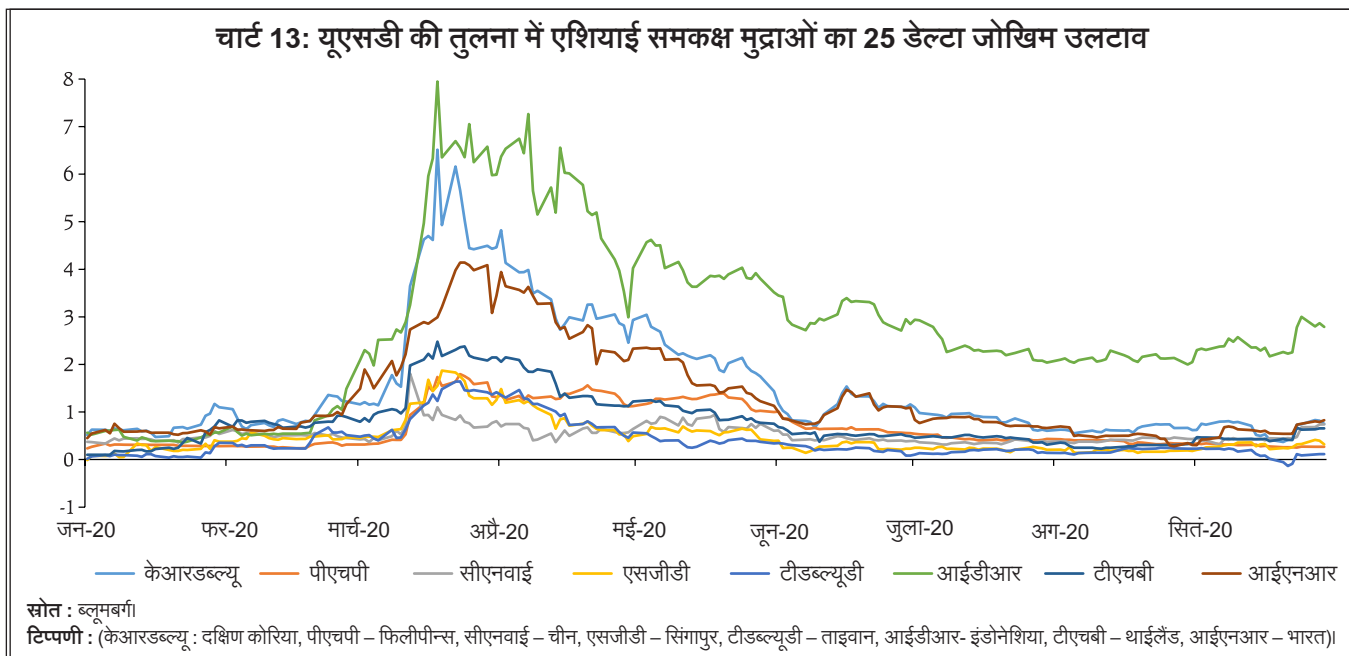
सभी एशियाई समकक्ष मुद्राओं की निहित अस्थिरता या जोखिम उलटाव (आरआर)³ मार्च 2020 में बढ़ा, जो मुद्रा जोड़ी के संबंध में बाज़ार भाव से बाह्य मूल्य पर क्रय और विक्रय विकल्पों (25 डेल्टा) की निहित अस्थिरताओं के बीच का अंतर होता है।

आईएनआर के मामले में, आरआर मार्च में 4.14 की उंचाई से नीचे गिरा और तत्पश्चात लगातार लगभग 1 पर रहा, जो आईएनआर के संबंध में मूल्यहास कम होने की प्रत्याशा को दर्शाता है (चार्ट 13)।

चार्ट 12: मार्च में फोरेक्स रिज़र्व में परिवर्तन – मध्यक्षेप हेतु प्रॉक्सी



³ धनात्मक मान का आशय जोड़ी में अन्य मुद्रा की तुलना में अमेरिकी डॉलर को लेकर तेज रुख वाली संभावना से है। इसके अलावा, निरपेक्ष मान अधिक होने से कीमत में उतार-चढ़ाव की प्रत्याशा भी अधिक होती है। संक्षेप में कहें तो अमेरिकी डॉलर की तुलना में सभी एशियाई समकक्ष मुद्राओं में मूल्यहास की प्रत्याशा की गई थी।



VI. निष्कर्ष

अन्य मौद्रिक और विनियामकीय उपायों के साथ ही विदेशी मुद्रा बाजार में मध्यक्षेप करने की बदौलत विनिमय बाजार में अस्थिरता को काबू में करने और वित्तीय स्थिरता को होने वाले खतरों को रोकने में आसानी हुई। अस्थिरता, जिसे विभिन्न प्रकार के संकेतकों के जरिए मापा जाता है, मार्च में बढ़ने के तुरंत बाद सामान्य हुई और पूर्व की दबावग्रस्त घटनाओं की अपेक्षा कम रही। बहु-देशीय तुलना से भी इसका पता चलता है।

संदर्भ :

OECD. (2020, June). *Report to G20 International Financial Architecture Working Group, COVID-19 and Global Capital Flows*

Janak Raj, Sitikantha Pattanaik, Indranil Bhattacharya and Abhilasha. (2018, August). Reserve Bank of India. Monthly Bulletin. *Forex Market Operations and Liquidity Management*.

Linda S. Goldberg (2009). Federal Reserve Bank of New York. *Exchange Rates and Foreign Direct Investment*.

Jerome Hericourt, Sandra Poncet. (2013). *Exchange Rate Volatility, Financial Constraints and Trade: Empirical Evidence from Chinese Firms*.

Chongcheul Cheong, Tesfa Mehari, Leighton Vaughan Williams. (2005, November). *The effects of exchange rate volatility on price competitiveness and trade volumes in the UK: A disaggregated approach*, *Journal of Policy Modeling*, Volume 27, Issue 8.

Manjusha Senapati, Rajesh Kavediya (2020, September). RBI Working Paper Series. *Measuring Financial Stress in India*.

Tobias Adrian, Fabio Natalucci. (2020, April). IMF Blog. *COVID-19 Crisis Poses Threat to Financial Stability*.

Monetary Policy Report. (2020, October). Reserve Bank of India.

सेवा और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण: हालिया प्रवृत्ति*

रिजर्व बैंक का तिमाही और सेवा और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण (एसआईओएस) वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही से किए जा रहे हैं, जो सेवा और आधारभूत संरचना क्षेत्र की कंपनियों के उनके खुद के प्रदर्शन और निकट भविष्य में उनकी संभावना के बारे में अवधारणा प्रदान करता है। रिजर्व बैंक के अन्य प्रगामी सर्वेक्षणों की तुलना में इसकी प्रतिक्रिया दर धीमी होती है किंतु प्रमुख मापदंडों की बाबत समग्र प्रतिक्रिया में व्यापक आंतरिक स्थिरता होती है। इस लेख में इसकी शुरुआत से लेकर अब तक के प्रमुख मापदंडों के सर्वेक्षण और उसमें उतार-चढ़ाव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कोविड-19 महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में गंभीर संकुचन के बाद कारोबार रुख बहाली के पथ पर चल पड़ा है लेकिन अभी भी इसे महामारी के पूर्व वाले स्तर पर पहुंचना बाकी है।

भूमिका

कारोबारी प्रवृत्ति सर्वेक्षण में निकट भविष्य के लिए मौजूदा व्यापार स्थितियों और उनकी योजनाओं और अपेक्षाओं के बारे में कारोबार प्रबंधकों का अभिमत लिया जाता है। इन सर्वेक्षणों को कारोबारी दृष्टिकोण/प्रत्याशा/अभिमत/जलवायु सर्वेक्षण के रूप में भी जाना जाता है और इनका उद्देश्य आर्थिक नीति निर्माताओं, विश्लेषकों और कारोबार योजनाकारों को व्यापक आर्थिक और क्षेत्रीय दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। इस तरह के सर्वेक्षणों से प्राप्त जानकारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण घटना चक्र का पूर्वानुमान लगाने में बहुमूल्य साबित होते हैं।

कारोबारी परिस्थितियों से संबंधित सर्वेक्षण अक्सर औसत दर्जे के पारंपरिक आँकड़ों से आगे निकल जाते हैं और, साथ ही साथ आर्थिक स्थितियों (जैसे, समग्र कारोबारी स्थिति, निवेश वातावरण, उत्पादन बाधाओं) के संबंध में धारणाएं जुटाते हैं। संगठित कारोबार आम तौर पर कई आर्थिक क्षेत्रों (जैसे, उद्योग, आधारभूत संरचना, खुदरा व्यापार, सेवाएँ) में कार्य करते हैं, जिनमें विभिन्न फ़ोकस क्षेत्र और मापदंड होते हैं। इसलिए, क्षेत्र-

* सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के एंटरप्राइज प्रभाग के शुभांगी लाटे और सुप्रिय मजूमदार द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त करते हों।

विशिष्ट कारोबार सर्वेक्षण, अक्सर उन पर निर्भर होते हैं, जहां प्रासंगिक प्रश्न कारोबारी संस्थाओं के अपेक्षाकृत एक समान समूह के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

इस लेख के बाकी हिस्सों को निम्नानुसार बांटा गया है। खंड II में सेवा क्षेत्र से संबंधित कारोबारी परिदृश्य सर्वेक्षणों पर अंतर-देशीय अनुभव प्रस्तुत किया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए तिमाही सेवा और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण का अवलोकन खंड III में दिया गया है और इसके निष्कर्षों को खंड IV में दिया गया है। खंड V का समापन कुछ प्रमुख बातों के साथ किया गया है।

II. अंतर-देशीय प्रथाएँ

कारोबार की प्रवृत्ति का सर्वेक्षण नियमित रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ कई उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है और अल्पावधिक आर्थिक गतिविधियों पर समय पर सूचना उत्पन्न करने का एक प्रभावी साधन साबित होता है। यूरोपीय आयोग यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न क्षेत्रों (यानी, उद्योग, सेवा, खुदरा व्यापार और विनिर्माण) के लिए सामंजस्यपूर्ण मासिक सर्वेक्षणों का समन्वय करता है। सामान्य प्रश्नों के अलावा, राष्ट्रीय प्राधिकारी अक्सर अपने प्रश्नावली में देश-विशिष्ट प्रश्न जोड़ते हैं।

सेवा क्षेत्र की फर्मों को कवर करने वाले प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा संचालित प्रमुख कारोबारी सर्वेक्षणों का सारांश परिशिष्ट सारणी 1 में दिया गया है।

III. आरबीआई का सेवा और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण

भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह (2009) ने नोट किया था कि सेवा क्षेत्र के विकास को समझना समग्र नीतियों की प्रभावशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवा क्षेत्र का भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और उच्च रोजगार वृद्धि दर्ज कर रहा है, विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र में। समूह ने सुझाव दिया कि व्यापार और सेवा क्षेत्र के अन्य उप-घटकों जैसे आईटी सेवा क्षेत्र, आतिथ्य सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवा क्षेत्र आदि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सेवा क्षेत्र के लिए एक कारोबार परिदृश्य सर्वेक्षण किया जा सकता है।

तदनुसार, कुछ प्रायोगिक कार्य के बाद, एसआईओएस वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही से तिमाही आधार पर किया जा रहा है, जिसमें सर्वेक्षण संबंधी बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस), जहां बाहरी विशेषज्ञ भाग लेते हैं, के मार्गदर्शन में पिछले कुछ अवधि में सर्वेक्षण प्रशावली में कुछ परिशोधन किए गए हैं। सर्वेक्षण सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मौजूदा कारोबार स्थितियों और निकट अवधि में प्रत्याशाओं के संबंध में भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

लक्ष्य समूह और प्रतिक्रियाएँ

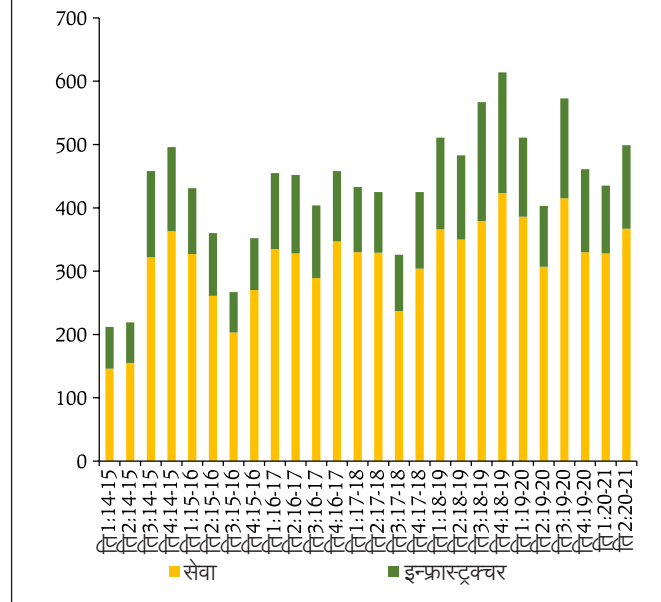
सर्वेक्षण प्रशावली को सेवा और आधारभूत संरचना क्षेत्र की कंपनियों के एक पैनल के बीच रखा गया है। आकार और उद्योग का उचित प्रतिनिधित्व पाने के लिए नमूना फ्रेम का चयन किया जाता है। फ्रेम को वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाता है और एक वर्ष के दौरान किए गए सर्वेक्षण दौर के लिए तय किया जाता है। प्रारंभिक दौर में लगभग 800 कंपनियों से फ्रेम का धीरे-धीरे विस्तार करके लगभग 3,500 कंपनियों के लिए किया गया है। सर्वेक्षण में भागीदारी स्वैच्छिक है।

यह माना जाता है कि सेवा क्षेत्र की कंपनियों की संख्या बहुत बड़ी है, जहां संख्या के मामले में छोटी कंपनियां हावी हैं और उनकी बहिर्गमन दर-अधिक है। तदनुसार, प्रतिक्रिया दर आम तौर पर रिज़र्व बैंक के अन्य कारोबार सर्वेक्षणों की तुलना में कम है, (जैसे, औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आईओएस), ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस), बैंक ऋण सर्वेक्षण (बीएलएस))। शुरुआत से लेकर अभी तक के सभी सर्वेक्षण दौर की प्रतिक्रियाओं की वास्तविक संख्या चार्ट 1 में दी गई है।

सर्वेक्षण प्रशावली

सेवा और आधारभूत संरचना कंपनियों में वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों या वित्त प्रमुखों से एक संरचित प्रशावली में अपने व्यापार प्रोफाइल पर कुछ बुनियादी जानकारी के साथ चुनिंदा कारोबारी मापदंडों पर अपनी धारणा बताने का आग्रह किया जाता है।¹ यह वर्तमान तिमाही की कारोबारी स्थिति और समग्र

चार्ट 1: एसआईओएस के लिए उत्तरदाताओं की संख्या



कारोबारी स्थिति, मांग संकेतक, रोजगार की स्थिति, मूल्य की स्थिति, वित्तीय स्थिति और लाभ मार्जिन के संबंध में आगामी तिमाही के लिए प्रत्याशाओं का आकलन करता है, जो नीति विश्लेषण और अनुसंधान के लिए उपयोगी प्रगामी इनपुट प्रदान करते हैं।

सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं को तीन-सूत्रीय पैमाने (जैसे, वृद्धि, कमी और कोई परिवर्तन नहीं) पर एकत्र किया जाता है। कारोबार को अनुकूल और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में फीडबैक प्रशावली के एक अतिरिक्त ब्लॉक में एकत्र की जाती है। उत्तरदाता विभिन्न समष्टि-आर्थिक मापदंडों (जैसे, वार्षिक मुद्रास्फीति दर, समग्र आर्थिक उत्पादन में वार्षिक वृद्धि, अर्थव्यवस्था में निवेश, रुपया-अमेरिकी डॉलर विनिमय दर और कारोबारी बाधाएं) के साथ-साथ सर्वेक्षण प्रशावली में क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों के बारे में कोई अन्य टिप्पणी / सुझाव पर अपना रुख भी व्यक्त कर सकते हैं।

कार्यपद्धति: सर्वेक्षण डेटा का विश्लेषण

मूल्यांकन और प्रत्याशा तिमाहियों दोनों के लिए प्रत्येक कारोबार मापदंड हेतु सर्वेक्षण के प्रत्येक दौर में उत्तरदाताओं के तीन भाग (अर्थात, वृद्धि, कमी और कोई परिवर्तन नहीं) रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत) हैं। इन्हें 'निवल प्रतिक्रियाएँ (एनआर)' या 'डिफ्यूजन इंडिसीज (डीआई)' के संदर्भ में प्रत्येक

¹ एसआईओएस प्रशावली आरबीआई की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx?FCId=40 पर उपलब्ध है, और इसे 'फॉर्म' के अंतर्गत रखा गया है (आरबीआई होमपेज के नीचे 'और लिंक्स' देखें) और उप-शीर्ष 'सर्वेक्षण'।

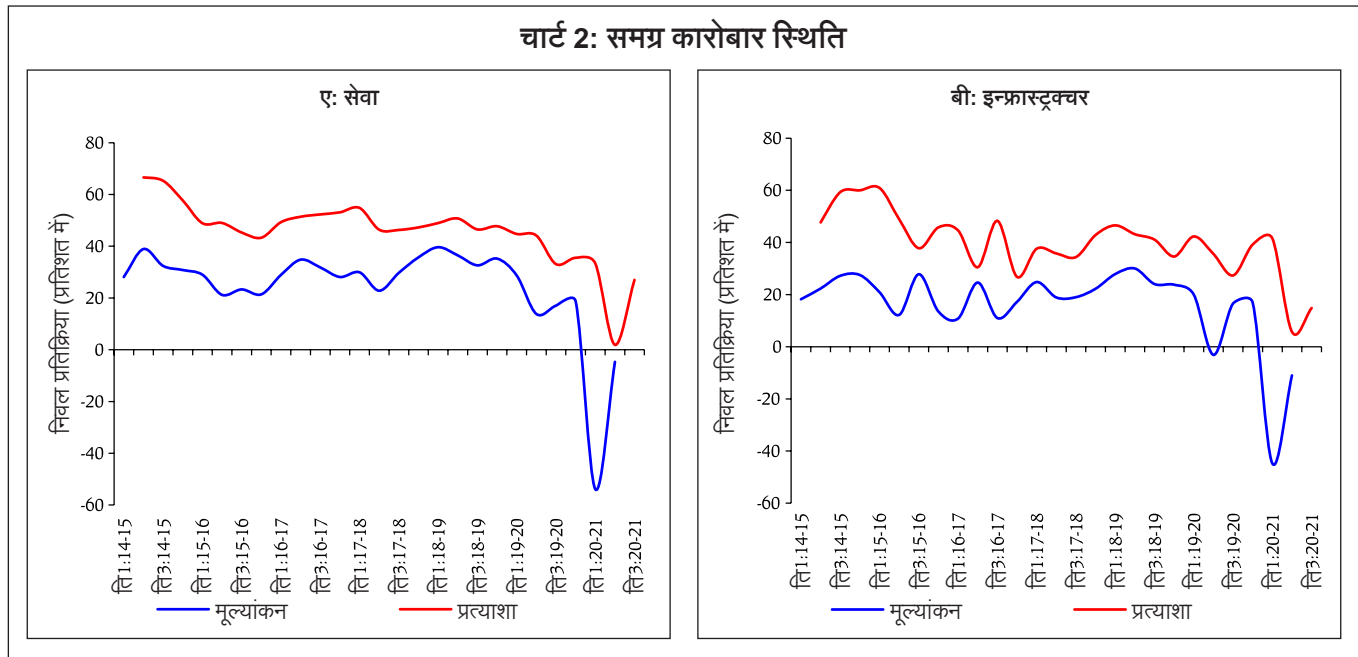
पैरामीटर/अवधि के लिए एक ही व्यापक संख्या में संक्षेपित किया गया है² एनआर -100 से +100 तक 'शून्य' मान के साथ निराशावाद/संकुचन से आशावाद/विस्तार अलग करने वाला हो सकता है। दूसरी ओर, डीआई, मध्य-बिंदु के रूप में 0 से 100 तक होता है (ओईसीडी, 2003)। दो सारांश सूचकांक समय के साथ अग्रानुक्रम में चलते हैं क्योंकि अंतर अनिवार्य रूप से पैमाने का है। आगे के खंड में, एनआर का उपयोग एसआईओएस परिणामों का विश्लेषण करने के लिए किया गया है।

IV. सर्वेक्षण निष्कर्ष

सर्वेक्षण के पहले दौर (अप्रैल-जून 2014) से जुलाई-सितंबर 2020 तक के एसआईओएस मापदंडों में उतार-चढ़ाव नीचे दिए गए हैं³

समग्र कारोबारी स्थिति

कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव से पहले वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही तक छह साल की अवधि के दौरान उत्तरोत्तर गिरावट के बावजूद सेवाओं और आधारभूत संरचना कंपनियों का समग्र रुख आशावादी क्षेत्र में बरकरार रहा। सेवा क्षेत्र के लिए अंतिम तिमाही में स्थिति में गिरावट दर्ज की गई, हालांकि उत्तरदाताओं की समग्र धारणा यह थी कि आधारभूत संरचना कंपनियां एक संकुचन क्षेत्र में रहेंगी (चार्ट 2)। चूंकि जनवरी-मार्च 2020 के सर्वेक्षण के अधिकांश उत्तर मार्च 2020 की शुरुआत में प्राप्त हुए थे, इसलिए इसने इसके बाद की तिमाही में गतिविधियों के सिकुड़ जाने की भविष्यवाणी नहीं की। सर्वेक्षण के सभी प्रमुख मापदंडों के लिए यह सत्य है।

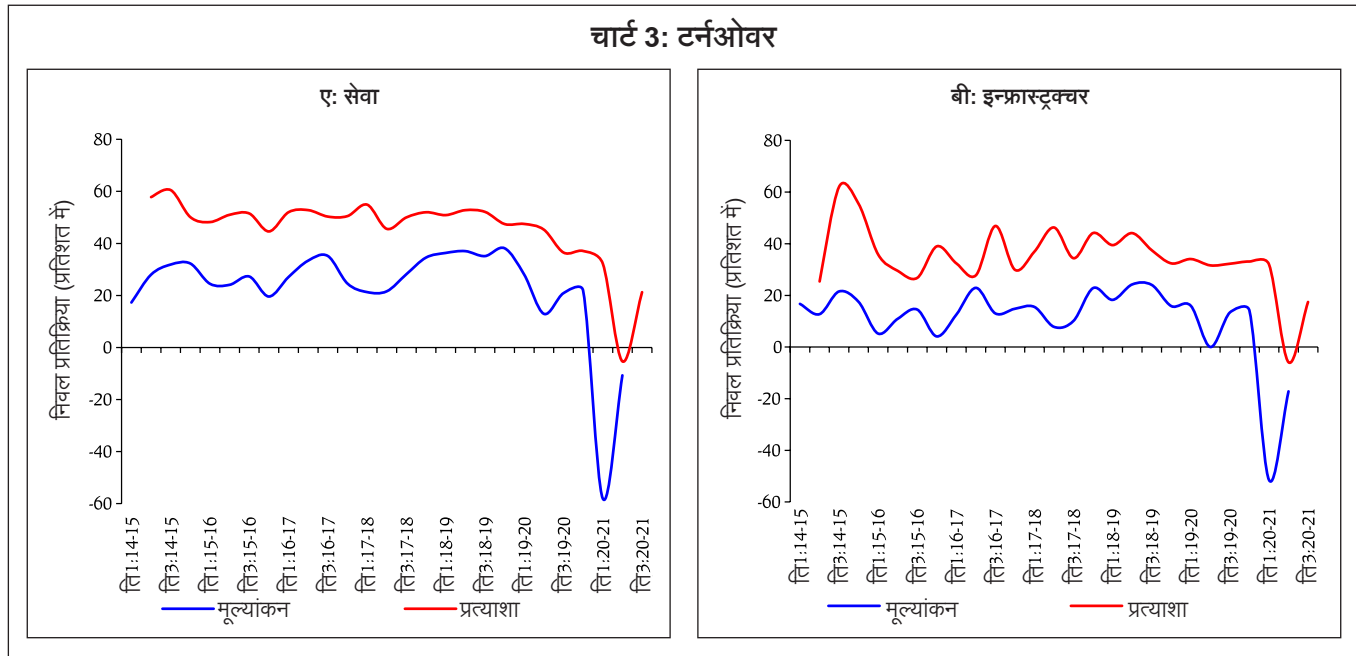


² निवल प्रतिक्रियाओं (एनआर) की गणना के लिए, कमी की रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत वृद्धि की रिपोर्ट करने वाले प्रतिशत से घटाया जाता है; जबकि, डिप्यूजन इंडेक्स (डीआई) को अनुकूल के अंश (वृद्धि) उत्तर और साथ ही साथ बिना किसी परिवर्तन के उत्तर के आधा भाग के रूप में परिभाषित किया गया है। माना कि ए, बी और सी को क्रमशः वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं, और कुल में उत्तरों में कमी हैं, तब

$$\text{एनआर} = 100 (\text{ए} - \text{सी}), \text{ जबकि}$$

$$\text{डीआई} = 100 (\text{ए} + \text{बी} / 2)। \text{ यह बीजगणितीय रूप से दिखाया जा सकता है कि एनआर} = 2 (\text{डीआई} - 50) \text{ या डीआई} = (100 + \text{एनआर}) / 2।$$

³ सर्वेक्षण के परिणाम उत्तरदाताओं के सामूहिक विचारों को दर्शाते हैं। 27वें सर्वेक्षण दौर (अक्टूबर-दिसंबर 2020) के लिए विस्तृत एसआईओएस डेटा आरबीआई की वेबसाइट पर अन्य मौद्रिक नीति सर्वेक्षणों की तर्ज पर जारी किया जाएगा (जैसे, औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आईओएस), ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोगिता सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस)); मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संकल्प के बाद सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।



यह भी ध्यान देना दिलचस्प है कि सभी तिमाहियों के लिए आकलन पिछली तिमाही में व्यक्त की गई प्रत्याशाओं से कम है। यह अधिकांश अन्य मापदंडों के लिए भी सत्य है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए बैंक की तिमाही आईओएस में इसी तरह की घटना देखी जाती है और यह कारोबारी प्रत्याशाओं में आशावादी पूर्वाग्रह को इंगित करता है (आरबीआई, 2020)।

कुल कारोबार/बिक्री

इस प्रश्न में कंपनियों द्वारा माल की बिक्री या सेवाएं प्रदान करके जुटाए गए सकल राजस्व के बारे में प्रतिक्रिया मांगी गई है।⁴ महामारी के कारण समग्र व्यापार स्थिति के मामले में वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान एक गिरावट को छोड़कर कुल कारोबार संबंधी रुख वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक अच्छे पक्ष को दर्शाते हैं (चार्ट 3)। बाद की तिमाही में रुख में सुधार हुआ, हालांकि मूल्यांकन संकुचन क्षेत्र में बना रहा। उत्तरदाताओं को आगामी तिमाही (यानी, वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही) में और सुधार की उम्मीद है।

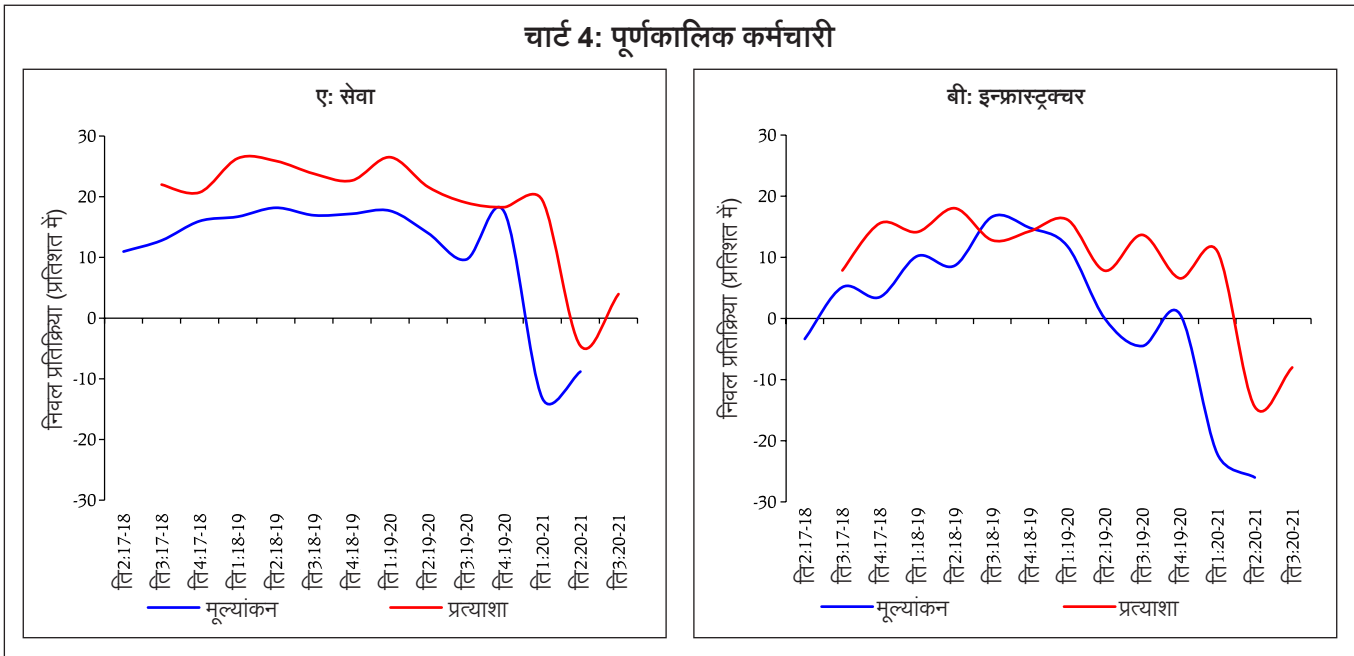
⁴ ट्रेडिंग कंपनियों के मामले में सकल बिक्री और होटल/रेस्तरां कारोबार में लगी कंपनियों के लिए उहरने, भोजन या अन्य सेवाओं, आदि से कुल आय है।

पूर्णकालिक कर्मचारी

पूर्णकालिक कर्मचारियों के संबंध में कॉर्पोरेट परिप्रेक्ष्य (जैसे, चाहे वे नियमित कर्मचारियों को बढ़ाने जा रहे हों, या नौकरियों में कटौती कर रहे हैं या पूर्णकालिक कर्मचारियों की अपनी क्षमता को बनाए रख रहे हैं) सर्वेक्षण के 14वें दौर (अर्थात्, वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही) के बाद से एकत्र किए जा रहे हैं। जहां महामारी के प्रकोप से पहले सेवा क्षेत्र के लिए रुख विस्तार क्षेत्र में थीं, वहीं आधारभूत संरचना कंपनियों में वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही से पूर्णकालिक कर्मचारियों में गिरावट देखी जा रही थी (चार्ट 4)। सर्वेक्षण के हालिया दौर से पता चलता है कि रुख को पूर्व-महामारी स्तर पर वापस आना बाकी है।

अंशकालिक कर्मचारी

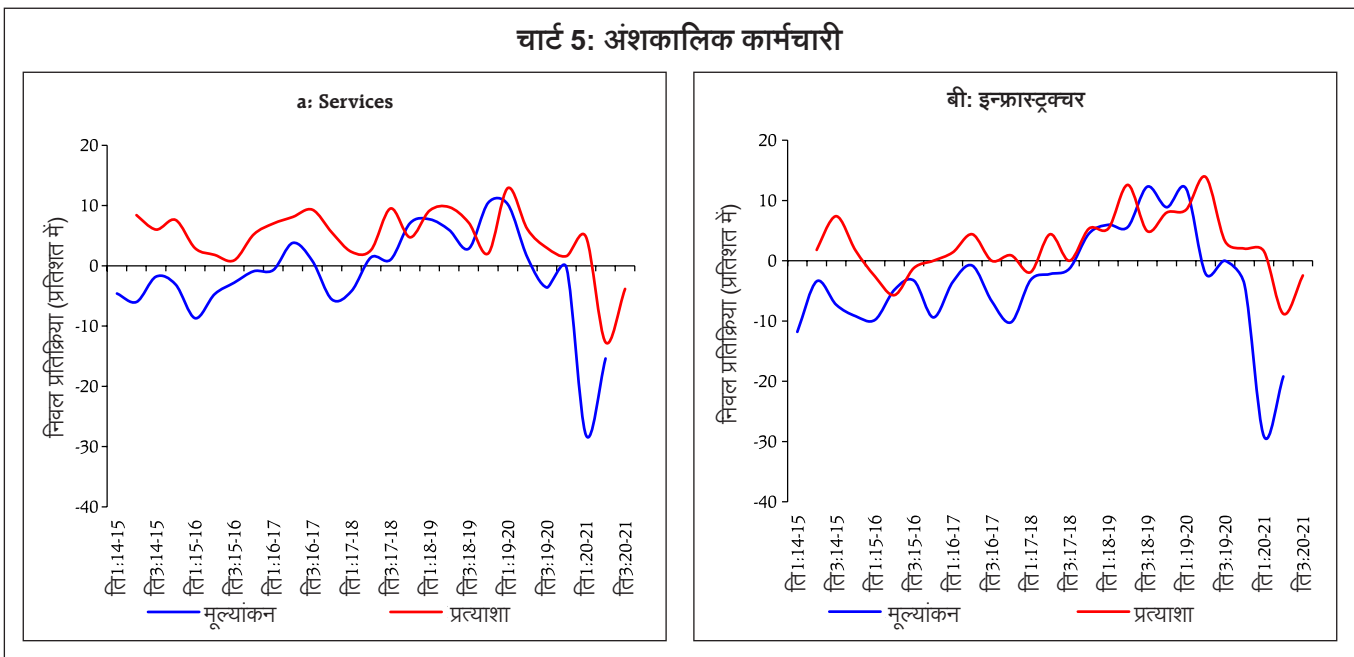
गतिविधियों की मात्रा में तेज बदलाव के कारण, सेवाओं और आधारभूत संरचना के क्षेत्र की कंपनियां अक्सर मांग की शर्तों में बदलाव को पूरा करने के लिए विनिर्माण कंपनियों की तुलना में अधिक लचीले ढंग से अंशकालिक/अनुबंध कर्मचारियों का उपयोग करते हैं। निवल आधार पर देखें तो उत्तरदाताओं वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही तक विशेष रूप से सेवा

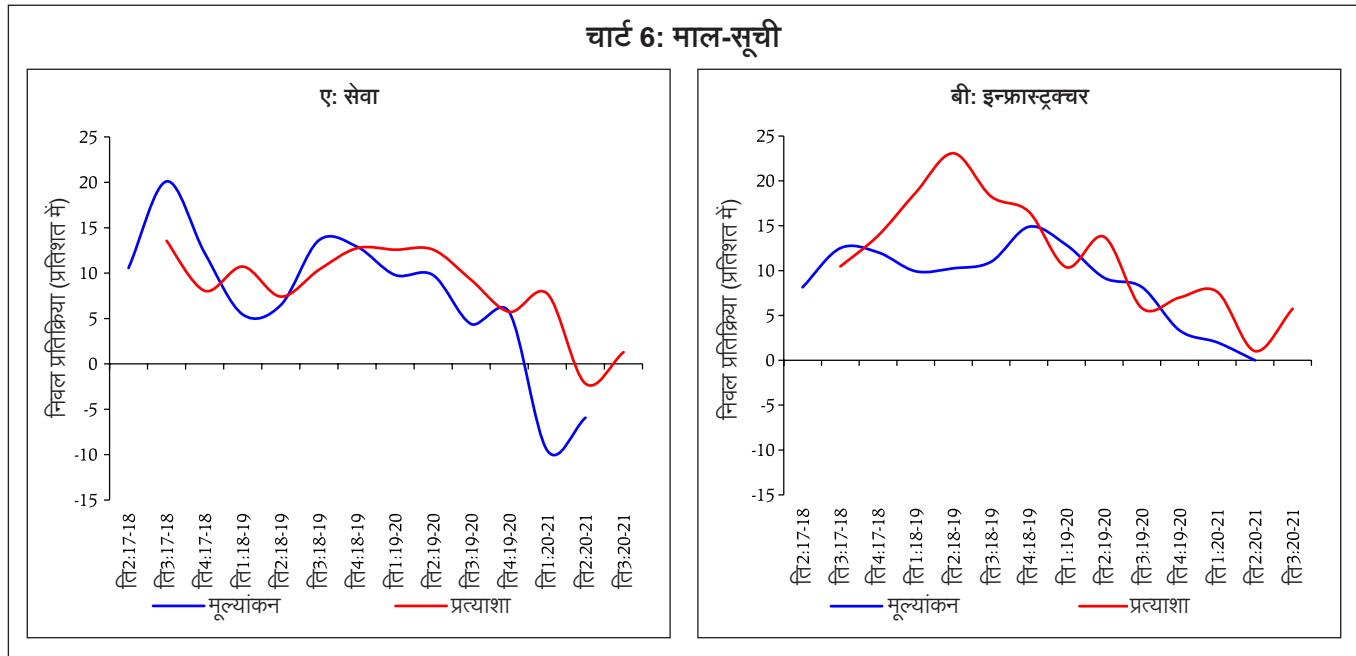


क्षेत्र में अंशकालिक कर्मचारियों को लेने पर सकारात्मक थे, लेकिन वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही के बाद से रुख प्रतिकूल हो गया (चार्ट 5)। सर्वेक्षण के हालिया दौर में कुछ सुधार दिखता है, हालांकि अभी भी रुख नकारात्मक क्षेत्र में बरकरार है।

माल सूची

माल सूची (वस्तु/सामग्री जो किसी कारोबार में पुनर्विक्रय के लिए या सेवाएं प्रदान करने के उपयोग के अंतिम उद्देश्य के लिए रखी जाती है) से संबंधित प्रश्न को वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में सर्वेक्षण प्रश्नावली में शामिल किया गया था। सेवा क्षेत्र के





लिए माल सूची संबंधी रुख विस्तार क्षेत्र में था लेकिन वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के बाद से घटना शुरू हो गया और महामारी की स्थिति के कारण वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सिकुड़ कर संकुचन क्षेत्र में आ गया (चार्ट 6)। हालांकि, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए रुख ने विस्तार क्षेत्र में कम आशापूर्ण दृष्टि के साथ जारी रखा।

वित्त की उपलब्धता और वित्त की लागत

अपने कारोबारी परिचालनों को प्रोत्सहित करने के लिए वित्त की लागत और उपलब्धता (सीओएफ़) के संबंध में कॉर्पोरेट के विचार वित्तीय नियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट होते हैं⁵ चूंकि सीओएफ़ में वृद्धि कारोबार के लिए प्रतिकूल है (व्यापार मापदंडों के बहुमत के लिए जहां वृद्धि सकारात्मक भावनाओं को इंगित करती है), इसलिए सीओएफ़ के लिए एनआर सीओएफ़ में गिरावट (डी) की प्रत्याशा करने वाले उत्तरदाताओं के अनुपात को दर्शाता है जो इसकी वृद्धि (आई) की प्रत्याशा करते हैं।

सीओएफ़ पर एनआर में वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में सुधार शुरू होने से पहले वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही तक

एक वर्ष के लिए लगातार गिरावट आई, हालांकि यह ऋणात्मक क्षेत्र में बना रहा (चार्ट 7)। सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए वित्त की उपलब्धता (एओएफ) (आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोतों से) महामारी के प्रकोप तक आशावादी क्षेत्र में थी, हालांकि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां निराशावादी रुख के बारे में बहुत पहले से (वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही के बाद से) बता रही थीं।

वेतन/मजदूरी

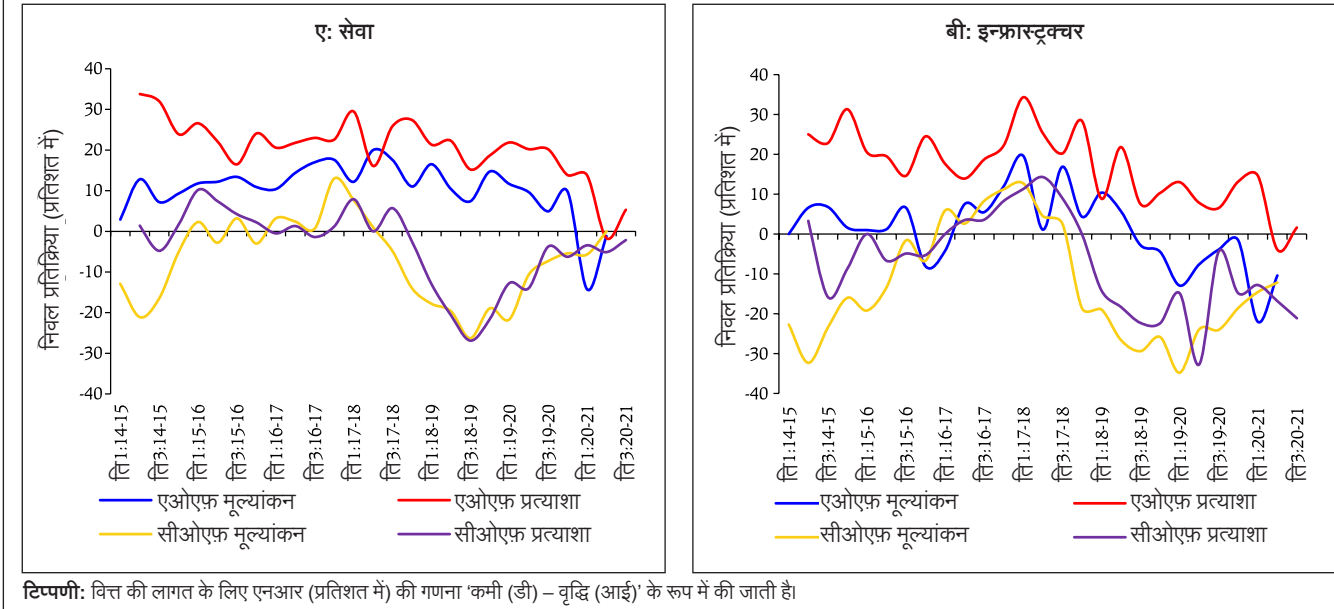
इस मानदंड को कर्मचारियों के वेतन के लिए कंपनियों द्वारा वहन की गई लागत पर रुख को भांपने के लिए वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही वाले दौर के दौरान सर्वेक्षण प्रश्नावली में शामिल किया गया था। यहाँ भी, एनआर की गणना डी-आई के रूप में की जाती है। सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों दोनों ने महामारी के प्रकोप तक निरंतर दबाव महसूस किया। इसके बाद, इससे पहले कि वेतन दबाव फिर से बढ़ना शुरू हो गया वेतन वृद्धि का मूल्यांकन किया गया क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने एक चौथाई से अधिक कर्मचारियों को नौकरी पर कम रखने को माना (चार्ट 8)।

विक्रय मूल्य और इनपुट की लागत

विक्रय मूल्य (एसपी) मानदंड, जिसे वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही के दौरान सर्वेक्षण प्रश्नावली में जोड़ा गया था, में सेवाओं की कीमत या बेचे गए माल को शामिल किया जाता है।

⁵ वित्त की लागत में बैंकों/वित्तीय संस्थानों/कारोबार साझेदारों आदि को भुगतान किया गया ब्याज शामिल होता है, और इसमें वे धन शामिल नहीं होते हैं जो अधिशेष लाभ से कारोबार में वापस रखे जाते हैं।

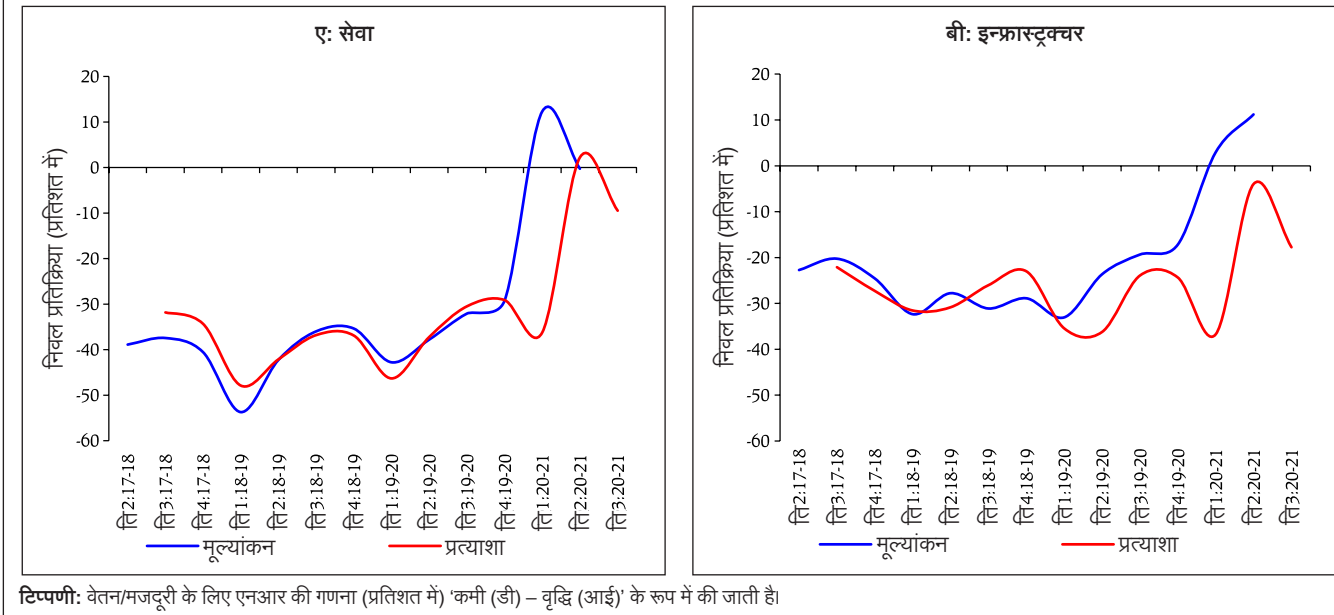
चार्ट 7: वित्त की उपलब्धता और वित्त की लागत



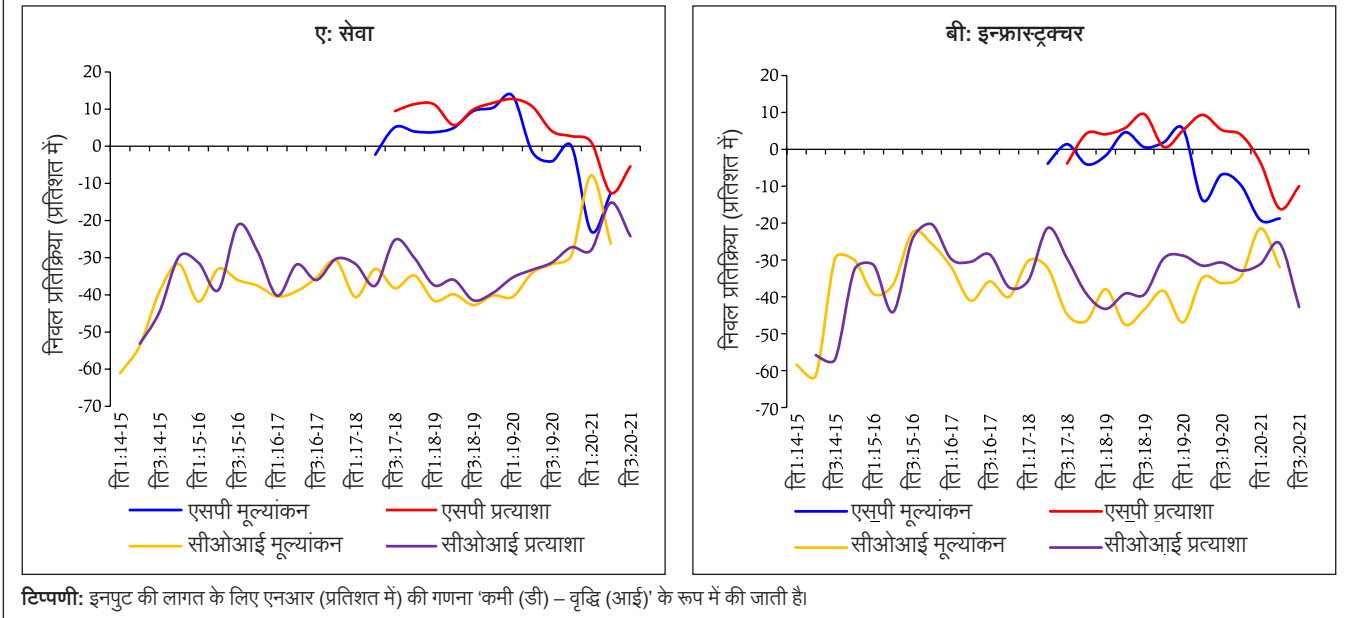
इनपुट की लागत (सीओआई) संबंधी धारणा, जो सर्वेक्षण के पहले दौर से एकत्र की जा रही है, कंपनी द्वारा किए जा रहे कारोबार के लिए भुगतान की गई कीमतों को कवर करती है। उत्तरदाताओं ने वर्ष 2019-20 तक बड़ी इनपुट लागत दबाव (सभी मापदंडों के

बीच अधिकतम एनआर पैमाने के साथ) और कम कीमत निर्धारण क्षमता के बारे में सूचना दी, जो कि लंबी अवधि से अधिक मूल्य पर बिक्री बढ़ाने में बाधाओं को दर्शाती है (चार्ट 9)। एसपी संबंधी रुख में वर्ष 2019-20 से इनपुट लागत दबाव में कुछ मॉडरेशन के

चार्ट 8: वेतन/मजदूरी



चार्ट 9: बिक्री मूल्य और इनपुट की लागत



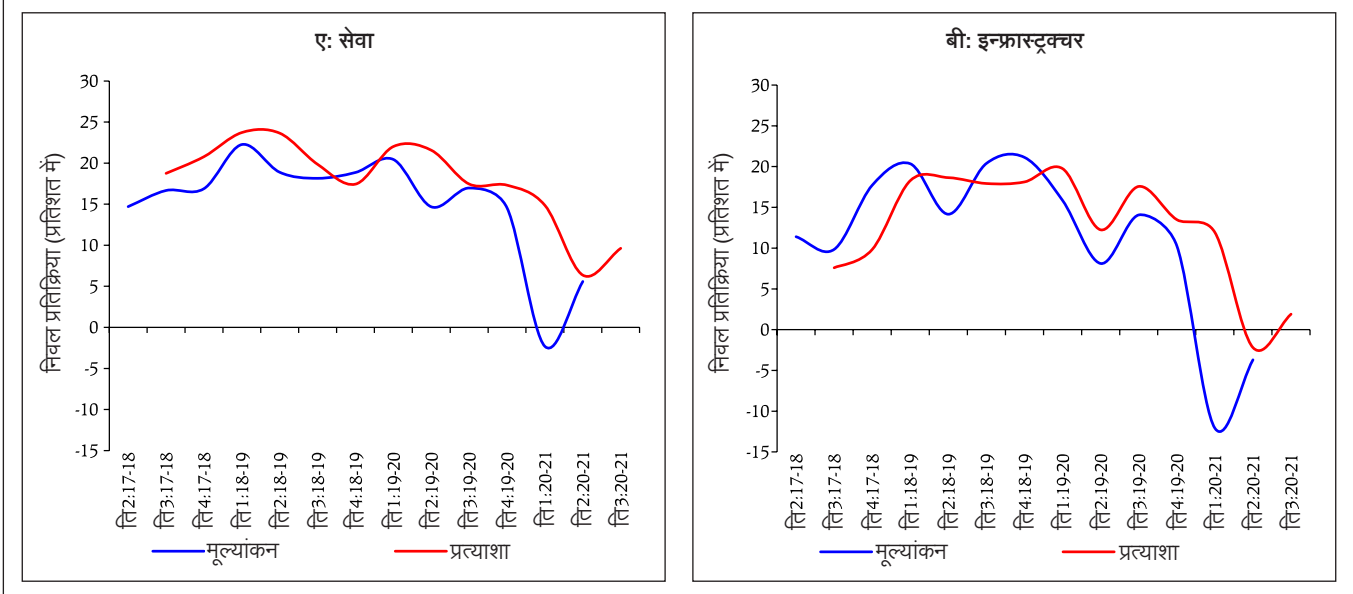
साथ गिरावट देखी गई, जो आम तौर पर निवल आधार पर सीओआई के साथ एक व्युत्क्रम संबंध साझा करते हैं।

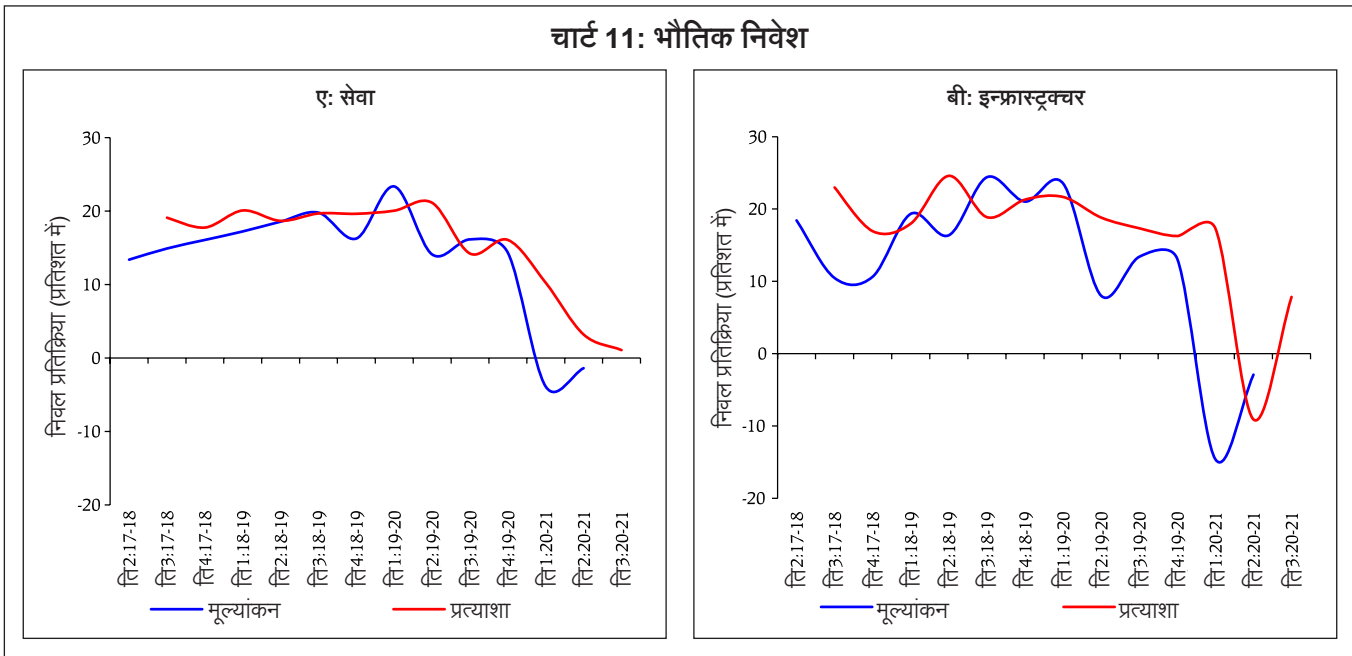
तकनीकी / सेवा क्षमता

कंपनियों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने की अधिकतम क्षमता का मूल्यांकन तकनीकी / सेवा क्षमता पर कॉर्पोरेट प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अधिकांश

कंपनियां महामारी के प्रकोप से पहले सर्वेक्षण अवधि के दौरान अपनी कारोबारी अपेक्षाओं को पूरा करने की अपनी क्षमता के बारे में सकारात्मक रहीं। कई अन्य मापदंडों के विपरीत, कंपनियों का वास्तविक मूल्यांकन पिछली तिमाही में उनकी प्रत्याशा से प्रणालीगत रूप से कम नहीं था और कारोबार क्षमता को आमतौर पर कम समय में पर्याप्त तौर पर देखा गया था।

चार्ट 10: तकनीकी/सेवा क्षमता



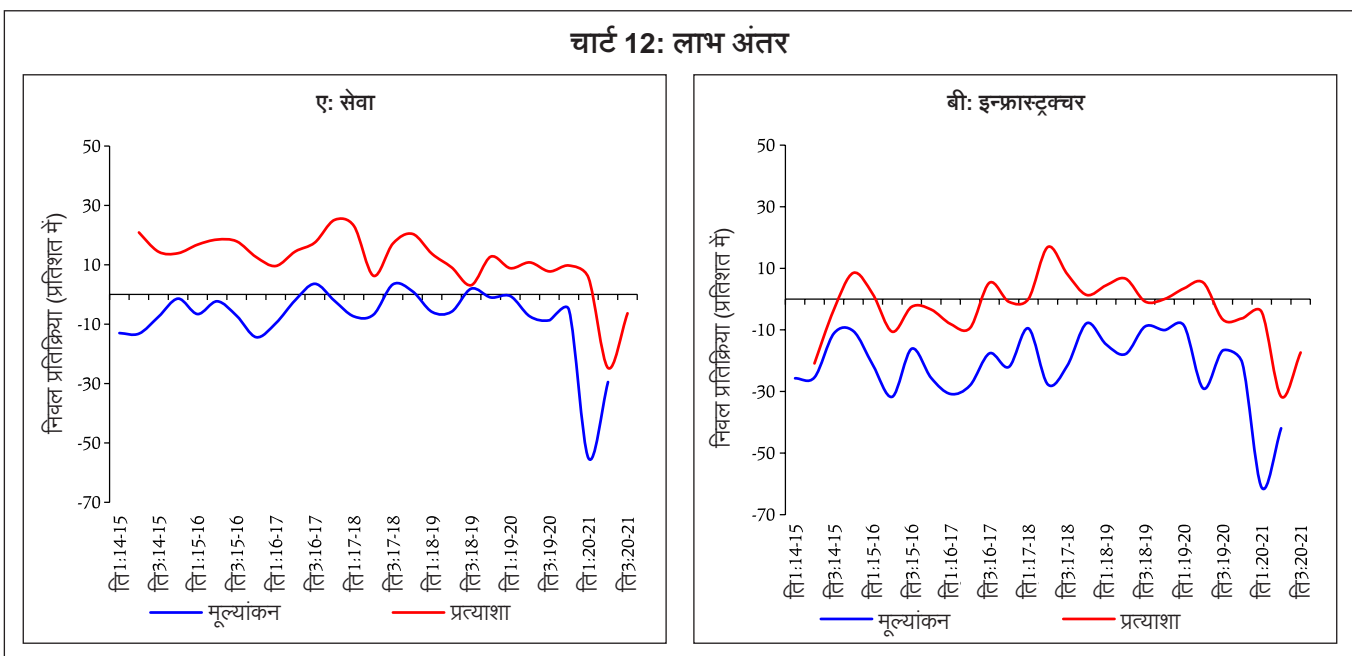


भौतिक निवेश

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियां, होटल, अस्पताल, शिक्षा संस्थान, सॉफ्टवेयर फर्म और अन्य सेवा क्षेत्र की कंपनियां भवन, उपकरण और अन्य अचल परिसंपत्तियों को अर्जित करने के लिए भौतिक निवेश करती हैं। भौतिक निवेश संबंधी रुख तकनीकी और सेवा क्षमता के लिए काफी हद तक समान थीं, जो उत्तरदाता फर्मों के बीच निरंतर आंतरिक योजना और आत्मविश्वास को दर्शा रही थी (चार्ट 10 और 11)।

लाभ का अंतर

वर्ष 2019-20 तक, निवल आधार पर, सेवा कंपनियों आमतौर पर अगली तिमाही के लिए लाभ अंतर के बारे में आशावादी थीं, हालांकि बाद का आकलन इतना सकारात्मक नहीं था; इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने शून्य के आसपास वाली प्रत्याशाओं के साथ सेवा क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में कम आशावाद व्यक्त किया (चार्ट 12)। वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनियों के दोनों समूहों ने लाभ मार्जिन पर नकारात्मक दृष्टिकोण



व्यक्त किया, हालांकि पहली तिमाही में देखी गई तेज गिरावट से वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान निराशावादी रुख में कमी आई।

V. निष्कर्ष

एसआईओएस कॉर्पोरेट परिणामों और आधिकारिक आंकड़ों से पहले सेवाओं और आधारभूत संरचना क्षेत्रों की कारोबारी रुख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसकी प्रतिक्रिया दर विनिर्माण क्षेत्र और बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के अन्य प्रगामी सर्वेक्षणों की तुलना में कम है, लेकिन प्रमुख मापदंडों पर प्रतिक्रियाओं में व्यापक आंतरिक स्थिरता है। विनिर्माण कंपनियों के समान, सेवा और आधारभूत संरचना क्षेत्रों में कंपनियों का परिणाम मूल्यांकन उनकी प्रारंभिक अपेक्षाओं से कम रहा है।

महामारी की वजह से लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के कारण वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अधिकांश कारोबार संबंधी मापदंडों पर भारी असर पड़ा। कारोबारी रुख बाद के सर्वेक्षण के दौर में बहाली के पथ पर अग्रसर हो गई है लेकिन अभी तक सभी मापदंडों पर देखें तो यह महामारी से पहले के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है।

संदर्भ:

Banca di Italia (2017), "Survey on Industrial and Service Firms – Methods and Sources" https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/metodi-e-fonti-note/metodi-note-2017/en_survey_methodology_invid.pdf

Bank of England (2017), Definitions for the Agents' scores <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/agents-summary/definitions.pdf?la=en&hash=73F78FCEFB9B8FA55F11C42F39EBE1306039165>

Bank of Japan (2020), TANKAN (Short-Term Economic Survey of Enterprises in Japan), May <https://www.boj.or.jp/en/statistics/outline/exp/tk/data/extk04a.pdf>

Banque de France, <http://www.banque-france.fr/en/economics-statistics/business-and-survey/business-surveys.html>

Bloom, Nick, Philip Bunn, Paul Mizen, Pawel Smietanka, Greg Thwaites, Garry Young (2017), "Tracking the views of British businesses: Evidence from the Decision Maker Panel", Bank of England Quarterly Bulletin 2017 Q2.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2003), "Business Tendency Surveys - A Handbook".

Reserve Bank of India (2009), "Report of the Working Group on Surveys", Reserve Bank of India Bulletin, September.

Reserve Bank of India (2020), "Sentiments of Indian Manufacturers in 2018-19", Reserve Bank of India Bulletin, February.

European Commission (2020), "The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys – User Guide", Directorate-General For Economic and Financial Affairs (updated in February 2020). https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/methodology-business-and-consumer-surveys_en

Federal Reserve Bank of Dallas, "About the Texas Service Sector Outlook Survey". <https://www.dallasfed.org/research/surveys/tssos/about.aspx>

Waddell, Sonya Ravindranath (2015), "Predicting Economic Activity through Richmond Fed Surveys" Econ Focus, Federal Reserve Bank of Richmond.

परिशिष्ट सारणी 1: सेवाओं में कारोबार स्थिति संबंधी सर्वेक्षण: देश की प्रथाएँ (जारी)

संस्थान	आवृत्ति	भाग लेने वाली फर्में	नमूने का आकार	वस्तुओं का कवरेज
बैंक डी फ्रांस	मासिक	विनिर्माण, सेवा, निर्माण और खुदरा व्यापार	10000	प्रकाशन से ठीक पहले वाले महीने में आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन, साथ में तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि के बारे में पूर्वानुमान एकत्र किया जाता है।
फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ डेवलास	मासिक	सेवा फर्म्स	230	प्रमुख संकेतकों (जैसे, राजस्व, रोजगार, कीमतें और कंपनी के दृष्टिकोण) और व्यापक आर्थिक स्थितियों (सामान्य कारोबार गतिविधि) संबंधी धारणा के लिए कारोबारी स्थितियों में परिवर्तन। उत्तर में पिछले महीने में परिवर्तन और आगामी छह महीने की गतिविधि के लिए प्रत्याशाओं को कवर किया जाता है।
फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ रिचमंड	मासिक	खुदरा व्यापारी और सेवा फर्म्स	लगभग 100	खुदरा विक्रेता बिक्री राजस्व, कीमती बिक्री, माल-सूची और खरीददार ट्रैफिक के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि सेवा फर्म अपने राजस्व पर रिपोर्ट करते हैं। उत्तरदाताओं के दोनों सेट अगले छह महीनों के दौरान रोजगार और मजदूरी, कीमत और ग्राहकों की प्रत्याशाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
बैंक ऑफ जापान	तिमाही	फर्म्स	10000	उद्यमों का कारोबारी रुझान, निर्णय सर्वेक्षण के साथ समग्र कॉर्पोरेट गतिविधि, जो कारोबारी परिस्थितियों और आर्थिक गतिविधियों पर वर्तमान स्थिति और दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया देने वाले उद्यमों के दृष्टिकोण को शामिल करता है, और उत्तर देने वाले उद्यमों के कारोबारी योजनाओं के लिए वास्तविक परिणाम और को कवर करने वाला एक मात्रात्मक सर्वेक्षण है, जिसमें बिक्री, लाभ और निश्चित निवेश के आंकड़े शामिल होते हैं।
बैंक ऑफ इटली	वार्षिक	औद्योगिक एवं सेवा फर्म्स	5000	रोजगार, निवेश (वास्तविक और नियोजित दोनों), टर्नओवर, क्षमता उपयोग, कर्ज और व्यापार प्राप्य। यह अन्य आर्थिक प्रश्नों पर भी जानकारी एकत्र करता है, जो आर्थिक अनुसंधान के लिए विशेष रूप से रुचि रखते हैं और साल-दर-साल अलग-अलग होते हैं (जैसे, कॉर्पोरेट कार्यनीतियाँ और अभिशासन, फर्म का आकार, भौतिक, मानव और संगठनात्मक पूंजी एवं बिजली)।

परिशिष्ट सारणी 1: सेवाओं में कारोबार स्थिति संबंधी सर्वेक्षण: देश की प्रथाएँ (समाप्त)

संस्थान	आवृत्ति	भाग लेने वाली फर्में	नमूने का आकार	वस्तुओं का कवरेज
बैंक ऑफ इंग्लैंड	तिमाही	फर्म्स	700	एजेंटों की कारोबारी स्थितियों का मात्रात्मक मूल्यांकन (-5 से +5 के पैमाने पर), जो सभी आर्थिक क्षेत्रों के कारोबारों के साथ चर्चा को दर्शाता है। ये स्कोर इंगित करते हैं कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू कैसे व्यवहार कर रहे हैं।
यूरोपियन कमीशन	तिमाही / मासिक (ज्यादातर मामलों में मासिक सर्वेक्षण में तिमाही सर्वेक्षण शामिल होते हैं)	उद्योग, सेवा, खुदरा व्यापार और अर्थव्यवस्था के आधार पर सामान्य या अलग-अलग शेड्यूल के माध्यम से निर्माण	कवर की गई अर्थव्यवस्थाओं के लिए अलग	33 यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न क्षेत्रों के लिए सामंजस्यपूर्ण सर्वेक्षण। इस पर तिमाही प्राशन कि 1) मुख्य कारक वर्तमान में आपके कारोबार को सीमित कर रहे हैं और 2) यदि मांग का विस्तार हुआ तो क्या आप अपने वर्तमान संसाधनों के साथ गतिविधि की मात्रा बढ़ा सकते हैं? यदि हाँ, तो कितना (प्रतिशत)? पिछले तीन महीनों के दौरान कारोबार की स्थिति, मांग (टर्नओवर) और रोजगार में गतिविधियों के संबंध में मासिक प्रश्न और अगले तीन महीनों में मांग (टर्नओवर), रोजगार और कीमतें संबंधी प्रत्याशाएँ अर्थव्यवस्थाएं अक्सर अपनी अन्य अपेक्षाओं के आधार पर अतिरिक्त प्रश्न रखती हैं।

स्रोत: केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटें (विवरण संदर्भ सूची में)।

बैंक ऋण सर्वेक्षण- हालिया रुझान*

रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किए गए भारत में बैंक ऋण सर्वेक्षण, प्रमुख क्षेत्रों में निकट अवधि में ऋण की मांग और ऋण की शर्तों तथा उनके दृष्टिकोण के बारे में बैंकों की धारणाओं पर प्रकाश डालता है। पहले दौर (वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही) के बाद से सर्वेक्षण और इसके संक्षिप्त परिणाम इस लेख में प्रस्तुत किए गए हैं। विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में उधारकर्ताओं की धारणाओं और उधारदाताओं के रुख में एक व्यापक संबंध देखने को मिलता है। कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल-जून 2020 के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उधार देने की शर्तों के संबंध में बैंकों के रुख में लगातार सुधार हुआ है।

भूमिका

बैंक की प्रभुत्व वाली भारत जैसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने में ऋण आवश्यक तत्व की भूमिका निभाता है और इसका पूर्वानुमान नीति निर्माण में एक उपयोगी इनपुट हो सकता है। ऋण संबंधी जानकारी को प्रायः इसकी मांग और वित्तपोषण की शर्तों के बारे में बैंकों की धारणाओं के साथ पूरक किया जाता है, जो कि समर्पित बैंक ऋण सर्वेक्षण (बीएलएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ ऋण अधिकारियों के सर्वेक्षण या ऋण शर्त सर्वेक्षण के रूप में भी जाना जाता है।

बैंकों के उधार देने संबंधी विकल्प विभिन्न कारणों पर निर्भर करते हैं जैसे कि समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण, चलनिधि की शर्तों, उधारकर्ताओं की साख, संबंधित क्षेत्र से जुड़ी अनिश्चितता, जोखिम प्रीमियम, पोर्टफोलियो मिश्रण और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं सहित अन्य में अपेक्षित वापसी। इस संदर्भ में, बीएलएस ऋण बाजार की शर्तों के संबंध में उधारदाता के गुणात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, विशेष रूप से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए ऋण की मांग और बैंकों की ऋण शर्तों पर बदलती आर्थिक या वित्तीय स्थितियों का प्रभाव।

आंतरिक कार्य समूह (2009) की सिफारिशों के बाद, रिजर्व बैंक ने 2010 में ऋण शर्त सर्वेक्षण (सीआरसीएस) शुरू किया।

* एंटरप्राइज सर्वेक्षण प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के विजया गंगाधरन और सुप्रिया मजूमदार द्वारा तैयार किया गया। इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

इसके प्रभावली में उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के साथ-साथ तकनीकी विशेषज्ञों और प्रतिक्रिया देने वाले बैंकों से प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ संशोधन किए गए। वर्ष 2017 में बैंक ऋण सर्वेक्षण (बीएलएस) के रूप में इसे फिर से शुरू किया गया। मौजूदा लेख में इसकी कार्यप्रणाली, इसके परिणामों में रुझान और आधिकारिक आंकड़ों एवं अन्य सर्वेक्षणों के साथ इसकी तुलना की गयी है।

लेख का बाकी हिस्सा छह खंडों में विभाजित है। खंड II बीएलएस पर अंतर-देशीय प्रथाओं को प्रस्तुत करता है। खंड III रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित तिमाही बीएलएस की कार्यप्रणाली का विहंगावलोकन प्रदान करता है; खंड IV सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रकाश डालता है और खंड V में अन्य चुनिंदा आर्थिक श्रृंखलाओं के साथ इसके संबंधों के बारे में चर्चा की गयी है। खंड VI में निष्कर्ष दिया गया है।

II. अंतर-देशीय प्रथाएँ

बैंक ऋण सर्वेक्षण नियमित रूप से प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूरो क्षेत्र के देशों) और कुछ अन्य विकासशील और उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं जैसे जमैका, नाइजीरिया और थाईलैंड, द्वारा केंद्रीय बैंकों द्वारा नियमित रूप से कराए जाते हैं, जो आम तौर पर अपने समग्र परिणाम को सार्वजनिक क्षेत्र में जारी करते हैं। यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) केंद्रीय, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी यूरोप (सीईएसईई) क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र के रुझान और चुनौतियों की निगरानी के लिए अर्ध-वार्षिक बीएलएस का प्रबंधन किया गया है।

बीएलएस बैंकों के बीच आयोजित किया जाता है और अक्सर अन्य ऋण संस्थानों को भी कवर किया जाता है और उत्तरदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक महीने तक का समय दिया जाता है। इसके उत्तरदाता आमतौर पर वरिष्ठ ऋण अधिकारी / ऋण विभाग के प्रमुख और समतुल्य पदों पर आसीन अन्य वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो 3 या 5-बिंदु स्केल पर संरचित प्रभावली के माध्यम से प्रचलित ऋण बाजार की शर्तों और तत्काल भविष्य के लिए उनकी धारणाओं एवं इरादों पर गुणात्मक मूल्यांकन प्रदान करते हैं। कई केंद्रीय बैंक तिमाही आधार पर इन सर्वेक्षणों को संचालित करते हैं, जबकि कुछ (जैसे, रिजर्व बैंक ऑफ़ न्यूजीलैंड) प्रत्येक छह महीने में उधारदाताओं से संपर्क करते हैं।

सर्वेक्षण प्रश्न आम तौर पर ऋण की मांग, ऋण मानकों और निबंधन / शर्तों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण को प्रभावित करने वाले कारकों (जैसे, कारोबार, हाउसहोल्ड्स, गैर-वित्तीय निगम) से संबंधित होते हैं। वे बैकवर्ड लुकिंग होते हैं (जैसे पिछले तीन महीनों के दौरान हुई प्रगति) और / या फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं (जैसे, अगले तीन महीनों में प्रत्याशित बदलाव)। कुछ केंद्रीय बैंक सर्वेक्षण (उदाहरण के लिए, बैंक ऑफ जापान और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी)) विशेष रूप से उत्तरदाताओं से अनुरोध करते हैं कि वे ऋण की मांग के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए सामान्य मौसमी बदलावों की अनदेखी करें। प्रतिक्रियाओं को आम तौर पर एकल सांख्यिकीय, अर्थात् निवल प्रतिशत संतुलन या प्रसार सूचकांक के रूप में एकत्र किया जाता है - ईसीबी सर्वेक्षण के लिए दोनों गणना की जाती हैं (सारणी 1)।

ईसीबी के बीएलएस डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि चूंकि परिणाम अन्य आंकड़ों के अनुरूप थे, सर्वेक्षण आर्थिक और वित्तीय रुझानों की नीति निर्माताओं की समझ को और बढ़ा सकता है (बर्ग एवं अन्य, 2005)। सर्वेक्षण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रोजेक्शन संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करता है और विशिष्ट क्षेत्रों पर सर्वेक्षण के परिणाम उन क्षेत्रों में वास्तविक

गतिविधि की भविष्यवाणी करने के लिए प्रासंगिक हैं (कनिंघम, 2006)।

मानक बीएलएस प्रश्नावली के जवाबों का विश्लेषण करने के अलावा, एक अन्य अध्ययन ने वित्तीय संकट के दौरान ईसीबी के मानक और गैर-मानक उपायों की प्रभावशीलता के बारे में पेश किए गए तदर्थ प्रश्नों का मूल्यांकन किया। यह पाया गया कि बैंकों के थोक और खुदरा बाजारों में पर्याप्त धन तक पहुंच है या नहीं, इस बारे में बारीकियों को समझने में सर्वेक्षण उपयोगी था कि क्या बैंक निधीयन और बैंक उधारी पर सरकारी कर्ज के तनाव का प्रभाव; और ईसीबी की नकारात्मक जमा सुविधा की दर से बैंकों की निवल ब्याज आय और बैंक ऋण कैसे प्रभावित होते हैं (कोल्लर-उलब्रिच एवं अन्य, 2016)। ग्लोबल वेक्टर ऑटोरोग्रेसिव (जीवीएआर) फ्रेमवर्क में सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग करते हुए, एक अध्ययन में पाया गया कि सामान्य रूप से विस्तारवादी मौद्रिक नीतियों के परिणामस्वरूप कम क्रेडिट मानक थे, जो बदले में मौद्रिक नीति के महत्व को मजबूती प्रदान कर रहे थे। हालांकि, विस्तारवादी प्रभाव अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों के बारे में घोषणाओं के समय मौन था, जो कि अंतर्निहित आर्थिक संभावनाओं के अपग्रेडिंग के रूप में पठित सिग्नलिंग प्रभाव के कारण होने की संभावना थी (फाइलार्डो और सिकलो, 2020)।

सारणी 1: बैंक ऋण या ऋण परिस्थिति सर्वेक्षण पर चुनिंदा केंद्रीय बैंकों के अनुभव

केंद्रीय बैंक और सर्वेक्षण के नाम	आवधिकता	वर्तमान नमूना	संकलन और एकत्रित डेटा
अमेरिकी फेडरल रिज़र्व सीनियर लोन ऑफिसर ओपिनियन सर्वे ऑन बैंक लेंडिंग प्रैक्टिसेस	तिमाही (1964 से)	• बड़े घरेलू वाणिज्यिक बैंक • विदेशी बैंकों की बड़ी अमेरिकी शाखाएं / एजेंसियां	• निवल प्रतिशत संतुलन • बैकवर्ड लुकिंग (3 महीना)
बैंक ऑफ कनाडा सीनियर लोन ऑफिसर सर्वे	तिमाही (1999 से)	• कनाडा में प्रमुख वित्तीय संस्थान	• विचार संतुलन • वर्तमान तिमाही के लिए (तिमाही की समाप्ति के समय एकत्र किए गए विचार जिसके लिए परिणाम रिपोर्ट किए गए हैं)
बैंक ऑफ जापान सीनियर लोन ऑफिसर ओपिनियन सर्वे ऑन बैंक लेंडिंग प्रैक्टिसेस ऐट लार्ज जाइपनीज बाइंक्स	तिमाही (2000 से)	• ऋणों की औसत राशि बकाया के मामले में बड़े बैंक	• प्रसार सूचकांक • बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग (3 महीना)
यूरोपियन सेंट्रल बैंक द यूरो एरिया बैंक लेंडिंग सर्वे	तिमाही (2003 से)	• प्रतिनिधि नमूना यूरो क्षेत्र के बैंक, संबंधित राष्ट्रीय बैंकिंग संरचनाओं की विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं।	• निवल प्रतिशत संतुलन और प्रसार सूचकांक • बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग (कुछ सवालों के लिए 6 महीने और अन्य के लिए 3 महीने) • व्यक्तिगत बैंक परिणामों को यूरो क्षेत्र के देशों के लिए राष्ट्रीय परिणामों के लिए एकत्र किया जाता है, और दूसरे चरण में, राष्ट्रीय बीएलएस परिणामों को यूरो क्षेत्र बीएलएस परिणामों के लिए एकत्र किया जाता है।
बैंक ऑफ इंग्लैंड क्रेडिट कंडीशन सर्वे	तिमाही (2007 से)	• बैंक • समाज के उधारदाताओं का निर्माण	• निवल प्रतिशत संतुलन • बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग (3 महीना)

स्रोत: केंद्रीय बैंकों की वेबसाइट (संदर्भ सूची में विस्तार से दिया गया है)।

III. रिजर्व बैंक का ऋण सर्वेक्षण

रिजर्व बैंक का बीएलएस मोटे तौर पर अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए समान सर्वेक्षणों के अनुरूप है। यह प्रचलित ऋण बाजार की शर्तों के बारे में सर्वेक्षणकर्ताओं की प्रतिक्रिया प्रदान करता है और भविष्य में डेटा उपलब्ध होने से पहले बैंक ऋणों की भविष्य की मांग के साथ-साथ उनके निबंधन और शर्तों में भी बदलाव के संकेत देता है।

कार्यप्रणाली, नमूना आकार और प्रतिक्रिया दर

सर्वेक्षण का नमूना भारत में शीर्ष 30 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के एक पैनल को कवर करता है, जो कुल बकाया ऋण का 90 प्रतिशत से अधिक है। उत्तरदाताओं का एक निश्चित पैनल वित्तीय वर्ष के दौरान रद्द कर दिया जाता है और नवीनतम वित्तीय वर्ष में ऋण बकाया के आधार पर पैनल को अपडेट किया जाता है (बैंकिंग कारोबार / विलय को ध्यान में रख कर)। लक्ष्य उत्तरदाता बैंकों के ऋण विभाग या वरिष्ठ ऋण अधिकारियों के प्रमुख होते हैं, जिन्हें आम तौर पर सर्वेक्षण प्रश्नावली का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। बीएलएस में भागीदारी स्वैच्छिक है और प्रतिक्रिया की दर 85 प्रतिशत से अधिक है।

सर्वेक्षण दोगुने बिंदुओं के लिए बैंक के गुणात्मक दृष्टिकोण की तलाश करता है - पिछली तिमाही की तुलना में वर्तमान तिमाही के मूल्यांकन और वर्तमान तिमाही के मुकाबले आगामी तिमाही के लिए प्रत्याशाओं का मूल्यांकन करता है। सर्वेक्षण में प्रयुक्त बहु-विकल्प प्रश्नावली व्यापक आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करती है। ऋण की मांग के मामले में, मौजूदा तिमाही के बदलावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है और निम्नलिखित क्षेत्र के लिए अगली तिमाही के लिए 5-सूत्री (अर्थात्, पर्याप्त वृद्धि, मामूली वृद्धि, समान (कोई परिवर्तन नहीं), मामूली कमी और पर्याप्त गिरावट) प्रत्याशाएँ होती हैं:

- i. सभी सेक्टर
- ii. कृषि
- iii. खनन और उत्खनन (कोयला सहित)
- iv. विनिर्माण
- v. इन्फ्रास्ट्रक्चर
- vi. सेवा
- vii. खुदरा/व्यक्तिगत

इसी तरह के सवाल ऋण के निबंधन और शर्तों संबंधी 5-पॉइंट स्केल पर पूछे जाते हैं। ऋण की निबंधन और शर्तों एक अनुमोदित ऋण के लिए विशिष्ट हैं, ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच सहमत शर्तों और ऋण संविदा में रखी गई हैं। ऋण की निबंधन और शर्तों कीमत और गैर-कीमत दोनों पहलुओं को कवर करती हैं और इसमें प्रासंगिक संदर्भ / ब्याज दर, ऋण के आकार और अन्य गैर-ब्याज शुल्क (जैसे शुल्क, संपार्श्विक या गारंटी की आवश्यकता, ऋण प्रसंविदा, सहमत ऋण परिपक्वता) समाहित होता है। ऋण की शर्तें उधारकर्ता की विशेषताओं पर सशर्त हैं और बैंक के ऋण अनुमोदन मानदंडों के साथ बदल सकती हैं।

सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं का एकत्रीकरण

बीएलएस में एकत्र की गई प्रतिक्रियाएं 5-पॉइंट स्केल पर हैं और उन्हें एक ही संख्या में संक्षेपित किया जाता है जिसे नेट रिस्पांस (एनआर)¹ कहा जाता है, {जिसे बैलेंस स्टैटिस्टिक्स (बीएस) स्कोर के रूप में भी जाना जाता है}, जो कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के अनुपात के बीच भारित अंतर है, जहां 'कोई परिवर्तन नहीं / समान' प्रतिक्रियाओं को शून्य भार सौंपा गया है। एनआर मान -100 से +100 तक माना जा सकता है: एनआर के सकारात्मक मान पैरामीटर / क्षेत्र (जैसे, ऋण मांग में वृद्धि का अनुभव या ऋण नियमों और शर्तों में ढील) के लिए आशावाद का संकेत देते हैं जबकि शून्य से नीचे का मूल्य निराशावाद को दर्शाता है (जैसे, कम ऋण मांग या ऋण नियमों और शर्तों को कड़ा करना)। इस प्रकार निवल प्रतिक्रिया गुणात्मक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने में मदद करती है जो रुख में परिवर्तन की दिशा को इंगित करती है; हालाँकि, यह कड़ाई से परिवर्तन के परिमाण का अनुमान नहीं लगाता है।

¹ निवल प्रतिक्रिया (NR) = $\{1 * P_2 + 0.5 * P_1 + 0 * P_0 + (-0.5) * P_{(-1)} + (-1) * P_{(-2)}\}$, जहां, $P_i = i^{\text{th}}$ श्रेणी के लिए प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत है, अर्थात् P_2 = बैंकों की ऋण मांग की 'पर्याप्त वृद्धि' के रूप में ऋण की मांग या ऋण के निबंधन और शर्तों 'बहुत ही आसान' के रूप में, P_1 = बैंकों की ऋण की मांग को 'मामूली वृद्धि' या ऋण संबंधी निबंधन और शर्तों के रूप में रिपोर्ट करना 'कुछ हद तक सहज' के रूप में, P_0 = बैंकों की ऋण मांग या ऋण की निबंधन और शर्तों को रिपोर्ट करने के लिए 'समान / कोई परिवर्तन नहीं' रहने के लिए, $P_{(-1)}$ = 'प्रतिशत में कमी' या 'कुछ हद तक सख्ती' के रूप में ऋण की निबंधन और शर्तों के रूप में बैंकों की ऋण मांग की रिपोर्ट करने वाले का प्रतिशत और $P_{(-2)}$ = 'पर्याप्त कमी' या 'उल्लेखनीय सख्ती' के रूप में ऋण संबंधी निबंधन एवं शर्तों के तौर पर बैंकों की ऋण मांग रिपोर्ट करने वाले बैंकों का प्रतिशत।

IV. सर्वेक्षण निष्कर्ष

वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत के बाद से लेकर अब तक बीएलएस सर्वेक्षणों के तेरह दौर पूरे हो गए हैं। ऋण की मांग और ऋण निबंधन और शर्तों पर बैंकों की धारणाओं में व्यापक उतार-चढ़ाव को इस खंड में प्रस्तुत किया गया है (विवरण 1 से 4)²

ऋण की मांग

कोविडी -19 महामारी और संबंधित लॉकडाउन ने अप्रैल-जून 2020 के दौरान सभी क्षेत्रों में ऋण मांग में उल्लेखनीय संकुचन किया, जिसने भारतीय बैंकों के बीच रुख को गंभीर रूप से कम कर दिया (विवरण 1)। हालांकि, जुलाई-सितंबर 2020 के दौरान, ऋण अधिकारियों का रुख जल्दी से ठीक हो गया, और इसमें व्यापक आधार पर सुधार हुआ था। इन्फ्रास्ट्रक्चर, खनन और उत्खनन क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम आशावादी रुख दर्ज किया गया। लॉकडाउन तिमाही (2020-21 की पहली तिमाही) के दौरान सबसे तेज गिरावट दर्ज करने के बाद खुदरा / व्यक्तिगत ऋण मांग का मूल्यांकन किया गया था।

जनवरी-मार्च 2020 के दौरान आयोजित बीएलएस के ग्यारहवें दौर में, वरिष्ठ ऋण अधिकारियों ने सभी क्षेत्रों के लिए ऋण

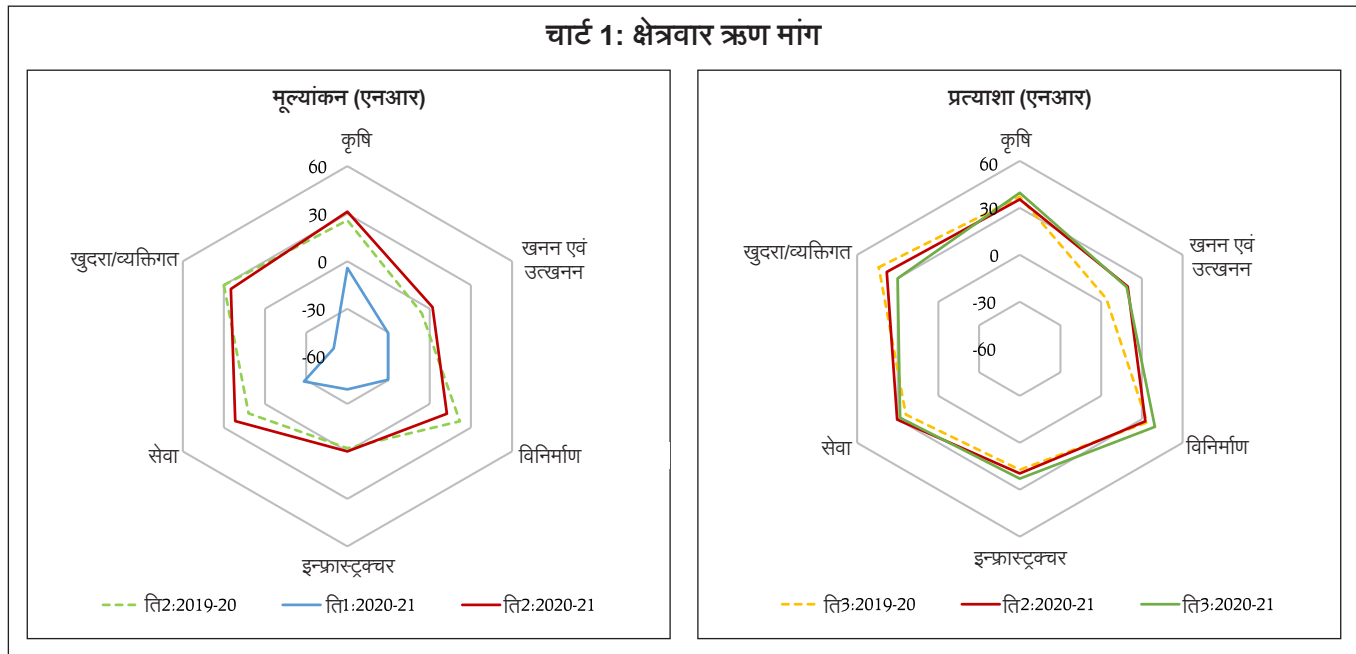
मांग के लिए कम आशावादी रुख व्यक्त किया, लेकिन अग्रिम में संकुचन का अनुमान नहीं लगाया गया क्योंकि वे कोविडी-19 महामारी की गंभीर और औचक प्रकृति के कारण, पूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं कर सकते थे जो बाद में देखने को मिला (विवरण 2)। बाद के दो सर्वेक्षण दौरों ने तिमाही-दर-तिमाही ऋण मांग में सुधार का संकेत दिया। प्रमुख क्षेत्रों में, बैंकों ने हाल के दिनों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बाद खुदरा / व्यक्तिगत ऋण और कृषि क्षेत्रों की उच्च मांग की उम्मीद की है।

अप्रैल-जून 2020 में बताए गए कम मूल्यांकन से पुनर्जीवित, सेक्टर-विशिष्ट एनआर की तुलना जुलाई-सितंबर 2020 में सेक्टरों में ऋण की मांग पर बैंकों की आशावाद को इंगित करती है (चार्ट 1)। बैंकों को वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान ऋण मांग में सुधार की उम्मीद है।

ऋण की निबंधन और शर्तों

बैंककर्मों ऋण के निबंधन और शर्तों में अचानक तिमाही-दर-तिमाही बदलाव नहीं करते हैं; ये क्षेत्रों में ऋण के प्रदर्शन, समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों और क्षेत्रों में विकास के अवसरों पर अधिक निर्भर हैं। कृषि और व्यक्तिगत ऋण खंडों के लिए एनआर हमेशा

चार्ट 1: क्षेत्रवार ऋण मांग



² सर्वेक्षण के नतीजे उत्तरदाताओं के सामूहिक विचारों को दर्शाते हैं। 14वें सर्वेक्षण दौर (अक्टूबर-दिसंबर 2020) के लिए विस्तृत बीएलएस डेटा अन्य मौद्रिक नीति सर्वेक्षणों की तर्ज पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के प्रस्ताव को सार्वजनिक डोमेन में रखे जाने के बाद रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा {उदाहरण के लिए, औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आईओएस), ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और कैपिटलाइजेशन यूटिलाइजेशन सर्वे (ओबीआईसीयूएस)}।

सकारात्मक क्षेत्रों में रहा है जो इन क्षेत्रों में बेहतर ऋण निबंधन और शर्तों को दर्शाता है (विवरण 3)। लॉकडाउन तिमाही के दौरान मूल्यांकन को रोकते हुए सेवा क्षेत्र के लिए ऋण संबंधी निबंधन और शर्तों पर भी रुख को कम करने का संकेत दिया। हालाँकि, इन्फ्रास्ट्रक्चर, खनन और उत्खनन क्षेत्र के लिए ज़्यादातर बैंकों ने ऋण की शर्तों में कुछ सख्ती की सूचना दी थी।

क्षेत्र-विशिष्ट एनआर की तुलना से संकेत मिलता है कि बैंकों ने जुलाई-सितंबर 2020 में बोर्ड के बेहतर ऋण संबंधी निबंधन और शर्तों को पिछली तिमाही में कम मूल्यांकन से पुनर्जीवित किया। वे वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान 'ऋण निबंधन और शर्तों को और आसान बनाने' की प्रत्याशा करते हैं।

V. आधिकारिक सांख्यिकी और अन्य सर्वेक्षण के बीच सर्वेक्षण परिणाम संबंध

इस खंड में सर्वेक्षण परिणामों की तुलना वास्तविक ऋण रुझानों के साथ-साथ अन्य सर्वेक्षणों से की गई है

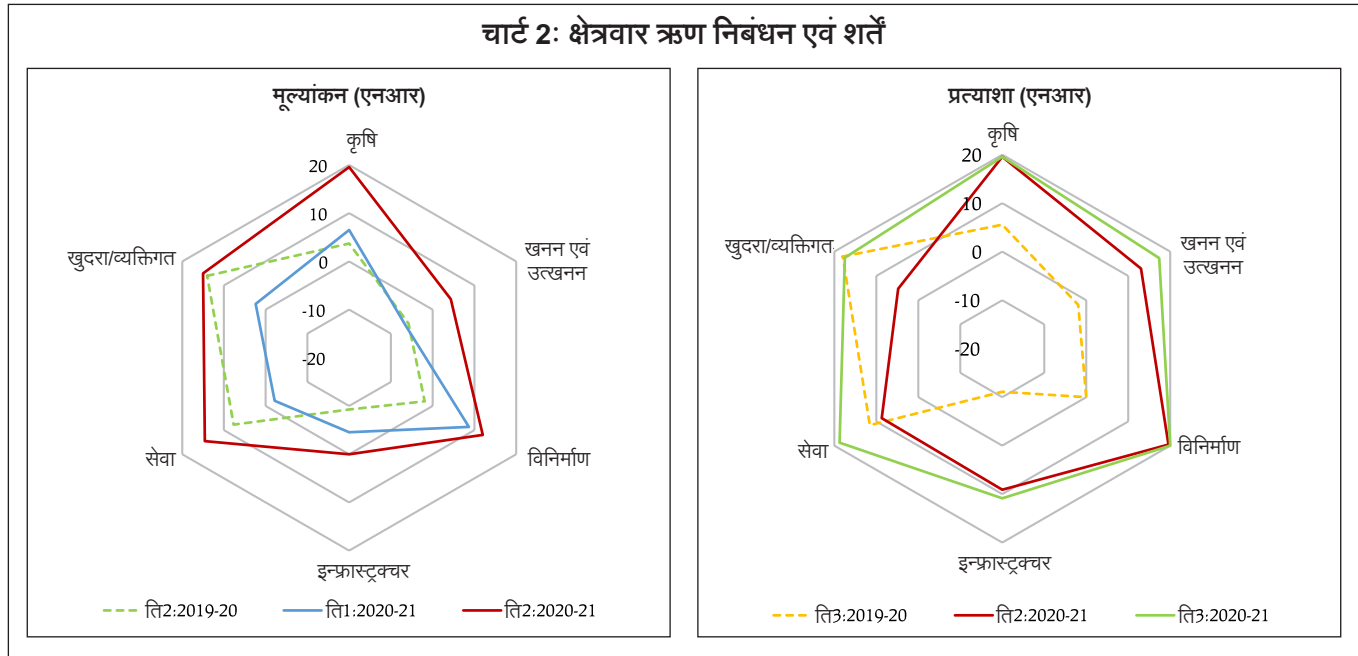
ताकि उन्हें प्रभावी नीतिगत इनपुट के रूप में उपयोग किया जा सके।

बीएलएस और वास्तविक बैंक ऋण

ऋण मांग परिस्थितियों में परिवर्तन के बारे में बैंकों का मूल्यांकन एससीबी द्वारा वास्तविक ऋण में वृद्धि के अच्छा-खासा करीब है, जिसके आंकड़े बाद में जारी किए जाते हैं। ऋण की मांग पर उनकी प्रत्याशाएँ आम तौर पर अधिक आशावादी रही हैं, लेकिन मोटे तौर पर ऋण वृद्धि चक्र में आमूलचूल परिवर्तन को शामिल करती है।

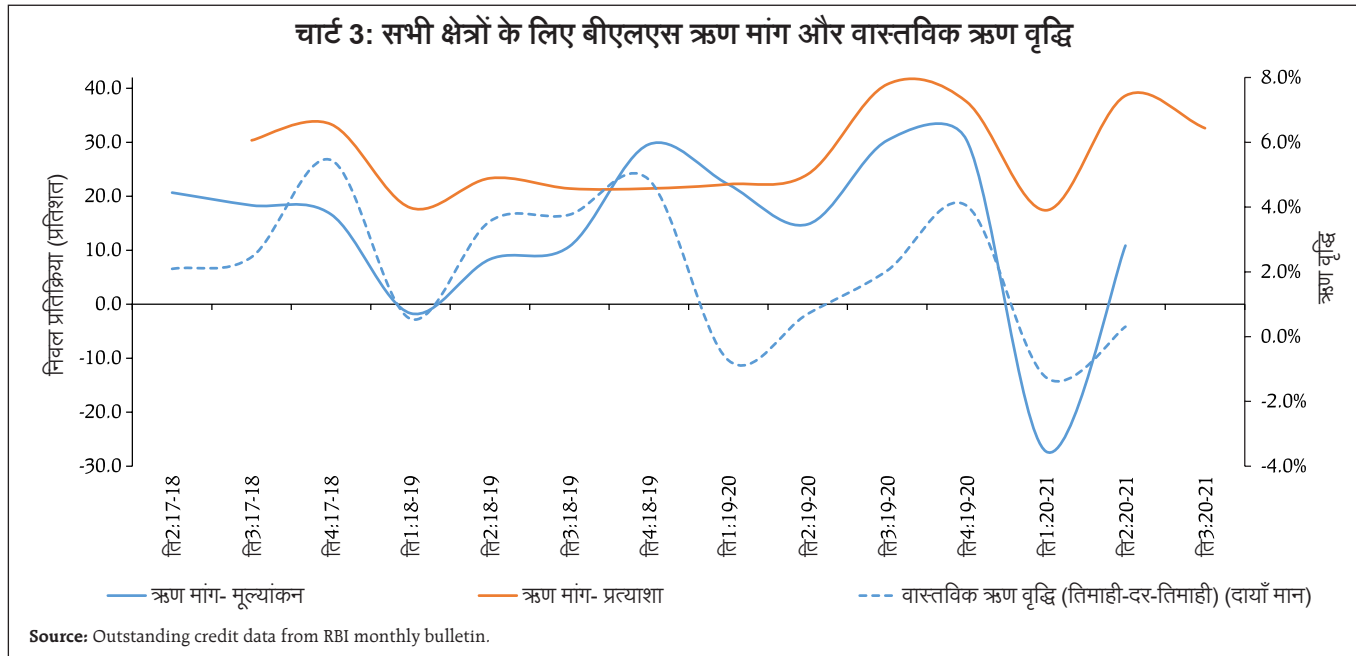
उधारकर्ताओं और उधारदाताओं द्वारा विनिर्माण क्षेत्र के लिए ऋण परिस्थितियों का मूल्यांकन

बीएलएस आपूर्ति पक्ष पर नजर डालता है (यानी, उधारदाता का दृष्टिकोण) जबकि आरबीआई का तिमाही औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस)³ विनिर्माताओं से वित्त की उपलब्धता (बैंकों और अन्य घरेलू स्रोतों से)⁴ पर मांग पक्ष मूल्यांकन और दृष्टिकोण तलाशता है, जो उधारकर्ताओं के महत्वपूर्ण भागीदार हैं।



³ आईओएस डेटा आरबीआई की वेबसाइट पर तिमाही आधार पर जारी किए जाते हैं (नवीनतम वेब रिलीज़ के लिए 9 अक्टूबर, 2020 वेब-लिंक देखें <https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=19984>) का है।

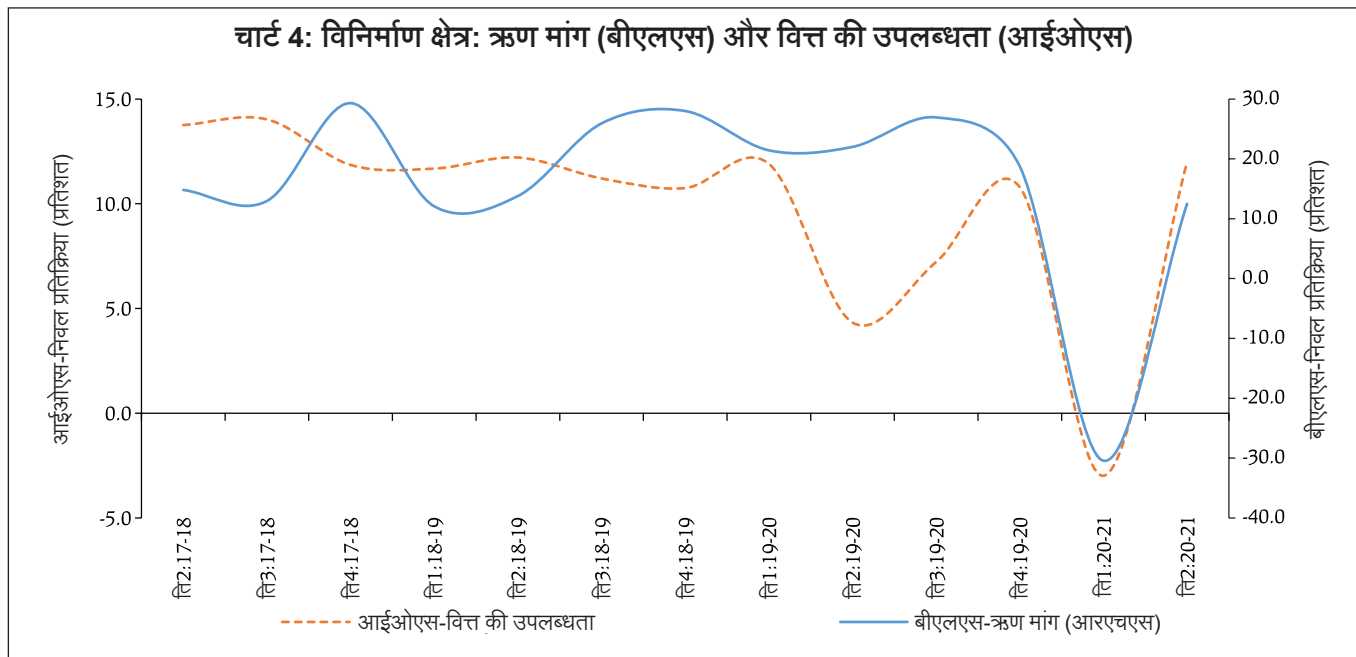
⁴ आईओएस में निर्माताओं के बीच रखे गए पैरामीटर 'वित्त की उपलब्धता' (बैंकों और अन्य घरेलू स्रोतों से, यानी वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार आदि से), 'वित्त की उपलब्धता (आंतरिक स्रोतों से)' और 'वित्त की उपलब्धता' (विदेशों से, यदि लागू हो) हैं।



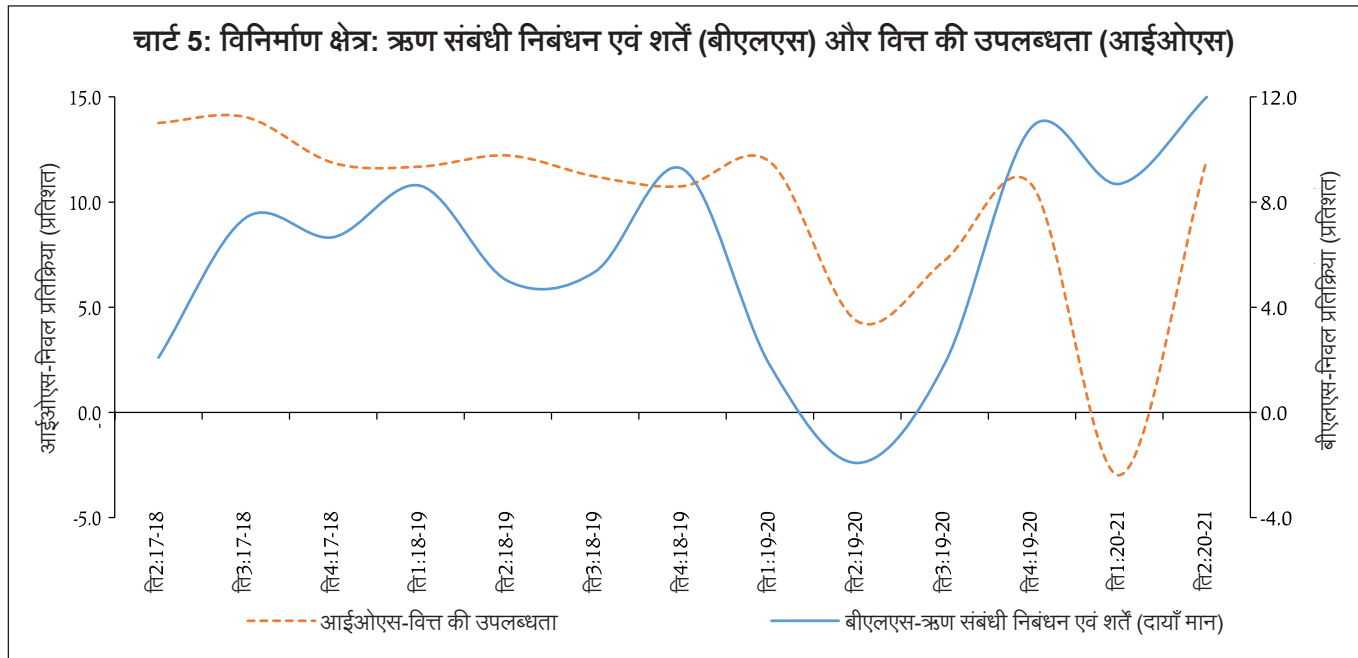
आईओएस 3-बिंदु स्केल (सुधार / खराब / कोई परिवर्तन नहीं) पर वित्त की उपलब्धता पर राय एकत्र करता है और परिणाम निवल प्रतिक्रियाओं⁵ के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

आईओएस से वित्त की उपलब्धता (बैंकों और अन्य स्रोतों से) पर बीएलएस और विनिर्माताओं के रुख से 'विनिर्माण क्षेत्र से

ऋण की मांग' पर बैंकों का मूल्यांकन कुछ समय बिंदुओं पर समान दिशात्मक परिवर्तनों का संकेत देता है, लेकिन अन्य मामलों में संभवतः धारणा/ बड़े परिवर्तन का मिलान नहीं होता है क्योंकि गैर-बैंक स्रोतों से समान मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है, जो वित्त के एक बड़े हिस्से के लिए लेखांकन हो सकता है (चार्ट 4)।



⁵ आईओएस मापदंडों के लिए एनआर की गणना सकारात्मक (आशावादी) प्रतिक्रियाओं के प्रतिशत में से ऋणात्मक (निराशावादी) प्रतिक्रियाओं को घटाकर की जाती है।



विनिर्माण क्षेत्र के लिए ऋण की शर्तों को आसान बनाने के बारे में बैंकों की धारणा आम तौर पर इसी तरह की है क्योंकि विनिर्माताओं की वित्त की उपलब्धता में सुधार का रुख है (चार्ट 5)। दो सर्वेक्षणों से निकलने वाली राय के संतुलन का सह-संचलन विनिर्माण क्षेत्र के लिए ऋण परिस्थिति की जानकारी को पुष्ट करता है।

VI निष्कर्ष

सर्वेक्षण के नतीजों से पता चलता है कि अप्रैल-जून 2020 के दौरान महामारी के गंभीर प्रभाव के बाद, उधार देने की परिस्थिति में बैंकों के रुख में व्यापक सुधार हुआ है। प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि खुदरा / व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में धारणाओं में वापस उछाल आया है, जो इस अवधि के

दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थीं। उत्तरदाता अन्य प्रमुख क्षेत्रों की तुलना में इन्फ्रास्ट्रक्चर, खनन और उत्खनन क्षेत्रों के लिए कम आशावादी थे।

एक दूरगामी दृष्टिकोण को देखते हुए, बीएलएस वास्तविक ऋण वृद्धि की अच्छी तरह से अनुकरण करता है और चूंकि सर्वेक्षण के परिणाम पहले से उपलब्ध हैं, इसलिए यह नीति निर्माताओं के लिए अंतर्निहित रुझानों को कम करने के लिए एक उपयोगी उपकरण साबित हो सकता है। बीएलएस में परिलक्षित आईओएस और ऋणदाताओं के रुख से उधारकर्ताओं की धारणाओं में एक व्यापक संबंध भी देखने को मिलता है। आगे चलकर, बीएलएस परिणामों की नियमित उपलब्धता से ऋण बाजार परिस्थितियों का लाभकारी पूर्वानुमान प्रदान करने की संभावना है।

विवरण 1: क्षेत्र-वार ऋण माँग के लिए निवल प्रतिक्रिया – वर्तमान तिमाही के लिए मूल्यांकन

(प्रतिशत)

सर्वेक्षण दौर संख्या	सर्वेक्षण मूल्यांकन तिमाही	सभी क्षेत्र	कृषि	खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	विनिर्माण	इन्फ्रास्ट्रक्चर	सेवा	खुदरा/व्यक्तिगत ऋण
1	ति2:17-18	20.7	27.6	3.4	14.8	1.9	8.9	36.5
2	ति3:17-18	18.3	31.7	-8.3	13.0	7.1	22.4	31.3
3	ति4:17-18	16.7	23.3	-13.8	29.3	25.0	23.3	50.0
4	ति1:18-19	-1.7	25.0	3.4	12.1	0.0	16.7	26.8
5	ति2:18-19	8.3	10.0	-3.3	13.8	1.7	18.3	31.0
6	ति3:18-19	10.7	24.1	0.0	25.9	1.8	14.3	44.0
7	ति4:18-19	29.6	28.8	7.4	28.0	5.6	18.5	36.0
8	ति1:19-20	22.2	29.3	-1.9	21.4	10.3	17.9	23.1
9	ति2:19-20	14.8	25.9	-5.8	22.0	-1.9	12.0	30.0
10	ति3:19-20	30.4	30.4	9.3	26.9	3.7	17.3	46.2
11	ति4:19-20	30.4	36.0	0.0	18.8	4.3	13.0	32.5
12	ति1:20-21	-27.3	-4.2	-30.4	-30.4	-39.1	-28.3	-50.0
13	ति2:20-21	10.9	31.3	2.1	12.5	0.0	21.7	25.0

विवरण 2: क्षेत्र-वार ऋण माँग के लिए निवल प्रतिक्रिया – अगली तिमाही के लिए प्रत्याशाएँ

(प्रतिशत)

सर्वेक्षण दौर संख्या	सर्वेक्षण मूल्यांकन तिमाही	सभी क्षेत्र	कृषि	खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	विनिर्माण	इन्फ्रास्ट्रक्चर	सेवा	खुदरा/व्यक्तिगत ऋण
1	ति3:17-18	30.4	37.9	10.3	24.1	16.7	28.6	46.2
2	ति4:17-18	33.3	38.3	8.3	26.8	20.4	29.3	39.6
3	ति1:18-19	17.9	30.0	8.6	19.0	8.6	23.3	42.9
4	ति2:18-19	23.3	41.7	1.7	25.9	13.8	25.0	41.1
5	ति3:18-19	21.4	17.9	5.2	22.2	3.6	17.9	38.9
6	ति4:18-19	21.4	24.1	5.8	31.5	10.7	23.2	38.0
7	ति1:19-20	22.2	25.0	1.9	16.0	1.9	14.8	22.0
8	ति2:19-20	24.1	29.3	0.0	26.8	5.2	25.0	36.5
9	ति3:19-20	40.7	37.0	3.8	34.0	17.3	24.0	44.0
10	ति4:19-20	37.5	32.1	5.6	34.6	18.5	23.1	48.1
11	ति1:20-21	17.4	24.0	-4.2	12.5	8.7	15.2	30.0
12	ति2:20-21	38.6	35.4	19.6	32.6	19.6	30.4	38.1
13	ति3:20-21	32.6	39.6	18.8	39.6	22.9	28.3	30.0

विवरण 3: क्षेत्र-वार ऋण संबंधी निबंधन एवं शर्तों के लिए निवल प्रतिक्रिया – वर्तमान तिमाही के लिए मूल्यांकन

(प्रतिशत)

सर्वेक्षण दौर संख्या	सर्वेक्षण मूल्यांकन तिमाही	सभी क्षेत्र	कृषि	खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	विनिर्माण	इन्फ्रास्ट्रक्चर	सेवा	खुदरा/व्यक्तिगत ऋण
1	ति2:17-18	5.6	12.1	3.6	2.1	-1.9	4.0	13.0
2	ति3:17-18	7.1	10.0	-1.7	7.4	8.9	11.1	12.5
3	ति4:17-18	8.3	6.7	-8.9	6.7	0.0	0.0	24.1
4	ति1:18-19	0.0	6.7	-7.1	8.6	-11.7	8.6	12.5
5	ति2:18-19	-5.0	8.3	-6.9	5.0	-15.0	5.2	15.5
6	ति3:18-19	-5.6	5.6	-7.7	5.4	-14.3	3.6	16.7
7	ति4:18-19	13.5	11.5	5.6	9.3	-1.9	7.4	13.5
8	ति1:19-20	5.6	7.1	-1.9	1.8	-15.5	10.3	14.8
9	ति2:19-20	6.3	3.7	-5.8	-1.9	-9.3	7.7	14.0
10	ति3:19-20	5.8	7.1	1.9	1.9	-7.4	3.7	26.9
11	ति4:19-20	10.9	8.3	-2.0	10.9	-6.5	2.1	18.4
12	ति1:20-21	-2.2	6.5	-6.5	8.7	-4.5	-2.2	2.4
13	ति2:20-21	0.0	19.6	4.3	12.0	0.0	14.6	15.0

विवरण 4: क्षेत्र-वार ऋण संबंधी निबंधन एवं शर्तों के लिए निवल प्रतिक्रिया – अगली तिमाही के लिए प्रत्याशाएँ

(प्रतिशत)

सर्वेक्षण दौर संख्या	सर्वेक्षण मूल्यांकन तिमाही	सभी क्षेत्र	कृषि	खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	विनिर्माण	इन्फ्रास्ट्रक्चर	सेवा	खुदरा/व्यक्तिगत ऋण
1	ति3:17-18	7.7	12.5	5.6	6.8	2.0	8.0	15.2
2	ति4:17-18	8.9	16.7	1.7	13.0	10.7	14.8	18.8
3	ति1:18-19	1.7	6.7	-1.8	10.0	0.0	5.4	18.5
4	ति2:18-19	1.7	8.3	-5.4	6.9	-8.3	8.6	12.5
5	ति3:18-19	3.3	5.0	-3.4	5.0	-10.0	3.4	15.5
6	ति4:18-19	7.7	5.6	0.0	7.1	-12.5	10.7	18.5
7	ति1:19-20	15.4	7.7	3.7	11.1	0.0	5.6	11.5
8	ति2:19-20	9.3	3.6	0.0	10.7	-13.8	13.8	16.7
9	ति3:19-20	2.1	5.6	-1.9	0.0	-11.1	11.5	18.0
10	ति4:19-20	11.5	7.1	1.9	7.4	-7.4	3.7	21.2
11	ति1:20-21	8.7	8.3	-4.0	8.7	-10.9	0.0	10.5
12	ति2:20-21	15.2	19.6	13.0	19.6	9.1	8.7	4.8
13	ति3:20-21	17.4	19.6	17.4	20.0	10.9	18.8	17.5

संदर्भ

- Berg, Jesper., van Rixtel, Adrian A.R.J.M., Ferrando, Annalisa., de Bondt, Gabe and Scopel, Silvia., (2005), "The Bank Lending Survey for the Euro Area". ECB Occasional Paper No. 23, February 2005, <https://ssrn.com/abstract=752072>.
- Bank of England (2007), "Bank of England Credit Conditions Survey", Quarterly Bulletin, Q3.
- European Central Bank (2018), "User guide to the euro area bank lending survey", https://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/bls_user_guide_201811.en.pdf.
- Filardo, Andrew J. and Siklos, Pierre L., (2020), "The cross-border credit channel and lending standards surveys", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol.67.
- Köhler-Ulbrich, Petra., Hempell, Hannah S., Scopel, Silvia., (2016), "The euro area bank lending survey: Role, development and use in monetary policy preparation", European Central Bank Occasional Paper Series, No.179, September.
- Faruqui, Umar, Paul Gilbert, and Wendy Kei., (2008), "Bank of Canada's Senior Loan Officer Survey", Bank of Canada Review, Autumn, <https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/faruqui.pdf>.
- Bank of Japan, "Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices at Large Japanese Banks", <https://www.boj.or.jp/en/statistics/dl/loan/loos/index.htm>.
- Board of Governors of the Federal Reserve System, "Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices", <https://www.federalreserve.gov/data/sloos/about.htm>.
- Reserve Bank of India, Database on Indian Economy, <https://dbie.rbi.org.in>.
- Reserve Bank of India (2009), "Report of the Working Group on Surveys", Reserve Bank of India Bulletin, September.
- Cunningham, Thomas J., (2006), "The Predictive Power of the Senior Loan Officer Survey: Do Lending Officers Know Anything Special?", Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper, November.

भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर मौसमी परिवर्तन का प्रभाव*

यह लेख 80 चुनिंदा आर्थिक/वित्तीय समय श्रृंखलाओं के मौसमी कारकों को प्रस्तुत करता है जिसमें मुद्रा, बैंकिंग, कीमत सांख्यिकी, उत्पादन डेटा, सेवा क्षेत्र संकेतक, पण्य व्यापार और भुगतान के वैकल्पिक प्रकार शामिल हैं। यह लेख पाता है कि उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले अधिकांश कारक मार्च के आस-पास मौसमी चरम पर होते हैं और कीमत पर प्रभाव डालने वाले कारक इसी समय के आस-पास मौसमी गर्त पर होते हैं। पिछली दशक की तुलना में खाद्य उत्पादों और प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ाव में वृद्धि हुई है। जहां तक भुगतान विधियों का संबंध है, थोक लेनदेन से जुड़े लिखत मार्च के दौरान चरम पर होते हैं, जबकि खुदरा भुगतान के मामले में मौसमी चरम त्योहारों के दौरान पाए जाते हैं।

भूमिका

आर्थिक श्रृंखलाओं में साप्ताहिक, मासिक या तिमाही आधार पर बार-बार होने वाले मौसमी उतार-चढ़ाव एक प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं एवं इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसमी परिवर्तन प्रभाव डालने वाले आर्थिक कारक की सही अंतर्निहित विशेषताओं और उसकी डेटा जनरेट करने की प्रक्रिया के साथ-साथ प्रभाव डालने वाले कारकों के बीच के आपसी संबंधों को अस्पष्ट करता है। उसी समय, मौसमी उतार-चढ़ाव को सही ढंग से समझने से प्रवृत्ति में बदलावों का सटीक पूर्वानुमान करने में आसानी होती है। इस संदर्भ में, मॉडलिंग और पूर्वानुमान के प्रयोजन से सूचना का उचित रूप से उपयोग करने के लिए आर्थिक वेरीअबल के मौसमी कारकों का अभिनिर्धारण और पृथक्करण पहला कदम है।

समय श्रृंखला डेटा का प्रतिरूप तैयार करते समय मौसमी परिवर्तन का माप और मौसमी समायोजन करना सर्वोत्तम प्रथा के रूप में स्थापित हुआ है। बहु देशी अनुभव बताता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मौसमी परिवर्तन के लिए समायोजन करने के बाद

* यह लेख मॉडलिंग और पूर्वानुमान प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के श्रीजयश्री सरदार, कश्यप गुप्ता और जुगनू अंसारी द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

तिमाही-दर-तिमाही वार्षिकीकृत परिवर्तन दरों के संदर्भ में जीडीपी वृद्धि का माप करता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मुद्रास्फीति रिपोर्ट सामान्यतः मौसमी तौर पर समायोजित डेटा का उपयोग करती है। बैंक ऑफ कनाडा की तिमाही वित्तीय रिपोर्ट बैंक नोटों की मौसमी मांग के आकलन का प्रकाशन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2016) ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक सांख्यिकी में सदस्य देशों को सूचित किया कि वे उनके 'मुद्रा की कुल राशियों के लिए मानकीकृत रिपोर्ट फॉर्म' में मौसमी तौर पर समायोजित व्यापक मुद्रा डेटा रिपोर्ट करें।

रिजर्व बैंक 1980 की दशक से महत्वपूर्ण समष्टि-आर्थिक वेरीअबल के लिए मासिक मौसमी कारकों का प्रकाशन करता आ रहा है। यह लेख 2019-20 तक के मौसमी कारकों की गणना और अद्यतन करने के जरिए इस प्रयास को आगे जारी रखता है। शेष लेख इस प्रकार प्रस्तुत है। खंड II में कार्य-प्रणाली की उत्पत्ति और मौसमी कारकों के वैश्विक उपयोग से जुड़े साहित्य की समीक्षा की गई है। खंड III में अध्ययन के लिए चुने गए आर्थिक वेरीअबल और मौसमी कारकों तक पहुंचने के लिए तकनीक के विकल्प की व्याख्या की गई है। खंड IV 2017-18 तक के डेटा के आलोक में औसत मासिक मौसमी कारकों पर आधारित समष्टि-आर्थिक वेरीअबल के विभिन्न समूहों के लिए मौसमी परिवर्तन के स्वरूप को पेश करता है। खंड V में मौसमी परिवर्तन के स्वरूप में अस्थायी बदलावों और मौसमी उतार-चढ़ाव के अनुभवजन्य मूल्यांकन के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। खंड VI में कतिपय नीतिगत नज़रिया पेश किया गया है।

II. अध्ययन की समीक्षा

अध्ययन में, समय श्रृंखलाओं के मामले में यह माना जाता है कि उसकी रचना आर्थोगोनल घटकों, जैसे, रुझान, मौसमी परिवर्तन, चक्रीय और अनियमित घटकों से होती हैं। ऐडिटिव मॉडल में, समय श्रृंखलाओं को ऊपर बताए गए चार घटकों के जोड़ के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि मल्टिप्लिकेटिव मॉडल में समय श्रृंखला घटकों की उपज है। मौसमी परिवर्तन रुझान और चक्रीय के अलावा समय श्रृंखलाओं की वार्षिक या मासिक पूर्वानुमान योग्य विभिन्नता है। मौसमी परिवर्तन समष्टि-आर्थिक कारकों के अल्प-कालिक विश्लेषण में प्रमुख भूमिका अदा करता है और प्रभावशाली निर्णय लेने में सहायक होता है।

यह अध्ययन मौसमी परिवर्तन की व्यावहारिक प्रवृत्ति को हिसाब में लेते हुए आर्थिक समय श्रृंखलाओं के संगत अल्प व दीर्घ-कालिक संचलनों को उजागर करता है (मन्ना, एवं अन्य, 2003; एचसीएसओ, 2017)। यह पाया गया है कि मौसमी कारकों के प्राक्कलन आर्थिक वेरीअबल्स के रुझान-आधारित पूर्वानुमानों को बेहतर करता है (लेम्बके, 2015)। मौसमी समायोजन को आर्थिक वेरीअबल्स, विशेष रूप से मूल मुद्रास्फीति में अनवरत घटक प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्मूदिंग और फिल्टरिंग तकनीकों के साथ नियोजित किया गया है (सामंता, एवं अन्य, 2000)। मौसमी परिवर्तन प्राप्त करने के लिए गैर-पैरामेट्रीक सिंग्युलर स्पेक्ट्रम विश्लेषण के उपयोग की चर्चा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) सिग्नल एक्सट्रैक्शन (चेन, एवं अन्य, 2013) और अन्य संबंधित क्षेत्रों के संदर्भ में की गई है।

मौसमी कारकों के अनुमान के संबंध में साहित्य का एक लंबा इतिहास है, जिसकी शुरुआत चल औसत की तुलना में अनुपात पद्धति (मैकाले, 1931) से हुई है, जिसे अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा 1954-55 में जनगणना विधियों के रूप में और अधिक परिष्कृत किया गया था। मौसमी और रुझान/चक्र घटकों की स्पष्ट कार्यात्मक विशिष्टता पर गहन शोध की बदौलत मौसमी समायोजन विधियों के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं। X-11 विधि (यूएस सेंसस ब्यूरो, 1965) ने कार्यात्मक लचीलापन प्रदान किया जैसे कि गुणक के साथ-साथ घटकों के योगात्मक प्रतिनिधित्व, अधिकतम मान के लिए उपचार और मौसमी परिवर्तन के लिए विभिन्न परीक्षण (शिसकिन, एवं अन्य, 1967)। X-11 विधि, जो चल औसत या लिनीअर स्मूदिंग फिल्टर पर आधारित है, की हालांकि एक बड़ी मजबूरी है कि उसमें हाल के वर्ष के अनुमानों की विश्वसनीयता की कमी थी जो सेन्ट्रल ऑब्जर्वेशन के मुकाबले एंड पाइंट्स के लिए समान भार देने में असमर्थता के कारण है। इस वजह से एकदम हाल के ऑब्जर्वेशन के अनुमानों में बार-बार संशोधन किया गया क्योंकि अधिक डेटा पाइंट जुड़ते जाते हैं (डागम, 1980)।

सांख्यिकी कनाडा की X-11-एआरआईएमए पद्धति ने श्रृंखला के दोनों सिरों पर एक वर्ष के लिए मूल समय श्रृंखला डेटा को एक्सट्रापोलेट करने के लिए X-11 विधि में एक ऑटोरिग्रसिव इंटीग्रेटेड मूविंग ऑवरेज (एआरआईएमए) मॉडल को शामिल किया। इससे 'एंड पाइंट्स' की समस्या से निपटने में मदद मिली

और जब मौसमी परिवर्तन यादृच्छिक तरीके से तेजी से बढ़ रहा होता है तो ऐसे परिदृश्य में मौसमी कारकों के लिए मजबूत अनुमान प्राप्त करने में मदद मिली। यूएस सेंसस ब्यूरो ने X-12-एआरआईएमए को X-11 के एक वर्धित वर्शन के रूप में विकसित किया है और रेगएआरआईएमए नाम से एक विशेषता जोड़ी है, जिसमें अंतर्निहित या प्रयोक्ता-परिभाषित रिग्रेसर का विकल्प है जो स्टॉक क्रय-विक्रय दिवस और अवकाश के असर के साथ-साथ श्रृंखलाओं में व्यवधान जैसे स्तरों में यकायक बदलाव का अनुमान लगाने में सहयोग करता है (यूएस सेंसस ब्यूरो, 2011)।

यूएस सेंसस ब्यूरो का नवीनतम X-13 एआरआईएमए-एसईएटीएस (एआरआईएमए टाइम सीरीज में सिग्नल एक्सट्रैक्शन) X-11 रूप का वर्धित वर्शन है जिसमें दो अतिरिक्त विकल्प हैं, जैसे, स्वतः मॉडल चयन के लिए टीआरएएमओ (टाइम सीरीज रिगेशन विद एआरआईएमए नॉइज़, मिसिसिंग वैल्यूज़ एंड आउटलाइअर्स) और मौसमी समायोजन प्रक्रिया संपादित करने के लिए एआरआईएमए टाइम सीरीज में सीज़नल एक्सट्रैक्शन (एसईएटीएस) (गोमेज़, एवं अन्य, 1996; 2001ए; 2001बी; यूएस सेंसस ब्यूरो, 2011)।

III. डेटा और कार्य-प्रणाली

सर्वोत्तम देशीय प्रथाओं के अनुरूप एवं रिज़र्व बैंक में अतीत में निर्धारित मानकों की मर्यादा को बनाए रखते हुए, यहां समष्टिआर्थिक संकेतकों में मुद्रा, बैंकिंग, कीमत सांख्यिकी, उत्पादन संबंधी डेटा, सेवा क्षेत्र संकेतकों और पण्य व्यापार को शामिल किया गया है। भारत में भुगतान के वैकल्पिक प्रकारों, जैसे, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), पेपर समाशोधन, खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (आरईसी) एवं कार्ड भुगतान की तीव्र वृद्धि को जानते हुए उनके मौसमी परिवर्तन का विश्लेषण भी किया गया है।

खास तौर पर, क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग किए गए 80 मासिक समष्टिआर्थिक वेरीअबल्स में 14 मौद्रिक एवं बैंकिंग संकेतक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से संबंधित 21 श्रेणियां, थोकमूल्य से संबंधित नौ, औद्योगिक उत्पादन के 23, सेवा क्षेत्र संकेतकों के छः, पण्य व्यापार पर तीन और वैकल्पिक भुगतान संकेतकों पर चार श्रृंखलाएं शामिल हैं। मौसमी कारकों को अधिकांशतः समय श्रृंखलाओं से प्राप्त किया जाता है जो काफी पहले अर्थात् अप्रैल 1994 से होता रहा है (अनुबंध सारणी 1)।

यूएस सेन्सस ब्यूरो के X13-ARIMA-SEATS सॉफ्टवेयर को भारतीय स्थितियों, अर्थात् दिवाली और भारतीय व्यापार दिवस के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए, के अनुरूप व्यवस्थित करने के बाद उसका इस्तेमाल करके मौसमी कारकों का गुणक मॉडल के तहत अनुमान लगाया गया है।

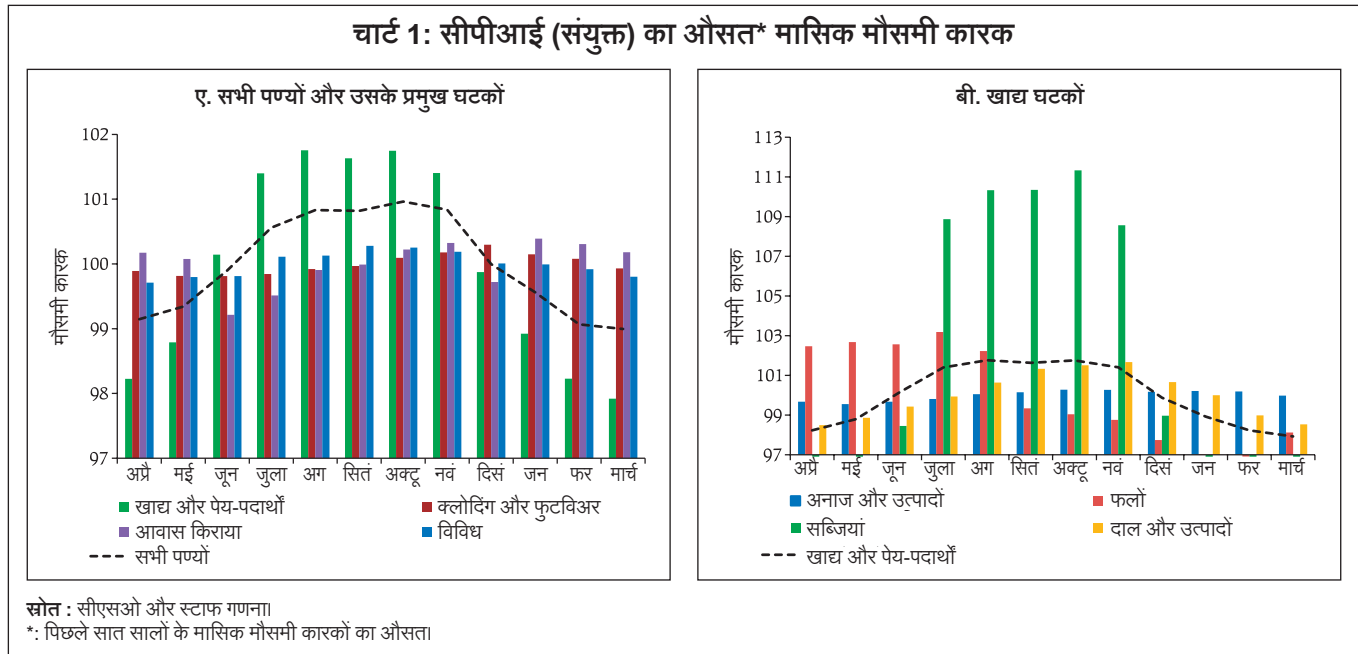
मौसमी समायोजन दो तरीकों से किए जा सकते हैं; i) प्रत्यक्ष दृष्टिकोण – मौसमी समायोजन प्रक्रिया का कुल श्रृंखलाओं पर प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करना; और ii) परोक्ष दृष्टिकोण – पहले संयुक्त श्रृंखलाओं के प्रत्येक घटकों को मौसमी तौर पर समायोजित करना और फिर मौसमी समायोजित मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन घटकों को जोड़ना (मन्ना एवं अन्य, 2003)। इस लेख में प्रत्यक्ष दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

IV. परिणामों का विश्लेषण

यहां सोचे गए सभी समष्टिआर्थिक वेरीअबल्लज विभिन्न मौसमी परिवर्तन दर्शाते हैं (अनुबंध सारणी 2 एवं 3)।¹ 14 प्रमुख मौद्रिक एवं बैंकिंग संकेतकों में से 11 संकेतक मार्च या अप्रैल (लगभग वित्त वर्ष के अंत में) के दौरान मौसमी चरम पर थे, जबकि अधिकांश इन सीरीज़ में मौसमी गर्त या तो अगस्त अथवा दिसंबर

में पाए गए थे। उदाहरण के लिए, बैंक ऋण मार्च में मौसमी चरम पर थे, जबकि इसी माह में बैंकों के निवेश मौसमी गर्त पर थे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की मांग जमाओं में सर्वाधिक मौसमी उतार-चढ़ाव देखने को मिला (औसत मौसमी कारक (एसएफ़) रेंज² 9.3 पर) जिसके बाद आरक्षित मुद्रा (औसत एसएफ़ रेंज 6.0 पर) और नकदी शेष एवं आरबीआई (एससीबी) के पास जमा शेष (औसत एसएफ़ रेंज 5.8 पर) का स्थान आता है। दूसरी तरफ़, एससीबी की मीयादी जमाओं में सबसे कम मौसमी उतार-चढ़ाव देखने को मिला (औसत एसएफ़ रेंज 1.3 पर) जो दर्शाता है कि बैंक जमाएं स्थायी आय एवं निम्न जोखिम के लिए बचत का एक पसंदीदा रास्ता है (अनुबंध सारणी 4)।

कीमतों की बात करें तो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) हेडलाइन में जुलाई और नवंबर के बीच मौसमी उतार-चढ़ाव अधिक होने का अनुभव होता है, जो मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों की वजह से है। सीपीआई-खाद्य सब्जियों की कीमतों के मौसमी स्वरूप द्वारा संचालित होता है। फलों की कीमतें गर्मियों (अप्रैल-अगस्त) के दौरान चरम पर होती हैं और सब्जियां बरसात (जुलाई-नवंबर) के आसपास, जो कम उपलब्धता और सतत मांग की वजह से है (चार्ट 1)।



¹ यदि दस से कम वर्षों के लिए आंकड़े उपलब्ध होते हैं, तो इसी अवधि का औसत लिया जाता है।

² रेंज, जो डिस्पर्शन का माप होता है, की गणना अधिकतम और न्यूनतम मासिक मौसमी कारकों के बीच के अंतर के रूप में जाती है। रेंज का उच्च मान वेरीअबल में उच्च मौसमी परिवर्तन दर्शाता है जिसके चलते वर्ष की किसी निश्चित अवधि में गतिविधियां/कीमतें अधिकाधिक होती हैं। औसत मौसमी कारक रेंज पिछले दस सालों के औसत मौसमी कारकों का रेंज होता है।

सीपीआई-सब्जियों ने सर्वाधिक मौसमी उतार-चढ़ाव दर्शाया (नौ-वर्षीय औसत एसएफ रेंज 23.0 पर)। सब्जियों में, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों का औसत एसएफ रेंज क्रमशः 65.6, 40.4 और 35.6 दर्ज किया गया। फलों में सब्जियों की अपेक्षा कम मौसमी उतार-चढ़ाव (6.3 का औसत एसएफ रेंज) पाया गया। इसके अलावा, अनाज और उत्पादों (औसत एसएफ रेंज 0.7 पर) की कीमतों में दाल और उत्पादों (औसत एसएफ रेंज 3.2 पर) की अपेक्षा कम मौसमी उतार-चढ़ाव पाया गया, जहां आपूर्ति और मांग के बीच बेमेलपन लगातार देखने को मिला, जो संभवतः उत्पादन संबंधी अनिश्चितता एवं आर्थिक विकास से संबद्ध खान-पान में बदलाव की वजह से था। दूसरी तरफ, सीपीआई - गैर-मादक पेय ने सबसे कम मौसमी उतार-चढ़ाव दर्शाया (औसत एसएफ रेंज 0.3 पर), जिसका कारण उपभोक्ताओं के बीच स्वस्थ जीवन शैली एवं सेहत को लेकर बढ़ती जागरूकता है। कुल सीपीआई सीरीज़ [सीपीआई-संयुक्त, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आईडब्ल्यू), कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आरएल)] में मौसमी उतार-चढ़ाव कम है जबकि कुछ एक घटकों में अधिक है, मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं में (अनुबंध सारणी 4)।

डब्ल्यूपीआई सीरीज़ में मौसमी गर्त मौसमी चरम के विस्तार के सापेक्ष केवल दो महीनों (मार्च और दिसंबर) में ही संकेद्रित थे। डब्ल्यूपीआई-सभी पण्यों में मौसमी उतार-चढ़ाव प्रधान रूप से प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों द्वारा संचालित थे, विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं, जिसका मौसमी स्वरूप सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों की तरह ही है। ईंधन और बिजली की कीमतों में सर्वाधिक मौसमी उतार-चढ़ाव (औसत एसएफ रेंज 19.4 पर) दर्ज किया गया और विनिर्मित उत्पाद समूह के बीच खाद्य उत्पादों के विनिर्माण में सबसे कम मौसमी उतार-चढ़ाव (औसत एसएफ रेंज 2.2 पर) पाया गया (अनुबंध सारणी 4)।

जहां तक पैदावार में मौसमी उतार-चढ़ाव का संबंध है, औद्योगिक उत्पादन अधिकाधिक मौसम अनुकूल होता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ने 13.0 का औसत एसएफ रेंज दर्शाया है। प्रमुख क्षेत्रों के बीच, खनन में सर्वाधिक मौसमी उतार-चढ़ाव (औसत एसएफ रेंज 30.8 पर) पाया गया; उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं में

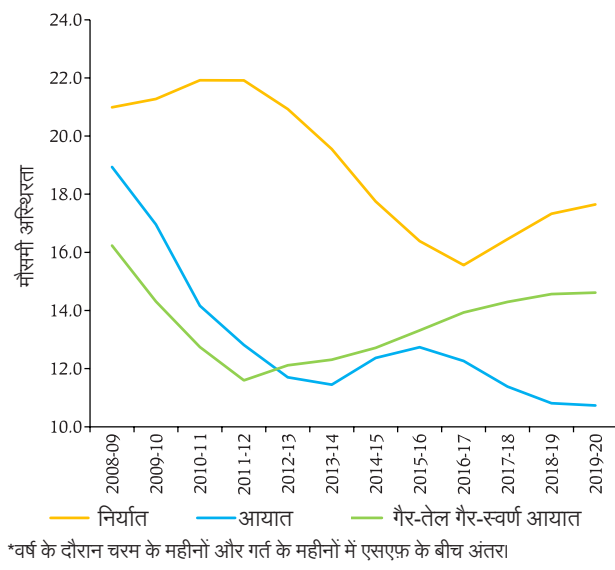
सर्वाधिक मौसमी उतार-चढ़ाव (औसत एसएफ रेंज 35.1 पर) पाया गया। आईआईपी सीरीज़ में मौसमी चरम अधिकांशतः मार्च में पाया गया, जो वित्त वर्ष का आखिरी महीना है, जो वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की वजह से हो सकता है; दूसरी तरफ, मौसमी गर्त तितर-बितर थे। सीमेंट उत्पादन में जुलाई से नवंबर के मौसम में थोड़ी कमी आई, जो भारत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून का मौसम होता है। उर्वरक उत्पादन में फरवरी से जून के मौसम में गिरावट दर्ज की गई, जो रबी फसलों की कटाई का समय होता है और कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिहाज से मंदी का मौसम है।

छः में से चार सेवा क्षेत्र संकेतकों ने मार्च में मौसमी चरम दर्ज किया। केवल घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय यातायात के मामले में, मौसमी चरम क्रमशः मई और जनवरी से मेल खाता है, जो छुट्टी का मौसम है।

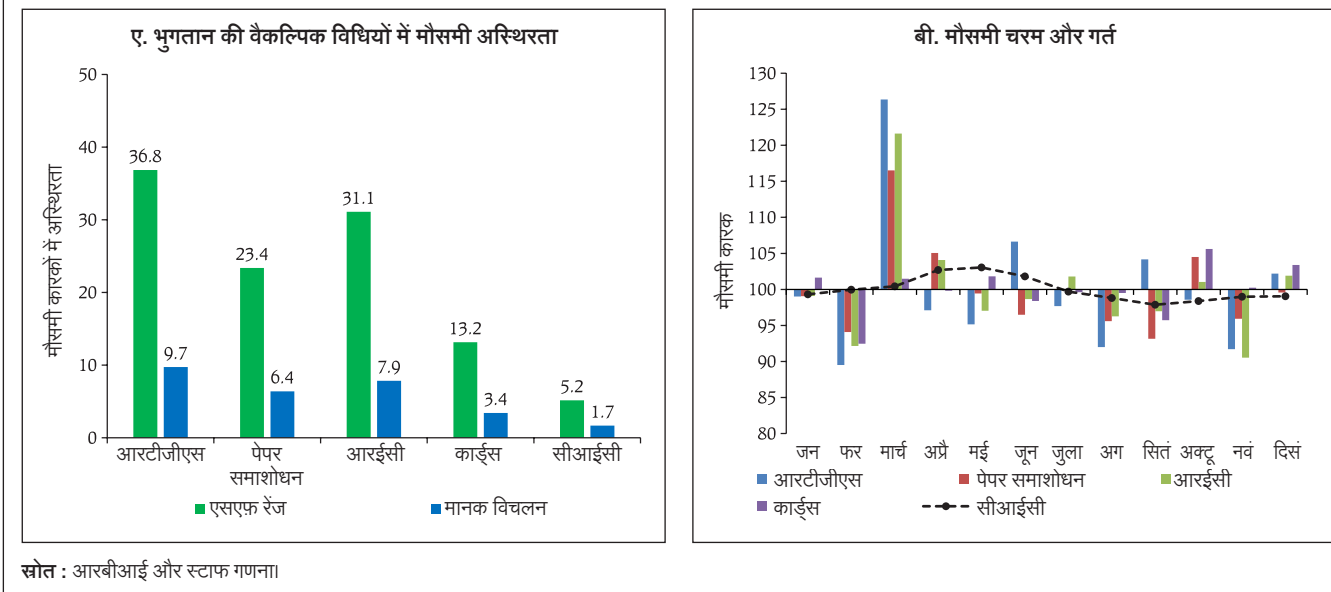
पण्य निर्यातों के मामले में मौसमी चरम मार्च में अपरिवर्तित रहा, जो औद्योगिक उत्पादन में मौसमी चरम से मेल खाता है जबकि गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात भी दिसंबर में अपरिवर्तित रहा, लेकिन आयात में मौसमी चरम पूर्ववर्ती मार्च के बदले अक्टूबर में पाया गया (चार्ट 2 एवं अनुबंध सारणी 2)।

भुगतान की वैकल्पिक विधियों का विश्लेषण दर्शाता है कि आरटीजीएस, पेपर समाशोधन और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक

चार्ट 2: पण्य वस्तुओं के व्यापार में मौसमी अस्थिरता*



चार्ट 3: भुगतान की वैकल्पिक विधियों और संचलनगत मुद्रा में मौसमी अस्थिरता

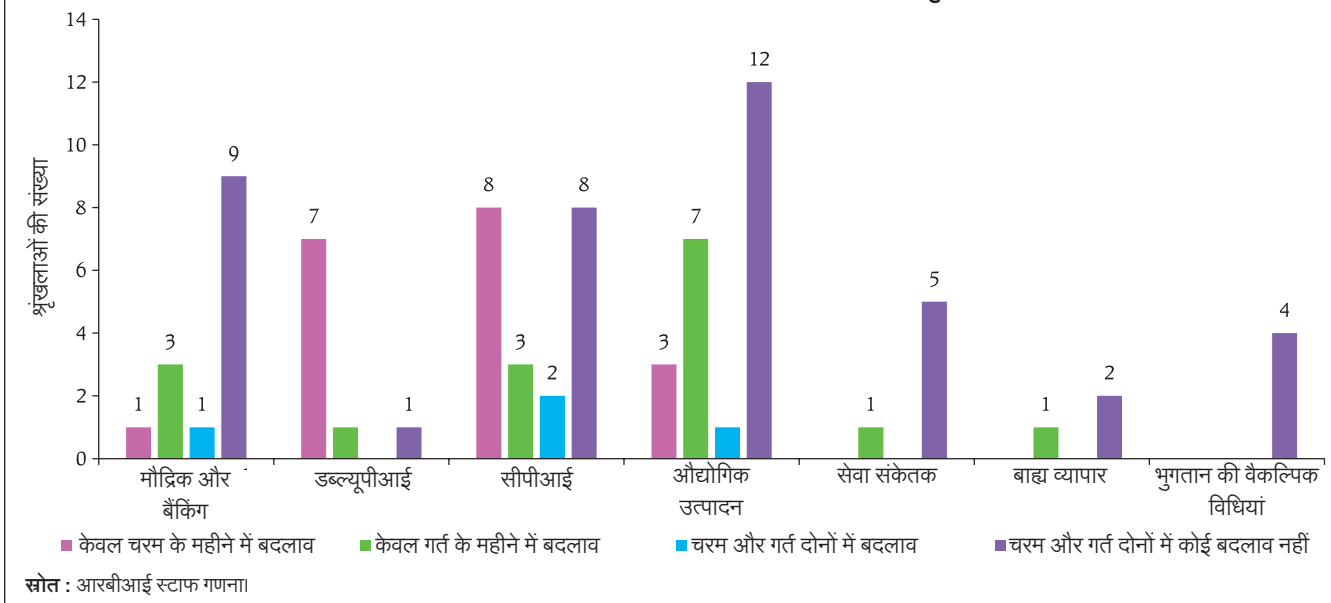


समाशोधन ने अधिक मौसमी उतार-चढ़ाव दर्ज किया और वे मार्च में चरम पर थे, जो दर्शाता है कि वार्षिक वित्त वर्ष की समाप्ति में ऑनलाइन लेनदेन का अधिकाधिक उपयोग किया गया है, जबकि कार्ड भुगतान विधि के उपयोग में मौसमी चरम त्योहार के मौसम अक्टूबर के आसपास खपत-मांग के दौरान पाया गया। दूसरी तरफ, यह पाया गया कि मौसमी गर्त फरवरी, सितंबर और नवंबर में फैले हुए थे (चार्ट 3 और अनुबंध सारणी 2)।

V. क्या मौसमी उतार-चढ़ाव में बदलाव आया है ?

मौसमी उतार-चढ़ाव के स्वरूप में बदलाव को पहचानने का एक सरल तरीका होगा कि 2019-20 के नतीजों के साथ पिछले पांच सालों (2014-15 से 2018-19) के औसत मौसमी कारकों की तुलना की जाए। चुने गए 80 श्रृंखलाओं में से 41 श्रृंखलाओं के संबंध में चरम और गर्त अपरिवर्तित रहे जबकि चार श्रृंखलाओं के मामलों में चरम और गर्त दोनों में बदलाव दर्ज किए गए (चार्ट 4

चार्ट 4: बदलते मौसमी चरम और गर्त के महीनों के दृष्टांत



और अनुबंध सारणी 5)। मौसमी उतार-चढ़ाव में यह बदलाव मुख्यतः सीपीआई के मामले में गौर किया गया। सीपीआई-सभी पण्यों में मौसमी चरम पूर्ववर्ती अक्टूबर से आगे बढ़कर 2019-20 में नवंबर में पाया गया, जो मुख्यतः सब्जियों की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में मौसमी चरम भी पूर्ववर्ती अगस्त से आगे बढ़कर नवंबर में पाया गया, जो थोकमूल्य बाजार में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में मौसमी चरम के अनुरूप था। इसके अलावा, 2019-20 में औद्योगिक उत्पादन के घटकों के मौसमी चरम में काफी नज़दीकियां पाई गईं।

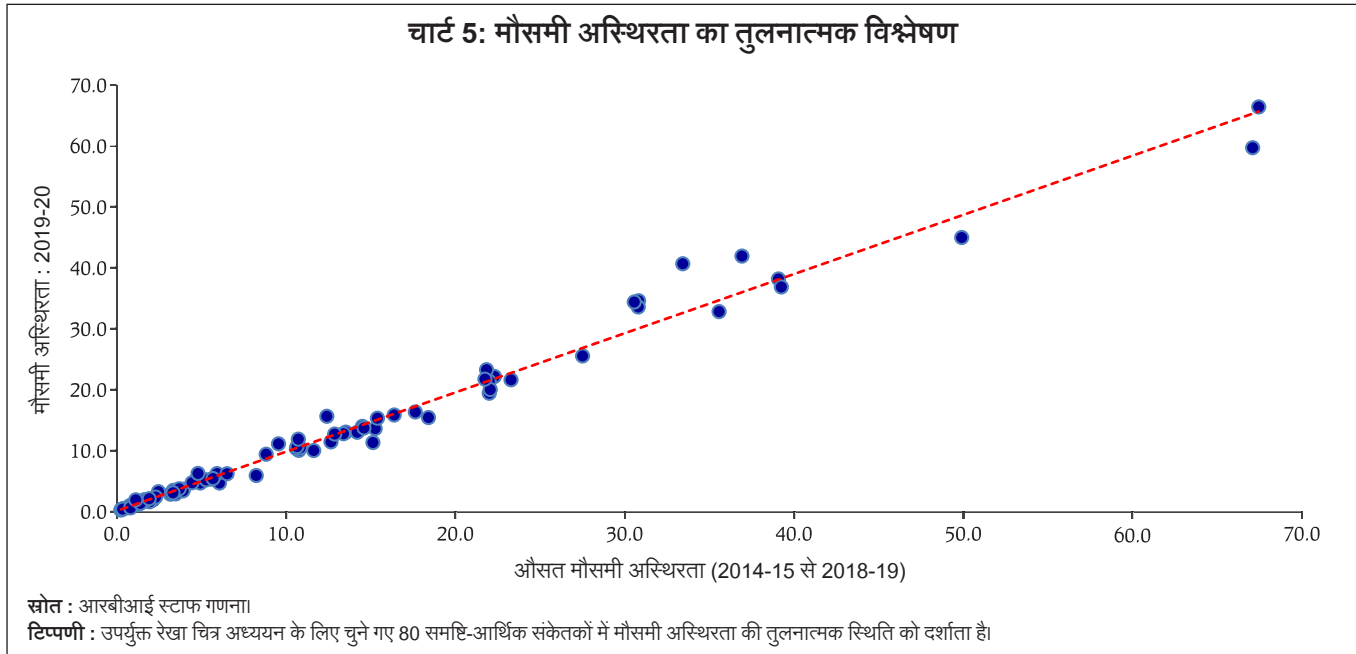
समय के साथ मौसमी कारकों में 'गतिमान मौसमी उतार-चढ़ाव'— बदलाव की छान-बीन करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन प्रवृत्ति की मौजूदगी का पता लगाना महत्वपूर्ण है। मौसमी उतार-चढ़ाव में गिरावट (वृद्धि) की प्रवृत्ति दर्शाती है कि समय के साथ मौसमी उतार-चढ़ाव में कमी (बढ़ी) आई है।

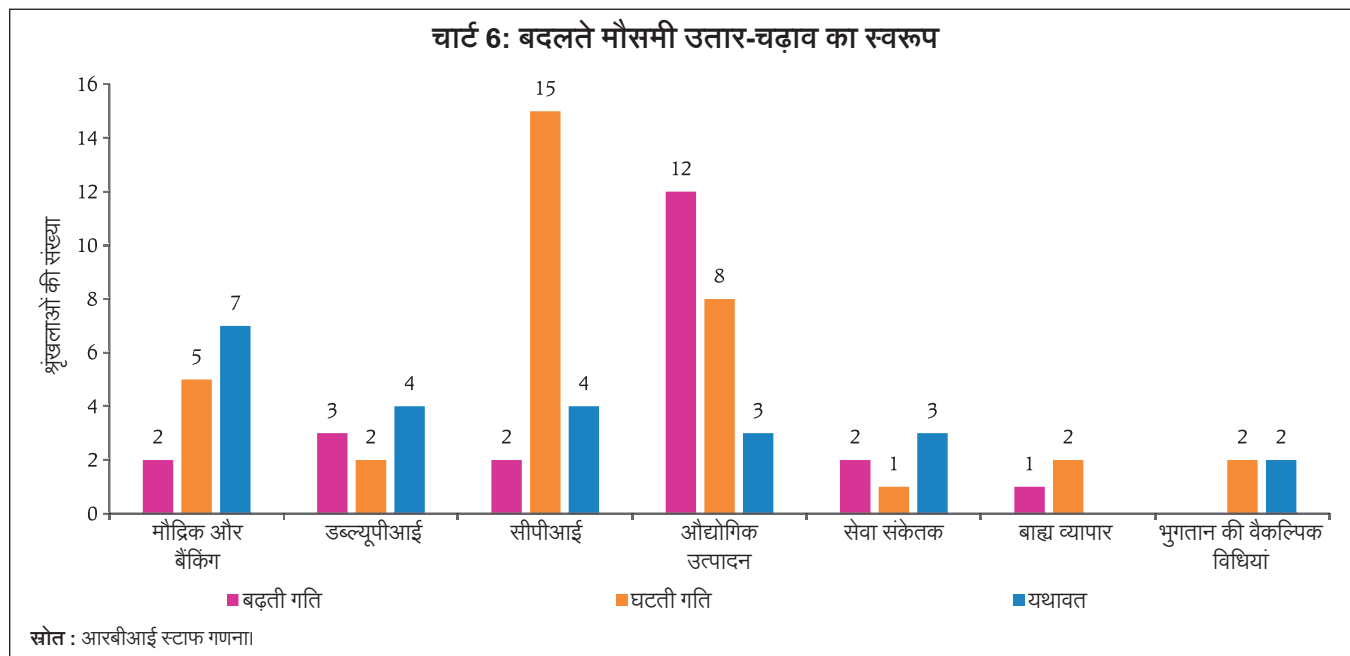
जहां अधिकांश मामलों में, मौसमी अस्थिरता/उतार-चढ़ाव (अधिकतम और न्यूनतम मासिक मौसमी कारकों के बीच का अंतर) 2019-20 में पिछले पांच वर्षों के औसत के सदृश रही

(चार्ट 5), वहीं अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि 35 श्रृंखलाओं के मामलों में मौसमी उतार-चढ़ाव पिछले 10 वर्षों की लंबी समयावधि में कम हुए हैं (अनुबंध सारणी 6)। दूसरी तरफ, मौसमी उतार-चढ़ाव दूसरे 22 सीरीज़ में अधिक प्रकट था।

पिछले 10 सालों में मौद्रिक और बैंकिंग एग्रीगेट्स में मौसमी उतार-चढ़ाव या तो कम हुआ या मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा, जो यकीनन बैंकिंग सेवाओं की बेहतर उपलब्धता को दर्शाता है। यद्यपि सामान्य आईआईपी में मौसमी उतार-चढ़ाव अपरिवर्तित रहा, लेकिन खनन, विनिर्माण एवं विद्युत में मौसमी अस्थिरता में वृद्धि दर्ज की गई। मानसून सीज़न के दौरान खनन गतिविधि, विशेष रूप से कोयला, बारिश और कमजोर रेल यातायात की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसलिए, यह माना जाता है कि कोयला एवं अन्य खनीजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सक्रिय सीज़न के दौरान उच्च उत्पादन होने की वजह से समय के साथ मौसमी उतार-चढ़ाव में वृद्धि हुई है। अधिकांश सीपीआई-संयुक्त तत्वों के मामले में मौसमी अस्थिरता में कमी आई है; टमाटर, मांस और मछली की खुदरा कीमतों में मौसमी परिवर्तन अधिक पाया गया जबकि आलू एवं प्याज की कीमतों में मौसमी परिवर्तन कम पाया गया। थोकमूल्य बाजार में, डब्ल्यूपीआई-सभी

चार्ट 5: मौसमी अस्थिरता का तुलनात्मक विश्लेषण





पण्यों में मुख्य रूप से रसायनों और रसायन के उत्पादों की कीमतों की वजह से अधिक मौसमी अस्थिरता पाई गई (चार्ट 6)।

VI. निष्कर्ष

अर्थव्यवस्था का सटीक अध्ययन करने और नीति संबंधी निर्णय लेने में मौसमी समायोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पाया गया है कि वित्त वर्ष की समाप्ति के आस-पास और कृषिजन्य सीजन की शुरुआत में संचलनगत मुद्रा की अत्यधिक मौसमी मांग देश में कारगर मुद्रा प्रबंधन के संबंध में संकेत देता है, इसी तरह, बैंकों की जमाओं के मौसमी स्वरूप की जानकारी का उपयोग कर बैंकों के संसाधनों को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है।

सब्जियों की कीमतों की वजह से, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति ने मानसून सीजन के दौरान कीमत संबंधी दबाव दर्शाया। सामान्य खुदरा कीमतों में मौसमी चरम 2019-20 में अक्टूबर से आगे बढ़कर नवंबर में पाया गया, जो थोकमूल्य बाजार के अनुरूप है। यह ऐसी अवधियों के दौरान कारगर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की मांग करता है।

अधिकांश औद्योगिक उत्पादन श्रेणियां मार्च में चरम पर होती हैं जबकि उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन दिसंबर में चरम पर होता है। कपड़ों के विनिर्माण में मौसमी चरम

पूर्ववर्ती अगस्त से आगे बढ़कर दिसंबर में पाया जाने लगा जो देश में सर्दी का सीजन होता है। आयात और निर्यात मार्च के दौरान चरम पर थे। इसके अलावा, बैंक ऋण मार्च में चरम पर होते हैं, जो स्पष्ट तौर पर वर्ष के अंत में लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी दबाव की वजह से है। बैंक और ऋण संस्थाओं द्वारा, त्योहारों के आस-पास पैदा होने वाली मांग को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित तरीके से ऋण उपलब्ध कराने से लाभप्रद क्रियाकलापों को प्रोत्साहन मिलेगा।

संदर्भ :

Bank of Canada, (2018). Quarterly Financial Report. June 30, Bank of Canada.

Bank of England, (2019). Inflation Report. February, Bank of England.

Dagum, E. B., (1980). The X-11-ARIMA Seasonal Adjustment Method. Statistics Canada.

Deutsche Bundesbank, (2018). Monthly Report. Vol. 70, No.9, Deutsche Bundesbank, September.

Gomez, V. and Maravall, A., (1996). Programs TRAMO and SEATS: Instructions for the User. Bank of Spain.

- Gomez, V. and Maravall, A., (2001a). Automatic modeling methods for univariate series. In D. Pena, G. C. Tiao, and R. S. Tsay (Eds.), *A Course in Time Series Analysis*. New York, NY: J. Wiley and Sons.
- Gomez, V. and Maravall, A., (2001b). Seasonal adjustment and signal extraction in economic time series. In D. Pena, G. C. Tiao, and R. S. Tsay (Eds.), *A Course in Time Series Analysis*. New York, NY: J. Wiley and Sons.
- HCSO (2007). *Seasonal Adjustments – Methods and Practices*. Budapest, July, Hungarian Central Statistics Office.
- IMF, (2016). *Monetary and Financial Statistics Manual and Compilation Guide*. International Monetary Fund.
- Lembke, Ron (2015). *Forecasting with Seasonality*. Retrieved from <http://business.unr.edu/faculty/ronlembke/handouts/Seasonality%20Final17.pdf>.
- Macaulay, F. R. (1931). *The Smoothing of Time Series*. National Bureau of Economic Research, Inc.
- Manna, M., Peronaci, R., (2003). *Seasonal Adjustment*. European Central Bank.
- Reserve Bank of India (2017). *Monthly Seasonal Factors of Selected Economic Time Series. 2016-17*, Reserve Bank of India Bulletin, September, Vol. LXXI, No. 9.
- Samanta, G.P. and Bhattarjee, M., (2000). Are Seasonal Adjustment and HP-Filter Useful in Estimating Core Inflation in India? *International Journal of Development Banking*, Vol. 18, No. 2, July, pp. 61-75.
- Shiskin, J., Young, A.H. and Musgrave, J.C., (1967). *The X-11 Variant of Census Method II Seasonal Adjustment Programme*. Technical Paper No. 15, Bureau of the Census, U.S. Department of Commerce.
- US Census Bureau (1965). *Estimating Trading-Day Seasonal Variation in Monthly Economic Time Series*. US Bureau of the Census Technical Paper No. 12.
- U.S. Census Bureau (2011). *X-12-ARIMA Reference Manual, Version 0.3*. Time Series Research Staff, Statistical Research Division (<https://www.census.gov/ts/x12a/v03/x12adocV03.pdf>).
- U.S. Census Bureau (2017). *X-13-ARIMA-SEATS Reference Manual, Version 1.1*. *Time Series Research Staff, Center for Statistical Research and Methodology* (<https://www.census.gov/ts/x13as/docX13AS.pdf>).

अनुबंध

सारणी 1: मौसमी कारकों का अनुमान करने हेतु उपयोग की गई समयवधि

क्षेत्रों/वेरीअबल्स के नाम	समयवधि	क्षेत्रों/वेरीअबल्स के नाम	समयवधि		
मौद्रिक और बैंकिंग संकेतक (14 श्रृंखलाएं)		औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (23 श्रृंखलाएं)			
ए.1.1 व्यापक मुद्रा (एम3)	अप्रैल 1994 से मार्च 2020	ई. आईआईपी (आधार 2011-12=100) सामान्य सूचकांक	अप्रैल 1994 से मार्च 2020		
ए.1.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण		अप्रैल 2012 से मार्च 2020	ई.1.1 आईआईपी – प्राथमिक वस्तुएं	अप्रैल 2012 से मार्च 2020	
ए.1.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण			ई.1.2 आईआईपी – पूंजी वस्तुएं		
ए.1.2 संकीर्ण मुद्रा (एम1)			ई.1.3 आईआईपी – मध्यवर्ती वस्तुएं		
ए.1.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम)			ई.1.4 आईआईपी – इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं		
ए.1.3.1 संचलनगत मुद्रा			ई.1.5 आईआईपी – उपभोक्ता वस्तुएं		
ए.2.1 कुल जमाराशियां (एससीबी)			ई.1.5.1 आईआईपी – टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं		
ए.2.1.1 मांग जमाराशियां (एससीबी)			ई.1.5.2 आईआईपी – गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं		
ए.2.1.2 मीयादी जमाराशियां (एससीबी)			ई.2.1 आईआईपी – खनन		
ए.3.1 नकदी शेष और आरबीआई के पास जमा शेष (एससीबी)			ई.2.2 आईआईपी – विनिर्माण		
ए.3.2 बैंक ऋण (एससीबी)			अप्रैल 1994 से मार्च 2020		ई.2.2.1 आईआईपी – खाद्य उत्पादों का विनिर्माण
ए.3.2.1 उधार, नकदी ऋण एवं ओवरड्राफ्ट (एससीबी)					ई.2.2.2 आईआईपी – पेय-पदार्थों का विनिर्माण
ए.3.2.2 खाद्य से इतर ऋण (एससीबी)					ई.2.2.3 आईआईपी – कपड़ों का विनिर्माण
ए.3.3 निवेश (एससीबी)					ई.2.2.4 आईआईपी – रसायन और रसायन के उत्पादों का विनिर्माण
मूल्य सूचकांक (सीपीआई: 21 श्रृंखलाएं और डब्ल्यूपीआई: 9 श्रृंखलाएं)	अप्रैल 1994 से मार्च 2020	ई.2.2.5 आईआईपी – मोटर वाहनों, ट्रैलरों और सेमी-ट्रैलरों का विनिर्माण			
बी. सीपीआई (आधार: 2012=100) सभी पण्यों		ई.2.3 आईआईपी – विद्युत			
बी.1 सीपीआई – खाद्य एवं पेय-पदार्थ		अप्रैल 2011 से मार्च 2020		ई.3 सीमेंट उत्पादन	
बी.1.1 सीपीआई – अनाज और उत्पाद				ई.4 इस्पात उत्पादन	
बी.1.2 सीपीआई – मांस और मछली				ई.5 कोयला उत्पादन	
बी.1.3 सीपीआई – अण्डा				ई.6 कच्चा तेल उत्पादन	
बी.1.4 सीपीआई – दूध और उत्पाद			ई.7 पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन		
बी.1.5 सीपीआई – फल			ई.8 उर्वरक उत्पादन		
बी.1.6 सीपीआई – सब्जियां			ई.9 प्राकृतिक गैस उत्पादन		
बी.1.6.1 सीपीआई – आलू			सेवा क्षेत्र के संकेतक (6 श्रृंखलाएं)		
बी.1.6.2 सीपीआई – प्याज	एफ.1 वाणिज्यिक मोटर वाहनों का उत्पादन				
बी.1.6.3 सीपीआई – टमाटर	एफ.2 प्रमुख बंदरगाहों पर चढ़ाए-उतारे गए माल				
बी.1.7 सीपीआई – दाल और उत्पाद	एफ.3 रेल मालगाड़ी यातायात				
बी.1.8 सीपीआई – मसाले	एफ.4 वाणिज्यिक मोटर वाहनों की बिक्री				
बी.1.9 सीपीआई – गैर-मादक पेय पदार्थ	एफ.5 उड़ान भरने वाले यात्री (किमी.) – घरेलू				
बी.1.10 सीपीआई – तैयार आहार, स्नैक्स, मिठाइयां आदि	एफ.6 उड़ान भरने वाले यात्री (किमी.) – अंतरराष्ट्रीय				
बी.2 सीपीआई – क्लोदिंग और फुटवेअर	अप्रैल 1994 से मार्च 2020	पण्य व्यापार (3 श्रृंखलाएं)			
बी.3 सीपीआई – आवास		जी.1 निर्यात			
बी.4 सीपीआई – विविध		जी.2 आयात			
सी.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 2001=100)	जनवरी 2000 से मार्च 2020	जी.3 गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात			
सी.2 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)		भुगतान की वैकल्पिक विधियां (4 श्रृंखलाएं)			
सी.3 ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)		एच.1 तत्काल सकल निपटान			
डी. डब्ल्यूपीआई (आधार : 2011-12=100) सभी पण्यों	अप्रैल 1994 से मार्च 2020	एच.2 पेपर समाशोधन			
डी.1 डब्ल्यूपीआई – प्राथमिक वस्तुएं		अप्रैल 2004 से मार्च 2020	एच.3 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन		
डी.1.1 डब्ल्यूपीआई – खाद्य वस्तुएं			अप्रैल 2005 से मार्च 2020	एच.4 काईस	
डी.2 डब्ल्यूपीआई – ईंधन और विद्युत				अप्रैल 2004 से मार्च 2020	
डी.3 डब्ल्यूपीआई – विनिर्मित उत्पाद					
डी.3.1 डब्ल्यूपीआई – खाद्य उत्पादों का विनिर्माण					
डी.3.2 डब्ल्यूपीआई – रसायन और रसायन के उत्पादों का विनिर्माण					
डी.3.3 डब्ल्यूपीआई – मूल मिश्र धातुओं और धातु उत्पादों का विनिर्माण					
डी.3.4 डब्ल्यूपीआई – मशीनरी और मशीन टूल्स का विनिर्माण					

टिप्पणी :

1. सीपीआई-संयुक्त डेटा केवल जनवरी 2011 से उपलब्ध है।
2. सीपीआई-आईडब्ल्यू, एएल और आरएल डेटा को मोटे तौर पर सीपीआई-आईडब्ल्यू के नवीनतम आधार वर्ष के अनुरूप किया गया है।
3. आईआईपी उपयोग-आधारित एवं अलग-अलग क्षेत्रों (एनआईसी-2 अंक स्तर) के डेटा को अप्रैल 2012 के बाद से लिया गया था क्योंकि पिछले आधार वर्ष से कवरेज में बड़े बदलाव आने की वजह से पुरानी श्रृंखलाओं की गणना नहीं की जा सकी।
4. इस अध्ययन के लिए उपयोग किए जा रहे सभी डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था डेटाबेस, भारतीय रिजर्व बैंक में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं।

सारणी 2: विभिन्न महीनों में पाए गए चरम और गर्त की संख्या*

क्षेत्र/उप-क्षेत्र		अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सित	अक्टू	नव	दिसं	जन	फर	मार्च	कुल
मौद्रिक और बैंकिंग	चरम	4	1		1	1							7	14
	गर्त					4	1	2		4	2		1	14
सीपीआई	चरम			1	2	1	2	3	8	2	2			21
	गर्त	7	4	2					1			3	4	21
डब्ल्यूपीआई	चरम	2	2		2	1	1	1						9
	गर्त									4	1	1	3	9
औद्योगिक उत्पादन	चरम		2		1	1		3		2			14	23
	गर्त	6		1		3	5		2	1		5		23
सेवा संकेतक	चरम		1								1		4	6
	गर्त	1		1			4							6
बाह्य व्यापार	चरम							1		1			1	3
	गर्त								1			2		3
भुगतान की वैकल्पिक विधियां	चरम							1					3	4
	गर्त						1		1			2		4
कुल	चरम	6	6	1	6	4	3	9	8	5	3	0	29	80
	गर्त	14	4	4	0	7	11	2	5	9	3	13	8	80

*टिप्पणी :

1. सामान्य तौर पर, मौसमी चरम और गर्त का निर्णय पिछले 10 सालों के औसत मौसमी कारकों के आधार पर किया जाता है।
2. रिक्त कक्ष कोई चरम या गर्त न पाया जाना इंगित करता है।

सारणी 3: चुनिन्दा आर्थिक समय श्रृंखलाओं के औसत* मासिक मौसमी कारक (जारी)

श्रृंखलाएं/महीना	अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं	दिसं	जन	फर	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मौद्रिक और बैंकिंग संकेतक (14 श्रृंखलाएं)												
ए.1.1 व्यापक मुद्रा (एम3)	101.2	100.8	100.0	100.1	99.8	99.6	99.9	99.6	99.2	99.5	99.6	100.7
ए.1.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	101.2	101.1	100.8	101.8	101.2	99.7	99.8	99.7	97.9	99.1	99.1	98.7
ए.1.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	100.9	100.3	100.2	99.5	99.1	99.3	99.4	99.2	99.7	100.0	100.4	102.2
ए.1.2 संकीर्ण मुद्रा (एम1)	102.0	101.4	100.6	99.2	98.8	99.1	99.0	98.7	98.8	98.7	99.9	103.7
ए.1.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम)	102.0	101.7	101.1	99.7	98.9	98.4	98.2	98.9	98.8	99.0	99.2	104.1
ए.1.3.1 संचलनगत मुद्रा	102.7	103.0	101.8	99.7	98.8	97.9	98.4	99.0	99.0	99.3	100.0	100.4
ए.2.1 कुल जमाराशियां (एससीबी)	100.9	100.4	99.8	100.2	99.9	99.8	100.1	99.8	99.4	99.5	99.5	100.8
ए.2.1.1 मांग जमाराशियां (एससीबी)	101.1	99.4	99.6	98.4	98.3	101.0	98.0	98.9	100.7	98.2	98.9	107.3
ए.2.1.2 मीयादी जमाराशियां (एससीबी)	100.7	100.5	99.8	100.3	100.0	99.6	100.4	100.0	99.4	99.7	99.6	100.0
ए.3.1 नकदी शेष और आरबीआई के पास जमा शेष (एससीबी)	101.8	99.7	101.7	99.9	100.5	101.1	98.7	101.4	101.2	96.1	99.0	99.7
ए.3.2 बैंक ऋण (एससीबी)	101.0	100.3	100.3	99.5	99.0	99.3	99.2	99.1	99.9	99.9	100.3	102.3
ए.3.2.1 उधार, नकदी ऋण एवं ओवरड्राफ्ट (एससीबी)	100.6	100.2	100.4	99.1	98.9	100.2	99.4	99.2	100.0	99.9	100.1	102.0
ए.3.2.2 खाद्य से इतर ऋण (एससीबी)	101.0	100.2	100.2	99.3	99.0	99.5	99.4	99.1	99.8	99.8	100.1	102.5
ए.3.3 निवेश (एससीबी)	100.1	100.4	100.2	101.0	101.6	101.0	100.8	100.5	99.0	99.1	99.1	97.6
मूल्य सूचकांक (सीपीआई: 21 श्रृंखलाएं और डब्ल्यूपीआई: 9 श्रृंखलाएं)												
बी. सीपीआई (आधार: 2012=100) सभी पण्यों	99.1	99.3	99.9	100.6	100.8	100.8	101.0	100.8	100.0	99.6	99.1	99.0
बी.1 सीपीआई – खाद्य एवं पेय-पदार्थ	98.2	98.8	100.1	101.4	101.8	101.6	101.7	101.4	99.9	98.9	98.2	97.9
बी.1.1 सीपीआई – अनाज और उत्पाद	99.7	99.6	99.7	99.8	100.0	100.1	100.3	100.3	100.2	100.2	100.2	100.0
बी.1.2 सीपीआई – मांस और मछली	99.7	100.5	101.9	101.9	100.8	100.0	99.4	98.8	98.8	99.6	99.3	99.4
बी.1.3 सीपीआई – अण्डा	97.0	96.9	98.4	100.2	99.3	98.9	99.1	101.2	103.0	103.8	102.1	100.0
बी.1.4 सीपीआई – दूध और उत्पाद	99.6	99.9	100.0	100.2	100.2	100.2	100.1	100.2	100.1	99.9	99.9	99.7
बी.1.5 सीपीआई – फल	102.5	102.7	102.6	103.2	102.2	99.3	99.0	98.8	97.7	97.0	96.9	98.1
बी.1.6 सीपीआई – सब्जियां	89.4	92.8	98.4	108.9	110.3	110.3	111.3	108.6	99.0	93.3	89.7	88.3
बी.1.6.1 सीपीआई – आलू	86.9	96.1	103.2	109.5	113.0	112.3	114.3	115.3	102.3	86.7	79.6	80.6
बी.1.6.2 सीपीआई – प्याज	80.7	79.8	85.7	98.1	109.6	115.1	118.7	120.1	110.4	102.6	94.4	84.7
बी.1.6.3 सीपीआई – टमाटर	80.7	92.1	110.6	138.4	122.6	108.7	108.8	115.8	92.1	81.4	72.8	75.7
बी.1.7 सीपीआई – दाल और उत्पाद	98.5	98.9	99.4	99.9	100.6	101.3	101.5	101.7	100.7	100.0	99.0	98.5
बी.1.8 सीपीआई – मसाले	99.3	99.4	99.6	99.9	100.2	100.3	100.4	100.4	100.5	100.3	99.9	99.6
बी.1.9 सीपीआई – गैर-मादक पेय पदार्थ	99.9	100.0	100.0	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	100.0	100.0	99.9	99.8
बी.1.10 सीपीआई – तैयार आहार, स्नैक्स, मिठाइयां आदि	99.8	99.7	99.8	99.9	100.0	100.1	100.1	100.3	100.2	100.1	100.1	99.9
बी.2 सीपीआई – क्लोदिंग और फुटवेअर	99.9	99.8	99.8	99.8	99.9	100.0	100.1	100.2	100.3	100.1	100.1	99.9
बी.3 सीपीआई – आवास	100.2	100.1	99.2	99.5	99.9	100.0	100.2	100.3	99.7	100.4	100.3	100.2
बी.4 सीपीआई – विविध	99.7	99.8	99.8	100.1	100.1	100.3	100.3	100.2	100.0	100.0	99.9	99.8
सी.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 2001=100)	98.8	99.2	99.4	99.8	101.0	100.9	100.7	101.1	100.8	99.8	99.5	99.0
सी.2 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	98.9	99.1	99.5	100.1	100.6	100.8	100.8	101.0	100.6	100.1	99.6	99.0
सी.3 ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	98.9	99.2	99.5	100.2	100.4	100.8	100.8	100.9	100.5	100.1	99.6	99.1
डी. डब्ल्यूपीआई (आधार : 2011-12=100) सभी पण्यों	99.6	99.7	100.1	100.2	100.2	100.2	100.3	100.1	99.9	100.0	99.9	99.6
डी.1 डब्ल्यूपीआई – प्राथमिक वस्तुएं	99.8	100.1	100.0	100.6	100.5	100.6	100.5	100.3	99.5	99.5	99.3	99.3
डी.1.1 डब्ल्यूपीआई – खाद्य वस्तुएं	99.1	99.5	100.4	101.5	102.0	101.4	101.2	101.3	99.3	98.6	98.0	97.6
डी.2 डब्ल्यूपीआई – ईंधन और विद्युत	95.2	96.8	101.7	106.0	107.5	107.3	108.1	108.1	97.2	94.2	88.7	88.9
डी.3 डब्ल्यूपीआई – विनिर्मित उत्पाद	98.4	99.1	100.4	101.7	101.9	101.8	102.3	102.1	99.3	98.7	97.2	97.0
डी.3.1 डब्ल्यूपीआई – खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	98.9	99.0	99.3	100.0	100.5	100.6	101.0	101.0	100.6	100.3	99.8	99.1
डी.3.2 डब्ल्यूपीआई – रसायन और रसायन के उत्पादों का विनिर्माण	99.0	99.4	99.7	100.7	101.0	101.0	101.2	100.6	99.7	99.4	99.4	98.9
डी.3.3 डब्ल्यूपीआई – मूल मिश्र धातुओं और धातु उत्पादों का विनिर्माण	98.9	98.0	97.7	98.5	99.4	99.4	99.6	101.0	101.6	102.6	102.3	101.0
डी.3.4 डब्ल्यूपीआई – मशीनरी और मशीन टूल्स का विनिर्माण	97.6	98.7	99.0	100.5	101.4	101.4	103.3	102.7	101.4	99.5	97.7	97.0

सारणी 3: चुनिन्दा आर्थिक समय श्रृंखलाओं के औसत* मासिक मौसमी कारक (समाप्त)

श्रृंखलाएं/महीना	अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं	दिसं	जन	फर	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (23 श्रृंखलाएं)												
ई. आईआईपी (आधार 2011-12=100) सामान्य सूचकांक	96.6	100.1	98.6	98.0	96.8	97.9	99.5	97.8	103.2	103.2	98.7	109.6
ई.1.1 आईआईपी – प्राथमिक वस्तुएं	97.2	102.4	99.4	97.7	97.3	94.9	100.4	98.3	103.5	104.2	96.0	108.8
ई.1.2 आईआईपी – पूंजी वस्तुएं	89.2	97.1	98.7	94.8	96.7	102.1	96.4	97.8	101.8	98.1	102.6	124.3
ई.1.3 आईआईपी – मध्यवर्ती वस्तुएं	98.0	100.1	98.5	100.4	100.0	99.9	99.0	97.7	101.1	100.9	97.4	107.5
ई.1.4 आईआईपी – इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	99.5	104.3	101.5	99.9	97.3	96.0	97.7	94.4	100.4	103.6	99.1	107.0
ई.1.5 आईआईपी – उपभोक्ता वस्तुएं	95.4	98.6	96.4	97.7	97.1	100.4	101.7	99.3	103.9	103.1	100.1	106.2
ई.1.5.1 आईआईपी – टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	95.8	99.2	97.2	98.8	97.9	105.5	107.8	99.3	97.6	98.9	96.5	104.6
ई.1.5.2 आईआईपी – गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	94.9	99.5	95.3	95.8	95.9	96.1	96.1	100.8	108.1	106.3	102.8	108.7
ई.2.1 आईआईपी – खनन	97.9	100.6	96.1	91.2	89.6	88.6	97.6	100.5	107.2	109.0	103.0	119.4
ई.2.2 आईआईपी – विनिर्माण	96.0	99.7	98.4	98.7	97.4	99.0	99.7	97.9	103.1	102.6	98.8	108.5
ई.2.2.1 आईआईपी – खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	94.2	88.2	85.8	90.3	88.4	89.0	94.6	104.2	122.5	119.9	112.8	110.0
ई.2.2.2 आईआईपी – पेय-पदार्थों का विनिर्माण	119.8	130.2	108.0	88.9	85.8	89.8	91.0	85.9	90.0	95.1	98.8	118.1
ई.2.2.3 आईआईपी – कपड़ों का विनिर्माण	97.8	99.0	98.0	100.9	102.4	101.1	101.3	99.3	101.6	100.9	96.1	101.7
ई.2.2.4 आईआईपी – रसायन और रसायन के उत्पादों का विनिर्माण	94.7	100.5	99.5	103.8	101.6	101.0	100.5	98.5	101.1	100.8	93.8	104.7
ई.2.2.5 आईआईपी – मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण	99.0	100.5	97.4	100.2	99.4	101.1	100.4	100.8	93.0	99.8	100.2	108.3
ई.2.3 आईआईपी – विद्युत	100.1	105.2	100.5	102.6	102.3	99.6	102.5	94.7	97.7	99.0	92.2	102.5
ई.3 सीमेंट उत्पादन	103.9	103.4	100.5	96.8	90.5	91.8	98.6	92.5	102.0	105.9	100.9	112.9
ई.4 इस्पात उत्पादन	98.5	104.2	99.3	100.1	98.8	96.6	98.9	95.7	100.4	103.7	98.1	105.7
ई.5 कोयला उत्पादन	91.8	94.1	89.7	83.0	81.4	81.4	95.3	103.0	113.3	117.0	112.1	138.2
ई.6 कच्चा तेल उत्पादन	98.9	101.8	99.3	101.7	101.4	97.9	101.9	99.0	102.0	101.3	92.2	102.7
ई.7 पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन	95.8	100.9	99.3	101.3	100.5	95.5	102.2	98.6	103.2	102.8	95.2	104.6
ई.8 उर्वरक उत्पादन	82.2	95.2	99.4	104.2	106.1	104.5	107.3	104.1	105.5	102.9	93.7	95.3
ई.9 प्राकृतिक गैस उत्पादन	97.4	101.4	98.6	101.9	101.5	98.6	102.4	99.8	102.6	101.9	91.8	102.1
सेवा क्षेत्र के संकेतक (6 श्रृंखलाएं)												
एफ.1 वाणिज्यिक मोटर वाहनों का उत्पादन	95.6	96.5	92.1	95.9	96.8	98.3	101.5	99.8	92.7	106.7	107.2	116.7
एफ.2 प्रमुख बंदरगाहों पर चढ़ाए-उतारे गए माल	100.0	103.9	97.3	99.5	98.3	93.1	98.5	98.7	102.5	104.5	94.8	108.5
एफ.3 रेल मालगाड़ी यातायात	97.3	100.9	97.1	98.1	95.2	93.5	98.4	98.4	103.5	106.5	97.7	113.2
एफ.4 वाणिज्यिक मोटर वाहनों की बिक्री	86.6	91.1	96.3	93.6	95.4	106.7	99.4	94.4	97.9	104.5	104.6	129.9
एफ.5 उड़ान भरने वाले यात्री (किमी.) – घरेलू	100.7	110.7	102.4	96.9	94.7	90.6	99.1	100.2	107.3	102.9	96.0	99.1
एफ.6 उड़ान भरने वाले यात्री (किमी.0 – अंतरराष्ट्रीय	96.4	101.2	99.6	103.4	102.8	93.0	93.5	95.7	107.1	110.9	95.0	102.5
पण्य व्यापार (3 श्रृंखलाएं)												
जी.1 निर्यात	97.2	101.2	99.0	98.6	97.3	102.4	98.8	95.0	102.3	98.0	96.6	113.8
जी.2 आयात	98.0	103.3	99.3	102.3	98.7	100.9	104.6	99.3	100.9	97.9	92.9	103.0
जी.3 गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात	95.7	99.3	101.3	103.4	99.2	102.0	102.6	101.7	104.7	99.2	91.9	98.9
भुगतान की वैकल्पिक विधियां (4 श्रृंखलाएं)												
एच.1 तत्काल सकल निपटान	97.1	95.2	106.6	97.7	92.0	104.2	98.6	91.7	102.2	99.0	89.5	126.4
एच.2 पेपर समाशोधन	105.1	99.4	96.5	100.0	95.6	93.2	104.5	95.9	99.6	99.1	94.1	116.5
एच.3 आरईसी	104.1	97.0	98.7	101.8	96.3	97.0	101.0	90.5	101.9	99.1	92.2	121.6
एच.4 कार्ड्स	99.8	101.8	98.4	99.6	99.5	95.7	105.6	100.2	103.4	101.6	92.5	101.5

*: सामान्य तौर पर, पिछले दस सालों का औसत मासिक मौसमी कारक यहां, औसत मासिक मौसमी कारकों की गणना पिछले 10 सालों (अर्थात्, अप्रैल 2010 से मार्च 2020) के आधार पर की गई है।

टिप्पणी :

1. मौसमी कारक : 100 से विचलन मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर, आईआईपी-विनिर्माण के मौसमी कारक में मार्च के दौरान वृद्धि (108.5) होती है और अप्रैल के दौरान गिरावट (96.0) आती है, जो दर्शाता है कि मौसमी उतार-चढ़ाव की वजह से विनिर्माण उत्पादन मार्च के दौरान बढ़ता है और फरवरी के दौरान घटता है।
2. सभी सीपीआई सूचकांकों के मामले में, औसत मासिक मौसमी कारकों की गणना पिछले 9 सालों (अर्थात्, जनवरी 2011 से मार्च 2019) के आधार पर की गई है।
3. आईआईपी (संपूर्ण, खनन, विनिर्माण और विद्युत) की पिछली श्रृंखलाओं एवं डब्ल्यूपीआई श्रृंखलाओं की गणना करने के लिए औसत लिंकिंग कारक का उपयोग किया गया है। औसत लिंकिंग कारक की गणना अप्रैल 2012 से मार्च 2020 की आम अवधि की आईआईपी/डब्ल्यूपीआई श्रृंखलाओं के आधार पर की गई थी। हालांकि, आईआईपी की पिछली श्रृंखलाओं को कवरेज में बड़े बदलाव होने की वजह से और अलग-अलग स्तर पर (उपयोग आधारित और एनआईसी-2 अंक स्तर) समेकित नहीं किया गया था।
4. 'मोटे अंकों में' दर्शाई गई संख्याएं संगत श्रृंखलाओं के चरम और गर्त को दर्शाते हैं।

सारणी 4: मौसमी कारकों का दायरा (चरम और गर्त के बीच अंतर) (जारी)

शृंखलाएं/ वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	औसत एसएफ़ का दायरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मौद्रिक और बैंकिंग संकेतक (14 शृंखलाएं)											
ए.1.1 व्यापक मुद्रा (एम3)	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0
ए.1.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4.6	4.1	3.8	3.6	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0	3.9	3.8
ए.1.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	3.7	3.3	3.0	2.8	2.7	2.8	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1
ए.1.2 संकीर्ण मुद्रा (एम1)	4.7	4.1	4.0	4.2	4.4	5.3	6.1	7.0	7.8	8.2	5.0
ए.1.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम)	7.1	6.8	6.4	6.1	5.7	5.4	5.2	4.9	4.8	4.7	6.0
ए.1.3.1 संचलनगत मुद्रा	5.9	5.6	5.2	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.9	5.2
ए.2.1 कुल जमाराशियां (एससीबी)	2.3	2.0	1.7	1.6	1.5	1.4	1.7	1.9	2.0	2.0	1.5
ए.2.1.1 मांग जमाराशियां (एससीबी)	11.0	8.5	6.6	6.0	6.9	9.5	11.9	13.9	14.8	15.1	9.3
ए.2.1.2 मीयादी जमाराशियां (एससीबी)	2.0	1.9	1.6	1.4	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	1.3
ए.3.1 नकदी शेष और आरबीआई के पास जमा शेष (एससीबी)	10.7	9.1	7.0	5.4	4.5	4.9	5.4	5.8	6.0	6.1	5.8
ए.3.2 बैंक ऋण (एससीबी)	4.0	3.6	3.2	3.0	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2
ए.3.2.1 उधार, नकदी ऋण एवं ओवरड्राफ्ट (एससीबी)	3.7	3.2	2.7	2.4	2.4	2.7	3.0	3.2	3.4	3.5	3.1
ए.3.2.2 खाद्य से इतर ऋण (एससीबी)	4.0	3.6	3.1	2.8	2.7	3.1	3.6	3.9	4.0	3.9	3.5
ए.3.3 निवेश (एससीबी)	4.8	4.6	4.4	4.1	3.7	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	4.0
मूल्य सूचकांक (सीपीआई: 21 शृंखलाएं और डब्ल्यूपीआई: 9 शृंखलाएं)											
बी. सीपीआई (आधार: 2012=100) सभी पण्यों		2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	2.0
बी.1 सीपीआई – खाद्य एवं पेय-पदार्थ		4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.6	3.6	3.7	3.8
बी.1.1 सीपीआई – अनाज और उत्पाद		1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7
बी.1.2 सीपीआई – मांस और मछली		3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.1
बी.1.3 सीपीआई – अण्डा		8.0	7.8	7.5	7.0	6.5	6.2	5.9	5.9	5.9	6.9
बी.1.4 सीपीआई – दूध और उत्पाद		0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6
बी.1.5 सीपीआई – फल		6.5	6.5	6.4	6.3	6.2	6.2	6.2	6.4	6.5	6.3
बी.1.6 सीपीआई – सब्जियां		24.5	24.5	24.1	23.8	22.8	22.1	21.3	21.7	22.3	23.0
बी.1.6.1 सीपीआई – आलू		38.0	37.9	37.4	36.9	36.3	35.1	33.1	31.8	30.8	35.6
बी.1.6.2 सीपीआई – प्याज		45.0	44.7	43.3	42.0	38.8	37.4	37.0	38.0	39.1	40.4
बी.1.6.3 सीपीआई – टमाटर		63.1	63.8	65.3	66.1	66.3	66.4	66.6	66.9	67.5	65.6
बी.1.7 सीपीआई – दाल और उत्पाद		3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.4	3.3	3.2	2.5	3.2
बी.1.8 सीपीआई – मसाले		1.8	1.7	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	0.8	1.3
बी.1.9 सीपीआई – गैर-मादक पेय पदार्थ		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
बी.1.10 सीपीआई – तैयार आहार, स्नैक्स, मिठाइयां आदि		0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
बी.2 सीपीआई – क्लोदिंग और फुटविअर		0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5
बी.3 सीपीआई – आवास		1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2
बी.4 सीपीआई – विविध		0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6
सी.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 2001=100)	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2
सी.2 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.6	2.0
सी.3 ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6	2.0
डी. डब्ल्यूपीआई (आधार : 2011-12=100) सभी पण्यों	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7
डी.1 डब्ल्यूपीआई – प्राथमिक वस्तुएं	1.4	1.3	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3
डी.1.1 डब्ल्यूपीआई – खाद्य वस्तुएं	3.6	3.9	4.3	4.8	5.1	5.1	4.9	4.6	4.4	4.5	4.4
डी.2 डब्ल्यूपीआई – ईंधन और विद्युत	17.3	17.3	18.2	19.8	21.5	22.0	22.2	22.7	23.5	23.3	19.4
डी.3 डब्ल्यूपीआई – विनिर्मित उत्पाद	5.2	5.2	5.2	5.3	5.6	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	5.3
डी.3.1 डब्ल्यूपीआई – खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	2.2
डी.3.2 डब्ल्यूपीआई – रसायन और रसायन के उत्पादों का विनिर्माण	2.4	2.9	3.2	3.1	2.9	2.4	1.9	1.5	1.2	1.1	2.3
डी.3.3 डब्ल्यूपीआई – मूल मिश्र धातुओं और धातु उत्पादों का विनिर्माण	4.5	4.4	4.5	4.8	5.2	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3	4.9
डी.3.4 डब्ल्यूपीआई – मशीनरी और मशीन टूल्स का विनिर्माण	6.3	6.2	6.5	6.8	7.3	7.2	6.9	6.1	5.4	4.8	6.3

सारणी 4: मौसमी कारकों का दायरा (चरम और गर्त के बीच अंतर) (समाप्त)

श्रृंखलाएं/ वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	औसत एसएफ का दायरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (23 श्रृंखलाएं)											
ई. आईआईपी (आधार 2011-12=100) सामान्य सूचकांक	14.4	14.0	13.4	12.7	12.7	12.9	13.0	13.4	13.5	13.5	13.0
ई.1.1 आईआईपी – प्राथमिक वस्तुएं			13.5	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.3	14.5	13.9
ई.1.2 आईआईपी – पूंजी वस्तुएं			39.2	38.4	36.8	35.2	33.2	32.0	31.0	30.8	35.1
ई.1.3 आईआईपी – मध्यवर्ती वस्तुएं			10.2	10.2	10.2	10.1	10.2	10.4	10.7	10.8	10.1
ई.1.4 आईआईपी – इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं			11.6	12.0	12.3	12.7	13.1	13.6	13.8	14.2	12.7
ई.1.5 आईआईपी – उपभोक्ता वस्तुएं			12.0	11.7	11.2	10.7	10.1	9.9	10.1	10.6	10.8
ई.1.5.1 आईआईपी – टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं			13.9	13.8	13.3	12.5	11.3	10.3	10.0	9.6	11.9
ई.1.5.2 आईआईपी – गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं			15.4	15.1	14.3	14.0	13.7	13.9	14.6	15.3	13.8
ई.2.1 आईआईपी – खनन	28.0	29.0	29.7	30.5	31.2	32.1	32.9	34.2	35.1	35.6	30.8
ई.2.2 आईआईपी – विनिर्माण	12.6	12.2	12.0	12.3	12.4	12.6	12.7	13.1	13.2	13.4	12.5
ई.2.2.1 आईआईपी – खाद्य उत्पादों का विनिर्माण			36.3	36.3	35.9	35.9	36.6	37.6	38.5	39.3	36.7
ई.2.2.2 आईआईपी – पेय-पदार्थों का विनिर्माण			55.3	54.4	51.3	46.0	39.7	35.3	32.9	33.4	44.5
ई.2.2.3 आईआईपी – कपड़ों का विनिर्माण			8.9	8.5	7.5	6.4	5.2	5.2	5.5	5.7	6.4
ई.2.2.4 आईआईपी – रसायन और रसायन के उत्पादों का विनिर्माण			11.1	10.8	10.6	10.9	11.7	12.3	12.6	12.7	10.9
ई.2.2.5 आईआईपी – मोटर वाहनों, ट्रैलरों और सेमी-ट्रैलरों का विनिर्माण			13.5	13.9	14.6	15.6	16.2	16.6	16.5	16.4	15.3
ई.2.3 आईआईपी – विद्युत	11.3	10.7	11.2	12.0	13.1	14.2	15.5	16.7	17.9	18.4	13.0
ई.3 सीमेंट उत्पादन	23.3	23.9	23.6	23.3	22.1	21.4	20.9	21.1	21.5	22.0	22.4
ई.4 इस्पात उत्पादन	10.3	10.0	10.1	10.1	9.8	9.6	10.0	10.6	11.2	11.6	10.0
ई.5 कोयला उत्पादन	54.6	55.2	55.1	55.0	55.4	56.6	59.1	62.4	65.3	67.1	56.8
ई.6 कच्चा तेल उत्पादन	10.2	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.4
ई.7 पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन	9.3	9.9	10.4	10.6	10.2	9.7	9.5	9.5	9.1	8.8	9.5
ई.8 उर्वरक उत्पादन	26.7	27.0	27.4	27.3	26.4	24.6	22.8	21.9	21.4	21.9	25.1
ई.9 प्राकृतिक गैस उत्पादन	11.1	10.9	10.7	10.9	10.9	11.0	10.9	10.6	10.5	10.7	10.7
सेवा क्षेत्र के संकेतक (6 श्रृंखलाएं)											
एफ.1 वाणिज्यिक मोटर वाहनों का उत्पादन	28.6	28.7	25.6	24.0	24.1	25.8	25.9	26.2	26.1	27.5	24.7
एफ.2 प्रमुख बंदरगाहों पर चढ़ाए-उतारे गए माल	15.9	15.9	14.8	14.6	14.8	15.3	15.6	15.7	15.5	15.4	15.4
एफ.3 रेल मालगाड़ी यातायात	20.6	20.6	19.3	18.8	18.3	18.4	19.1	20.3	21.3	22.0	19.7
एफ.4 वाणिज्यिक मोटर वाहनों की बिक्री	41.8	41.7	40.7	41.3	41.9	43.2	44.7	46.9	48.5	49.9	43.3
एफ.5 उड़ान भरने वाले यात्री (किमी.) – घरेलू	25.8	25.8	24.1	22.1	19.7	17.3	15.1	13.6	12.7	12.4	20.1
एफ.6 उड़ान भरने वाले यात्री (किमी.0 – अंतरराष्ट्रीय	15.2	16.1	16.9	18.1	18.8	19.5	20.0	20.8	21.3	22.1	17.9
पण्य व्यापार (3 श्रृंखलाएं)											
जी.1 निर्यात	21.9	21.9	20.9	19.6	17.8	16.4	15.6	16.5	17.3	17.6	18.8
जी.2 आयात	14.2	12.8	11.7	11.4	12.4	12.7	12.3	11.4	10.8	10.7	11.8
जी.3 गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात	12.7	11.6	12.1	12.3	12.7	13.3	13.9	14.3	14.6	14.6	12.8
भूगतान की वैकल्पिक विधियां (4 श्रृंखलाएं)											
एच.1 तत्काल सकल निपटान	26.9	34.8	39.9	42.6	44.5	44.5	42.5	40.2	38.4	36.9	36.8
एच.2 पेपर समाशोधन	25.2	25.7	25.3	24.3	22.9	21.9	21.3	21.3	21.5	21.8	23.4
एच.3 आरईसी	23.3	29.1	33.7	35.9	36.5	36.1	34.8	33.2	31.7	30.6	31.1
एच.4 कार्ड्स	14.3	14.0	13.3	12.6	12.5	12.6	12.8	13.0	12.9	12.9	13.2

टिप्पणी:

- इन श्रृंखलाओं हेतु मौसमी समायोजन उपलब्धता के आधार पर 10 वर्षों के डेटा पर आधारित है। हालांकि यूके और यूएस सेन्सस ब्यूरो दोनों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) के दिशानिर्देशों के मुताबिक एक स्थिर मासिक मौसमी कारकों का अनुमान करने के लिए दस से अधिक सालों के डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए।
- औसत मौसमी कारक दायरा पिछले दस सालों के औसत मौसमी कारकों का दायरा है; दायरे की गणना अधिकतम और न्यूनतम मासिक मौसमी कारकों के बीच अंतर के रूप में की जाती है।

सारणी 5: पिछले 5 वर्षों की तुलना में 2019-20 में मौसमी चरम और गर्त में परिवर्तन (2014-15 से 2018-19) (जारी)

शृंखलाएं	2014-15 से 2018-19 के एसएफ़ पर आधारित				2018-19 के एसएफ़ पर आधारित			
	चरम वाले माह	चरम मान	गर्त वाले माह	गर्त मान	चरम वाले माह	चरम मान	गर्त वाले माह	गर्त मान
मौद्रिक और बैंकिंग संकेतक (14 शृंखलाएं)								
ए.1.1 व्यापक मुद्रा (एम3)	अप्रै	101.1	दिसं	99.2	अप्रै	101.1	दिसं	99.0
ए.1.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	जुला	101.7	मार्च	98.0	अग	101.7	मार्च	97.7
ए.1.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	मार्च	102.0	अग	99.1	मार्च	102.2	अग	99.0
ए.1.2 संकीर्ण मुद्रा (एम1)	मार्च	104.3	जन	98.3	मार्च	105.8	दिसं	97.6
ए.1.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम)	मार्च	103.6	अक्टू	98.4	मार्च	103.1	नवं	98.4
ए.1.3.1 संचलनगत मुद्रा	मई	102.8	सितं	98.0	मई	102.8	सितं	97.8
ए.2.1 कुल जमाराशियां (एससीबी)	मार्च	101.0	फर	99.3	मार्च	101.2	फर	99.3
ए.2.1.1 मांग जमाराशियां (एससीबी)	मार्च	108.3	जन	96.9	मार्च	111.4	जन	96.3
ए.2.1.2 मीयादी जमाराशियां (एससीबी)	अप्रै	100.5	फर	99.6	अप्रै	100.3	दिसं	99.6
ए.3.1 नकदी शेष और आरबीआई के पास जमा शेष (एससीबी)	दिसं	102.3	जन	97.6	मार्च	104.1	जुला	98.0
ए.3.2 बैंक ऋण (एससीबी)	मार्च	102.1	अग	99.1	मार्च	102.2	अग	99.0
ए.3.2.1 उधार, नकदी ऋण एवं ओवरड्राफ्ट (एससीबी)	मार्च	101.9	अग	99.0	मार्च	102.3	अग	98.8
ए.3.2.2 खाद्य से इतर ऋण (एससीबी)	मार्च	102.4	अग	99.0	मार्च	102.8	अग	98.9
ए.3.3 निवेश (एससीबी)	अग	101.2	मार्च	97.7	अग	101.3	मार्च	98.0
मूल्य सूचकांक (सीपीआई: 21 शृंखलाएं और डब्ल्यूपीआई: 9 शृंखलाएं)								
बी. सीपीआई (आधार: 2012=100) सभी पण्यों	अक्टू	100.9	मार्च	99.1	नवं	100.8	मार्च	99.1
बी.1 सीपीआई – खाद्य एवं पेय-पदार्थ	अग	101.7	मार्च	98.0	नवं	101.7	मार्च	98.0
बी.1.1 सीपीआई – अनाज और उत्पाद	नवं	100.3	मई	99.6	नवं	100.3	मई	99.7
बी.1.2 सीपीआई – मांस और मछली	जुला	102.0	नवं	98.9	जून	102.1	अक्टू	98.8
बी.1.3 सीपीआई – अण्डा	जन	103.3	मई	97.0	जन	103.1	मई	97.1
बी.1.4 सीपीआई – दूध और उत्पाद	नवं	100.2	अप्रै	99.7	अक्टू	100.1	अप्रै	99.8
बी.1.5 सीपीआई – फल	जुला	103.0	फर	96.7	जुला	102.9	जन	96.4
बी.1.6 सीपीआई – सब्जियां	अक्टू	110.7	मार्च	88.5	नवं	111.3	मार्च	89.0
बी.1.6.1 सीपीआई – आलू	नवं	115.2	फर	80.5	नवं	113.6	फर	82.7
बी.1.6.2 सीपीआई – प्याज	नवं	119.5	मई	81.3	नवं	122.9	मई	83.8
बी.1.6.3 सीपीआई – टमाटर	जुला	139.4	फर	73.0	जुला	140.7	फर	73.2
बी.1.7 सीपीआई – दाल और उत्पाद	नवं	101.7	अप्रै	98.4	सितं	101.0	अप्रै	98.6
बी.1.8 सीपीआई – मसाले	दिसं	100.5	अप्रै	99.4	दिसं	100.5	अप्रै	99.6
बी.1.9 सीपीआई – गैर-मादक पेय पदार्थ	सितं	100.1	मार्च	99.8	अग	100.1	मार्च	99.9
बी.1.10 सीपीआई – तैयार आहार, स्नैक्स, मिठाइयां आदि	नवं	100.2	मई	99.8	नवं	100.2	जून	99.9
बी.2 सीपीआई – क्लोदिंग और फुटविअर	दिसं	100.2	मई	99.8	दिसं	100.2	मार्च	99.9
बी.3 सीपीआई – आवास	नवं	100.4	जून	99.2	नवं	100.4	जून	99.1
बी.4 सीपीआई – विविध	सितं	100.2	अप्रै	99.8	नवं	100.2	जून	99.8
सी.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 2001=100)	अग	101.2	मार्च	98.8	अग	101.2	मार्च	98.9
सी.2 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	नवं	100.9	अप्रै	98.9	दिसं	100.7	अप्रै	99.1
सी.3 ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	नवं	100.9	अप्रै	98.9	दिसं	100.7	अप्रै	99.1
डी. डब्ल्यूपीआई (आधार : 2011-12=100) सभी पण्यों	अग	100.3	मार्च	99.7	अग	100.4	फर	99.6
डी.1 डब्ल्यूपीआई – प्राथमिक वस्तुएं	अक्टू	100.6	मार्च	99.2	नवं	100.7	मार्च	99.3
डी.1.1 डब्ल्यूपीआई – खाद्य वस्तुएं	अग	102.1	मार्च	97.4	नवं	101.9	मार्च	97.4
डी.2 डब्ल्यूपीआई – ईंधन और विद्युत	अक्टू	109.2	मार्च	87.6	नवं	110.6	मार्च	87.3
डी.3 डब्ल्यूपीआई – विनिर्मित उत्पाद	अक्टू	102.2	मार्च	96.8	नवं	102.5	मार्च	96.9
डी.3.1 डब्ल्यूपीआई – खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	नवं	100.9	अप्रै	98.8	नवं	100.8	अप्रै	98.9
डी.3.2 डब्ल्यूपीआई – रसायन और रसायन के उत्पादों का विनिर्माण	सितं	101.0	मार्च	99.0	अक्टू	100.6	मार्च	99.5
डी.3.3 डब्ल्यूपीआई – मूल मिश्र धातुओं और धातु उत्पादों का विनिर्माण	जन	102.7	जून	97.4	फर	102.6	जून	97.4

**सारणी 5: पिछले 5 वर्षों की तुलना में 2019-20 में मौसमी चरम और गर्त में परिवर्तन
(2014-15 से 2018-19) (समाप्त)**

श्रृंखलाएं	2014-15 से 2018-19 के एसएफ़ पर आधारित				2018-19 के एसएफ़ पर आधारित			
	चरम वाले माह	चरम मान	गर्त वाले माह	गर्त मान	चरम वाले माह	चरम मान	गर्त वाले माह	गर्त मान
डी.3.4 डब्ल्यूपीआई – मशीनरी और मशीन टूल्स का विनिर्माण	अक्टू	103.4	अप्रै	97.1	नव	102.4	अप्रै	97.6
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (23 श्रृंखलाएं)								
ई. आईआईपी (आधार 2011-12=100) सामान्य सूचकांक	मार्च	109.3	अप्रै	96.2	मार्च	109.7	अप्रै	96.2
ई.1.1 आईआईपी – प्राथमिक वस्तुएं	मार्च	108.9	सितं	94.9	मार्च	109.3	सितं	94.8
ई.1.2 आईआईपी – पूंजी वस्तुएं	मार्च	123.1	अप्रै	89.5	मार्च	121.5	अप्रै	90.7
ई.1.3 आईआईपी – मध्यवर्ती वस्तुएं	मार्च	107.8	फर	97.7	मार्च	108.3	अप्रै	97.5
ई.1.4 आईआईपी – इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	मार्च	107.5	नव	94.5	मार्च	108.9	सितं	94.7
ई.1.5 आईआईपी – उपभोक्ता वस्तुएं	मार्च	105.7	अप्रै	95.4	मार्च	105.5	जून	94.9
ई.1.5.1 आईआईपी – टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	अक्टू	107.3	अप्रै	96.1	अक्टू	105.8	फर	96.2
ई.1.5.2 आईआईपी – गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	मार्च	108.1	अप्रै	94.4	दिसं	107.9	जून	92.7
ई.2.1 आईआईपी – खनन	मार्च	121.0	सितं	88.2	मार्च	121.8	अग	86.2
ई.2.2 आईआईपी – विनिर्माण	मार्च	108.3	अप्रै	95.5	मार्च	108.7	अप्रै	95.3
ई.2.2.1 आईआईपी – खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	दिसं	122.5	जून	85.6	दिसं	124.0	जून	84.7
ई.2.2.2 आईआईपी – पेय-पदार्थों का विनिर्माण	मई	127.7	नव	87.0	मई	122.3	अक्टू	88.9
ई.2.2.3 आईआईपी – कपड़ों का विनिर्माण	अग	101.9	फर	96.4	दिसं	102.8	फर	97.1
ई.2.2.4 आईआईपी – रसायन और रसायन के उत्पादों का विनिर्माण	मार्च	105.4	फर	93.9	मार्च	107.0	फर	94.4
ई.2.2.5 आईआईपी – मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण	मार्च	108.5	दिसं	92.6	मार्च	108.9	दिसं	92.5
ई.2.3 आईआईपी – विद्युत	मई	106.2	फर	90.8	मई	108.0	फर	89.6
ई.3 सीमेंट उत्पादन	मार्च	111.9	अग	90.5	मार्च	112.1	अग	90.1
ई.4 इस्पात उत्पादन	मार्च	106.7	नव	96.6	मार्च	108.5	सितं	96.9
ई.5 कोयला उत्पादन	मार्च	140.1	अग	80.3	मार्च	144.4	अग	77.3
ई.6 कच्चा तेल उत्पादन	मार्च	102.7	फर	92.2	मार्च	103.0	फर	92.1
ई.7 पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन	मार्च	104.4	फर	94.9	मार्च	103.6	फर	94.8
ई.8 उर्वरक उत्पादन	अक्टू	106.3	अप्रै	83.0	दिसं	105.1	अप्रै	83.3
ई.9 प्राकृतिक गैस उत्पादन	अक्टू	102.7	फर	92.0	दिसं	103.2	फर	92.6
सेवा क्षेत्र के संकेतक (6 श्रृंखलाएं)								
एफ.1 वाणिज्यिक मोटर वाहनों का उत्पादन	मार्च	116.5	दिसं	90.9	मार्च	118.5	अग	91.0
एफ.2 प्रमुख बंदरगाहों पर चढ़ाए-उतारे गए माल	मार्च	108.9	सितं	93.5	मार्च	108.8	सितं	93.4
एफ.3 रेल मालगाड़ी यातायात	मार्च	113.3	सितं	93.8	मार्च	114.7	सितं	92.7
एफ.4 वाणिज्यिक मोटर वाहनों की बिक्री	मार्च	131.6	अप्रै	86.6	मार्च	134.9	अप्रै	85.0
एफ.5 उड़ान भरने वाले यात्री (किमी.) – घरेलू	मई	108.7	सितं	93.0	मई	106.7	सितं	94.3
एफ.6 उड़ान भरने वाले यात्री (किमी.0 – अंतरराष्ट्रीय	जन	112.6	सितं	92.6	जन	114.4	सितं	92.4
पण्य व्यापार (3 श्रृंखलाएं)								
जी.1 निर्यात	मार्च	112.8	नव	96.4	मार्च	113.4	जुला	95.8
जी.2 आयात	मार्च	104.8	फर	92.9	मार्च	103.7	फर	92.9
जी.3 गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात	दिसं	104.9	फर	91.1	दिसं	104.7	फर	90.1
भुगतान की वैकल्पिक विधियां (4 श्रृंखलाएं)								
एच.1 तत्काल सकल निपटान	मार्च	129.9	फर	87.9	मार्च	125.4	फर	88.4
एच.2 पेपर समाशोधन	मार्च	115.4	सितं	93.6	मार्च	115.0	सितं	93.3
एच.3 आरईसी	मार्च	125.8	नव	91.4	मार्च	123.9	नव	93.3
एच.4 कार्ड्स	अक्टू	105.4	फर	92.6	अक्टू	106.2	फर	93.4

सारणी 6: पिछले 5 वर्षों की तुलना में 2019-20 में मौसमी अस्थिरता में बदलाव (2014-15 से 2018-19)

वैरीअबल के नाम	2019-20	औसत दायरा*	बदलाव	वैरीअबल के नाम	2019-20	औसत दायरा*	बदलाव
1	2	3	4	5	6	7	8
मौद्रिक और बैंकिंग संकेतक (14 श्रृंखलाएं)				डी.3.2 डब्ल्यूपीआई – रसायन और रसायन के उत्पादों का विनिर्माण			
ए.1.1 व्यापक मुद्रा (एम3)	2.1	2.0	0.2	डी.3.3 डब्ल्यूपीआई – मूल मिश्र धातुओं और धातु उत्पादों का विनिर्माण	1.1	2.0	-0.9
ए.1.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3.9	3.7	0.3	डी.3.4 डब्ल्यूपीआई – मशीनरी और मशीन टूल्स का विनिर्माण	5.3	5.3	0.0
ए.1.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	3.2	2.9	0.2		4.8	6.3	-1.5
ए.1.2 संकीर्ण मुद्रा (एम1)	8.2	6.0	2.3	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (23 श्रृंखलाएं)			
ए.1.3 आरक्षित मुद्रा (आरएम)	4.7	5.2	-0.5	ई. आईआईपी (आधार 2011-12=100) सामान्य सूचकांक	13.5	13.1	0.5
ए.1.3.1 संचलनगत मुद्रा	4.9	4.7	0.2	ई.1.1 आईआईपी – प्राथमिक वस्तुएं	14.5	14.0	0.5
ए.2.1 कुल जमाराशियां (एससीबी)	2.0	1.6	0.3	ई.1.2 आईआईपी – पूंजी वस्तुएं	30.8	33.6	-2.8
ए.2.1.1 मांग जमाराशियां (एससीबी)	15.1	11.4	3.8	ई.1.3 आईआईपी – मध्यवर्ती वस्तुएं	10.8	10.1	0.7
ए.2.1.2 मीयादी जमाराशियां (एससीबी)	0.8	0.9	-0.2	ई.1.4 आईआईपी – इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	14.2	13.0	1.2
ए.3.1 नकदी शेष और आरबीआई के पास जमा शेष (एससीबी)	6.1	4.7	1.3	ई.1.5 आईआईपी – उपभोक्ता वस्तुएं	10.6	10.4	0.2
ए.3.2 बैंक ऋण (एससीबी)	3.2	3.0	0.2	ई.1.5.1 आईआईपी – टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	9.6	11.2	-1.6
ए.3.2.1 उधार, नकदी ऋण एवं ओवरड्राफ्ट (एससीबी)	3.5	2.9	0.5	ई.1.5.2 आईआईपी – गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	15.3	13.7	1.6
ए.3.2.2 खाद्य से इतर ऋण (एससीबी)	3.9	3.4	0.5	ई.2.1 आईआईपी – खनन	35.6	32.9	2.7
ए.3.3 निवेश (एससीबी)	3.3	3.5	-0.2	ई.2.2 आईआईपी – विनिर्माण	13.4	12.8	0.6
मूल्य सूचकांक (सीपीआई): 21 श्रृंखलाएं और डब्ल्यूपीआई: 9 श्रृंखलाएं				ई.2.2.1 आईआईपी – खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	39.3	36.9	2.4
बी. सीपीआई (आधार: 2012=100) सभी पण्यों	1.7	1.8	-0.1	ई.2.2.2 आईआईपी – पेय-पदार्थों का विनिर्माण	33.4	40.7	-7.3
बी.1 सीपीआई – खाद्य एवं पेय-पदार्थ	3.7	3.8	-0.1	ई.2.2.3 आईआईपी – कपड़ों का विनिर्माण	5.7	5.5	0.2
बी.1.1 सीपीआई – अनाज	0.6	0.7	-0.1	ई.2.2.4 आईआईपी – रसायन और रसायन के उत्पादों का विनिर्माण	12.7	11.5	1.2
बी.1.1.1 सीपीआई – मांस और मछली	3.3	3.1	0.2	ई.2.2.5 आईआईपी – मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण	16.4	15.9	0.5
बी.1.1.2 सीपीआई – मांस और मछली	3.3	3.1	0.2	ई.2.3 आईआईपी – विद्युत	18.4	15.5	2.9
बी.1.1.3 सीपीआई – अण्डा	5.9	6.3	-0.3	ई.3 सीमेंट उत्पादन	22.0	21.4	0.6
बी.1.1.4 सीपीआई – दूध और उत्पाद	0.3	0.5	-0.1	ई.4 इस्पात उत्पादन	11.6	10.1	1.6
बी.1.1.5 सीपीआई – फल	6.5	6.3	0.3	ई.5 कोयला उत्पादन	67.1	59.8	7.4
बी.1.1.6 सीपीआई – सब्जियां	22.3	22.2	0.1	ई.6 कच्चा तेल उत्पादन	10.8	10.5	0.3
बी.1.1.6.1 सीपीआई – आलू	30.8	34.7	-3.8	ई.7 पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन	8.8	9.5	-0.6
बी.1.1.6.2 सीपीआई – प्याज	39.1	38.2	0.9	ई.8 उर्वरक उत्पादन	21.9	23.3	-1.5
बी.1.1.6.3 सीपीआई – टमाटर	67.5	66.5	1.0	ई.9 प्राकृतिक गैस उत्पादन	10.7	10.7	-0.1
बी.1.1.7 सीपीआई – दाल और उत्पाद	2.5	3.3	-0.9	सेवा क्षेत्र के संकेतक (6 श्रृंखलाएं)			
बी.1.1.8 सीपीआई – मसाले	0.8	1.1	-0.3	एफ.1 वाणिज्यिक मोटर वाहनों का उत्पादन	27.5	25.6	2.0
बी.1.1.9 सीपीआई – गैर-मादक पेय पदार्थ	0.2	0.3	-0.1	एफ.2 प्रमुख बंदरगाहों पर चढ़ाए-उतारे गए माल	15.4	15.4	0.0
बी.1.1.10 सीपीआई – तैयार आहार, स्नैक्स, मिठाइयां आदि।	0.4	0.5	-0.1	एफ.3 रेल मालगाड़ी यातायात	22.0	19.5	2.5
बी.2 सीपीआई – क्लोदिंग और फुटवियर	0.3	0.4	-0.1	एफ.4 वाणिज्यिक मोटर वाहनों की बिक्री	49.9	45.0	4.9
बी.3 सीपीआई – आवास	1.3	1.2	0.1	एफ.5 उड़ान भरने वाले यात्री (किमी.) – घरेलू	12.4	15.7	-3.3
बी.4 सीपीआई – विविध	0.3	0.4	-0.1	एफ.6 उड़ान भरने वाले यात्री (किमी.0 – अंतरराष्ट्रीय)	22.1	20.1	2.0
सी.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 2001=100)	2.3	2.4	-0.1	पण्य व्यापार (3 श्रृंखलाएं)			
सी.2 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	1.6	2.0	-0.3	जी.1 निर्यात	17.6	16.4	1.2
सी.3 ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	1.6	1.9	-0.3	जी.2 आयात	10.7	11.9	-1.2
डी. डब्ल्यूपीआई (आधार: 2011-12=100) सभी पण्यों	0.8	0.7	0.2	जी.3 गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात	14.6	13.8	0.8
डी.1 डब्ल्यूपीआई – प्राथमिक वस्तुएं	1.4	1.4	0.0	भुगतान की वैकल्पिक विधियां (4 श्रृंखलाएं)			
डी.1.1 डब्ल्यूपीआई – खाद्य वस्तुएं	4.5	4.8	-0.3	एच.1 तत्काल सकल निपटान	36.9	42.0	-5.0
डी.2 डब्ल्यूपीआई – ईंधन और विद्युत	23.3	21.7	1.6	एच.2 पेपर समाशोधन	21.8	21.8	0.0
डी.3 डब्ल्यूपीआई – विनिर्मित उत्पाद	5.6	5.4	0.2	एच.3 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	30.6	34.5	-3.9
डी.3.1 डब्ल्यूपीआई – खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	1.9	2.2	-0.2	एच.4 कार्ड्स	12.9	12.8	0.1

*2018-19 को समाप्त 5 वर्ष के मासिक मौसमी कारकों का औसत दायरा।

सारणी 7: पिछले पांच वर्षों के दौरान मासिक मौसमी कारकों के औसत दायरे पर आधारित शीर्ष-बीस और सबसे निचली-बीस श्रृंखलाओं की सूची एवं समवर्ती चरम और गर्त के महीने

शीर्ष-बीस श्रृंखलाओं के नाम	औसत दायरा	चरम के महीने	गर्त के महीने
1	2	3	4
बी.1 .6.3 सीपीआई – टमाटर	65.6	जुला	फर
ई.5 कोयला उत्पादन	56.8	मार्च	अग
ई.2.2.2 आईआईपी – पेय-पदार्थों का विनिर्माण	44.5	मई	अग
एफ.4 वाणिज्यिक मोटर वाहनों की बिक्री	43.3	मार्च	अप्रै
बी.1 .6.2 सीपीआई – प्याज	40.4	नवं	मई
एच.1 आरटीजीएस	36.8	मार्च	फर
ई.2.2.1 आईआईपी – खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	36.7	दिसं	जून
बी.1 .6.1 सीपीआई - आलू	35.6	नवं	फर
ई.1.2 आईआईपी – पूंजी वस्तुएं	35.1	मार्च	अप्रै
एच.3 आरईसी	31.1	मार्च	नवं
ई.2.1 आईआईपी – खनन	30.8	मार्च	सितं
ई.8 उर्वरक उत्पादन	25.1	अक्टू	अप्रै
एफ.1 वाणिज्यिक मोटर वाहनों का उत्पादन	24.7	मार्च	जून
एच.2 पेपर समाशोधन	23.4	मार्च	सितं
बी.1 .6 सीपीआई – सब्जियां	23.0	अक्टू	मार्च
ई.3 सीमेंट उत्पादन	22.4	मार्च	अग
एफ.5 उड़ान भरने वाले (किमी.) यात्री - घरेलू	20.1	मई	सितं
एफ.3 रेल मालगाड़ी यातायात	19.7	मार्च	सितं
डी.2 डब्ल्यूपीआई – ईंधन और विद्युत	19.4	नवं	फर
जी.1 निर्यात	18.8	मार्च	नवं
बी.1 .9 सीपीआई – गैर-मादक पेय-पदार्थ	0.3	सितं	मार्च
बी.2 सीपीआई – क्लोदिंग और फुटविअर	0.5	दिसं	जून
बी.1 .10 सीपीआई – तैयार आहार, स्नैक्स, मिठाइयां आदि	0.6	नवं	मई
बी.4 सीपीआई – विविध	0.6	सितं	अप्रै
बी.1 .4 सीपीआई – दूध और उत्पाद	0.6	नवं	अप्रै
बी.1 .1 सीपीआई – अनाज और उत्पाद	0.7	अक्टू	मई
डी. डब्ल्यूपीआई (आधार : 2011-12=100) सभी पण्यों	0.7	अक्टू	मार्च
बी.3 सीपीआई – आवास	1.2	जन	जून
बी.1 .8 सीपीआई – मसाले	1.3	दिसं	अप्रै
ए.2.1.2 मीयादी जमाराशियां (एससीबी)	1.3	अप्रै	दिसं
बी.1 डब्ल्यूपीआई – प्राथमिक वस्तुएं	1.3	सितं	फर
ए.2.1 कुल जमाराशियां (एससीबी)	1.5	अप्रै	दिसं
बी. सीपीआई (आधार : 2012=100) सभी पण्यों	2.0	अक्टू	मार्च
सी.3 ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	2.0	नवं	अप्रै
सी.2 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1986-87=100)	2.0	नवं	अप्रै
ए.1.1 व्यापक मुद्रा (एम3)	2.0	अप्रै	दिसं
डी.3.1 डब्ल्यूपीआई – खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	2.2	नवं	अप्रै
सी.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 2001=100)	2.2	नवं	अप्रै
डी.3.2 डब्ल्यूपीआई – रसायन और रसायन उत्पादों का विनिर्माण	2.3	अक्टू	मार्च
ए.3.3.1 उधार, नकदी, ऋण और ओवरड्राफ्ट (एससीबी)	3.1	मार्च	अग

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी लेखा और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक शृंखला

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	145
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	146
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	147
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय	148
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	149
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	149
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	150
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	151
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	152
9	कुल चलनिधि राशियां	152
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	153
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	153
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	154
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	154
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	155
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	156
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	157
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	158
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	159
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	159
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	159
21	थोक मूल्य सूचकांक	160
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	164
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	164
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	165
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	165
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	166
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	167
28	वाणिज्यिक पत्र	167
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	167
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	168

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	169
32	विदेशी मुद्रा भंडार	169
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	169
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	170
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	170
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	171
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	171
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	172
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	173
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	174
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	175
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	176
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	177
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	179
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	180
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	181
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	182
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	183
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	184

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2019-20	2019-20		2020-21	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	3.9	4.8	4.3	-22.8	-7.0
1.1.1 कृषि	4.0	3.0	3.5	3.4	3.4
1.1.2 उद्योग	0.8	3.8	-0.2	-33.8	0.1
1.1.3 सेवाएं	5.0	5.5	6.1	-24.3	-11.1
1.1क अंतिम खपत व्यय	6.3	5.6	7.8	-19.2	-13.3
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	-2.8	4.6	-3.9	-47.1	-7.3
	2019-20	2019		2020	
		सित.	अक्टू.	सित.	अक्टू.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-0.8	-4.6	-6.6	0.2	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	7.9	9.4	10.3	10.5	11.1
2.1.2 ऋण	6.1	8.8	8.9	5.1	5.4
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	6.1	8.7	8.8	5.1	5.5
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	10.6	7.1	7.0	20.3	21.5
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	9.4	12.0	15.3	14.4	12.8
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	8.9	9.6	10.6	12.2	11.6
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.25	18.75	18.50	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.6	4.8	4.9	3.6	3.8
3.4 ऋण-जमा अनुपात	76.4	75.7	75.8	72.0	71.9
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	60.3	-0.9	17.0	-14.3	0.5
3.6 निवेश-जमा अनुपात	27.6	28.6	28.3	31.1	31.0
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	36.2	93.3	73.3	100.6	85.4
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.40	5.40	5.15	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	4.00	5.15	4.90	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.65	5.65	5.40	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.65	5.65	5.40	4.25	4.25
4.5 आधार दर	8.15/9.40	8.95/9.40	8.95/9.40	7.40/9.00	7.40/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.40/7.90	7.80/8.30	7.70/8.20	6.65/7.15	6.65/7.10
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	5.90/6.40	6.25/7.00	6.25/6.85	4.90/5.50	4.90/5.50
4.8 बचत जमा दर	3.00/3.50	3.25/3.50	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	5.05	5.31	5.07	3.41	3.19
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.36	5.41	5.04	3.36	3.20
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.97	5.50	5.21	3.58	3.36
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.94	5.60	5.30	3.73	3.45
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.71	6.85	6.54	6.04	5.91
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	74.84	70.84	70.96	73.73	73.97
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	82.64	77.32	78.81	86.04	86.97
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरीकी डॉलर					
1-माह (%)	8.98	3.98	3.38	3.74	3.24
3-माह (%)	5.93	3.95	3.61	3.80	3.46
6-माह (%)	5.05	4.23	3.99	3.91	3.89
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.76	4.0	4.6	7.3	7.6
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	7.54	7.0	7.6	5.6	6.0
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.69	0.3	0.0	1.3	1.5
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	6.77	5.5	6.0	5.1	4.7
6.3.2 ईंधन और पावर	-1.63	-6.7	-8.1	-9.5	-10.9
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	0.29	-0.4	-0.9	1.6	2.1
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-7.66	-12.0	-15.0	-19.6	-11.5
7.2 निर्यात	-5.06	-6.6	-1.7	6.0	-5.1

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2019-20	2019	2020				
		नव.	अक्टू. 30	नव. 6	नव. 13	नव. 20	नव. 27'
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2412993	2230697	2688725	2707002	2750848	2743952	2744155
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	10	12	12	15	13	12	12
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2413003	2230709	2688737	2707017	2750861	2743964	2744167
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	103439	88261	117206	121673	118331	116497	113222
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2308718	2141628	2570667	2584508	2631727	2626673	2630160
1.2.3 रुपया सिक्का	846	820	864	836	803	794	785
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1187409	896950	1439019	1473924	1488583	1488733	1445616
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	100	100	100	101	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	42	43	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	536186	542975	453999	450857	459105	471488	461900
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7603	4657	5623	5426	5398	5209	5547
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3445	2784	2405	2488	2633	2426	2414
2.1.1.7 अन्य बैंक	32641	31479	26036	25768	27150	25555	27334
2.1.1.8 अन्य	605100	313483	950693	989243	994154	983912	944501
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	2291	1430	120	-	-	-	3778
2.1.2 अन्य देयताएं	1350333	1135150	1424609	1472092	1481763	1465565	1462954
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	2537742	2032100	2863628	2946016	2970346	2954298	2908570
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	10	12	12	15	13	12	12
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1006357	891144	1300811	1340061	1355753	1355621	1349768
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	50477	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1967	1261	4190	9037	21447	10731	2112
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	285623	23012	115757	114463	114588	114711	77097
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	23320	23402	23402	23246	23596
2.2.3.7 एक्विजिमेंट बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	10064	4913	12931	12974	12974	10563	9216
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	2300	-	10480	-	-	-	9703
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1042951	1003900	1239727	1283809	1284235	1283729	1284031
2.2.6 अन्य आस्तियां	137993	107858	156400	162255	157934	155685	153035
2.2.6.1 सोना	127644	102903	151494	157268	152949	150577	147429

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	विक्रय	क्रय	दीर्घावधि रिपो परिचालन	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	म्यूचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा	एनबीफसी/एचएफसीएस के लिए विशेष चलनिधि योजना **	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12+13-2-4-7-8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अक्टू. 1, 2020	-	524913	-	-	40	-225	-	-	4550	-	-	-	-	-520548
अक्टू. 2, 2020	-	540	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-522
अक्टू. 3, 2020	-	36242	-	-	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-35752
अक्टू. 4, 2020	-	662	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-658
अक्टू. 5, 2020	-	564267	-	-	121	-	-	10000	10000	-	-	-	-	-564146
अक्टू. 6, 2020	-	543339	-	-	0	-	-	-	1000	-	-	-	-	-542339
अक्टू. 7, 2020	-	534641	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-534641
अक्टू. 8, 2020	-	545888	-	-	0	-	-	-	5790	-	-	-	-	-540098
अक्टू. 9, 2020	-	539325	-	-	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-539315
अक्टू. 10, 2020	-	672	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-672
अक्टू. 11, 2020	-	598	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-598
अक्टू. 12, 2020	-	531112	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-531112
अक्टू. 13, 2020	-	556230	-	-	0	-400	-	-	-	-	-	-	-	-556630
अक्टू. 14, 2020	-	560045	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-560045
अक्टू. 15, 2020	-	565593	-	-	0	625	-	-	-	-	-	-	-	-564968
अक्टू. 16, 2020	-	571248	-	-	10	-1130	-	-	20000	-	-	-	-	-552368
अक्टू. 17, 2020	-	20932	-	-	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-20470
अक्टू. 18, 2020	-	229	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-229
अक्टू. 19, 2020	-	563075	-	-	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-563060
अक्टू. 20, 2020	-	559247	-	-	125	-110	-	-	1595	-	-	-	-	-557637
अक्टू. 21, 2020	-	512847	-	-	0	-	-	-	1640	-	-	-	-	-511207
अक्टू. 22, 2020	-	541262	-	-	0	-	-	-	1130	-	-	-	-	-540132
अक्टू. 23, 2020	-	569336	-	-	6	-	-	-	10000	-	-	-	-	-559330
अक्टू. 24, 2020	-	2027	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-2025
अक्टू. 25, 2020	-	543	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-543
अक्टू. 26, 2020	-	561933	-	-	0	46	-	-	600	-	-	-	-	-561287
अक्टू. 27, 2020	-	585365	-	-	1	-37	-	-	-	-	-	-	-	-585401
अक्टू. 28, 2020	-	583101	-	-	160	32	-	-	-	-	-	-	-	-582909
अक्टू. 29, 2020	-	602552	-	-	0	-770	-	-	-	-	-	-	-	-603322
अक्टू. 30, 2020	-	4318	-	-	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-4006
अक्टू. 31, 2020	-	45921	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-45865

नोट: # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) शामिल है।

** 01 जुलाई 2020 के आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार और ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2019-20	2019	2020	
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	45097	7102	8172	15640
1.1 क्रय (+)	72205	7302	13322	15640
1.2 विक्रय (-)	27108	200	5150	0
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	312005	50257	60803	114896
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	45097	18453	42487	58127
(करोड़ ₹)	312005	125266	317967	432863
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	-4939	-7473	13881	13556

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2019-20	2019	2020	
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7713	0	0	0
1.2 विक्रय (-)	7713	0	0	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	-500	0	0	0

**सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)**

मद	31 अक्टूबर 2020 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	2520	0	2520
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	5212	0	5212
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	14884	0	14884
4. 1 वर्ष से अधिक	960	10020	-9060
कुल (1+2+3+4)	23576	10020	13556

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2019-20	2019	2020					
			नव. 22	जून 19	जुला. 31	अग. 28	सित. 25	अक्टू. 23
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	1262	3231	310	80	300	50	6	266
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	10000	2800	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	4782	1604	326	30	-	-	-	-
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	50000	65000	65000	65000	65000	75000
4.2 बकाया	-	-	26894	34376	34166	37691	36488	33234
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	6044	4835	27530	34486	34466	37741	36494	33500

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एक्जिम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू/एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2019-20	2019	2020		
		अक्टू. 25	सितं. 25	अक्टू. 9	अक्टू. 23
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2349748	2161881	2585243	2609154	2619578
1.1 संचलन में नोट	2420964	2231090	2656476	2675166	2688064
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25605	25302	25738	25738	25738
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	97563	95254	97715	92494	94967
2 जनता की जमाराशियां	1776200	1508717	1739732	1633779	1666403
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1737692	1477505	1696910	1590906	1625686
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	31212	42822	42873	40717
3 एम₁ (1 + 2)	4125948	3670598	4324974	4242933	4285981
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	150963	138452	150963	150963	150963
5 एम₂ (3 + 4)	4276911	3809050	4475937	4393896	4436944
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	12674016	12284764	13414790	13563304	13517758
7 एम₃ (3 + 6)	16799963	15955362	17739765	17806236	17803739
8 कुल डाकघर जमाराशियां	433441	395413	433441	433441	433441
9 एम₄ (7 + 8)	17233404	16350775	18173206	18239677	18237180

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019	2020		
		अक्टू. 25	सितं. 25	अक्टू. 9	अक्टू. 23
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	4852157	5518318	5629859	5587218
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	992192	966959	836430	925601	905454
1.1.1 सरकार पर दावे	1047808	993464	1196304	1225283	1248802
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1045314	992794	1185788	1209805	1242339
1.1.1.2 राज्य सरकारें	2494	670	10516	15478	6463
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाशियां	55616	26505	359874	299682	343348
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	55573	26462	359832	299640	343305
1.1.2.2 राज्य सरकारें	43	43	42	42	43
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3968170	3885198	4681888	4704258	4681764
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	10457195	10933906	11005588	10999620
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13166	7680	14740	14804	14792
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11025478	10449515	10919166	10990784	10984828
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10370861	9840562	10271581	10343517	10338868
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	637776	592379	637509	637577	636209
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	16842	16574	10076	9690	9750
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	3801036	3344957	4230223	4274652	4365595
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	3590402	3126960	3985569	4029998	4120941
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	3590636	3127169	3985812	4030241	4121184
3.1.2 विदेशी देयताएं	234	209	243	243	243
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	210634	217997	244655	244655	244655
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26045	26481	26481	26481
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	3026427	2724992	2969164	3130344	3175175
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1378342	1094490	1384384	1382173	1412121
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1648085	1630502	1584780	1748171	1763054
एम₃ (1+2+3+4-5)	16799963	15955362	17739765	17806236	17803739

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019		2020	
		अक्टू. 25	सितं. 25	अक्टू. 9	अक्टू. 23
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4125948	3670598	4324974	4242933	4285981
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	9745776	9117554	10285464	10272135	10294913
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	16923893	16111023	17826724	17896404	17894503
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2161881	2585243	2609154	2619578
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	14226198	13581853	14942443	14989133	14978869
1.2.1 मांग जमाराशियां	1737692	1477505	1696910	1590906	1625686
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	12488506	12104348	13245533	13398227	13353183
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5619828	5446957	5960490	6029202	6008932
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	169419	167104	73353	72796	180512
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6868678	6657391	7285043	7369025	7344251
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	31212	42822	42873	40717
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	309439	336077	256217	255245	255339
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	16856406	16210358	17430220	17599976	17548475
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	4852157	5518318	5629859	5587218
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	992192	966959	836430	925601	905454
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3968170	3885198	4681888	4704258	4681764
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11896044	11358201	11911902	11970117	11961257
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	13166	7680	40026	39946	38919
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11882878	11350521	11871876	11930171	11922338
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	846284	892285	940628	929553	926628
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26045	26481	26481	26481
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3612303	3046312	4110620	4125488	4222595
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3126960	3985569	4029998	4120941
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	21900	-80647	125051	95490	101655
2.4 पूंजी खाता	2670439	2440799	2811108	2810840	2862261
2.5 अन्य मदें (निवल)	900725	730894	929489	1044700	1040788

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2019-20	2019		2020	
		अक्टू.	अग.	सितं.	अक्टू.
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	16923893	16111023	17752801	17826724	17894503
2 डाकघर जमाराशियां	433441	395413	433441	433441	433441
3 एल₁ (1 + 2)	17357334	16506436	18186242	18260165	18327944
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	57479	2932	40801	38481	35342
4.1 सावधि मुद्रा उधार	7928	2656	7940	5700	3114
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	46249	31	29300	29300	28700
4.3 सावधि जमाराशियां	3302	245	3561	3481	3528
5 एल₂ (3 + 4)	17414813	16509368	18227043	18298646	18363286
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	..
7 एल₃ (5 + 6)	17446718	18330551	..

टिप्पणी: नवंबर 2019 के बाद से, वित्तीय संस्थानों की देनदारियों पर अद्यतन डेटा इस सारणी में शामिल किया गया है, और इसलिए, पिछले डेटा के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019		2020	
		अक्टू. 25	सितं. 25	अक्टू. 9	अक्टू. 23
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2447312	2257135	2682957	2701647	2714545
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	543888	587853	463610	473475	470552
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	505131	548240	429915	439497	437010
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	31212	42822	42873	40717
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3029707	2876200	3189389	3217995	3225814
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	791299	817685	561723	543689	490513
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	992192	966959	836430	925601	905454
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	989741	966332	825956	910165	899034
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1044468	992089	1185063	1208894	1241461
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1044468	992089	1185063	1208894	1241461
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	846	705	725	911	878
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	55573	26462	359832	299640	343305
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	2451	627	10474	15436	6420
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-214059	-156954	-314733	-421858	-453860
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-214059	-156954	-289447	-396716	-429733
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	13166	7680	40026	39946	38919
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	5920	1884	-	-	-
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	25286	25142	24127
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26045	26481	26481	26481
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3126960	3985569	4029998	4120941
2.3.1 सोना	230527	191868	264971	267714	271325
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3359893	2935109	3720615	3762301	3849633
2.4 पूंजी खाता	1165066	982299	1223306	1219439	1251601
2.5 अन्य मदें (निवल)	213276	112191	161078	162734	160520

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया							
	2019-20	2019		2020				अक्टू. 30
		नव. 1	सितं. 25	अक्टू. 2	अक्टू. 9	अक्टू. 16	अक्टू. 23	
	1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3029707	2867866	3189389	3214558	3217995	3230396	3225814	3244482
1 घटक								
1.1 संचलन में मुद्रा	2447312	2257789	2682957	2680043	2701647	2706406	2714545	2715266
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	543888	578304	463610	490054	473475	483520	470552	488063
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	31774	42822	44461	42873	40470	40717	41154
2 स्रोत								
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	992192	1061602	836430	947103	925601	948664	905454	944911
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-214059	-271081	-289447	-380786	-396716	-431556	-429733	-467693
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	13166	7266	14740	14794	14804	14805	14792	14795
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3149078	3985569	3986639	4029998	4061127	4120941	4150295
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26123	26481	26481	26481	26481	26481	26541
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1378342	1105121	1384384	1379673	1382173	1389125	1412121	1424366

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार/ माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019	2020		
		अक्टू. 25	सितं. 25	अक्टू. 9	अक्टू. 23
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	13381983	12797668	14093146	14136871	14126937
1.1.1 मांग जमाराशियां	1617003	1361293	1576060	1469979	1505254
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11764979	11436375	12517086	12666892	12621683
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5294241	5146369	5632689	5700101	5679757
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	169419	167104	73353	72796	180512
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6470739	6290006	6884397	6966791	6941925
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	309439	336077	256217	255245	255339
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	14966910	14416362	15654684	15735315	15707913
2.1.1 सरकार को ऋण	3738696	3675526	4437464	4459740	4438623
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11228214	10740836	11217220	11275575	11269289
2.1.2.1 बैंक ऋण	10370861	9840562	10271581	10343517	10338868
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10319097	9770784	10205154	10280124	10272209
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	11378	8984	12345	10098	11146
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	8653	7967	1629	1370	1610
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	837321	883322	931666	920590	917666
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	21900	-80647	125051	95490	101655
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	315641	229900	361222	328506	330844
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	185510	180416	169257	165077	164575
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	108231	130131	66914	67939	64614
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	899410	790274	806963	918826	951675
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	536186	548240	429915	439497	437010
2.3.2 उपलब्ध नकदी	87260	85079	87601	82613	84932
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-275964	-156954	-289447	-396716	-429733
2.4 पूंजी खाता	1481202	1434329	1563631	1567231	1586490
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	715597	557914	673704	790285	792477
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	495445	380921	484513	451923	499287
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	65654	-42589	71093	71079	67861

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 27, 2020 की स्थिति	2019	2020		
		अक्टू. 25	सितं. 25	अक्टू. 9	अक्टू. 23
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3747349	3683493	4439092	4461110	4440234
2 वाणिज्यिक पत्र	104526	97516	92022	90233	88846
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	14106	11329	11862	11788	11363
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	75415	65652	71294	71983	71675
3.3 अन्य	5734	5519	5037	5110	5430
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	125710	126026	123873	122530	126667
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	226559	245773	304478	310741	306660
4.3 अन्य	191690	191125	148503	146918	146949
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	35610	56587	40302	30257	31182
5.2 वित्तीय संस्थाएं	97665	83483	132981	131032	128894

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति								
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक				
	2019-20	2019		2020		2019-20	2019		2020
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	सितं.		अक्टू.	सितं.	
1	2	3	4	5	6	7	8		
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	219	219	209	209	142	142	133	133	
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	320240	260623	282300	277344	314513	255643	277072	272212	
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	239943	188936	221020	210418	234348	184140	215993	205487	
1.2 बैंकों से उधार राशि	64001	59888	45238	50821	64001	59827	45238	50821	
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	16295	11799	16042	16105	16163	11675	15841	15903	
2 अन्य के प्रति देयताएं	14905949	14184753	15498736	15729998	14480607	13825214	15069677	15299087	
2.1 कुल जमाराशियां	13975551	13324129	14674707	14835434	13567492	12978084	14262403	14420166	
2.1.1 मांग	1653242	1392881	1611292	1607133	1617003	1361293	1576060	1571688	
2.1.2 मीयादी	12322309	11931247	13063416	13228301	11950489	11616791	12686343	12848478	
2.2 उधार	313908	339832	260780	266573	309439	336077	256217	262303	
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	616491	520792	563249	627991	603676	511052	551057	616618	
3 रिजर्व बैंक से उधार	285623	22273	121530	115757	285623	22273	121495	115757	
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2 अन्य	285623	22273	121530	115757	285623	22273	121495	115757	
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	643038	649788	531956	556984	623446	633319	517516	541685	
4.1 उपलब्ध नकदी	89671	87248	89701	89841	87260	85079	87601	87687	
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	553367	562540	442255	467143	536186	548240	429915	453999	
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	323680	359754	280547	274768	260238	307216	218022	214988	
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	181460	261933	187592	188421	155401	236433	153034	155188	
5.1.1 चालू खाते में	17204	16691	16665	21027	14457	14136	14410	19033	
5.1.2 अन्य खातों में	164256	245242	170927	167394	140945	222297	138624	136155	
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	43335	27172	33823	29172	20273	11047	11399	7726	
5.3 बैंकों को अग्रिम	38266	28927	21840	20510	30531	25437	21374	20000	
5.4 अन्य आस्तियां	60619	41722	37292	36664	54032	34298	32214	32074	
6 निवेश	3865544	3781133	4571333	4598216	3747349	3683493	4439092	4468253	
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3850819	3766764	4563197	4590310	3738696	3675526	4437463	4466596	
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	14724	14368	8135	7907	8653	7967	1629	1656	
7 बैंक ऋण	10705336	10127275	10603062	10708653	10370861	9840562	10271581	10374805	
7क खाद्यान्न ऋण	82172	96810	96831	100684	51763	69779	66427	70281	
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	10480934	9917389	10440241	10533796	10149509	9634456	10110780	10202821	
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	26214	26014	20538	26560	25658	24720	20266	25409	
7.3 देशी बिल - भुनाए गए	147209	126797	95214	102180	145683	125199	94174	101192	
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20866	24353	18608	17129	20458	24071	18357	16879	
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	30114	32723	28463	28988	29554	32117	28004	28505	

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2019	2020		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			अक्टू. 25	सितं. 25		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	9263134	8733113	9183525	9213059	-0.5	5.5
1.1 खाद्यान्न ऋण	51590	69555	66204	66428	28.8	-4.5
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	9211544	8663558	9117321	9146631	-0.7	5.6
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1157796	1134705	1194488	1218717	5.3	7.4
1.2.2 उद्योग	2905151	2786751	2774867	2739841	-5.7	-1.7
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	381825	359018	360833	361563	-5.3	0.7
1.2.2.2 मझौले	105598	105558	120210	123150	16.6	16.7
1.2.2.3 बड़े	2417728	2322175	2293824	2255128	-6.7	-2.9
1.2.3 सेवाएं	2594945	2352418	2576254	2576581	-0.7	9.5
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	144466	139102	147616	148172	2.6	6.5
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20051	19062	19828	19368	-3.4	1.6
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	45977	43398	48378	48594	5.7	12.0
1.2.3.4 नौवहन	6557	5893	5099	5364	-18.2	-9.0
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	177085	169783	175455	178191	0.6	5.0
1.2.3.6 व्यापार	552392	505037	566336	575886	4.3	14.0
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	263397	218722	263499	268058	1.8	22.6
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	288995	286315	302837	307828	6.5	7.5
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	229770	220300	230025	227992	-0.8	3.5
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	807383	713344	802552	778739	-3.5	9.2
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	611264	536499	580965	594275	-2.8	10.8
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	2553652	2389684	2571712	2611492	2.3	9.3
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	9298	5557	6661	6881	-26.0	23.8
1.2.4.2 आवास	1338964	1268734	1359824	1373277	2.6	8.2
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	79496	62902	63167	61460	-22.7	-2.3
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	5334	5056	6325	6296	18.0	24.5
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	108094	105026	105640	110207	2.0	4.9
1.2.4.6 शिक्षा	65745	67238	65146	65432	-0.5	-2.7
1.2.4.7 वाहन ऋण	220609	206720	221388	224022	1.5	8.4
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	726112	668451	743561	763917	5.2	14.3
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2897461	2766084	2884154	2930417	1.1	5.9
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1146624	1125522	1180052	1203789	5.0	7.0
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	1149394	1053403	1127110	1125326	-2.1	6.8
1.2अ.2.1 विनिर्माण	381826	359018	360833	361562	-5.3	0.7
1.2अ.2.2 सेवाएं	767568	694385	766277	763764	-0.5	10.0
1.2अ.3 आवास	449945	455536	464642	462216	2.7	1.5
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	38237	32525	32333	32760	-14.3	0.7
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	51906	53736	51898	51789	-0.2	-3.6
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	388	397	515	540	39.2	36.0
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	731409	704413	743792	727814	-0.5	3.3
1.2अ.8 निर्यात ऋण	16114	14040	14831	13850	-14.0	-1.4

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2019	2020		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष 2020
			अक्टू. 25	सितं. 25		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	2905151	2786751	2774867	2739841	-5.7	-1.7
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	43927	41176	41366	42944	-2.2	4.3
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	154146	139693	148446	144158	-6.5	3.2
1.2.1 चीनी	27382	25914	20783	18371	-32.9	-29.1
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19240	17681	18412	17956	-6.7	1.6
1.2.3 चाय	5375	5497	5587	5851	8.9	6.4
1.2.4 अन्य	102149	90601	103664	101980	-0.2	12.6
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	16522	14717	14961	14830	-10.2	0.8
1.4 वस्त्र	192424	187677	188917	185856	-3.4	-1.0
1.4.1 सूती वस्त्र	89283	83999	84905	84289	-5.6	0.3
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2116	2209	2420	2318	9.5	4.9
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	26074	25763	26996	26628	2.1	3.4
1.4.4 अन्य वस्त्र	74951	75706	74596	72621	-3.1	-4.1
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11098	11052	11856	11368	2.4	2.9
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	12233	11992	13039	12786	4.5	6.6
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	30965	30507	33118	33159	7.1	8.7
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	75834	52477	60536	61172	-19.3	16.6
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	202949	176120	175174	171479	-15.5	-2.6
1.9.1 उर्वरक	49066	34080	34167	36560	-25.5	7.3
1.9.2 औषधि और दवाइयां	53427	48873	50111	48477	-9.3	-0.8
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	42233	39743	35851	35172	-16.7	-11.5
1.9.4 अन्य	58223	53424	55045	51270	-11.9	-4.0
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	50415	46919	49187	47580	-5.6	1.4
1.11 कांच और कांच के सामान	8777	8687	8989	8748	-0.3	0.7
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	58689	60587	58324	57789	-1.5	-4.6
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	350325	351144	343016	337746	-3.6	-3.8
1.13.1 लोहा और स्टील	262396	268259	252654	247448	-5.7	-7.8
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	87929	82885	90362	90298	2.7	8.9
1.14 सभी अभियांत्रिकी	157259	166861	140249	137361	-12.7	-17.7
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	30159	35706	27706	27146	-10.0	-24.0
1.14.2 अन्य	127100	131155	112543	110215	-13.3	-16.0
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	82606	82552	90109	88400	7.0	7.1
1.16 रत्न और आभूषण	59515	62792	55619	57374	-3.6	-8.6
1.17 निर्माण	104288	99394	104600	104447	0.2	5.1
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1053913	1019784	1015238	999104	-5.2	-2.0
1.18.1 पावर	559774	559953	551886	552553	-1.3	-1.3
1.18.2 दूरसंचार	143760	127493	114825	100969	-29.8	-20.8
1.18.3 सड़क	190676	185424	198304	197379	3.5	6.4
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	159703	146914	150223	148203	-7.2	0.9
1.19 अन्य उद्योग	239266	222620	222123	223540	-6.6	0.4

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

I मद्	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2019-20	2019		2020					
		सितं. 27	जुला. 03	जुला. 17	जुला. 31	अग. 14	अग. 28	सितं. 11	सितं. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	31	31	31	31	31	31	31
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	124101.8	63866.3	126452.9	127076.2	126359.1	125939.1	126547.5	126582.5	126143.1
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	26213.8	19061.0	25074.2	25271.3	24479.1	24074.5	24751.6	24479.0	22274.4
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5295.0	5430.9	4876.4	4823.2	4000.0	3821.7	3773.1	3873.1	4189.6
2.1.1.2 अन्य	14,523.6	10077.7	13533.9	13870.4	13837.0	13677.4	14264.3	14492.2	13472.0
2.1.2 बैंकों से उधार	100.0	20.0	0.0	0.0	268.7	135.0	264.9	209.9	229.9
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	6295.2	3532.4	6663.9	6577.6	6373.3	6440.4	6449.2	5903.7	4382.9
2.2 मीयादी देयताएं	167684.5	108182.2	176605.2	176793.3	174061.7	172745.5	171640.9	171314.7	172128.5
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	56564.0	53432.8	62166.3	61276.4	59247.7	58983.7	57209.2	57723.3	56835.6
2.2.1.2 अन्य	109578.2	53788.6	112919.0	113205.8	112522.0	112261.6	112283.2	112090.2	112671.1
2.2.2 बैंकों से उधार	630.2	0.0	629.9	629.9	629.9	629.9	629.9	629.9	673.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	912.1	960.7	890.0	1681.1	1662.1	870.2	1518.6	871.2	1948.9
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	52772.2	45028.6	55890.4	56131.0	57274.5	57354.0	53795.3	56629.9	57927.2
4.1 मांग	13764.4	13568.4	12098.1	12152.6	14236.6	14067.2	13174.5	13809.3	14065.7
4.2 मीयादी	39007.8	31460.2	43792.3	43978.5	43037.9	43286.7	40620.8	42820.6	43861.5
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	9428.2	5497.1	6999.4	7149.1	7112.2	6875.5	6841.4	6879.6	7000.4
5.1 उपलब्ध नकदी	750.5	296.4	685.9	677.3	552.6	572.4	592.3	575.6	555.1
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	8677.8	5200.8	6313.4	6471.7	6559.6	6303.2	6249.1	6304.0	6445.3
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1521.7	874.6	1049.6	1134.0	965.4	809.9	807.4	983.9	988.1
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	50626.9	31887.1	55424.4	55598.4	56888.2	58199.1	55743.6	56942.0	59312.3
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	25283.9	20119.8	29114.7	28181.5	25336.5	25269.1	25414.9	27749.8	26346.6
9 बैंक ऋण (10.1+11)	110905.5	63753.9	110067.3	111344.7	112074.1	112631.8	113285.8	112267.8	111857.3
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	110901.5	63752.8	110066.6	111344.0	112073.4	112631.2	113285.2	112252.0	111841.4
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	81300.1	74965.4	80854.4	81068.7	80109.4	79793.4	77827.8	79526.6	79397.4
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	4.0	1.1	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	15.7	15.9

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2019-20			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	अक्टू.'19	सितं.'20	अक्टू.'20(अ)	अक्टू.'19	सितं.'20	अक्टू.'20(अ)	अक्टू.'19	सितं.'20	अक्टू.'20(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	146.3	149.6	147.5	148.3	159.6	163.3	151.9	164.4	167.4	149.6	161.4	164.8
1.1 अनाज और उत्पाद	140.7	143.2	141.4	141.0	146.0	145.1	143.5	150.6	149.8	141.8	147.5	146.6
1.2 मांस और मछली	163.3	161.4	162.6	161.6	186.3	188.8	159.8	193.7	195.4	161.0	188.9	191.1
1.3 अंडा	142.1	145.7	143.5	141.2	159.2	171.6	144.7	164.8	177.0	142.6	161.4	173.7
1.4 दूध और उत्पाद	146.5	146.0	146.3	146.5	153.6	153.8	145.6	153.7	153.9	146.2	153.6	153.8
1.5 तेल और चर्बी	127.1	121.8	125.1	125.6	142.6	145.4	121.1	135.7	138.0	123.9	140.1	142.7
1.6 फल	144.0	148.8	146.2	145.7	147.2	146.6	150.6	155.7	150.7	148.0	151.2	148.5
1.7 सब्जी	163.5	187.8	171.7	178.8	200.6	221.8	207.2	226.0	248.3	188.4	209.2	230.8
1.8 दाल और उत्पाद	133.7	132.0	133.1	133.1	150.3	155.9	131.2	152.2	158.7	132.5	150.9	156.8
1.9 चीनी और उत्पाद	112.0	113.4	112.5	113.6	115.3	114.8	114.8	118.1	117.2	114.0	116.2	115.6
1.10 मसाले	145.6	145.1	145.5	145.5	160.9	161.9	145.2	161.3	161.5	145.4	161.0	161.8
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	138.8	130.2	135.2	138.6	147.4	150.0	130.2	139.2	141.5	135.1	144.0	146.5
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	157.6	156.7	157.2	157.4	161.9	162.7	156.8	164.8	165.1	157.1	163.2	163.8
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	166.3	169.0	167.0	166.3	182.7	183.5	169.3	188.7	188.9	167.1	184.3	184.9
3 कपड़ा और जूते	151.3	143.7	148.3	151.0	155.0	155.6	143.9	148.3	148.8	148.2	152.3	152.9
3.1 कपड़ा	152.0	145.7	149.5	151.7	155.7	156.4	145.9	150.5	151.0	149.4	153.7	154.3
3.2 जूते	146.9	132.4	140.9	146.7	150.6	151.0	132.4	136.1	136.4	140.8	144.6	144.9
4 आवास	--	152.2	152.2	--	--	--	153.0	156.5	158.0	153.0	156.5	158.0
5 ईंधन और लाइट	148.6	131.5	142.2	147.7	146.8	147.7	128.9	137.1	137.4	140.6	143.1	143.8
6 विविध	145.6	135.9	140.9	145.7	154.3	154.5	136.0	146.2	146.6	141.0	150.4	150.7
6.1 घरेलू सामान और सेवा	150.6	138.7	145.0	150.6	152.0	152.7	138.7	145.1	145.1	145.0	148.7	149.1
6.2 स्वास्थ्य	153.6	142.1	149.3	153.7	159.5	160.4	142.4	151.0	152.0	149.4	156.3	157.2
6.3 परिवहन और संचार	132.6	122.2	127.1	131.7	146.4	146.1	121.5	135.4	135.3	126.3	140.6	140.4
6.4 मनोरंजन	148.3	135.9	141.3	148.7	152.4	153.4	136.2	142.0	144.3	141.7	146.5	148.3
6.5 शिक्षा	159.8	150.9	154.5	160.7	162.5	161.7	151.7	155.7	156.4	155.4	158.5	158.6
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	139.2	138.4	138.9	140.3	156.2	156.1	139.5	158.1	158.0	140.0	157.0	156.9
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	147.3	145.1	146.3	148.3	157.5	159.7	146.0	155.2	156.8	147.2	156.4	158.4

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अर्न्तम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2019-20	2020		
				अक्टू.	सितं.	अक्टू.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	--	--	118.1	119.5
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	980	987	1037	1052
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	--	986	993	1043	1057

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2019-20	2019		2020	
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	सितं.
	1	2	3	4	
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	37018	38214	50784	50698	
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	42514	45578	63337	61320	

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			अक्टू.	अग.	सितं. (अ)	अक्टू. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	121.8	122.0	122.0	122.9	123.8
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	143.3	145.5	146.7	150.3	152.4
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	155.8	160.2	163.0	168.1	170.4
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.6	160.8	159.7	158.3	158.1
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	174.7	194.2	187.6	210.0	222.3
1.1.1.3 दूध	4.440	146.7	146.2	152.3	153.8	154.3
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	147.0	145.6	153.4	150.7	148.0
1.1.1.5 मसाले	0.529	143.9	148.8	143.8	149.1	153.0
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.0	142.9	169.9	172.1	167.0
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	128.7	126.1	125.5	126.7	129.7
1.1.2.1 फाइबर	0.839	128.2	126.4	106.9	121.2	114.2
1.1.2.2 तिलहन	1.115	151.4	151.4	155.8	155.5	158.0
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	104.8	103.1	104.8	104.6	109.6
1.1.2.4 फूल	0.204	238.0	207.4	235.2	203.4	231.7
1.1.3 खनिज	0.833	154.5	153.6	167.6	166.5	167.6
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	147.4	147.3	162.6	160.6	162.6
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	179.0	176.0	185.1	187.0	185.1
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	85.3	82.8	72.2	72.0	72.0
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	102.2	102.3	92.0	91.0	91.1
1.2.1 कोल	2.138	125.3	126.5	126.4	126.4	126.4
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	138.1	141.9	141.6	141.6	141.6
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	129.1	131.1	131.1	131.1	131.1
1.2.2 खनिज तेल	7.950	92.3	92.8	78.4	77.7	76.2
1.2.3 बिजली	3.064	111.8	110.0	103.4	101.0	105.3
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	118.3	117.8	119.4	119.8	120.3
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	133.9	134.6	139.8	140.0	140.7
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.5	139.6	138.1	138.0	136.9
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	136.1	139.3	140.1	146.1	136.3
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	113.5	119.9	119.7	118.4
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	119.3	116.6	134.1	136.7	140.5
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	145.0	145.8	145.6	145.3	145.7
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	146.3	148.3	144.4	143.7	142.9
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	135.5	136.8	107.7	106.6	107.5
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	133.5	133.3	137.5	137.8	137.9
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	118.3	119.9	120.1	119.7	118.6
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	127.2	128.5	127.5	127.5	127.8
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.7	135.8	134.4	132.4	131.3
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	139.7	142.8	189.7	179.5	183.9
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	132.4	134.4	146.0	146.0	145.8
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	128.7	126.7	132.6	134.0	130.7
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	159.9	167.5	146.8	143.2	141.9
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	173.6	180.1	168.5	171.1	170.0
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	123.6	123.2	125.3	124.6	123.8
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	117.8	117.9	120.3	120.2	120.2
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	125.7	126.4	128.8	127.1	124.8
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	130.5	128.6	129.9	129.0	128.5
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	153.4	154.4	153.0	157.9	155.3
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	153.4	154.4	153.0	157.9	155.3

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			अक्टू.	अग.	सितं. (अ)	अक्टू. (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.7	117.3	113.0	113.4	114.7
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	107.9	107.4	100.3	101.2	102.3
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	130.1	129.3	128.5	127.8	129.9
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	114.5	115.2	115.1	114.6	113.8
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	134.5	135.2	131.3	131.0	130.8
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	143.1	143.0	148.8	154.8	155.6
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.8	117.8	114.4	114.5	115.5
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.3	138.4	137.5	138.1	138.2
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.2	138.9	137.2	137.8	137.1
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	135.9	136.8	138.3	138.8	141.1
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	118.6	118.5	118.1	118.1	118.0
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	105.5	105.5	102.5	102.4	102.8
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	136.3	136.4	139.0	138.4	138.6
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.3	120.0	120.1	120.3	119.9
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	133.7	133.7	133.6	134.6	133.5
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	122.2	120.9	119.2	118.4	120.3
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	135.5	135.8	135.4	136.6	134.7
1.3.7.3 बिल्डरों की बढईगीरी	0.036	176.2	176.1	188.0	188.2	189.6
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.7	125.9	124.8	127.5	125.5
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	121.1	120.1	119.0	119.8	119.2
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	125.0	123.0	120.6	121.6	120.6
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	115.0	114.7	119.3	119.9	120.9
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	121.2	120.9	116.1	116.8	115.0
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	150.6	152.1	152.7	155.1	155.2
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	150.6	152.1	152.7	155.1	155.2
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	117.5	117.1	116.1	116.0	116.8
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	119.9	118.9	115.0	114.7	115.2
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.1	122.9	123.7	123.2	123.1
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	112.4	112.1	112.4	112.7	115.5
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	122.6	123.0	125.3	124.8	125.8
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	114.7	113.8	112.7	114.0	114.3
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	118.6	118.4	119.6	119.3	120.0
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	114.2	113.7	113.2	112.7	112.9
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	97.9	97.3	88.1	88.4	89.4
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	127.3	126.8	130.7	129.2	131.0
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	127.3	126.8	130.7	129.2	131.0
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	108.5	108.4	107.6	108.7	109.7
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	98.0	97.4	97.7	97.9
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.5	94.1	91.7	91.7	90.8
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	115.4	115.5	115.0	116.7	118.3
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	116.7	115.4	116.6	116.8	116.5
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	124.5	121.0	126.3	128.3	127.6
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	108.7	109.3	107.7	108.9	109.0
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	102.8	102.5	107.0	107.5	107.5
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	113.9	112.7	106.9	107.9	108.0
1.3.13.5 सीमेन्ट, गूना और प्लास्टर	1.645	119.5	118.2	120.3	119.9	119.1

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
				अक्टू.	अग.	सितं. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेंट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.6	121.3	124.1	124.1	125.0
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	120.2	119.0	119.7	120.4	121.3
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	86.6	84.9	77.6	77.6	77.6
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	106.2	103.4	106.5	107.9	108.9
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	100.6	95.1	101.4	103.6	105.3
1.3.14.2 मेटेलिक आयसन	0.653	107.7	102.1	108.3	110.8	111.4
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	95.1	92.8	97.7	97.3	97.3
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	105.5	102.6	104.5	105.8	108.0
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	108.7	103.3	108.8	112.1	115.4
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	102.8	98.9	103.2	103.2	102.6
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	102.9	98.8	102.7	105.6	105.7
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.2	125.1	125.3	123.6	123.3
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	107.0	106.4	109.4	110.6	111.0
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	112.8	113.5	107.9	107.4	108.5
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	146.5	148.5	143.8	144.3	143.6
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.5	115.1	112.5	113.3	114.4
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	113.9	113.6	110.6	110.0	111.9
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	124.4	125.0	120.6	122.2	125.4
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	104.7	106.3	99.0	99.0	98.6
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	100.5	100.2	95.6	99.6	96.3
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	100.5	100.5	102.1	102.5	102.6
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	124.0	121.9	122.5	122.9	123.9
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	110.4	109.8	109.5	109.1	108.9
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	98.1	98.3	99.0	96.8	98.8
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.0	135.1	135.1	135.1	135.2
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	117.0	117.5	114.2	114.3	113.8
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	98.8	97.2	98.0	97.9	96.5
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	111.5	110.3	106.0	106.1	106.1
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	139.1	138.7	142.8	142.9	142.6
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.6	102.5	103.0	103.0	101.6
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	110.2	109.4	108.8	111.2	102.0
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	111.3	111.2	111.7	112.2	112.5
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	109.0	108.5	111.0	112.5	111.7
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.0	117.0	116.8	116.9	119.0
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	109.9	108.4	94.3	93.3	94.0
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	109.7	110.0	112.6	113.3	114.0
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	112.6	110.9	110.0	110.7
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.9	120.5	118.6	118.6	119.0
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	107.6	108.4	107.3	109.0
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	113.1	112.7	113.7	113.7	113.9
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	104.8	103.4	105.5	104.4	105.9
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.9	120.2	119.4	119.6	119.9
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.2	111.0	112.4	111.2	111.1
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गैयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	110.1	109.9	109.6	111.8	111.2
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	80.0	80.1	81.6	81.9	82.0
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	111.5	110.8	113.2	113.3	113.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			अक्टू.	अग.	सितं. (अ)	अक्टू. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	130.9	130.2	128.3	127.8	129.7
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	120.6	121.3	121.5	121.7	121.2
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.1	107.9	107.7	108.7	107.9
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.1	74.2	75.6	75.2	75.0
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	125.2	125.7	128.5	128.3	128.6
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.7	117.7	122.2	122.3	122.4
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	126.3	126.2	127.5	128.9	128.8
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	66.0	65.8	64.3	64.4	64.3
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	114.5	114.7	117.5	117.5	117.3
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	115.2	115.2	118.5	118.5	119.2
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	113.7	114.2	116.4	116.4	115.3
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	118.0	118.0	125.9	126.3	126.7
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	106.4	106.6	105.8	105.8	104.7
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	114.3	114.4	124.5	124.9	125.6
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	128.9	128.1	127.9	128.9	128.2
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	126.1	125.9	127.5	127.5	127.7
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	130.9	131.6	128.9	129.5	132.9
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	130.9	131.6	128.9	129.5	132.9
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	112.7	116.7	138.2	136.1	134.8
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	109.9	114.1	136.8	134.5	133.2
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.0	166.4	172.6	163.0	166.4
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	129.7	129.8	131.0	131.1	131.0
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	136.9	135.9	141.4	142.6	142.9
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	162.1	162.5	167.5	166.9	168.1
2 खाद्य सूचकांक	24.378	147.6	150.6	154.3	157.6	159.3

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2018-19	2019-20	अप्रैल-सितंबर		सितंबर	
				2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	130.1	129.0	128.7	101.6	122.9	123.2
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	107.9	109.6	100.5	85.1	86.4	87.6
1.2 विनिर्माण	77.63	131.5	129.6	129.9	99.2	126.0	125.3
1.3 बिजली	7.99	156.9	158.4	168.1	154.6	158.7	166.4
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	126.1	127.0	124.9	107.1	113.8	112.1
2.2 पूंजीगत माल	8.22	108.4	93.3	95.7	56.9	91.4	88.4
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	126.2	137.7	134.9	103.4	134.1	132.2
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	141.7	136.6	136.5	101.5	127.6	128.5
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	130.4	119.0	126.0	76.7	122.5	125.9
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.5	145.3	143.8	132.6	144.0	149.9

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-अक्टूबर			
	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	2019-20 (वास्तविक)	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2020-21	2019-20
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्ति	2020926	691903	907634	34.2	46.2
1.1 कर राजस्व (निवल)	1635909	575697	683486	35.2	41.4
1.2 करेतर राजस्व	385017	116206	224148	30.2	71.6
2 पूंजीगत प्राप्ति	224967	16397	26826	7.3	22.4
2.1 ऋण की वसूली	14967	10218	9461	68.3	63.8
2.2 अन्य प्राप्ति	210000	6179	17365	2.9	16.5
3 कुल प्राप्ति (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	2245893	708300	934460	31.5	44.9
4 राजस्व व्यय	2630145	1464099	1453632	55.7	59.4
4.1 ब्याज भुगतान	708203	333456	289565	47.1	43.8
5 पूंजी व्यय	412085	197355	201273	47.9	59.4
6 कुल व्यय (4+5)	3042230	1661454	1654905	54.6	59.4
7 राजस्व घाटा (4-1)	609219	772196	545998	126.8	112.6
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	796337	953154	720445	119.7	102.4
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	88134	619698	430880	703.1	995.4

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2020-21

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वाभित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2019-20	2019		2020				
		नवें. 1	सितं. 25	अक्टू. 2	अक्टू. 9	अक्टू. 16	अक्टू. 23	अक्टू. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	10165	18346	13536	9530	3640	3105	2885	2540
1.2 प्राथमिक व्यापारी	9190	15582	32019	24382	17211	15438	12884	15647
1.3 राज्य सरकारें	8173	73754	55395	49395	58030	63945	68665	70665
1.4 अन्य	48004	79312	127184	126234	135425	134863	134685	128809
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	66419	75756	181537	169429	163138	154693	152639	152250
2.2 प्राथमिक व्यापारी	43302	34123	65936	61973	56336	58086	57664	61725
2.3 राज्य सरकारें	13386	6419	4323	4323	3738	3753	4033	4033
2.4 अन्य	22465	27804	114302	118894	125604	126706	118301	101876
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	49660	62969	133861	133627	136507	134757	136500	135642
3.2 प्राथमिक व्यापारी	70672	60381	125921	123522	120865	126272	124833	129471
3.3 राज्य सरकारें	11945	17930	16502	16502	16792	16862	15842	15842
3.4 अन्य	70576	56950	122943	122855	123033	120230	122816	119782
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	155112	88365	102540	92390	80723	76585	117945	116438
4.4 अन्य	617	1547	604	831	519	308	392	392
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	423957	529327	993460	960667	960318	958709	951749	938281

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)		
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या				कुल अंकित मूल्य	
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2020-21										
सितं. 23	12000	84	29965	12332	41	11997	12332	24330	99.17	3.3578
अक्टू. 7	9000	87	44438	13006	32	8994	13006	22000	99.19	3.2754
अक्टू. 14	9000	104	51867	11053	38	8997	11053	20050	99.20	3.2489
अक्टू. 21	9000	85	55599	7053	21	8997	7053	16050	99.21	3.1878
अक्टू. 28	9000	88	38386	8053	39	8997	8053	17050	99.21	3.1972
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2020-21										
सितं. 23	13000	101	33086	6	63	12994	6	13000	98.25	3.5779
अक्टू. 7	3000	108	33408	1	5	2999	1	3000	98.32	3.4195
अक्टू. 14	3000	105	28977	0	12	3000	0	3000	98.34	3.3799
अक्टू. 21	3000	69	28284	0	12	3000	0	3000	98.36	3.3501
अक्टू. 28	3000	59	17305	0	26	3000	0	3000	98.35	3.3594
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2020-21										
सितं. 23	10000	81	24373	0	50	10000	0	10000	96.41	3.7312
अक्टू. 7	4000	88	22127	290	5	4000	290	4290	96.62	3.5092
अक्टू. 14	4000	71	23441	0	5	4000	0	4000	96.65	3.4751
अक्टू. 21	4000	54	19345	0	16	4000	0	4000	96.67	3.4595
अक्टू. 28	4000	69	13985	0	33	4000	0	4000	96.67	3.4542

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1	2	2
अक्टू.	1, 2020	1.80-3.90	3.40
अक्टू.	3, 2020	2.50-3.30	2.67
अक्टू.	5, 2020	1.80-4.00	3.41
अक्टू.	6, 2020	1.80-3.90	3.43
अक्टू.	7, 2020	1.80-3.90	3.44
अक्टू.	8, 2020	1.80-3.90	3.43
अक्टू.	9, 2020	1.50-3.90	3.39
अक्टू.	12, 2020	1.80-3.90	3.41
अक्टू.	13, 2020	1.80-3.90	3.39
अक्टू.	14, 2020	1.80-3.90	3.41
अक्टू.	15, 2020	1.80-3.85	3.40
अक्टू.	16, 2020	1.80-3.85	3.34
अक्टू.	17, 2020	2.50-3.30	2.69
अक्टू.	19, 2020	1.80-3.80	3.36
अक्टू.	20, 2020	1.80-3.80	3.35
अक्टू.	21, 2020	1.80-3.50	3.21
अक्टू.	22, 2020	1.80-3.50	3.14
अक्टू.	23, 2020	1.50-3.50	3.21
अक्टू.	26, 2020	1.80-3.50	3.21
अक्टू.	27, 2020	1.80-3.55	3.15
अक्टू.	28, 2020	1.80-3.50	3.20
अक्टू.	29, 2020	1.80-3.60	3.22
अक्टू.	31, 2020	2.50-4.00	3.58
नवंबर	2, 2020	1.80-3.45	3.17
नवंबर	3, 2020	1.80-3.50	3.18
नवंबर	4, 2020	1.80-3.45	3.15
नवंबर	5, 2020	1.80-3.45	3.15
नवंबर	6, 2020	1.75-3.50	3.17
नवंबर	7, 2020	2.45-3.90	3.61
नवंबर	9, 2020	1.80-3.50	3.20
नवंबर	10, 2020	1.80-3.50	3.13
नवंबर	11, 2020	1.80-3.50	3.18
नवंबर	12, 2020	1.80-3.45	3.18
नवंबर	13, 2020	1.80-3.50	3.21

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2019		2020		
	अक्टू. 25	सितं. 11	सितं. 25	अक्टू. 9	अक्टू. 23
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	171396.00	87710.00	75570.00	74825.00	78340.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	4406.72	617.75	6492.55	876.88	4634.88
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	5.33-7.28	4.07-4.40	3.51-5.75	3.53-5.75	3.65-4.25

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2019		2020		
	अक्टू. 31	सितं. 15	सितं. 30	अक्टू. 15	अक्टू. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	462308.75	418270.55	362310.10	395015.55	380112.20
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	80459.45	106924.35	86727.40	81950.20	40838.65
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	5.03-14.08	3.10-8.87	3.32-11.86	3.25-11.94	3.19-14.19

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2019-20	2019	2020					
		नवं. 1	सितं. 25	अक्टू. 2	अक्टू. 9	अक्टू. 16	अक्टू. 23	अक्टू. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	26815	18807	20575	16084	19586	20132	13824	10675
2 नोटिस मुद्रा	3660	5927	382	6150	323	4399	804	4481
3 मीयादी मुद्रा	790	680	857	399	942	426	816	545
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	300691	355067	310900	358058	285175	396264	336437	397522
5 बाजार रिपो	221719	229569	309908	413981	369855	447695	313102	350328
6 कापरेट बांड में रिपो	2468	1270	4666	2525	4120	9400	3099	5545
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	70784	52906	64764	50786	41953	46714	56477
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	93960	46843	44251	49417	40590	84843	59684	91127
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5800	2596	3902	6628	6404	6259	4546	4932
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3720	1093	13686	11182	7424	5547	5238	5243
10.2 182-दिवसीय	2380	1785	6978	9720	3399	7254	2112	4644
10.3 364-दिवसीय	2900	1865	1373	1955	5209	1720	2841	2662
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	2310							
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	111070	54183	70190	78901	63026	105624	74420	108608
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	-	3	2059	3570	6088	4334	3265	429

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2019-20		2019-20 (अप्रै.-अक्टू.)		2020-21 (अप्रै.-अक्टू.)*		अक्टू. 2019		अक्टू. 2020*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	72	64926	48	59331	39	80719	6	333	15	3837
1ए प्रीमियम	70	43259	47	37967	39	77315	5	283	15	3747
1.1 पब्लिक	57	9867	37	8076	25	20175	4	98	12	3284
1.1.1 प्रीमियम	55	9434	36	7929	25	17540	3	78	12	3224
1.2 राइट्स	15	55059	11	51255	14	60544	2	235	3	553
1.2.1 प्रीमियम	15	33825	11	30038	14	59775	2	205	3	524
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	34	14984	23	8766	7	1332	3	973	1	300
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	34	14984	23	8766	7	1332	3	973	1	300
3.1.1 पब्लिक	34	14984	23	8766	7	1332	3	973	1	300
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	106	79910	71	68097	46	82050	9	1306	16	4137
4.1 पब्लिक	91	24851	60	16842	32	21507	7	1071	13	3584
4.2 राइट्स	15	55059	11	51255	14	60544	2	235	3	553

टिप्पणी: अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2019-20	2019		2020			
			अक्टू.	जून	जुला.	अग.	सित्त.	अक्टू.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	2219854	186358	166384	177954	170329	202583	182846
	मिलियन अमरीकी डॉलर	313361	26233	21972	23729	22810	27569	24891
1.1 तेल	करोड ₹	292340	24467	14318	13146	14292	26511	12134
	मिलियन अमरीकी डॉलर	41289	3444	1891	1753	1914	3608	1652
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1927514	161892	152067	164808	156037	176072	170712
	मिलियन अमरीकी डॉलर	272072	22789	20081	21976	20896	23961	23239
2 आयात	करोड ₹	3360954	269853	161447	213563	220087	222699	246857
	मिलियन अमरीकी डॉलर	474709	37986	21320	28478	29474	30307	33605
2.1 तेल	करोड ₹	925168	69111	37618	48990	48092	42808	43935
	मिलियन अमरीकी डॉलर	130550	9729	4968	6533	6441	5826	5981
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2435787	200742	123830	164574	171994	179892	202921
	मिलियन अमरीकी डॉलर	344159	28258	16352	21945	23033	24481	27624
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1141100	-83495	4937	-35610	-49758	-20116	-64011
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-161348	-11753	652	-4748	-6664	-2738	-8714
3.1 तेल	करोड ₹	-632828	-44645	-23300	-35844	-33800	-16297	-31801
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-89262	-6284	-3077	-4780	-4526	-2218	-4329
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-508273	-38850	28237	234	-15958	-3819	-32209
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-72087	-5469	3729	31	-2137	-520	-4385

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2019	2020					
			नव. 15	अक्टू. 9	अक्टू. 16	अक्टू. 23	अक्टू. 30	नव. 6
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड ₹	3219968	4034267	4071872	4126040	4155181	4218823	4274151
	मिलियन अमरीकी डॉलर	448249	551505	555120	560532	560715	568494	572771
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	2991738	3721726	3757930	3809474	3841209	3894208	3956961
	मिलियन अमरीकी डॉलर	416472	508783	512322	517524	518339	524742	530268
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	191868	267715	269084	271325	268701	278941	271280
	मिलियन अमरीकी डॉलर	26709	36598	36685	36860	36259	37587	36354
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1046	1048	1048	1048	1048	1048	1049
	करोड ₹	10309	10826	10855	10949	10980	11046	11103
	मिलियन अमरीकी डॉलर	1435	1480	1480	1487	1482	1488	1488
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	26053	34000	34003	34292	34291	34628	34807
	मिलियन अमरीकी डॉलर	3633	4644	4634	4661	4636	4676	4661

* अंतर, यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2019-20	2019	2020		2019-20	2020-21
		अक्टू.	सित्त.	अक्टू.	अप्रै.-अक्टू.	अप्रै.-अक्टू.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130581	133720	137293	137959	6045	5989
1.1 एफसीएनआर (बी)	24244	24710	22291	21955	1540	-2289
1.2 एनआर (ई) आरए	90367	93045	98101	98992	3376	7434
1.3 एनआरओ	15969	15965	16901	17012	1128	844

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2019-20	2019-20	2020-21	2019	2020	
		अप्रै.-अक्टू.	अप्रै.-अक्टू.	अक्टू.	सितं.	अक्टू.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	43013	23953	27494	2646	2380	4627
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	56006	31651	32870	4064	3257	5109
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	74390	42062	46822	6016	4282	6871
1.1.1.1.1 इक्विटी	51734	30109	36232	3330	3021	5451
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	3265	2925	217	61	2	45
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	39364	22604	31244	2496	2373	4357
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7348	3778	3873	654	531	929
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1757	802	898	120	116	120
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	14175	8009	8617	1197	1155	1197
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	8482	3944	1973	1489	107	224
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	18384	10411	13952	1952	1026	1763
1.1.1.2.1 इक्विटी	18212	10319	13928	1916	1024	1754
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	173	92	24	36	2	9
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	12993	7698	5376	1418	876	481
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	7572	4373	2767	1077	419	553
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3151	1838	1846	263	263	263
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5674	2856	2712	288	1029	487
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3403	1369	1949	209	834	821
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	1403	9899	10853	2580	-748	2943
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	552	9843	11120	2682	-332	2998
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	-851	-56	267	101	416	55
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	44417	33852	38347	5226	1632	7571

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2019-20	2019	2020		
		अक्टू.	अग.	सितं.	अक्टू.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	18760.69	1523.77	1156.62	1648.17	938.37
1.1 जमाराशियां	623.37	39.57	46.55	123.46	23.34
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	86.43	8.65	5.85	8.26	3.85
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	431.41	38.80	27.37	73.61	22.80
1.4 उपहार	1907.71	148.39	124.99	225.36	108.89
1.5 दान	22.33	0.71	0.68	0.61	1.29
1.6 यात्रा	6955.98	578.97	303.21	358.12	272.98
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3439.74	256.77	232.86	416.70	162.64
1.8 चिकित्सा उपचार	33.90	3.18	1.65	2.51	3.66
1.9 विदेश में शिक्षा	4991.07	432.66	405.48	427.87	333.45
1.10 अन्य	268.75	16.08	7.98	11.68	5.47

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2018-19	2019-20	2019	2020	
			नवंबर	अक्टूबर	नवंबर
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	72.64	73.28	72.69	70.67	69.33
1.2 रीर	114.01	116.75	117.42	119.25	116.99
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	74.18	74.33	73.68	71.90	70.66
2.2 रीर	116.32	119.61	120.24	123.13	121.01
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	63.07	63.59	63.28	59.58	58.53
1.2 रीर	121.70	125.76	126.69	126.65	124.46
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	92.88	93.63	93.18	87.74	86.20
2.2 रीर	94.20	97.32	98.07	98.04	96.34

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

मद	2019-20	2019	2020	
		अक्टू.	सित.	अक्टू.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1292	100	99	76
1.2 राशि	38011	2877	5223	1733
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	41	2	-	1
2.2 राशि	14921	538	-	300
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1333	102	99	77
3.2 राशि	52932	3415	5223	2033
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.00	5.30	3.32	3.62
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.34	1.46	1.66	1.25
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-25.00	0.00-10.50	0.00-11.00	0.00-9.00

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	अप्रैल-जून 2019			अप्रैल-जून 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	299344	285360	13984	249201	229355	19846
1 चालू खाता (1.1+1.2)	160681	175686	-15004	122408	102634	19774
1.1 पण्य	82707	129481	-46774	52308	62326	-10017
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	77974	46204	31769	70100	40309	29791
1.2.1 सेवाएं	52196	32120	20075	46807	26304	20503
1.2.1.1 यात्रा	6950	6203	747	1848	2757	-909
1.2.1.2 परिवहन	5343	6104	-761	4866	4216	649
1.2.1.3 बीमा	588	409	179	565	378	186
1.2.1.4 जीएनआईई	151	307	-155	148	330	-182
1.2.1.5 विविध	39164	19098	20066	39380	18622	20758
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	22811	1812	20998	22622	1849	20773
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	11475	11715	-239	11282	11514	-232
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1287	519	769	1009	1062	-52
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	700	284	415	707	304	403
1.2.2 अंतरण	19963	1999	17964	18223	1237	16986
1.2.2.1 आधिकारिक	35	295	-260	27	258	-231
1.2.2.2 निजी	19928	1705	18224	18196	979	17217
1.2.3 आय	5815	12085	-6270	5070	12768	-7698
1.2.3.1 निवेश आय	4463	11446	-6983	3706	12098	-8392
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1352	639	713	1364	669	695
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	138298	109674	28624	126793	126241	552
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	88733	69898	18835	74487	74237	250
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	21555	7563	13993	11973	12365	-392
2.1.1.1 भारत में	21171	3976	17194	11829	9735	2094
2.1.1.1.1 इक्विटी	16665	3957	12708	6993	9725	-2732
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3349		3349	3957		3957
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1157	19	1138	879	10	869
2.1.1.2 विदेश में	384	3586	-3202	144	2630	-2486
2.1.1.2.1 इक्विटी	384	1592	-1208	144	1117	-972
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	788	-788	0	796	-796
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1206	-1206	0	718	-718
2.1.2 संविभाग निवेश	67178	62335	4843	62514	61872	642
2.1.2.1 भारत में	67073	61916	5156	61869	60772	1098
2.1.2.1.1 एफआईआई	67073	61916	5156	61869	60772	1098
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	50491	47378	3112	52749	48334	4414
2.1.2.1.1.2 ऋण	16582	14538	2044	9121	12437	-3317
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	105	419	-314	644	1100	-456
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	22209	12648	9561	18508	16227	2281
2.2.1 बाह्य सहायता	3018	1550	1468	5735	1645	4090
2.2.1.1 भारत द्वारा	2	29	-27	2	27	-26
2.2.1.2 भारत को	3016	1521	1495	5733	1618	4116
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	9763	3660	6103	3756	5369	-1613
2.2.2.1 भारत द्वारा	881	742	140	442	1003	-562
2.2.2.2 भारत को	8881	2918	5963	3315	4366	-1051
2.2.3 भारत को अल्पावधि	9428	7438	1990	9017	9213	-196
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	8028	7438	590	9017	8412	605
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	1400	0	1400	0	801	-801
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	17713	14280	3433	17690	15460	2230
2.3.1 वाणिज्य बैंक	17713	13897	3816	17690	14693	2997
2.3.1.1 आस्तियां	6339	3595	2744	6865	4383	2482
2.3.1.2 देयताएं	11375	10302	1072	10825	10310	515
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	10780	8026	2754	10653	7653	3000
2.3.2 अन्य	0	383	-383	0	767	-767
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	60	-60	0	55	-55
2.5 अन्य पूंजी	9643	12789	-3146	16108	20261	-4153
3 भूल-चूक	365	0	365	0	480	-480
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	13984	-13984	0	19846	-19846
4.1 आईएमएफ				0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)		13984	-13984		19846	-19846

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	अप्रैल-जून 2019			अप्रैल-जून 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2081832	1984578	97254	1890800	1740218	150582
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1117480	1221831	-104351	928766	778731	150034
1.1 पण्य	575199	900495	-325296	396887	472892	-76006
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	542281	321335	220945	531879	305839	226040
1.2.1 सेवाएं	363004	223387	139617	355144	199578	155566
1.2.1.1 यात्रा	48335	43139	5196	14024	20918	-6894
1.2.1.2 परिवहन	37157	42451	-5294	36918	31992	4926
1.2.1.3 बीमा	4088	2846	1242	4286	2872	1415
1.2.1.4 जीएनआईई	1052	2133	-1081	1123	2504	-1381
1.2.1.5 विविध	272372	132817	139554	298793	141293	157500
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	158639	12604	146036	171642	14027	157615
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	79808	81470	-1663	85604	87365	-1761
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	8953	3608	5346	7659	8056	-396
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4865	1976	2889	5364	2309	3055
1.2.2 अंतरण	138837	13904	124933	138268	9387	128881
1.2.2.1 आधिकारिक	242	2048	-1806	205	1959	-1754
1.2.2.2 निजी	138595	11855	126740	138063	7428	130635
1.2.3 आय	40440	84045	-43605	38467	96874	-58407
1.2.3.1 निवेश आय	31039	79602	-48563	28120	91796	-63677
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9401	4443	4958	10347	5077	5270
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	961814	762747	199067	962034	957847	4187
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	617107	486115	130992	565164	563268	1895
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	149908	52595	97313	90846	93819	-2973
2.1.1.1 भारत में	147234	27655	119579	89752	73864	15889
2.1.1.1.1 इक्विटी	115899	27522	88377	53061	73787	-20726
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	23291	0	23291	30021	0	30021
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	8045	133	7911	6671	77	6594
2.1.1.2 विदेश में	2673	24939	-22266	1094	19955	-18862
2.1.1.2.1 इक्विटी	2673	11075	-8402	1094	8472	-7378
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5478	-5478	0	6038	-6038
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	8386	-8386	0	5446	-5446
2.1.2 संविभाग निवेश	467199	433520	33679	474318	469449	4869
2.1.2.1 भारत में	466467	430607	35860	469430	461102	8328
2.1.2.1.1 एफआईआई	466467	430607	35860	469430	461102	8328
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	351144	329501	21644	400227	366734	33493
2.1.2.1.1.2 ऋण	115323	101107	14216	69203	94368	-25165
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	732	2913	-2181	4888	8347	-3459
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	154456	87960	66495	140429	123124	17305
2.2.1 बाह्य सहायता	20988	10780	10208	43513	12481	31031
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	201	-187	12	208	-197
2.2.1.2 भारत को	20974	10579	10395	43501	12273	31228
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	67896	25451	42446	28501	40739	-12238
2.2.2.1 भारत द्वारा	6131	5157	974	3350	7612	-4262
2.2.2.2 भारत को	61766	20294	41472	25151	33127	-7976
2.2.3 भारत को अल्पावधि	65571	51730	13841	68416	69904	-1488
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	55835	51730	4105	68416	63825	4591
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	9737	0	9737	0	6079	-6079
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	123189	99311	23878	134220	117303	16917
2.3.1 वाणिज्य बैंक	123189	96648	26540	134220	111481	22739
2.3.1.1 आस्तियां	44083	25000	19082	52088	33257	18831
2.3.1.2 देयताएं	79106	71648	7458	82132	78223	3908
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	74973	55820	19153	80826	58063	22763
2.3.2 अन्य	0	2662	-2662	0	5823	-5823
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	418	-418	0	419	-419
2.5 अन्य पूंजी	67063	88944	-21881	122221	153732	-31511
3 भूल-चूक	2538	0	2538	0	3640	-3640
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	97254	-97254	0	150582	-150582
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	97254	-97254	0	150582	-150582

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	अप्रैल-जून 2019			अप्रैल-जून 2020 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	160681	175657	-14977	122408	102610	19798
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	134903	161602	-26699	99115	88629	10486
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	82707	129481	-46774	52308	62326	-10017
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	82183	118031	-35848	52172	61638	-9466
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	524	0	524	137	0	137
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		11450	-11450	0	688	-688
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	52196	32120	20075	46807	26304	20503
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	33	18	14	77	6	71
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	45	413	-368	32	128	-97
1.अ.ख.3 परिवहन	5343	6104	-761	4866	4216	649
1.अ.ख.4 यात्रा	6950	6203	747	1848	2757	-909
1.अ.ख.5 निर्माण	754	754	0	659	625	34
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	588	409	179	565	378	186
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1287	519	769	1009	1062	-52
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	319	2091	-1771	399	1847	-1448
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	23604	2207	21397	23395	2269	21126
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	11475	11715	-239	11282	11514	-232
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	532	631	-99	500	347	153
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	151	307	-155	148	330	-182
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	1114	750	364	2026	823	1203
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	5815	12085	-6270	5070	12768	-7698
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1352	639	713	1364	669	695
1.आ.2 निवेश आय	3247	11246	-7999	3096	11916	-8820
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1607	4790	-3183	1349	7410	-6061
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	46	2503	-2457	24	1222	-1198
1.आ.2.3 अन्य निवेश	163	3938	-3774	66	3280	-3214
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1431	15	1415	1657	4	1653
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1216	200	1016	610	182	428
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	19963	1971	17992	18223	1212	17010
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	19928	1705	18224	18196	979	17217
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	19303	1217	18086	17596	739	16857
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	625	487	138	600	240	360
1.इ.2 सामान्य सरकार	34	266	-232	26	234	-207
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	87	909	-822	91	871	-780
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	11	824	-813	5	790	-786
2.2 पूँजी अंतरण	76	85	-9	86	81	5
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	138212	122778	15434	126703	145241	-18538
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	21555	7563	13993	11973	12365	-392
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	21171	3976	17194	11829	9735	2094
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	20014	3957	16057	10950	9725	1225
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	16665	3957	12708	6993	9725	-2732
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3349		3349	3957	0	3957
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1157	19	1138	879	10	869
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1157	19	1138	879	10	869
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	384	3586	-3202	144	2630	-2486
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	384	2380	-1996	144	1912	-1768
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	384	1592	-1208	144	1117	-972
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		788	-788	0	796	-796
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1206	-1206	0	718	-718
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1206	-1206	0	718	-718
3.2 संविभाग निवेश	67178	62335	4843	62514	61872	642
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	67073	61916	5156	61869	60772	1098
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	50491	47378	3112	52749	48334	4414
3.2.2 ऋण प्रतिभितियां	16582	14538	2044	9121	12437	-3317
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	105	419	-314	644	1100	-456
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	6703	5182	1521	11241	11303	-63
3.4 अन्य निवेश	42776	33714	9061	40975	39854	1121
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	10780	8409	2371	10653	8420	2233
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	383	-383	0	767	-767
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	10780	8026	2754	10653	7653	3000
3.4.2.3 सामान्य सरकार				0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र				0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	19714	11080	8633	16528	14054	2474
3.4.3अ भारत को ऋण	18830	10310	8520	16085	13024	3061
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	884	770	113	443	1031	-588
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	46	176	-131	40	47	-7
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	9428	7438	1990	9017	9213	-196
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	2808	6611	-3803	4737	8119	-3382
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	13984	-13984	0	19846	-19846
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण				0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए				0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए				0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	13984	-13984	0	19846	-19846
4. कुल आस्तियां / देयताएं	138212	122778	15434	126703	145241	-18538
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	77743	59493	18250	75768	72422	3346
4.2 ऋण लिखत	57661	42691	14971	46198	44853	1345
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	2808	20594	-17787	4737	27966	-23228
5. निवल भूल-चूक	365		365	0	480	-480

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोड़ ₹)

मद	अप्रैल-जून 2019			अप्रैल-जून 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	1117477	1221634	-104157	928760	778544	150216
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	938203	1123882	-185679	752031	672471	79560
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	575199	900495	-325296	396887	472892	-76006
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	571553	820866	-249314	395848	467673	-71825
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	3646	0	3646	1038	0	1038
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	79629	-79629	0	5219	-5219
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	363004	223387	139617	355144	199578	155566
1.अ.ख.1 अन्य के स्वाभिविक वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	227	127	100	588	45	542
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	312	2872	-2560	241	975	-733
1.अ.ख.3 परिवहन	37157	42451	-5294	36918	31992	4926
1.अ.ख.4 यात्रा	48335	43139	5196	14024	20918	-6894
1.अ.ख.5 निर्माण	5245	5244	1	5003	4743	260
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4088	2846	1242	4286	2872	1415
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	8953	3608	5346	7659	8056	-396
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	2221	14539	-12318	3026	14016	-10990
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	164158	15349	148809	177507	17215	160292
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	79808	81470	-1663	85604	87365	-1761
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3700	4390	-690	3792	2632	1160
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1052	2133	-1081	1123	2504	-1381
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	7747	5217	2529	15373	6247	9126
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	40440	84045	-43605	38467	96874	-58407
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9401	4443	4958	10347	5077	5270
1.आ.2 निवेश आय	22585	78213	-55628	23494	90414	-66921
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	11179	33314	-22134	10234	56223	-45989
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	321	17407	-17086	185	9273	-9088
1.आ.2.3 अन्य निवेश	1136	27386	-26250	500	24885	-24385
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	9949	107	9842	12574	34	12540
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	8454	1389	7065	4626	1382	3244
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	138835	13707	125128	138262	9200	129063
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तिय निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	138595	11855	126740	138063	7428	130635
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	134248	8465	125782	133511	5606	127905
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4347	3390	957	4553	1822	2731
1.इ.2 सामान्य सरकार	239	1852	-1612	199	1772	-1573
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	603	6322	-5719	690	6611	-5921
2.1 अनुत्पादित वित्तिय आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	76	5731	-5655	34	5996	-5961
2.2 पूँजी अंतरण	527	591	-64	656	615	41
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	961214	853875	107338	961350	1102005	-140655
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)	149908	52595	97313	90846	93819	-2973
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	147234	27655	119579	89752	73864	15889
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	139190	27522	111668	83082	73787	9295
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	115899	27522	88377	53061	73787	-20726
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	23291	0	23291	30021	0	30021
3.1.अ.2 ऋण लिखत	8045	133	7911	6671	77	6594
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	8045	133	7911	6671	77	6594
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	2673	24939	-22266	1094	19955	-18862
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	2673	16553	-13880	1094	14510	-13416
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	2673	11075	-8402	1094	8472	-7378
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5478	-5478	0	6038	-6038
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	8386	-8386	0	5446	-5446
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	8386	-8386	0	5446	-5446
3.2 संविभाग निवेश	467199	433520	33679	474318	469449	4869
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	466467	430607	35860	469430	461102	8328
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	351144	329501	21644	400227	366734	33493
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	115323	101107	14216	69203	94368	-25165
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	732	2913	-2181	4888	8347	-3459
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	46618	36037	10581	85289	85765	-476
3.4 अन्य निवेश	297489	234470	63019	310898	302390	8507
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	74973	58482	16490	80826	63886	16940
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	0	2662	-2662	0	5823	-5823
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	74973	55820	19153	80826	58063	22763
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईपीबी और बैंकिंग पूँजी)	137100	77059	60042	125407	106637	18770
3.4.3.अ भारत को ऋण	130956	71701	59255	122045	98817	23228
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	6145	5358	787	3361	7820	-4459
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	318	1226	-908	306	358	-53
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	65571	51730	13841	68416	69904	-1488
3.4.6 अन्य खाते प्राच्य/देय-अन्य	19527	45974	-26447	35943	61605	-25662
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	97254	-97254	0	150582	-150582
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	97254	-97254	0	150582	-150582
4. कुल आस्तियां / देयताएं	961214	853875	107338	961350	1102005	-140655
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	540675	413751	126924	574885	549501	25384
4.2 ऋण लिखत	401012	296897	104115	350523	340318	10205
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	19527	143227	-123700	35943	212187	-176244
5. निवल भूल-चूक	2538	0	2538	0	3640	-3640

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2019-20		2019		2020			
			जून		मार्च		जून	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	182957	418239	173165	417609	182957	418239	185442	419312
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	118442	395426	113118	399712	118442	395426	120210	395918
1.2 अन्य पूंजी	64515	22813	60047	17897	64515	22813	65233	23394
2 संविभाग निवेश	3847	246701	5012	266822	3847	246701	4303	241581
2.1 इक्विटी	602	134778	1806	151162	602	134778	824	138961
2.2 ऋण	3246	111923	3206	115660	3246	111923	3480	102621
3 अन्य निवेश	52422	427438	54140	429324	52422	427438	52489	432702
3.1 व्यापार ऋण	1460	104277	2121	107226	1460	104277	1233	103988
3.2 ऋण	6741	179767	9762	173725	6741	179767	7435	184385
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	26011	130761	24169	133846	26011	130761	27741	132942
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18210	12634	18089	14529	18210	12634	16080	11387
4 रिज़र्व्स	477807		429837		477807		505702	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	717033	1092378	662155	1113756	717033	1092378	747937	1093595
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-375345		-451601		-375345		-345658

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)					
	विव 2019-20	2019		2020		विव 2019-20	2019		2020	
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	सितं.		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
ए. निपटान प्रणाली										
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)										
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)			2.70	2.44			13397758	12416671		
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)			1.08	1.06			9021412	8849617		
1.1.1 आउटराइट			0.61	0.61			881023	900488		
1.1.2 रेपो			0.29	0.27			4115039	4108317		
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो			0.19	0.18			4025350	3840812		
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन			1.60	1.36			4238877	3435633		
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @			0.03	0.02			137470	131420		
बी. भुगतान प्रणाली										
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)										
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)			130.11	138.22			9489066	8496046		
1.1 ग्राहक लेनदेन			128.49	136.54			7993814	7226105		
1.2 इंटरबैंक लेनदेन			1.61	1.68			1495252	1269941		
II खुदरा										
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.7)			25506.62	28646.23			2817678	2993114		
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @			0.96	1.02			51	57		
2.2 एपीबीएस \$			1059.85	961.85			6243	5531		
2.3 आईएमपीएस			2796.08	3189.72			248662	274645		
2.4 एनएसीएच जमा \$			1179.79	1015.80			68176	91386		
2.5 एनईएफटी			2468.27	2761.65			2165515	2235389		
2.6 यूपीआई @			18001.67	20716.19			329032	386107		
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@			0.89	0.97			14	16		
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.4)			926.42	920.15			78240	79305		
3.1 भीम आधार पे @			15.28	10.55			205	192		
3.2 एनएसीएच नामे \$			857.43	848.34			77958	79022		
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @			53.71	61.26			77	91		
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)			5110.11	5863.58			126220	168169		
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)			1486.71	1718.03			51134	64652		
4.1.1 पीओएस आधारित \$			713.37	818.33			21986	26956		
4.1.2 अन्य \$			773.33	899.70			29148	37696		
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)			3623.40	4145.55			75086	103517		
4.2.1 पीओएस आधारित \$			1758.83	1983.98			30422	37110		
4.2.2 अन्य \$			1864.57	2161.57			44664	66408		
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)			4625.96	4589.96			16683	17802		
5.1 वॉलेट			3616.58	3631.45			13258	13696		
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)			1009.37	958.51			3425	4106		
5.2.1 पीओएस आधारित \$			32.50	37.11			910	1045		
5.2.2 अन्य \$			976.87	921.40			2515	3061		
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)			612.71	643.08			485243	524090		
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)			612.63	643.08			485114	524090		
6.2 अन्य			0.08	0.00			128	-		
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)			36781.81	40663.00			3524064	3782480		
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)			36911.91	40801.21			13013130	12278526		
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			36299.21	40158.13			12527887	11754436		

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)					
	वि. व. 2019-20	2019		2020		वि. व. 2019-20	2019		2020	
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	सितं.		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
ए. अन्य भुगतान चैनल										
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	-	-	20919.08	22713.54	-	-	704109	796402		
1.1 इंटर-बैंक \$	-	-	1907.78	2103.16	-	-	145405	158866		
1.2 इंटर-बैंक \$	-	-	19011.30	20610.38	-	-	558703	637535		
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	-	-	2822.04	2977.78	-	-	3436124	3407315		
2.1 इंटर-बैंक @	-	-	594.83	619.27	-	-	1678942	1646090		
2.2 इंटर-बैंक @	-	-	2227.20	2358.51	-	-	1757182	1761225		
बी. एटीएम										
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	-	-	5094.80	5688.24	-	-	243667	271622		
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	4.36	4.85	-	-	217	240		
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	5067.91	5658.36	-	-	242649	270488		
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	22.53	25.04	-	-	801	893		
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	-	-	33.62	42.54	-	-	123	156		
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	29.39	29.24	-	-	118	129		
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	4.23	13.30	-	-	5	27		
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	-	-	717.65	720.69	-	-	17096	18354		
5.1 एईपीएस @	-	-	717.65	720.69	-	-	17096	18354		

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	वि. व. 2019-20	2019		2020	
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	सितं.
	1	2	3	4	
भुगतान प्रणाली अवसंरचना					
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	-	-	9241.29	9335.85	
1.1 क्रेडिट कार्ड	-	-	586.94	594.20	
1.2 डेबिट कार्ड	-	-	8654.35	8741.65	
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	-	-	19960.47	19360.27	
2.1 वॉलेट @	-	-	18287.99	17795.35	
2.2 कार्ड @	-	-	1672.48	1564.92	
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	-	-	2.34	2.34	
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	-	-	2.10	2.10	
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	-	-	0.24	0.24	
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	-	-	3.28	3.49	
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	-	-	51.86	53.94	
6 भारत क्यूआर @	-	-	22.99	26.05	
7 यूपीआई क्यूआर *	-	-	604.07	657.45	

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2018-19	2019		2020	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	115714	9839	15814	15184	16911
	बकाया	918459	899191	1015010	1030037	1046766
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	91108	7130	12117	11091	11460
	बकाया	618418	606920	693812	704903	716363
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	31037	2360	3455	3106	2690
	बकाया	140247	134863	150462	153568	156258
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-31	-19	-31	-25	-20
	बकाया	3107	2877	2984	2959	2939
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	53	0	-827	-2	-3
	बकाया	10	-8	-18	-20	-23
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	10967	928	1753	1712	1887
	बकाया	192658	191653	203460	205172	207059
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	13990	1184	2070	2133	2131
	बकाया	55708	54446	69464	71597	73728
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25000	2451	4296	3999	4494
	बकाया	124292	121687	152622	156621	161115
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	71534	70179	86344	88247	90327
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	5910	5824	6749	6854	6970
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6901	6910	7328	7397	7464
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	39947	38774	52201	54123	56354
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	10081	215	1401	168	281
	बकाया	102401	101407	114842	115010	115291
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	11	11	0	0	0
	बकाया	-26	-26	-25	-25	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	16067	1732	3326	3524	3937
	बकाया	221517	219257	240900	244267	248022
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	11318	1262	2272	2458	2619
	बकाया	98492	94795	110050	112508	115127
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	334	3	0	0	1
	बकाया	263	300	-289	-289	-288
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18678	-1609	-971	-1713	-1120
	बकाया	19303	21232	6782	5069	3949
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	23018	2065	2025	2782	2452
	बकाया	93630	91314	113273	116055	118507
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	93	12	0	-1	0
	बकाया	2	-47	-179	-180	-180
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-18	-1	0	-2	-15
	बकाया	-80	-82	-82	-84	-99
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	9907	11745	11345	11188	11006
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	8539	977	371	569	1514
	बकाया	78524	73014	80298	80867	82381

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों के डाटा के अनुसार निवल प्राप्तियाँ हैं अर्थात् सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान।

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

श्रेणी	केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां				
	2019		2020		
	सित्त.	दिसं.	मार्च	जून	सित्त.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	6314426	6512659	6486585	6704983	7137069
1. वाणिज्य बैंक	39.66	39.05	40.41	38.98	38.55
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.42	0.39	0.39	0.36	0.34
3. बीमाकृत कंपनियां	24.86	24.90	25.09	26.24	25.33
4. म्यूच्युअल फंड	0.77	1.53	1.43	2.02	2.42
5. सहकारी बैंक	2.01	1.97	1.90	1.86	1.86
6. वित्तीय संस्थाएं	1.15	1.14	0.53	1.19	1.42
7. कॉरपोरेट	0.92	0.84	0.81	0.78	0.94
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.31	3.33	2.44	1.79	2.05
9. भविष्य निधियां	4.87	4.93	4.72	4.96	4.77
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	14.99	14.72	15.13	14.70	15.00
11. अन्य	7.05	7.23	7.17	7.11	7.32
11.1 राज्य सरकार	1.99	1.97	2.05	1.99	1.86

श्रेणी	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां				
	2019		2020		
	सित्त.	दिसं.	मार्च	जून	सित्त.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	2905169	3047353	3265990	3393099	3564979
1. वाणिज्य बैंक	32.53	32.46	34.99	33.54	34.60
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.72	0.64	0.76	0.74	0.54
3. बीमाकृत कंपनियां	33.39	32.50	31.63	30.85	30.26
4. म्यूच्युअल फंड	1.12	1.20	1.14	1.74	1.96
5. सहकारी बैंक	4.24	4.16	4.12	4.38	4.19
6. वित्तीय संस्थाएं	0.33	0.31	0.11	1.96	1.92
7. कॉरपोरेट	0.28	0.31	0.30	0.31	0.39
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	22.36	23.66	22.22	21.70	21.31
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	4.98	4.73	4.71	4.78	4.80
11.1 राज्य सरकार	0.16	0.17	0.18	0.18	0.18

श्रेणी	खजाना बिल				
	2019		2020		
	सित्त.	दिसं.	मार्च	जून	सित्त.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	538041	514588	538409	881362	982286
1. वाणिज्य बैंक	50.81	45.19	61.06	46.11	53.50
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.92	2.07	2.26	1.48	2.16
3. बीमाकृत कंपनियां	5.55	5.76	7.45	4.64	4.06
4. म्यूच्युअल फंड	14.08	20.42	13.24	23.45	19.90
5. सहकारी बैंक	2.55	2.07	2.55	1.95	1.63
6. वित्तीय संस्थाएं	1.82	2.12	0.58	1.67	1.34
7. कॉरपोरेट	1.57	1.66	1.89	1.43	1.63
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.01	0.01	0.02	0.05	0.00
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	11.27	4.80
11. अन्य	21.70	20.70	10.95	7.95	10.99
11.1 राज्य सरकार	17.91	16.36	6.22	4.35	7.76

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सं.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	3760611	4265969	4515946	5040747	5875914	6470254
1.1 गतिविधियां	2201287	2537905	2635110	2882758	3486519	3818358
1.1.1 राजस्व	1668250	1878417	2029044	2224367	2708218	2920507
1.1.2 पूंजी	412069	501213	519356	596774	694262	794599
1.1.3 ऋण	120968	158275	86710	61617	84038	103252
1.2 गैर गतिविधियां	1510810	1672646	1812455	2078276	2295105	2556504
1.2.1 राजस्व	1379727	1555239	1741432	1965907	2171963	2421566
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	648091	724448	814757	894520	969344	1091617
1.2.2 पूंजी	127306	115775	69370	111029	121159	132961
1.2.3 ऋण	3777	1632	1654	1340	1984	1977
1.3 अन्य	48514	55417	68381	79713	94290	95393
2. कुल प्राप्तियां	3778049	4288432	4528422	5023352	5779396	6524526
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2748374	3132201	3376416	3797731	4338225	4828088
2.1.1 कर प्राप्तियां	2297101	2622145	2978134	3278947	3547958	3951657
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1440952	1652377	1853859	2030050	2157126	2436871
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	852271	965622	1121189	1246083	1386652	1510287
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3878	4146	3086	2814	4180	4500
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	451272	510056	398282	518783	790267	876430
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	35779	33220	34224	36273	33272	30911
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	59827	69063	142433	140287	129507	232172
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	16561	20942	42213	44667	62499	18302
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	43266	48122	100219	95621	67008	213870
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	952410	1064704	997097	1102729	1408183	1409995
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	231090	617123	144792	387091	518093	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	60472	195816	-144847	325987	190241	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	708572	429585	844375	710119	885156	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	673298	689821	794856	795845	962386	1105573
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	80015	35038	71222	88961	213430	213430
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	35261	45688	42351	51004	42900	42529
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-3322	-6436	18423	-18298	-241	2978
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	13470	17792	25138	66289	32949	35987
3ख.1.6 नकद शेष	-17438	-22463	-12476	17395	96518	-54272
3ख.1.7 अन्य	158378	287268	49653	96014	55309	59147
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.3	27.7	26.4	26.6	28.9	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.4	27.9	26.5	26.5	28.4	29.0
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	20.0	20.3	19.7	20.0	21.3	21.5
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.7	17.0	17.4	17.3	17.4	17.6
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	6.9	5.8	5.8	6.9	6.3

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अक्टूबर 2020 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	1074	31	2003	31	1216	17
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	602	12	-	-	-	-
6	गोवा	112	27	93	19	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	236	1	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	573	27	244	9
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	1135	29	402	6
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	42	27	273	19	36	9
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	63	19	-	-
19	नगालैंड	187	31	207	23	124	10
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	439	10	137	8	-	-
23	राजस्थान	1580	27	753	13	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	1067	31	1359	29	733	14
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	312	25	585	20	234	3
29	पश्चिम बंगाल	165	8	163	6	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	अक्टूबर 2020 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8360	822	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1513	2	--	-
3	असम	4522	55	--	-
4	बिहार	7029	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4465	--	1	4750
6	गोवा	600	302	--	-
7	गुजरात	8585	485	--	-
8	हरियाणा	1401	1212	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	89	--	--	-
12	कर्नाटक	4268	--	--	21500
13	केरल	2167	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	926	--	-
15	महाराष्ट्र	41486	432	--	26000
16	मणिपुर	381	101	--	-
17	मेघालय	669	36	9	-
18	मिज़ोरम	467	39	--	-
19	नगालैंड	1656	33	--	-
20	उड़ीसा	13515	1466	85	20805
21	पुदुचेरी	296	--	--	807
22	पंजाब	701	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	2000
24	तमिलनाडु	6682	--	40	14678
25	तेलंगाना	5707	1245	--	-
26	त्रिपुरा	375	9	--	-
27	उत्तराखंड	566	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3190	80	--	-
29	पश्चिम बंगाल	8874	539	214	-
	कुल	127565	7784	665	90540

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियाँ

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2018-19		2019-20		2020-21						2020-21 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	अगस्त		सितंबर		अक्टूबर		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	30200	23824	42415	33444	5250	4667	7000	6417	6000	5417	37250	32584
2	अरुणाचल प्रदेश	719	693	1366	1287	-	-	-	-	-	-	428	428
3	असम	10595	8089	12906	10996	-	-	2300	2300	2000	2000	5300	5300
4	बिहार	14300	10903	25601	22601	4000	4000	4000	4000	4000	4000	16000	15000
5	छत्तीसगढ़	12900	12900	11680	10980	1300	1300	700	700	2000	1000	4000	3000
6	गोवा	2350	1850	2600	2000	200	200	400	400	200	-	1700	1400
7	गुजरात	36971	27437	38900	28600	5000	4000	5500	4500	3000	1000	22780	16823
8	हरियाणा	21265	17970	24677	20677	3000	3000	4500	4500	2000	1200	20500	17900
9	हिमाचल प्रदेश	4210	2108	6580	4460	-	-	-	-	1500	1500	2000	1200
10	जम्मू और कश्मीर	6684	4927	7869	6760	800	300	1405	1405	500	500	5205	3705
11	झारखंड	5509	4023	7500	5656	-	-	-	-	2600	2600	2600	2100
12	कर्नाटक	39600	32183	48500	42500	7000	7000	10000	10000	8000	6000	37000	35000
13	केरल	19500	13984	18073	12617	1000	1000	2000	2000	-	-	15930	15930
14	मध्य प्रदेश	20496	15001	22371	16550	2000	2000	2000	2000	3000	3000	14000	14000
15	महाराष्ट्र	20869	3107	48498	32998	3000	2154	14000	12000	11000	8673	59500	52450
16	मणिपुर	970	667	1757	1254	100	100	-	-	-	-	700	700
17	मेघालय	1122	863	1344	1070	-	-	600	550	250	250	1050	1000
18	मिज़ोरम	0	-123	900	745	-	-	132	132	-	-	442	342
19	नगालैंड	822	355	1000	423	-	-	150	150	250	150	750	550
20	उड़ीसा	5500	4500	7500	6500	-	-	-	-	-	-	3000	3000
21	पुदुचेरी	825	475	970	470	-	-	225	225	125	125	350	350
22	पंजाब	22115	17053	27355	18470	2250	1750	4410	3010	2785	535	14895	9945
23	राजस्थान	33178	20186	39092	24686	3450	2950	3500	3500	3000	1730	30450	23868
24	सिक्किम	1088	795	809	481	-	-	148	148	-	-	615	615
25	तमिलनाडु	43125	32278	62425	49826	9250	7375	3250	2000	6000	4125	54000	46194
26	तेलंगाना	26740	22183	37109	30697	3000	2583	4500	4083	3000	2583	25961	22627
27	त्रिपुरा	1543	1387	2928	2578	-	-	400	400	300	300	700	600
28	उत्तराखंड	46000	33307	69703	52744	1000	-200	6000	4000	8000	5524	21500	8791
29	उत्तरप्रदेश	6300	5289	5100	4500	-	-	1500	1500	1200	1200	3700	3000
30	पश्चिम बंगाल	42828	30431	56992	40882	4000	3500	4500	3000	3500	2500	25500	16500
	कुल	478323	348643	634521	487454	55600	47679	83120	72920	74210	55912	427806	354902

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
- 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
- 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
- 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
- 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
- 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
- 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
- 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
- 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम्₂ और एनएम्₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
- 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
- 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाए गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वेप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओ/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रेडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

○ बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।

○ जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2020-21 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खजाना बिलों (364-दिन के खजाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

:- नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खजाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2020	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैडबुक 2019-20	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैडबुक 2019-20	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2020-21 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1 और 2, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपेपर, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001।

एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।